

# **GURUKUL INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL**

**Quarterly**

**Jun – 2017**

**Issue – II**

**Volume – VII**

**UGC Approved Journal Sr. No. 48455**

**ISSN No. 2394-8426**

**International Impact Factor 2.254**



Online Published By

**Chief Editor**

**Mr. Mohan Hanumantrao Gitte**

Mob. No.: +91 92 73 75 9904

mohan.gitte@gmail.com,  
info@gurukuljournal.com

**Website**

**<http://gurukuljournal.com/>**

## Index

Paper No.	Title	Author	Page No.
1	21वीं सदी एवं अस्पृश्यता	डॉ० मकरन्द जायसवाल	1-6
2	शिक्षा का भूमंडलीकरण : एक समीक्षात्मक अध्ययन	डा० अनिल कुमार मिश्र	7-10
3	जाहिरात संस्थेची जाहीरात व्यवस्थापनात गरज	प्रा. राजेश एस. डोंगरे	11-13
4	स्थानिक स्वराज्य संस्थामधिल महिला नेतृत्व व वास्तविकता	डॉ. एन.आर. चिमुरकर	14-17
5	Extroversion and Introversion: A comparative study of cast and culture among college students	Dinesh R. Jaronde	18-21
6	The Ethical Issues in Accounting- What Yet and How Long?	Dr. Kajalbaran Jana	22-25
7	A Study On Local Body Elections In Tamil Nadu	S. Mohan & Dr.D. Ramakrishnan	26-31
8	The Effectiveness Of E- Banking Environment In Customer Life Service An Empirical Study	J Murali Krishnan	32-41
9	महाराष्ट्र राज्यातील दुग्धव्यवसाय : एक अभ्यास	वर्षा दामोदर शिंदे मधुकर पिराजी शेळके	42-47
10	महाराष्ट्रातील दारिद्र्य-एक आढावा	ज्योती मच्छिंद्र कांबळे	48-52
11	महाराष्ट्रातील रोजगार व स्वयंरोजगार निर्मितीत अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे योगदान	विलास आबासाहेब नरवडे	53-57
12	Analysis Of Parliamentary Elections (2014) In Punjab	Dr. Neeru Sharma	58-69
13	महिला सशक्तिकरण : गांधी जी के विचार	डॉ० राजीव कुमार	70-75
14	पंचायतराज व्यवस्थेमधील महिलांची स्थिती : एक आढावा	प्रा.डॉ. राजेंद्र सदाशिव मुद्दमवार	76-77
15	शैक्षणिक तंत्रज्ञान : शैक्षणिक गुणवत्ता विकासाचे प्रभावी साधन	श्री. प्रफुल एस. सिडाम	78-82
16	आधारभूत संरचनेचे आर्थिक विकासातील महत्व आणि भारतातील ऊर्जा आधार संरचना	प्रा. एस. एम. कोल्हापूर, प्रा. डॉ. वाय. एस. गायकवाड	83-88
17	Social Media Marketing	Dr. H. M. Kamdi	89-94
18	Symbolic Applications On Legacy Data In Libraries	Prof. Vijay Malekar, Dr. D. W. Deote	95-100
19	The Effective Communication Process - The Life Blood Of The Organization	Dr. Prashant M. Puranik	101-103
20	स्मरण प्रतिमान व संकल्पनाप्राप्ती प्रतिमानाची माध्यमिक स्तरावर परिणामकारकता -एक प्रायोगिक अध्ययन	आर. एम. माणुसमारे	104-107
21	Chronic Mass Poverty in India - a Social Perspective	Balasaheb A. Sarate	108-115
22	कुसुमाग्रजांच्या प्रेमकाव्यातील अंतरंग	प्रा. संतोष सदाशिव देठे	116-119
23	Maharashtra: A Global Health Destination	Prof. Dr. Sadashiv Laxman Shiragave & Mrs. Rupali M. Patil	120-127
24	A Study On Work-Life Balance Of Married Working Women With Reference To Co-Operative Banks, Solapur	Prof. Pedda Nagaratna S.	128-135
25	Information Need And Access Pattern Of Homoeopathic Teachers Of Bharatesh Homoeopathic	Mrs. Sunita S. Patil & Dr. Maranna .O.	136-140

	Medical College: A Study		
26	शेती विकासातील संबंधीत सार्वजनिक कंपन्या	प्रा. डॉ. एस.एल. शिरगावे & शेख कमरुन्निसा अ.हमीद	141-145
27	कुसुमाग्रजांच्या कवितेतील सामाजिकता	प्रा. संतोष सदाशिव देठे	146-149
28	A Study of 'corporate governance' effectiveness through Board Structure	Dr.Sadashiv L Shiragave, Mr. Sanjay P. Parab	150-161
29	India's Internal Security : Conceptual Perspective	Dr. Arvind Kumar	162-169
30	अंगणवाडीत जाणाऱ्या व किंडरगार्डनमध्ये जाणाऱ्या मुलांचा भाषाविकासाचा तुलनात्मक अभ्यास	प्रा. सविता आप्पासाहेब लोखंडे & डॉ. बालाजी रंगनाथराव लाहोरकर	170-174
31	ग्रामीण विकासातील महात्मा गांधीजींचे योगदान	डॉ. रामदास तु. कुलसंगे	175-178
32	घरगुती हिंसा एक समस्या	डॉ. किशोर उत्तमराव राऊत	179-183
33	बी.एड. कॉलेज मध्ये सूक्ष्माध्यापनापूर्वी आयोजलेल्या पाठ्यपुस्तक ओळख या उपक्रमाच्या परिणामकारकतेचा चिकित्सक अभ्यास	प्रा. सविता आप्पासाहेब लोखंडे & डॉ. बालाजी रंगनाथराव लाहोरकर	184-188
34	Professional Development Programme: Developing Coping Skills in Adolescents	Dr. Rashmi Singh	189-192
35	बीड जिल्ह्यातील जि.प.प्रा.शाळेत शैक्षणिक तंत्रज्ञानाच्या साधनांची उपलब्धता एक अभ्यास	गित्ते त्रिंबक गोविंद & डॉ.अंधारे एस.जी.	193-195
36	Quality Function Deployment Implementation for Characteristics Identification to Prevent Sand Inclusion Defect in Cast Iron Castings	V. S. Deshmukh, Dr. S.S.Sarda	196-199
37	परंपरागत समाजाभिमुख पर्यावरणपूरक बांबूव्यवसाय	डॉ.एस.एस.कावळे	200-204
38	आदिवासींच्या संदर्भातील शासनाच्या शैक्षणिक योजना आणि आदिवासी विकास	प्रा. शुभांगी रमेश भेंडे	205-210
39	भारतातील दारिद्र्याचे कारणे व उपाययोजना	प्रा.डॉ.नरेंद्र श्रीधर बागडे	211-214
40	बाल कामगार समस्येचे कारणे व उपाययोजना	प्रा.डॉ.कल्पना मंडलेकर	215-218
41	मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन	डॉ. सुभाष यादव	219-227

## 21वीं सदी एवं अस्पृश्यता

डॉ० मकरन्द जायसवाल

एसिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र)

के०बी०पी०जी० कालेज, मीरजापुर

जातीय संस्तरण में बटा हुआ भारतीय समाज में छुआ छूत या अस्पृश्यता का दंश अत्यन्त प्राचीन है, इसकी जड़ें बहुत ही गहरी हैं, जिसे बुद्ध, महावीर से लेकर महात्मा गांधी तक अनेकों लोगों के प्रयास के बाद भी यह 21वीं सदी में भी विद्यमान है, प्रस्तुत अध्ययन में भारतीय समाज में विद्यमान इसी रोग के विभिन्न स्वरूपों आयामों एवं बदलते प्रतिमानों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, ऐसा करने में एक ओर जहां अस्पृश्य जातियों द्वारा नई सामाजिक स्थिति की प्राप्ति तथा नये तदात्म्य की खोज के लिए की जाने वाली पहल का भी व्यवस्थित अध्ययन किया गया है, वहीं पिछड़ी जातियों की इस सम्बन्ध में प्रतिक्रिया को भी समझने की चेष्टा की गयी है, प्रस्तुत लेख पूर्वांचल के दो गांवों में ग्रामीण आधुनिकीकरण के अध्ययन के संदर्भ में प्राप्त तथ्यों पर आधारित है।

भारत जातियों का देश है, जिसके प्रभाव में आकर अन्य धर्मों के लोगों ने भी इसका अभ्यास प्रारम्भ कर दिया है, यह अस्पृश्यता एक सामाजिक यथार्थ है, इसका अस्तित्व सामाजिक यथार्थ के प्रमुख तीनों आयामों व्यक्ति समाज एवं संस्कृति ने समान रूप से देखा जा सकता है। वैयक्तिक आधार पर आज समाज में हमें तीन प्रकार के व्यक्तित्व देखने को मिलते हैं। पहली श्रेणी में आधुनिक व्यक्तित्व को रखा जा सकता है। यह आधुनिक परिस्थितियों से समायोजन करने में तुलनात्मक रूप से अधिक सफल होता है। व्यवहार में आधुनिक व्यक्ति वैयक्तिक स्वार्थ को प्राथमिकता देता है, साधारणतः ऐसे व्यक्ति महानगरों एवं नगरों में पाये जाते हैं यद्यपि ये गांवों में भी हो सकते हैं। नगरों में एक तो व्यक्ति की परम्परात्मक पहचान कम होती है, दूसरे वैयक्तिक योग्यता व क्षमता की तुलना में व्यक्ति की परम्परात्मक स्थिति का नगरीय जीवन में कोई मूल्य नहीं होता, जीवन में प्रतिस्पर्धा एवं भाग दौड़ अधिक होने के कारण नगरों में व्यक्ति बाजार में खाते समय, दुकानों से समान खरीदते समय बसों या रेल में यात्रा करते समय अथवा कारखानों या घरेलू कामकाज के लिए नौकर रखते समय जाति-पांति पर नहीं बल्कि अन्य चीजों पर ध्यान देता है, यद्यपि लौकिक आचरण एवं व्यवहार में आधुनिक व्यक्ति अस्पृश्यता व जाति-पांति के भेदभाव से मुक्त होता है, फिर भी व्यक्तिगत सामाजिक सम्बन्धों के मामले में वह तुलनात्मक रूप से अधिक उदार भले हो किन्तु जाति और वर्ग की सीमाओं से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता।

इसके विपरीत परम्परावादी व्यक्तित्व बाह्य धार्मिक आडम्बर से अनुप्रेरित तथा परम्परात्मक मानसिक जड़ता से ग्रसित होता है, सामान्यता ऐसे व्यक्ति ग्रामीण संचरना के अंग होते हैं जो आधुनिक शिक्षा व मूल्यों से कम परिचित होने के कारण विचार और दृष्टिकोण से

पुरातनवादी व अनुदार होते हैं। छुआछूत एवं सामाजिक भेदभाव के प्रति अधिक सचेत एवं कठोर होते हैं। तीसरे वर्ग में गतिमान व्यक्तित्व को रखा जा सकता है, गतिमान व्यक्तित्व परम्पराओं से उपर उठा तो अवश्य है, किन्तु आधुनिकता के अपेक्षित स्तर प्राप्त नहीं कर सका है, अस्पृश्यता के निराकरण की दृष्टि से इसकी पहल कमोवेश निष्क्रिय या उदासीन जैसी है, यह सैद्धान्तिक रूप से अस्पृश्यता के पक्ष में नहीं है किन्तु व्यवहारिक रूप से इसके प्रति अधिक सचेत या जागरूक भी नहीं है, कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के लोग जो समाज में आज अधिक संख्या में हैं व्यक्तिगत रूप से जन्मजात अस्पृश्यता को बुरा और त्याज्य मानते तो हैं किन्तु इसके विरुद्ध वे समाज एवं समुदाय से विरोध मोल लेने का साहस नहीं करते हैं, अस्पृश्य को स्पृश्य मान लेने भर से वे समझते हैं कि उनके कर्तव्यों की इतिश्री हो गयी या समाज में अस्पृश्यता का लोप हो गया और ऐसा करके उन्होंने सम्पूर्ण समाज या अस्पृश्यों पर कोई बहुत महान कार्य किया है।

अस्पृश्यता की धारणा केवल उच्च या मध्यम जातियों से ही सम्बद्ध नहीं है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यों में भी दूसरे के प्रति अथवा अस्पृश्यों की उच्च जातियों के प्रति हो सकती है। यह आवश्यक नहीं कि उच्च जातियां ही सामाजिक भेदभाव अधिक बरतती हो अस्पृश्यता की मनोवृत्ति जाति में नहीं बल्कि पिछड़ेपन एवं परम्परागत दृष्टिकोण से सम्बन्धित है, जबकि खुलापन आधुनिकीकरण का द्योतक है।

तुलनात्मक रूप से उच्च जातियां आधुनिकीकरण के अधिक निकट आ चुकी है, इसलिए वे सामाजिक विचार से उदार भी हुई है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी क्षेत्र का आर्थिक एवं तकनीकी विकास, शिक्षा एवं संचार माध्यमों का प्रसार, व्यवसाय का अधिकाधिक लौकिकीकरण तथा किसी अंश तक नगरीय सम्पर्क जो व्यक्ति में आधुनिकता के विकास में सहायक है अस्पृश्यता व सामाजिक भेदभाव के निराकरण में भी महत्वपूर्ण है। सामाजिक आधार पर व्यवहार के दोहरे मानदण्ड आज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आसानी से देखे जा सकते हैं, शहरों में अस्पृश्यता व सामाजिक भेदभाव हटा है किन्तु गांवों में कमोवेश अभी भी बना हुआ है, व्यक्ति जब शहर या दफ्तर में होता है तो वह इससे मुक्त होता है, किन्तु वहीं जब गांव या घर में होता है तो जातीय एवं सामाजिक बन्धनों के दायरे में आ जाता है।

शहरों में लोग एक दूसरे को नहीं जानते, यहां मंदिरों में आने-जाने, होटल या जलपान गृह आदि में खाते-पीते हैं। मॉल या मल्टीप्लेक्स में सिनेमा साथ-साथ बैठ कर देखते हैं किन्तु गांवों में सवर्ण अभी भी चमार, धोबी, खटीक या अन्य अस्पृश्यों के यहां पानी नहीं पीते हैं, गांवों में पूजा स्थलों पर अस्पृश्यों को जाने की अब मनाही तो नहीं है फिर भी छुआ छूट का भेदभाव किसी न किसी स्तर पर बना हुआ है। प्रायः देखा गया है कि ऐसे गांवों में जहां मंदिरों की देखभाल के लिए अलग पुजारी होते हैं, अस्पृश्य लोग भगवान की पूजा फाटक के बाहर से ही कर पाते हैं, फाटक के भीतर जाकर भगवान को जल पुष्प एवं प्रसाद चढ़ाने का अवसर उन्हें नहीं मिलता, हालांकि यह सब कार्य पुजारी स्वयं करते हैं और साधारणतः अस्पृश्यों को अन्दर जाने की अनुमति नहीं होती। सामान्यतः ब्राह्मण पुरोहिती का कार्य

हरिजनों व अन्य अस्पृश्यों के यहां नहीं करते, किन्तु अब ब्राह्मण उनके यहां शादी विवाह कराने तथा मंदिरों में पूजा पाठ एवं कथा का कार्य करने लगे हैं, फिर भी ब्राह्मण तथा अन्य उनके यहां का प्रसाद तभी ग्रहण करते हैं जबकि यह उनके द्वारा किसी सवर्ण के घर या सवर्णों के बर्तनों में बनवाया गया हो, अस्पृश्यों के यहां पुरोहिती का कार्य प्रायः गरीब, तुलनात्मक रूप से कम प्रवीण तमाम ऐसे ब्राह्मण करते हैं जिनके पास सवर्ण जनमानों का अभाव होता है, सवर्णों के पुरोहितों की तुलना में अस्पृश्यों के यहां पुरोहिताई करने वाले ब्राह्मणों को नीची नजरों से देखा जाता है।

सामाजिक अन्तःक्रिया के चार मुख्य दायरे वैयक्तिक पारिवारिक, सामुदायिक एवं सार्वजनिक हमें देखने को मिलते हैं। सार्वजनिक आधार पर अस्पृश्यता समाप्त कर दी गयी है, जब कि वैयक्तिक आधार पर जैसा हम लोगों ने पहले देखा कि अस्पृश्यता यदि पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है, तो इसमें भारी गिरावट अवश्य आई है, किन्तु अस्पृश्यों की नियोग्यताओं का परम्पराओं द्वारा निश्चित तथा सामाजिक रूप से लागू होने के कारण अस्पृश्यता को समाप्त करने की कानूनी घोषणा कर देने भर से अस्पृश्यता न तो समाप्त हो पायी है और न अस्पृश्यों की नियोग्यताएं ही दूर हो सकी है। व्यापक सामाजिक आधार पर दीर्घकालीन अस्तित्व ने अस्पृश्यता को भारतीय समाज में संस्थागत स्वरूप दे दिया है, इसलिए पारिवारिक व सामुदायिक जीवन में अस्पृश्यता बहुत कुछ ज्यों की त्यों बनी हुई है, सूट व टाई पहन कर कोई भी सवर्ण आफिस ने तो अस्पृश्यता या भेदभावत नहीं करता किन्तु वैयक्तिक जीवन में वह इसका पूर्ण रूपेण पालन करता है।

जहां तक सवर्णों का अस्पृश्यों के साथ आवास का प्रश्न है अभी भी इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हो सका है, गावों में अस्पृश्यों की बस्तियां अभी सवर्णों से पृथक है, हाँ आबादी बढ़ने के साथ कहीं-कहीं आवासीय दूरियां कम अवश्य हुई हैं, किन्तु आवासीय दूरियों के मिटने पर सामाजिक अन्तः क्रियाओं की सीमाएं अभी बनी हुयी है, शहरों में भी मकान किराये पर लेते देते समय, शासकीय व अर्द्धशासकीय गृहों के आवंटन के समय, छात्रावासों में कमरों के चुनाव आदि के समय कमोवेश जाति-पांति व छुआ छूत की भावना काम करती हैं, समान श्रेणी के अधिकारियों में अस्पृश्य जातियों को कार्यालय के बाहर समान श्रेणी का दर्जा नहीं दिया जाता है।

अस्पृश्यता से मुक्ति का दूसरा नाम समानता की पहल है, इसे अस्पृश्यों ने अब भली भांति समझ लिया है, समानता के प्रारम्भिक दौर में एक तरफ जहां अस्पृश्यों ने निम्न व गन्दे कार्यों का परित्याग किया, वहीं ऊंची जातियों ने संस्कारों जैसे जनेऊ पहनना, सवर्णों जैसे नाम एवं उपनाम रखना खान-पान, रहन-सहन तथा पूजा पाठ आदि में उनका बहुत कुछ अनुकरण भी किया है, उनके इन कार्यों और तदजनित सामाजिक संरचना में परिवर्तन को विद्वानों ने संस्कृतिकरण का नाम दिया है, इस प्रक्रिया का दूसरा दौर पाश्चात्त्यीकरण है, यह प्रक्रिया नगरों में काम करने वाले तुलनात्मक रूप से अधिक शिक्षित एवं लौकिक व्यवस्थाओं में लगे अस्पृश्यों में अधिक सामान्य है, इसके प्रभाव स्वरूप जनेऊ तथा पराम्परात्मक नाम व उपनाम



का परित्याग तथा आधुनिक नाम धारण करने, आधुनिक किस्म का रहन-सहन अपनाने तथा खान-पान एवं बात-बर्ताव करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। वास्तव में सामाजिक समानता की दौड़ में पिछड़ी जातियों ने जहां उच्च जातियों के संस्कार एवं मूल्यों को अपनाने की पहल की, वहीं उच्च जाति के लोगों का झुकाव पाश्चात्य रहन-सहन व मूल्यों की ओर अधिक गया है।

सांस्कृतिकरण के माध्यम से अपने में वांछित परिवर्तन लाने के उपरान्त भी परम्परात्मक आयाम पर पिछड़ी जातियां, उच्च जातियों के समानान्तर नहीं आ सकी है जबकि ऊंची जातियों पाश्चात्य जीवन मूल्यों को तेजी से अपनाते हुए आधुनिकता के आयाम पर इन्हें और अधिक मात दे रही है। इसका परिणाम यह हुआ है कि परम्परात्मक पैमाने पर तो ऊंची जातियों की दूरियां बहुत कुछ यथावत बनी रही, जबकि आधुनिकता की दौड़ में ऊंची व नीनी जातियों के बीच सामाजिक अन्तराल और बढ़ गया, वास्तव में आधुनिकीकरण के प्रारम्भिक दौर में सामाजिक विभेदों का बढ़ना अथवा अन्तर्विरोधों का उजागर होना स्वाभाविक है किन्तु यह स्थिति लम्बे समय तक नहीं रह सकती, यह बहुत सम्भव है कि आधुनिकीकरण के विकास के साथ समाज में समरूपता, समानता एवं संगति की प्रवृत्तियां अधिक शक्तिशाली हो।

वर्तमान समय में सामाजिक गतिशीलता का अधिक प्रभावकारी साधन अधिकाधिक राजनैतिक सहभागीकरण हो गया है, प्रजातान्त्रीकरण और वयस्क मताधिकार के फलस्वरूप राजनैतिक सत्ता को प्राप्त करना पिछड़ी एवं निम्न जाति के लोगों के लिए अब अधिक सरल एवं सम्भव हो गया है, राजनैतिक शक्ति का संचय जहां व्यक्ति एवं समूह के आर्थिक व शैक्षणिक हितों की वृद्धि में सहायक है, वहीं उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का परिचायक भी है, इसलिए निम्न जातियों ने यह स्पष्ट रूप से अनुभव कर लिया है कि उनके हाथ में आवश्यक सत्ता आने के बाद ही उनके लिए उच्च जातीय प्रतीकों व मूल्यों का अपनाना सहज व अर्थपूर्ण होगा, परिणाम स्वरूप राजनैतिक सत्ता हथियाने के लिए समाज में संघर्ष तीव्रतम हो गया है, व्यक्ति येक-केन प्रकारेण अपनी राजनैतिक स्थिति मजबूत करने में लगा है।

भारत में सामाजिक निकटता एवं अन्तःक्रिया क्षेत्र के रूप में जाति का अभी दूसरा विकल्प विकसित नहीं हो सका है, इसलिए जाति प्रत्यक्षा तथा परोक्ष रूप से राजनैतिक दांवपेंच व अखाडेबाजी का केन्द्र न गयी है, संविधान ने जाति धर्म व वंश से परे नागरिकता को सामाजिक गतिविधि का मूल आधार निरूपित किया है, किन्तु संविधान के तथाकथित रक्षकों ने वैयक्तिक व वर्गीय हितों की रक्षा के लिए परम्परागत आधारों को दोहन किया है, परिणाम स्वरूप या तो जातीय आधारों पर छोटे-छोटे राजनैतिक दलों का निर्माण हुआ है या बड़े राजनैतिक दल कमोवेश जातीय हितों के रक्षक के रूप में उभर कर आये हैं, जातियों के राजनैतिकरण के परिणाम स्वरूप दो पक्ष हमारे सामने उभरकर आये हैं, प्रथम जो जातीय आधार पर बने संगठन, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय के आस पास कभी बड़े सक्रिय थे, दूसरे राजनैतिक क्षितिज पर बहुत कुछ समान सामाजिक स्थिति रखने वाली जातियों का ध्रुवीकरण निकट वर्ती जातियों के संगठन के माध्यम से राजनैतिक सत्ता पर अधिक से अधिक नियंत्रण

प्राप्त करने के उद्देश्य से हुआ है जिससे कि सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर किया जा सके।

उम्मीदवारों के चुनाव के समय राजनैतिक दलों द्वारा मतदाओं की जातिगत एवं सम्प्रदायगत संख्या को प्राथमिकता दी जाती है, मतदाता भी कमावेश ऐसे दल के उम्मीदवार को प्राथमिकता देते हैं जो उनके जातीय हितों का पोषक हो और यदि उसके जीतने की सम्भावना कम होती है तो किसी ऐसे उम्मीदवार को चुनने हैं जो उनकी जाति का हो, राजनीति में जाति का प्रभाव निश्चित रूप से बढ़ा है, विशेष रूप में निम्न और मध्य जातियों में शिक्षा के प्रसार उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार तथा राजनैतिक जागृति के फलस्वरूप प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तरों पर राजनैतिक समीकरणों में बदलाव आया है, जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सम्बन्धी सुधारों के लागू किए जाने के फलस्वरूप ग्रामीण अंचल में भूमि उच्च जातियों से निम्न जातियों विशेष रूप से मध्य श्रेणी के किसान जातियों के हाथों में गयी, बढ़ती महंगाई एवं शारीरिक श्रम से बचने की प्रवृत्ति के कारण उच्च जातियों को ग्रामीण क्षेत्रों में अपना जीवन स्तर बनाए रखने में कठिनाई आई है, जबकि मध्य जातियों ने साधारण जीवन स्तर पर कठिन परिश्रम करते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है, फलस्वरूप गांवों में जमीन उच्च एवं कहीं-कहीं निम्न जातियों के हाथों से इन जातियों के हाथों में आयी है। आर्थिक संरचना की स्थिति मजबूत होने के साथ-साथ मध्यम जातियों के राजनैतिक प्रभाव में भी वृद्धि हुई है, इस परिवर्तन ने दबे या खुले रूप में अनेक संघर्षों को जन्म दिया है।

वास्तव में अस्पृश्यता की मूल समस्या सामाजिक समानता की समस्या है, जहां तक अस्पृश्यों की इस दिशा में पहल का प्रश्न है, इन संदर्भ में अम्बेडकर का प्रयास उल्लेखनीय है, अस्पृश्यों की मुख्य समस्या, उनकी दृष्टि में जन्म पर आधारित निम्न सामाजिक स्थिति का निवारण है, अस्पृश्यों की निम्न सामाजिक स्थिति का सम्बन्ध हिन्दू सामाजिक संरचना से जुड़ा हुआ है जो कठोर है, इसलिए इससे वास्तविक मुक्ति केवल हिन्दू समाज के लगाने पर ही सम्भव है, बहुत कुछ इसी कारण ही अम्बेडकर ने कहा कि "हिन्दू के रूप में जन्म लेना मेरे बस में नहीं था लेकिन हिन्दू के रूप में मैं मरुंगा नहीं।" किन्तु मानव की वास्तविक मुक्ति किस धर्म में निहित है, इस सम्बन्ध में अम्बेडकर विश्व के चार बड़े धर्मों की तुलना करते हुए कहते हैं कि यदि नये विश्व को धर्म की आवश्यकता है जो वास्तव में पहले की अपेक्षा अब कहीं अधिक है, तो इसकी पूर्ति केवल बौद्ध धर्म के द्वारा ही सम्भव है। अम्बेडकर और उनके अनुयायी गरीबी और सामाजिक विलगाव में भेद करते हैं, इन्हें गरीबी कम सामाजिक मजबूरी अधिक खटकती है, गरीब तो हर जगह और हर समाज में है और रहेंगे, किन्तु सामाजिक दृष्टि से जितने मजबूर हिन्दू समाज में अस्पृश्य है, उतने अन्यत्र नहीं है, गरीबी को दूर किया जा सकता है, किन्तु सामाजिक मजबूरी असाध्य है, अतः अम्बेडकर के लिए व्यवस्था में रह कर अस्पृश्यों की सामाजिक निर्योग्यता एवं भेदभाव को समाप्त कर पाना सम्भव नहीं था।

#### संदर्भ

1. अम्बेडकर बी०आर० — द बुद्ध एण्ड हिज़ धम्मा सिद्धार्थ पब्लिकेशन





मुम्बई-1974

द अनटचेबल्स : टू आर दे एजु हाई दे विकेम

अनटचेबल्स जोतबन महाविदार- बलरामपुर- 1970

2. श्री निवास एम0एन0 – कास्ट इन माडर्न इण्डिया एवं अदर एजेस  
बाम्बे पब्लिशिंग हाउस-मुम्बई-1962
3. माण्डेलबम डी0जी0 सोसाइटी इन इण्डिया – पापुलर प्रकाशन- मुम्बई-1972
4. ओमर टी0के0 – शिडयूल्ड कास्ट्स एण्ड शिडयूल्ड ट्राईब्स
5. राम नर्वदेश्वर – ग्रामीण शक्ति संचरना, समाजशास्त्र प्रकाशन वाराणसी-1976
6. दूबे- एस0सी0- रूरल सोशियोलॉजी इन इण्डिया पापुलर प्रकाशन मुम्बई-1969

## शिक्षा का भूमंडलीकरण : एक समीक्षात्मक अध्ययन

डा० अनिल कुमार मिश्र

एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग,  
डी०ए०वी० कालेज, कानपुर।

भूमंडलीकरण को बढ़ती भूमंडलीय अन्तर्सम्बद्धता के रूप में चित्रित किया जा सकता है। यह कोई परिणाम नहीं अपितु एक प्रक्रिया है, जो विश्व के विभिन्न भागों में बढ़ती अन्तर्सम्बद्धता की ओर झुकाव का इशारा करती है, न कि उनके परस्पर जुड़े होने की ओर। यह मुख्य रूप से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व प्रौद्योगिक सहजगुणों का एक विनिमय है जो समाजों के बीच उस वक्त होता है जब वे एक दूसरे से संपर्क में आते हैं।

भूमंडलीकरण की वर्तमान प्रक्रिया राष्ट्रीय नीतियों के वैश्वीकरण एवं राष्ट्रीय सरकारों की नीति निर्माण कार्ययोजनाओं में भी परिणत हुई है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों समेत राष्ट्रीय नीतियां जो कि अब तक किसी देश स्थित लोगों के अधिकार क्षेत्र में होती थी। उत्तरोत्तर अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों एवं बड़े निजी निगमों के प्रभाव में आती जा रही है। इन अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के बढ़ते दबावों के चलते राष्ट्रीय सरकारों को अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ा है जो कि मुक्त व्यापार में अधिक प्रयास और सामाजिक क्षेत्र में कम व्यय की अपेक्षा करती है। उन्हें करो में वृद्धि करनी पड़े या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, सफाई व्यवस्था, आवासीय परिदान, ईंधन, सार्वजनिक वितरण प्रणालियों एवं परिवहन आदि सामाजिक क्षेत्रों पर खर्चों को घटाकर सरकारी व्यय को कम करना पड़े। राष्ट्रीय सरकारों को जनउपभोग की अनिवार्य वस्तुओं या जिन्सों पर प्रयोज्य लागू मूल्य प्रणाली को सभारत करना पड़ा। भूमंडलीकरण के ताजा दौर में विश्व संगठनों की सापेक्षिक शक्ति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। एक ओर अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक के साथ-साथ व्यापार (WTO) एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो विश्व व्यापार को नियंत्रित करता है – भी अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। दूसरी ओर, विश्व संस्थाएं जिन्होंने अधिक मानव केन्द्रित हितों पर ध्यान केंद्रित किया है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की स्थिति पृष्ठभूमि में चली गई और कमजोर हो गई है। यह परिवर्तन विश्वस्तरीय परिवर्तन के कारण हुआ। अधिक शक्तिशाली संस्थाओं (IMF, WTO, WB) ने अर्थव्यवस्थाओं में बाजारों के बढ़े प्रयोग एवं कम सरकारी हस्तक्षेप की ओर अग्रसर किया है ताकि राष्ट्रीय सरकारों का नियंत्रण कम होने से व्यापार एवं पूंजी निवेश का मुक्त प्रवाह हो। विश्व संस्थाओं के शक्ति में यह बदलाव मानव जीवन के हर पहलू में प्रगट होता है। वैश्वीकरण के इस दौर में गरीब देश और गरीब हो रहे हैं और चुम्बकीय प्रवाह की तरह समृद्ध बर्गों की क्रय शक्ति बढ़ रही हैं। वैश्वीकरण का आधार वित्तीय पूंजी मुनाफे को अधिकाधिक बढ़ाने के लिये कोई भी आक्रामक स्वरूप में हर प्रकार की रियायत और आर्थिक सहायता जो गरीबों और मजदूरों का हक है, उसे भी छीन कर फैलाना लक्ष्य हो गया है।

अपने बाजार को बढ़ाने के लिये वह जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, गैस जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाओं और सहायता प्राप्त खाद्यान्नों तथा उर्वरकों का भी निजीकरण हो रहा है और कीमतें बढ़ रही हैं।

भारत एक विकासशील देश है। यहाँ 125 करोड़ लोग निवास करते हैं। किसी एक देश में निवास करने वाले सबसे अधिक गरीब व बेरोजगार यहीं पर हैं, सरकार गरीबी और बेरोजगारी के आंकड़ों को निरन्तर नये आधार व आंकड़ों के साथ प्रस्तुत करती है ताकि वैश्वीकरण उदारीकरण के औचित्य को सिद्ध कर सकें। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण इलाकों में गरीबी रेखा के नीचे जी रहे लोगों की संख्या 1998 में 45.3 प्रतिशत हो गयी है, जो 1990 में 35 प्रतिशत थी। यानि देश में आज 40 करोड़ की आबादी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है।

वैश्वीकरण और इसके सहउत्पाद उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों से भारतीय शिक्षा व्यवस्था के समक्ष एक बड़ा संकट खड़ा हुआ है। जिस देश की एक तिहाई आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रही हो उसकी शिक्षा व्यवस्था बाजार की शक्तियों के भरोसे छोड़ना उचित नहीं है। विशाल जनसंख्या की शिक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शैक्षिक बजट में बढ़ातरी जरूरी है जबकि वैश्वीकरण की नीतियाँ बजट को कम करने का दबाव बना रही हैं। उच्च शिक्षा के लिए सारी आर्थिक सहायताओं को खत्म करने तथा सभी संस्थाओं को आत्म-वित्तीयन (Self Finance) करने जैसे उपाय बताये जा रहे हैं। आत्मवित्तीयन के स्रोत होंगे, उपभोक्ता फीस को बढ़ाना, शिक्षा में किए गये निवेशों के लिए उद्योगों को कर में छूट देना और विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क प्रोत्साहित करना। उच्च शिक्षा की कई व्यवस्थाएँ निधियों की कमी के चलते चरमरा रही हैं। सरकार प्राथमिक स्तर से लेकर उच्चतम स्तर तक की शिक्षा पूँजीपतियों के हाथों में सौंप रही है। सरकार शिक्षा व्यवस्था में तीव्रता से निजीकरण के पक्ष में है ताकि उसे कम व्यय करना पड़े। इसके अतिरिक्त विदेशी शिक्षण संस्थाओं को यहाँ बाजार फैलाने के लिए शाखाएं खोलने की अनुमति दी गयी है। आखिर भारत में शिक्षा भी एक विशाल बाजार है।

वैश्वीकरण की शैक्षिक नीतियाँ भारत की शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं। भारत में सर्वसुलभ व सस्ती शिक्षा की आवश्यकता है। जिससे कि समाज के हाशिए पर रहने वाले लोग लाभान्वित हों। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था उच्च वर्ग, व उच्च मध्यम वर्ग को पोषित करती है जिसका प्रतिफल यह हुआ है कि भारत में बेरोजगारों की संख्या विस्फोटक रूप से बढ़ गयी है। ये बेरोजगार गैर कानूनी व गैर सामाजिक तरीके अपनाकर समाज में अव्यवस्था उत्पन्न कर रहे हैं।

स्वामी विवेकानन्द का विचार है कि देश उसी अनुपात में उन्नत हुआ करता है, जिस अनुपात में वहाँ के जनसमुदाय में गुणवत्तापरक शिक्षा और बुद्धि का प्रसार होता है। भारतवर्ष की पतनावस्था का मुख्य कारण यह रहा कि मट्टीभर लोगों ने देश की संपूर्ण शिक्षा और बुद्धि पर एकाधिपत्य कर लिया। भारत में वैश्वीकरण द्वारा आज ऐसी ही स्थिति पैदा की जा रही

है। उनके ही शब्दों में यदि हम पुनः उन्नत होना चाहते हैं, तो हम जनसमूह में शिक्षा का प्रचार करके वैसे हो सकते हैं। निम्न वर्ग के लोगों का विकास करने के लिए अच्छी शिक्षा देना ही उनकी एकमात्र सेवा करना है। जब तक करोड़ों मनुष्य अज्ञान में जीवन बिता रहे हैं, तब तक मैं उस प्रत्येक मनुष्य को देशद्रोही मानता हूँ। जो उनके श्रम से शिक्षित हुआ है और उनकी उपेक्षा करता है। हमारा महान राष्ट्रीय पाप है जनसमुदाय की उपेक्षा करना, और यही हमारे अधः पतन का कारण है। राजनीतिक चाहे जितनी अधिक मात्रा में रहे, पर तब तक कोई लाभ न होगा, जब तक भारतवर्ष की जनता पुनः एक बार सुशिक्षित न हो जाय।

महात्मागांधी देश में ऐसे शिक्षा व्यवस्था के समर्थक थे जिसमें सभी को शिक्षा प्राप्त हो। सच्ची शिक्षा वही होती है, जो आध्यत्मिक, बौद्धिक आर्थिक व सामाजिक शक्तियों का एक साथ विकास करें। वैश्वीकरण के शैक्षिक दर्शन में शिक्षा के द्वारा भौतिक मानव को तैयार किया जा रहा है जिसमें समाज व राष्ट्र के प्रति संवेदना नहीं है। ऐसे मनुष्य की सोच निरन्तर उपभोग पर आधारित है।

पं० दीनदयाल जी की शिक्षा की अवधारणा वैश्वीकरण की विचारधारा के विरुद्ध है। उनका मत है कि शिक्षा हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। शिक्षा का विक्रय समाज के लिए घातक है। अतः शिक्षा सुनिश्चित व निःशुल्क होनी चाहिए। शिक्षा का व्यय राज्य द्वारा होने के उपरान्त भी उसका सरकारीकरण नहीं होना चाहिए। वे शिक्षा व्यवस्था के सफल संचालन के लिए शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों, विषय विशेषज्ञों के स्वायत्तशासी आयोग द्वारा संचालन के पक्ष में थे। अधिकारों का दुरुपयोग कर शिक्षा संस्थानों द्वारा निजी सम्पत्ति बनाना समाज के साथ दुराचरण है। भारत के 'पब्लिक स्कूल' इस उद्देश्य के प्रतिकूल हैं। हम सबका कर्तव्य है कि समाज के निर्धन, दलित, शोषित आदिवासियों, गिरिवासियों के बीच ज्ञानदीप जलाकर शिक्षा उन्नयन के राष्ट्रीय यज्ञ में सहयोग करें।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर शिक्षा को मानव मुक्ति का रास्ता मानते थे। शिक्षा मानव को बौद्धिक और भावनात्मक रूप से इतना मजबूत और दृष्टिमान बनाती है कि वह स्वयं ही आगे बढ़ने का रास्ता, ज्ञान-सृजन का रास्ता और ज्ञान के सहारे अपनी मुक्ति की ओर जाने का रास्ता ढूँढने के योग्य हो जाता है। शिक्षा से समाज को लाभ होता है, अर्थव्यवस्था को भी लाभ होता है, लेकिन वह केवल आर्थिक लाभ नहीं होता और उसे किसी कारोबार में लगायी गयी लागत और उससे कमाये गए मुनाफे की तरह नहीं समझा जा सकता। अगर आगे बढ़ने से समाज को लाभ मिलता है, चाहे अर्थव्यवस्था के मजबूत बनने के रूप में मिले या समाज के अन्य आयामों को विकसित करने के रूप में मिले, वह अपने-आप मिलेगा और उसकी प्रक्रिया लागत-मुनाफे वाली नहीं होगी।

उपरोक्त महापुरुषों के विचार शिक्षा की वैश्वीकरण के विचार से मेल नहीं खाते। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मनुष्य उन पूंजीपतियों के तंत्र का एक पूर्जा बन जाता है, जिनका उद्देश्य केवल माल पैदा करना, माल को बेचना और अपने मुनाफे को अधिक से अधिक बढ़ाना है। अतः वैश्वीकृत समाज में मनुष्य को एक संसाधन और शिक्षा को संसाधन का विकास करने

वाली चीज माना जाता है। इस समाज में मनुष्य के स्वतंत्र अस्तित्व को नकारा जाता है और उसे अपने-आप में एक पूंजी और पूँजी को बढ़ाने वाले साधन के रूप में देखा जाता है। पूँजी के भूमंडलीकरण के इस दौर में, जिसमें एक वैश्विक बाजार बनाने और उस पर कब्जा जमाने की कोशिश पूँजीवादी और साम्राज्यवादी शक्तियां कर रही है, शिक्षा भी बाजार में बिकने वाली वस्तु बन गयी है और शिक्षित लोग भी एक संसाधन बन गए हैं, जिनका इस्तेमाल पूँजीपति अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए करते हैं। इसलिए संसाधन के रूप में मनुष्य का विकास करना व्यापार में लागत लगाकर मुनाफा कमाने जैसी प्रक्रिया है। आज के बाजारवादी समय में शिक्षा को इसी प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। जब हम मनुष्य-केंद्रित विकास की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य होता है— एक ऐसे समाज का निर्माण जिसमें पूँजी के आधार पर कोई मनुष्य दूसरे मनुष्यों का शोषण न करें, मनुष्य के शारीरिक और मानसिक श्रम से उत्पन्न चीजों पर पूँजीपतियों का नहीं, बल्कि सारे समाज का अधिकार हो, एक सुखी और सुंदर मानवीय जीवन के लिए आवश्यक सभी वस्तुएँ सभी मनुष्यों को उपलब्ध हो, उन चीजों का न्यायपूर्ण बंटवारा लोगों के श्रम और उनकी आवश्यकताओं को आधार पर हो, जो चीज एक व्यक्ति के हित में हो, वह सारे समाज के हित में हो, या जो चीज सबके हित में हो, उसे प्रत्येक व्यक्ति अपने हित में समझे। जाहिर है ऐसे समाज में शिक्षा का स्वरूप बिल्कुल भिन्न होगा। उसमें शिक्षा सभी मनुष्यों को भौतिक और मानसिक रूप से समृद्ध बनाकर उन्हें बेहतर मनुष्य बनाने वाली शिक्षा होगी।

### सन्दर्भ ग्रंथ सूची

- भार्गव, नरेश : वैश्वीकरण समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, रावत पब्लिकेशन, जयपुर-2014  
टैगोर, रविन्द्रनाथ : राष्ट्रवाद, नेशनल बुक ट्रस्ट, दिल्ली  
सिंह, अमित कुमार : भूमंडलीकरण और भारत, सामायिक प्रकाशन, नई दिल्ली-2009  
सेन, अर्मित्य व द्रीज, : भारत विकास की दशाएं, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली-2001  
सिंह, जे0पी0 : आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, पी.एच.आई. लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली -2016  
सिंह वी.एन.व सिंह : भारत में सामाजिक आन्दोलन, रावत पब्लिकेशन, जयपुर-2007  
जयमेजय  
स्वामी विवेकानन्द : शिक्षा, स्वामी ब्रह्मास्थानन्द प्रकाशन, नागपुर-2012  
उपाध्याय, रमेश व, : शिक्षा और भूमंडलीकरण, शब्द संधान, नयी दिल्ली-2008  
उपाध्याय, संज्ञा  
त्रिपाठी, प्रयागनारायण : महात्मागांधी और पं दीनदयाल उपाध्याय के जीवन दर्शन में साम्य, लोकहित प्रकाशन, लखनऊ-2013  
भारत में समाजशास्त्र MSO-004 (INGOU NOTES)  
योजना सितम्बर-2013

## जाहिरात संस्थेची जाहीरात व्यवस्थापनात गरज

प्रा. राजेश एस. डोंगरे

गुरुकुल कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, नांदा  
ता. कोरपना, जि. चंद्रपुर

गोषवारा

जाहिरात करण्याचे काम विशेष रूपाने करणा-या संस्थांना अथवा कंपन्यांना जाहिरात संस्था असे म्हणतात. या संस्था केवळ जाहिरात स्विकारण्याचे आणि विशिष्ट माध्यमातून त्या प्रवाहित करण्याचे कार्य करीत असतात. उत्पादक स्वःता हा आपल्या वस्तुचीच जाहिरात करीत असतात, परंतु उत्पादनाचे काम आणि जाहिरात करण्याचे काम अशी दोन्ही कामे भिन्न-भिन्न स्वरूपाची असल्याने. उत्पादन कार्य यशस्वीपणे करणा-या निर्मात्याला जाहिरातीचे काम तेवढ्याच यशस्वी पणे करता येईल असे नाही. तर जाहिरातीच्या कामात वेगळ्या कलेची आणि नैपुण्याची आवश्यकता असते. म्हणूनच केवळ जाहिराती तयार करण्याचे आणि त्या प्रत्यक्षात आणण्याचे काम स्वतंत्रपणे करणा-या संस्थांची गरज भासते. प्रथम पाश्चिमात्य राष्ट्रात अशा संस्था अस्तित्वात आल्या आणि त्याचा झपाट्याने विकास झाला. भारतातील सर्वात जुनी जाहिरात संस्था म्हणून हिन्दुस्थान थॉम्पसन असोशियेट लिमिटेडचा उल्लेख करावा लागेल. आज भारतात बंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता आणि चेन्नई अशा मोठ्या शहरांमधून जाहिरात संस्था मोठ्या प्रमाणात व्यवसाय करतात. भारतात सर्वात जास्त व्यवसाय हा मुंबई येथे आहे.

**बिज शब्द :** जाहिरात, उत्पादक, संस्था, सल्लागार, ग्राहक संबंध, माहिती पोहचविणे आणि विक्रयात वाढ प्रस्तावना:

सर्वसाधारणता जाहिरात विषयक सेवा उपलब्ध करून देना-या संस्थेला/संघटनेला “जाहिरात एजन्सी” असे म्हणण्याचा प्रघात आहे. हि संस्थ्या प्रसार माध्यमाशी संबंध ठेवणारी असली तरी ती स्वतंत्र असते. जाहिरातदाराची प्रतिनीधी किंवा सल्लागार म्हणून हि संस्था काम करते. कायदेशिररित्या पाहिले तर या संस्थाना एजन्ट किंवा प्रतिनीधी म्हणता येणार नाही कारण या संस्था सल्ला, सेवा पुरवितात किंवा प्रसार माध्यमातील जागा, वेळ जाहिरातदारासाठी आरक्षित करण्याचे काम करीत असतात, पुर्वीचे जाहिरात संस्थेचे स्वरूप आता थोडे बदलून व्यापक झाले आहे

जाहिरात संस्था प्रामुख्याने जाहिराती संबंधी आणि सामान्यता विपणना संबंधी सेवा देण्याकरीता स्थापन झालेली व्यवसायिक संस्था होय, असे स्टॅन्टन यानी प्रतिपादीत केले. जाहिरात संस्था संपूर्ण जाहिरात मेळा आयोजीत व कार्यरत करण्याचे कामही या संस्था पार करतात. एवढेच नाहीतर व्यवसाय संस्थेसाठी बाजापेठ संशोधनाचे कामही त्या करून देतात उत्पादनाच्या वेष्टनाचे डिझाइन, रंगसंगती मजकूर इत्यादी कसा असावा याविषयी जाहीरात संस्था सल्ला देतात. जाहिरातीसाठी कोणती माध्यमे प्रभावी ठरेल या सल्ला देतात व प्रत्यक्ष जाहिरात करून देतात. या कार्याच्या मोबदल्यात जाहिरात संस्थाना प्रसार माध्यमाकडून कमिशन मिळते. जाहिरातदाराला पुरविलेल्या अन्य सेवेबद्दल जाहिरातदाराकडून मोबदला मिळतो, थोडक्यात जाहिरात संस्था ही सेवा पुरविणारी संस्था असते.

**जाहिरात संस्थेचे कार्य:**

जाहिरात संस्था या केवळ जाहिरात प्रसारित करण्याचे कार्य करीत नाही तर याशिवाय त्या इतरही प्रकारचे विविध कार्य पार पाडीत असते.



- सल्लाकाराच्या भुमिकेत जाहिरात कशा प्रध्दतीने, किती प्रमाणात व कोणत्या काळात करावी व त्यावर कीती खर्च करावा याबाबत जाहिरात संस्था आपल्या ग्राहकाला सल्ला देतात .
- मजकूर लिखाण करणे, उत्तम प्रकारची चित्रे,नियोजन,जाहिरातपट व जाहिरात ध्वनीफीत तयार करणे आणि जाहिरात दाराच्या वतीने जनसंपर्क सुध्दा करणे .
- गरजेनुसार बाजारपेठ,ग्राहक व तत्सम संशोधनाचे कार्य सुध्दा जाहिरात संस्था पार पाडत असते.
- संपुर्ण जाहिरातीची सुत्रबद्ध योजना आखून देणे.
- जाहिरातदाराला त्याच्या जाहिरात खर्चासाठी पैशाची उपलब्धता करून देते
- ग्राहक आणि जाहिरातदार यांच्यातील दुवा म्हणुनही जाहिरात संस्था काय करीत असते व त्या अनुषंगाने येणारी इतरही कार्य जाहिरात करीत असते.
- सर्वात महत्वाचे म्हणजे जाहिरातीच्या प्रसारानंतर तीची प्रभावशिलता तपासण्याचे कार्य हे जाहिरात संस्था करते आणि त्याचा संपुर्ण अहवाल जाहिरातदाराला देत असते .

#### जाहिरात संस्थांचे प्रकार:-

जाहिरात संस्थेच्या कामाच्या स्वरूपावरून या साधारणता पुढील प्रकारात असतात.

- पुर्ण सेवा संस्था-

या जाहिरात संस्थेच्या प्रकारात ग्राहकांना संपुर्ण सेवा पुरविली जाते उदा. जाहिरातीचे नियोजन करणे,जाहिरातीची निर्मिती करणे व त्यानंतर जाहिरातीची प्रत्यक्ष अमलबजावणी करणे.

- मर्यादित सेवा संस्था-

या प्रकारच्या संस्थेत जाहिरात विषयक संपुर्ण सेवा न देता केवळ जाहिरातीची निर्मिती आणि जाहिरातीची कलात्मक बाजू यावरच संस्थेचा भर असतो. म्हणजेच जाहिरातीचे नियोजन व जाहिरातीची प्रत्यक्ष अमलबजावणी करण्याचे कार्य उत्पादकालाच करावे लागते. जाहिरातीचे मर्यादित कार्य करीत असल्यामुळे या प्रकाराला मर्यादित सेवा संस्था असे म्हणतात.

#### वैशिष्ट्य पुर्ण संस्था -

या प्रकारात काही वैशिष्ट्य पुर्ण जाहिरातीच केल्या जातात उदा. वित्तीय जाहिराती, भाग विक्रीची जाहिरात इत्यादी.

- प्रतिनिधीक संस्था -

नभोवाणी,स्थानिय,दुरदर्शन आणि स्थानिय वर्तमान पत्रातून जाहिरात देण्याबद्दलची सेवा या संस्था देत असतात. अशा संस्थांचा हा पुर्ण वेळ व्यवसाय नसतो. प्रसार माध्यमे व ग्राहक दोघांकडुनही यांना कमीशन मिळत असते.

#### ग्राहकाशी असणारे संबंध -

कोणत्याही व्यावसायिक संस्थेसाठी किंवा संघटनेसाठी ग्राहक हा सर्वात महत्वाचा घटक असतो. कारण हा सगळा खटाटोव ग्राहक मिळविण्यासाठी असतो आणि तेच एखाद्या संस्थेला प्रगतीच्या वाटेवर नाहीतर अधोगतीच्या वाटेवर नेत असते. त्यामुळे ग्राहकांच्या कायम संपर्कात राहुन त्यांच्याशी चांगले संबंध ठेवणे हे कोणत्याही संस्थेचे प्रथम कर्तव्य असते. हल्लीच्या काळी मध्यस्थांची एक मोठी साखळी निर्माण झाल्यामुळे कोणत्याही संस्थांच्या ग्राहकांशी सरळ संबंध येत नसतो. तरी सुध्दा ग्राहकांशी

संपर्क प्रस्थापित केला जातो. ग्राहकांच्या आवडी-निवडी, त्यांच्या गरजा विचारात घेऊन त्याच प्रकारे उत्पादन आणि त्यांच्या किंमती ठरविल्या जातात. उत्पादनाशी संबंधित असणाऱ्या तक्रारी ऐकून त्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्याचे कार्य संस्थेला करावे लागते. अशा प्रकारे ग्राहकांशी संबंध ठेवण्याचे काम संस्था करित असते.

निष्कर्ष :-

जाहिरात संस्था ज्यांना आपल्या वस्तुची जाहिरात करावयाची आहे. त्यांच्याकडून जाहिरातीचा संपुर्ण तपशिल मिळवितात आणि त्यानुसार जाहिरातीचा एक आराखडा तयार करतात. ज्या माध्यमातून जाहिरात दाखवायची असते त्यांची जागा अगोदरच या जाहिरात संस्थासाठी राखीव ठेवल्या असतात. प्रतिष्ठीत वर्तमानपत्रांशी त्यांचा तसा करार असतो. या जाहिरात संस्था आपल्या तज्ञ कर्मचाऱ्यांकडून जाहिराती तयार करवून घेतात. या संस्थांना जाहिरात कलेचे विशेष ज्ञान असल्याने जाहिरातीची वस्तु, ग्राहकांचा प्रकार आणि जाहिरात करावयाचे क्षेत्र यांचा योग्य विचार करून जाहिरात तयार केली जाते. या संस्था आपल्या कामाच्या मोबदल्यात विशिष्ट शेकडेवारीत कमिशन आकारतात.

उपरोक्त जाहिरात संस्थेच्या विविध कार्यप्रणाली वरून व जाहिरात संस्थेच्या स्वरूपातील विविध प्रकाराच्या अभ्यासाअंती जाहिरात संस्था कमित कमी शब्दात व कमी जागेत उत्कृष्ट व प्रभावशाली जाहिरात करण्याचे कसब या जाहिरात संस्थाजवळ असल्यामुळे त्याची लोकप्रियता जाहिरात व्यवस्थापनात वाढतच आहे. आज भारतात सर्वच शहरांमध्ये जाहिरात संस्था स्थापन झालेल्या आहेत. भारतातील बाजारपेठेच्या वेगाने होणारा विस्तार पाहता या सर्वच जाहिरात संस्थांना उत्तम असे भविष्य राहिल हे निश्चितच.

संदर्भ :-

- 1) डॉ. प्रकाश सोमलकर, “विपणन व्यवस्थापनाची तत्वे व प्रणाली”, सर साहित्य केंद्र, नागपुर - 2014
- 2) रेंगे गजानन, “जाहिरात कला आणि कल्पना”, आशुतोष प्रकाशन, मुंबई - 1976
- 3) जोशी पळणीटकर, “विपणन जाहिरात व विकयकला”, पिपळपुरे आणि कंपनी पब्लिशर्स, नागपुर - 1998
- 4) Rathor B.S., Advertising Management, Himalaya Pub. House, Bombay
- 5) Chunawala S. A., Sethia K.C., Foundation of Advertising Theory & Practice Himalaya Pub. House Bombay 1993.

## स्थानि स्वराज्य संस्थामधील महीला नेतृत्व व वास्तवि ता

डॉ. एन. आर. चिमूर र  
सरदार पटेल महाविद्यालय, चंदपूर  
nrchimurkar1@gmail.com

### प्रस्तावना

समाजाचे स्वरूप आणि त्याच्या अविरत तिथिलतेच्या प्रियेमध्ये स्त्री व पुरुष या दोघांचे समान योदान असते. परंतु समाजामध्ये ही नैसर्गिक तराामूळे पुरुष प्रधान संस्कृतीचा विास होऊन समाजामध्ये स्त्रिला दुय्यम स्थान प्राप्त झाले. भारतामध्येच नाही तर संपूर्ण पुथ्वीतलावर स्त्री व पुरुष असा भेदभाव ेला जातो वर्तमान परिस्थितीमध्येच नाही तर प्राचीन ाळापासून हा भेदभाव निरंतर सुरू आहे.

भारतीय संविधानामध्ये स्त्री व पुरुष समानता असली तरी राजीय स्तरावर स्त्री व पुरुषांचे समान प्रतिनिधित्व निर्माा झाले नाही. वयस् मतदानाच्या अधिाानुसार सैध्दांति दुष्टया महीलांना पुरुषांच्या बरोबरीने राजीय अधिार दिले असले तरी, व्यवहारी दुष्टया महीलांना राजीय सत्तेमध्ये त्यांच्या प्रमाात भागीदारी प्राप्त झाली नाही. मतदार सुचिमध्ये ५०% महीला असतांनाही सांसद व विधानसभेत १०% सुध्दा प्रतिनिधीत्व प्राप्त झाले नाही. ही भारतीय लो शाहीची शोांतिा आहे. स्थानि स्वराज्य संस्थात महीला आराानुसार महीलांचा राजीय सहभाा वाढून, स्थानि महीलांचे नेतृत्व उदयास आले असले तरी अधिातर महीला नेतृत्वाची स्थिती आज ही ठपूतली सार णी आहे.

### महिला आरारा व राजीय सहभाा

भारतातील ७०% लोांना स्वशासनाचा अधिार प्राप्त व्हावा या उद्देशानेच पंचायतराज संस्थांचा विास रयात आलेला आहे. परंतु स्थानि स्वराज्य संस्थामध्ये पुरुषी नेतृत्वाचे वर्चस्व निर्माा झाल्याने महीला नेतृत्व नाय होते. स्थानि स्वराज्य संस्थात महीलांचा राजीय सहभाा वाढावा, महीलांचे नेतृत्व निर्माा व्हावे. महीलांना राजीय दुष्टया सामरयाच्या उद्देशाने डिसेंबर १९९२ च्या ७३ व्या संविधान संशोधनाने स्थानि स्वराज्य संस्थात महीलांना १/३ टक्के आराराा प्राप्त झाले. यांचा परिााम असा झाला णी, देशात जवळ जवळ १० लाा महीला प्रतिनिधी सर्वप्रथम सार्वजनिक जीवनामध्ये सहभााी झाल्या. त्यामुळे ग्रामीा पातळीवर महीलांचा विास होऊन राजीय िया प्रियेस त्यांचा राजीय सहभाा वाढीस लााला आहे. सन २०१० च्या अधिनियमानुसार या स्थानि स्वराज्य संस्थामध्ये महीलांना ३३ टक्क्यावरून ५०% वर आराराा दिले असल्याने स्थानि स्वराज्य संस्थात सदस्य व पदाधिांा-यांमध्ये ५०% महीलांचा राजीय सहभााा ाढून महीला नेतृत्व उदयास आले आहे.

## महीला नेतृत्व व वास्तवि ता

स्थानि स्वराज्य संस्थामध्ये महिलांना आर ।। प्राप्त झाल्याने जिल्हापरीषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, नगरपाली ।, महानगरपाली । या संस्थात सदस्य व पदाधिारी पदावर महीला ५०% नी दिसू ला ।ल्या. महिलांना राजीय आर ।। प्राप्त झाल्याने स्थानि स्वराज्य संस्थात संयात्म राजीय सहभा । वाढला असला, तरी त्यांचा ूात्म राजीय सहभा । नाममाज आहे. पुरुषी नेतृत्वांनी हेतुपुरस्परपे महिला नेतृत्वांवर ुरघोडी र याचा प्रयत्न चालविला आहे. त्यामुळे पुरुषी समाजाच्या या बंदिस्त चौटीत आर ।। मिळलेल्या या महिला पदाधिं ।-यांची मानसि ुचंबना होत असल्याचे दिसून येते.

भारतामध्ये प्राचिन ाळापासून स्थानि स्वराज्य संस्था े ।त्या ना े ।त्या रूपात अस्तित्वात असल्याने, परंपरात पुरुषी नेतृत्वाचे वर्चस्व प्रस्तापित झाले होते त्यामुळे ावची महिला सरपंच असावी विचारही त्यांना शिवत नव्हता. आर ।।ामुळे सरपंच पदावर महीला त्यातही, दलित, आदीवासी, दुर्बल घटंतील महीला आरूढ झाल्या. त्यामुळे परंपरात घरा ेशाही असलेल्या राजीर ी लो ांच्या भुवय्या उंचावलेल्या ेल्या, सरपंचपद महीले डे जाार असेल तर घरच्याच महीलेचा शोध घेवु ला ।ले. तिच्या पदराआड राहुन आप । राजीर । रूश तो अशा अविर्भावात राजीर ।ाला सुरूवात झाली. जसे बिहारमध्ये "लालु ऐवजी राबडी" तसेच "नवऱ्या ऐवजी बाय े" असे चित्र दृष्टिस येते. हे पद जर दलित, आदीवासी महीलेला प्राप्त झालेले असेल, तर ावातील अशिात, मजोर, दुर्बल महीलांचा शोध घेऊन, तिला निवडून आ । याची व पदाधिारी बनवि याची जबाबदारी स्विारून, तिच्या माध्यमातून स्वतः राजीय रभार र याची राजीय ेळी पुरुषी नेत्यांनी चालविली आहे. आम्ही महीलेचे तैधर्ते आहोत. असे मा ून महीला नेत्यावर दबाव टा याचा, स्वतःच्या सोईनुसार ामे रून घे याचा प्रयत्न रीत असतात, अपयश आले तर महीलांना जबाबदार धरले जाते, आि यश आले तर मी सा पॉलिशी मे र आहे, अशा अविर्भावात फुशार ी मारली जाते.

स्थानि स्वराज्य संस्थामधील ाही महीला नेतृत्व ुशल संघट व र्थाम असूनही त्यांना स्वतःच्या इच्छानुसार राज्य रभार रू दिले जात नाही अशावेळी महीला नेत्यांचीच र्थामता, नेतृत्व ूांचे ाच्चि र ।ेले जात आहे.

महीलांच्या स्वावलंबी आत्मसन्मानपूर्व जीव ासाठी महीला समी र ाचे प्रयत्न रून राष्ट्रीय ते स्थानि पातळीपर्यंत महीलांचा राजीय सहभा । वाढला पाहीजे, त्यांची राजीय स,ीयता व र्थामता वाढीस ला ावी, या रीता अने धोर । आ ।ली जात आहेत. दुसरी डे माज या महीलांवर वर्चस्व प्रस्थापीत र याचे, त्यांचे मानसि ाच्ची र । र याचे प्रयत्न नेत्यांद्वारे ेले जात आहेत.

महीलांना स्थानि स्वराज्य संस्थात राजीय सहभागी प्राप्त झालेला असला, तरी पुरुषांचेच वर्चस्व प्रस्थापीत आहे. महीलांना राजीय कामधले बारगळे नाही समजत नाही असे समजले जाते. निर्यात निर्धारित प्रीयेमध्ये त्यांना सहभागी करून घेतले जात नाही. त्यांना नेवळ आदेश दिले जातात आपण महिला नेतृत्वाचे तारिहार, रीति ते आहेत अशी नेत्यांची भावना असल्याने, महिला पुरुषांच्या हातातलं बाहुलं बनले आहेत. हीच स्थानि स्वराज्य संस्था मधील महीला नेतृत्वाची वास्तविकता दिसून येते.

### मुल्यमापन

स्थानि स्वराज्य संस्थात महिलांना आरक्षण प्राप्त झाल्याने, राजीय सार्वजनिक जीवनामध्ये महीलांचा राजीय सहभाग वाढून महीला नेतृत्व उदयास आले. सामाजी चार दिवारीच्या बंधनातून मुक्त होऊन राजीय कार्यक्षमता, नेतृत्व सिद्ध करण्याची संधी प्राप्त झाली. यामुळे महीला नेतृत्वाची संस्थात्मक वाढ झाली असली, तरी सामाजी नेतृत्व क्षमता वाढीस लागलेली नाही. स्थानि स्वराज्य संस्थात महीला विविध पदावर आरूढ झाल्या असल्यातरी, त्यांना स्वयंम निर्वाचा अधिपत्य पुरुषी नेतृत्वाच्या अहंकारी ठेकेदारांनी सातत्याने नाकारला आहे. महीला नेतृत्व क्षमतेची मानसिक दडपणत व उपरुत भावनेत राहिल असे राजीय डावपेच आजून त्यांना पुरुषी अहंकाराच्या जोळात बंदिस्त करण्याचा प्रयत्न चालविल्याचे चिज दिसून येते. ज्या पुरुषी नेत्यांच्या पांढयावर महीला नेतृत्वाच्या विवासाचे व महिला सामाजी रणाचे दायित्व आहे. त्यांनीच महीला नेतृत्वाची कार्यक्षमता, सक्षमता, नेतृत्वक्षमता, निर्यात क्षमतेला विंडार पाडण्याचा चंग बांधला आहे, असे दिसून येते, हीच त्या अर्थाने महीला नेत्यांची वास्तविक परिस्थिती आहे.

जर महीला नेतृत्वाच्या क्षमतेचा, कार्यक्षमता, योजनेचा, राजीय सहभागणाचा व सक्षमतेचा मुल्यांकन केले तर, त्याचे परिणाम समाधानकारक नाही. स्थानि स्वराज्य संस्थामधील आरक्षणाने, महीलांना घराच्या बाहेर तराढलं, घराचा उंबरठा ओलांडून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हापरिषद, पर्यंत पोहचली परंतु त्यांची राजीय सहभागीना न्यूनतम आहे. त्याच्या कार्यात व धोरणात अनेक घटका बांधा पोहचवित आहेत. सध्या महीला नेतृत्वावर अनेक मर्यादा येत असल्या तरी भविष्यात त्यांचा विकास होईल महीला नेतृत्वांची जी पिढी आज नेतृत्व रीत आहे. ती स्थानि राजीय कामत असे नेतृत्व निर्माण करेल की, ज्यामुळे प्रादेशीक व राष्ट्रीय स्तरावर महीला नेतृत्वाला एका नवी दिशा प्रदान करेल.

### संदर्भ ग्रंथ



१. राठोड मधू - "पंचायतराज और महीला विास" आर. बी. एस. पब्लिशर्स जयपूर
२. डॉ. गोयल सुनिल - "भारतीय समाज में नारी" आर. बी. एस. पब्लिशर्स जयपूर
३. शर्मा प्रज्ञा - "महीला विास और सशक्ती र्ा" अविष्ार पब्लीेशन दिल्ली
४. सिंह बामेश्ववर - "भारत मे स्वशासन" राधा पब्लीेशन नवी दिल्ली
५. डॉ. पाटील वा. भा. "पंचायतराज" प्रशांत पब्लीेशन जळांव



## Extroversion and Introversion: A comparative study of cast and culture among college students

Dinesh R. Jaronde

Assistant Professor Dept. of Psychology  
Indira Mahavidyalaya Kalamb, Dist Yavatmal  
Email : dineshjaronde@gmail.com

### Abstract

The major aim of the study was to study the personality traits among schedule caste and schedule tribe and also urban and rural college students. The sample consist of 100 (50rural and 50 urban students) college students from yavatmal districts. Age range of the students 18 to 23 years and educational qualification was under graduates. For the study personality inventory was administered. After scoring the data the mean, standard deviation and t- test used. The result revealed that significant difference between scheduled caste and scheduled tribe college students on personality traits. And also significant difference between rural and urban area college students on personality traits. Study found that the impact of cast on extroversion/ introversion characteristics and influence of culture on extroversion/ introversion factor.

### Introduction

The term personality has been derived from the Latin word persona. Which was associated with the Greek theatre in ancient time. The Greek actors commonly use and to wear masks on their faces during ether performance on the stage. The mask worn by the actors was called persona. Every person each has a unique personality our personalities control our behavior, thought, emotions and even our unconscious feelings. An individual's personality is the complex of mental characteristic that makes them unique from other people.

Personality is the deeply fixed consistent distinctive and characteristic patterns of our thought feeling and behavior that define a persona own style of infracting with the physical and social environment. Personality is shown in many ways through behavior, thoughts and feelings. Personality is actually true nature and lies behind these elements. People create people and or creation of the community. Personality is who are inside our self through feeling ideas plans fears and all the rest character is who are to other people its social side of personality. Personality is the sum total of ones behaviors it's includes everything's about a person his social physical mental make-up.

**Muir**, "Personality is the whole individuals considered as a whole. It may be defined as the most characteristic integration of an individual's structures mode of interests, attitudes, behaviors, capacity and abilities.

**Cambridge University**, "Our personality means your behaviors, thought, emotion and your way of thinking"

**Gordon Allport**, "Described to major way to study personality the nomothetic and idiographic Nomothetic psychology seeks general laws can be applied to many different people such as the principle of self-actualization or the traits of extraversion. Ideographic psychology is and attempt to understand the unique aspects of particular individuals"

### Different types of traits -

#### 1) Extraversion -

This type has the tendency to live mostly the like to lives with others. His moral actions corresponds with society expectation, extrovert is largely conventions he behaves as he expected to behave he find society moral demands congenial. These want to join other groups who are more in number. Such type of people political, social worker etc.

#### 2) Introversion-

Introvert is the opposite of extrovert. Those people not blind to objective conditions he assimilates them in a more personal manner than the extrovert. Those are much more influenced in his thoughts and actions by the world as it appears to him than as it really is. Those people are always live alone in their rooms and do not want to go outside. They can make writer, philosopher, thinker and teacher.

Third type is ambivert between extrovert and introvert personalities there is other one type called ambivert they have middle mind and want to live in both parties.

### Review of Literature -

Kotac, Roman Gamez et.Al. (2010) - conducted a study on personality traits to anxiety, depressive, and substance use disorders. All diagnostics groups were high on neuroticism and low on conscientiousness. Many disorders also showed low extraversion with the largest effect sizes for dysthymic disorder and social phobia. Agreeableness and openness were largely unrelated to the analyzed diagnosis.

Jonathan William Marin (2010) - conducted study on an examination of social anxiety relationship support, self-esteem, personality traits and motivation for online gaming and internet usage generally contrary to the study hypothesis. This investigation found a positive relationship between the personality trait of openness and students overall time using the internet.

Murray (2005) - studied on the relationship between personality types. The study was conducted at a university in Indiana using under graduate volunteer. The hypothesis was that extraverts who have a higher self-esteem and low test anxiety would have better success with academic achievement than those who are introverts with low self-esteem and high level anxiety.

In present study two different factor are treated as independent variable the first one is cast. And second one is culture difference namely rural and urban. In this study has taken two cast first is schedule cast and second is schedule tribe. And dependent variable has used two factor are Extraversion and Introversion.

### Objective of the Study

The main objective of the study as well as follows.

- 1) To find out the impact of cast on extroversion/ introversion characteristics.
- 2) To search the influence of culture on extroversion/ introversion factor.

### Hypothesis

- 1) There is significant difference between scheduled caste and scheduled tribe college students on personality traits.
- 2) There is significant difference between rural and urban area college students on personality traits.

## Methodology

### Sample

The present study was conducted in Yavatmal district. The purpose of the study was to know Extroversion and Introversion: A comparative study of cast and culture. There were ten college taken from five Talukas. The total sample consisted of 100 under graduate students. The sample were selected by random sample technique. There ratio 1:1 schedule cast and scheduled tribe and also urban and rural college students. Age range of the students 18 to 23 years and educational qualification was under graduates.

### Tools

The test is designed by Dr. Yashwir shing and Dr. Harmohan singh. Test name is Personality Inventory (Extraversion – Introversion Scale). It is self-administering inventory. It is mainly for use on groups. Though it may be given to group of any size. There is no time limit for the test. Though it may take maximum ten minutes for satisfactory completion of the test. There is not right and wrong answer to the statement. The inventory is meant to find out difference between individuals and is not meant to rank good of bad individuals. The test consist of fifty six items. The test split half reliability is .80 and test – retest reliability is .72.

### Procedure of data collection

A booklet consisted of personal information schedule and personality inventory. The data collection of the study was carried out with the prior permeation of the students. Then all those students were made to sit in one class comfortably to establish good rapport with students.

### Research Design

In the present study the 2\*2 factorial design was employed to compare the impact of these variables on extraversion/ introversion and college students.

### Statistical treatment of data

In the present study Mean, Standard Deviation and t-test employed to test different hypothesis. The obtained numerical results were interpreted meaningfully before using the tests all assumption were checked.

### Result & Discussion

The purpose of the study was to Know “Extroversion and Introversion: A comparative study of cast and culture” In this study two hypothesis

1) Hypothesis no. 1 was there is significant difference between scheduled caste and scheduled tribe college students on personality traits. According this hypothesis

Table no. 1 shows Mean, SD and T ratio of Scheduled caste and Scheduled tribes

Students	N	Mean	SD	T ratio
Scheduled caste	30	81.07	4.72	3.78
Scheduled tribes	30	75.62	3.22	

Significant at .01 level

The calculated T ratio of above table was 3.78 which was significant at .01 level. It showed that the mean score of the scheduled caste and scheduled tribes students significantly differ on their personality traits. Means both cast are difference on extraversion/ introversion characteristics.

2) Hypothesis no. 2 was there is significant difference between rural and urban area college students on personality traits. According this hypothesis

Table no. 2 shows Mean, SD and T ratio of Rural and Urban area college students

Students	N	Mean	SD	T ratio
Rural	60	83.22	4.21	12.99
Urban	60	67.62	4.47	

Significant at .01 level

The calculated T ratio of above table was 3.78 which was significant at .01 level. It showed that the mean score of the rural and urban college students significantly differ on their personality traits. Means both culture factors are difference on extraversion/ introversion characteristics.

#### Reference–

- 1) International journal of education, issue July 2013, vol.2
- 2) Extraversion vs. introversion correlation with impulsivity sensation and stimuli- st. olaf, college
- 3) Introversion/ extraversion and teacher perception on Dominican efl. Files.eric.ed.gov
- 4) Inverted student in the classroom- scilearn.com
- 5) Study habits and introversion extraversion- journals.sagepub.com
- 6) Manuals of personality inventory-Dr. Yashvir shing and Dr. Harmohan singh

---

## The Ethical Issues in Accounting- What Yet and How Long?

**Dr. Kajalbaran Jana**

M.Com, Ph.D. MBA (Finance)

Assistant Professor

Department of Commerce

Tamralipta Mahavidyalaya

Tamluk: Purba Medinipur

West Bengal:721636

E-mail- [jkajalbaran@yahoo.com](mailto:jkajalbaran@yahoo.com)

### Abstract

The ethical issues in accounting are integral part of accounting since its basics. But being implicational aspect of accounting ethics are treated as applied ethics in business which determines the moral values of accounting practitioners. Still from very beginning of accountancy, series of accounting scandals are perpetrated in our accounting history. May be these have been given good lessons to us for further evaluative measures for accounting preparation; soon we have faced another scandal in this field with much complicity to address it.

So it is found that moral education can only impact on few people not on whole people in the frame. Then how long and what extent it would be gone through?

**Key Words: Ethical Issues, Business ethics, Moral Value, Scandal, Accounting History**

According to Wikipedia, "Accounting ethics is primarily a field of applied ethics and is part of business ethics and human ethics, the study of moral values and judgments as they apply to accountancy. It is an example of professional ethics. Accounting introduced by Luca Pacioli, and later expanded by government groups, professional organizations, and independent companies. Ethics are taught in accounting courses at higher education institutions as well as by companies training accountants and auditors."

### Need of Ethics

The nature of the work carried out by accountants and auditors requires a high level of ethics. Shareholders, potential shareholders, and other users of the financial statements rely heavily on the yearly financial statements of a company as they can use this information to make an informed decision about investment. They rely on the opinion of the accountants who prepared the statements, as well as the auditors that verified it, to present a true and fair view of the company. Knowledge of ethics can help accountants and auditors to overcome ethical dilemmas, allowing for the right choice that, although it may not benefit the company, will benefit the public who relies on the accountant/auditor's reporting

### Some Ethical Issues

From the 1980s to the present there have been multiple accounting scandals that were widely reported on by the media and resulted in fraud charges, bankruptcy protection requests, and the closure of companies and accounting firms. The scandals were the result of creative accounting, misleading financial analysis, as well as bribery. Various companies had issues with fraudulent

accounting practices, including Nugan Hand Bank, Phar-Mor, WorldCom, and AIG. One of the most widely reported violation of accounting ethics involved Enron, a multinational company that for several years had not shown a true or fair view of their financial statements. Their auditor Arthur Andersen, an accounting firm considered one of the "Big Five", signed off on the validity of the accounts despite the inaccuracies in the financial statements. When the unethical activities were reported, not only did Enron dissolve but Arthur Andersen also went out of business. Enron's shareholders lost \$25 billion as a result of the company's bankruptcy. Although only a fraction of Arthur Anderson's employees were involved with the scandal, the closure of the firm resulted in the loss of 85,000 jobs. In India such a big issues was 'Satyam Scandal', which made exemplary incident of violation of ethics in accounting. On 7 January 2009, the chairman of Satyam, Ramalinga Raju, resigned, confessing that he had manipulated the accounts by US\$1.47-Billion. The global corporate community was said to be shocked and scandalised.. In February 2009, CBI took over the investigation and filed three partial charge sheets (dated 7 April 2009, 24 November 2009, and 7 January 2010), over the course of the year.[citation needed] All charges arising from the discovery phase were later merged into a single charge sheet.[clarification needed. On 10 April 2015, Ramalinga Raju was convicted with 10 other members.

### **Ethical Rules and Principles Adopted**

According to John L. Carey, describing ethics in accounting, "When people need a doctor, or a lawyer, or a certified public accountant, they seek someone whom they can trust to do a good job — not for himself, but for them. They have to trust him, since they cannot appraise the quality of his 'product'. To trust him they must believe that he is competent, and that his primary motive is to help them."

- The International Financial Reporting Standards (IFRS) are standards and interpretations developed by the International Accounting Standards Board, which are principle-based. IFRS are used by over 115 countries including the European Union, Australia, and Hong Kong.
- The United States Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), the standard framework of guidelines for financial accounting, is largely rule-based. Critics have stated that the rules-based GAAP is partly responsible for the number of scandals that the United States has suffered. The principles-based approach to monitoring requires more professional judgment than the rules-based approach
- IFRS is based on "understandability, relevance, materiality, reliability, and comparability". Since IFRS has not been adopted by all countries; these practices do not make the international standards viable in the world domain. In particular, the United States has not yet conformed and still uses GAAP which makes comparing principles and rules difficult. In August 2008, the Securities and Exchange Commission (SEC) proposed that the United States switch from GAAP to IFRS, starting in 2014.

### **Scope of Ethical Education**

According to Stephen E. Loeb (1988), the ethical education is very necessary to cope with various ethical issues around the world. He suggests-



- Relate accounting education to moral issues.
- Recognize issues in accounting that have ethical implications.
- Develop "a sense of moral obligation" or responsibility.
- Develop the abilities needed to deal with ethical conflicts or dilemmas.
- Learn to deal with the uncertainties of the accounting profession.
- "Set the stage for" a change in ethical behaviour.
- Appreciate and understand the history and composition of all aspects of accounting ethics and their relationship to the general field of ethics.

#### **What is the Ethical Lesson?**

- Describes clearly the true nature of business transactions, assets, or liabilities;
- Classifies and records information in a timely and proper manner; and
- Represents the facts accurately and completely in all material aspects.
- Do not publish/ generate statement contains a materially false or misleading;
- Avoid statements or information furnished recklessly; or
- Omits or obscures information required to be included where such omission or obscurity would be misleading
- Further, the fundamental ethical principle of professional behaviour mentioned in IFRS to comply with relevant laws and regulations and not perform any action that would discredit the accounting profession.
- The fundamental ethical principle of integrity and Code of Professional Conduct and Ethics imposes an obligation on all professional accountants to be straightforward and honest in all professional and business relationships.
- In addition, the principle of confidentiality prohibits responsible persons from using confidential information acquired as a result of professional and business relationships to their personal advantage or the advantage of third parties.

#### **Conclusion:**

The various studies on ethical issues on accounting are suggested that self interest, failure to maintain objectivity and independence, improper leadership and poor organisational culture, lack of ethical courage to do what is right, lack of ethical sensitivity and failure to exercise proper professional judgement would be main responsible factors in lapses in this field. Given these areas of ethical risk, the challenge is for professional bodies to work with accounting academics in universities and colleges to improve the ethical knowledge and behaviour of accountants in the workplace. Earnings of management has increasingly become an issue for the accounting profession and the results of these studies demonstrate that professional bodies rated this issue highly, particularly for accountants in business entities. The earnings management was perceived to be less of an issue for accounting practices and the government or not-for-profit sectors. So, it may be concluded that ethical issues in accounting is always arisen because it is not merely an accounting matter and it is a moral perspective. So long people govern by self interest without maintaining objectivity to society, the ethical issues in accounting will be there and there and there.



**References:**

1. Love, Vincent J. (October 1, 2008). "Understanding Accounting Ethics, Second Edition" (Registration required). The CPA Journal. Retrieved May 18, 2009.
2. Jackling, Beverly; Barry J. Cooper; Philomena Leung; Steven Dellaportas (2007). "Professional Accounting Bodies' Perceptions of Ethical Issues, Causes of Ethical Failure and Ethics Education" (Registration required). Managerial Auditing Journal. 22 (9): 928–944. doi:10.1108/02686900710829426. Retrieved April 8, 2009.
3. Dellaportas, Steven (June 2006). "Making a Difference with a Discrete Course on Accounting Ethics" (Registration required). Journal of Business Ethics. 65 (4): 391–404. doi:10.1007/s10551-006-0020-7. Retrieved April 8, 2009.
4. Alexander, David; Anne Britton (2004). Financial Reporting. Cengage Learning EMEA. p. 160. ISBN 1-84480-033-4.
5. Dietz, David (April 26, 2002). "'Auditors Are Timid'". Pittsburgh Post-Gazette. Retrieved May 15, 2009.
6. Duska, Ronald F.; Brenda Shay Duska (2003). Accounting Ethics. Wiley-Blackwell. p. 28. ISBN 0-631-21651-0.
7. Gowthorpe, Catherine; John Blake (1998). Ethical Issues in Accounting. Routledge. p. 7. ISBN 0-415-17173-3.
8. Smith, L. Murphy (October 1, 2008). "Luca Pacioli: The Father of Accounting". Texas A&M University. Retrieved April 7, 2009.
9. Loeb, Stephen E. (Fall 1988). "Teaching Students Accounting Ethics: Some Crucial Issues" (Registration required). Issues in Accounting Education. 3: 316–329. Retrieved April 7, 2009.
10. Casler, Darwin J. (1964). The Evolution of CPA Ethics: A Profile of Professionalization. Michigan State University. p. 5.
11. Preston, Alistair M.; David J. Cooper; D. Paul Scarbrough; Robert C. Chilton (2006). J. Edward Ketz, ed. Accounting Ethics: Critical Perspectives on Business and Management (Changes in the Code of Ethics of the U.S. Accounting Profession, 1917 and 1988). Routledge. p. 209. ISBN 0-415-35078-6.
12. "Bookkeepers Repel Inference That Their Own Employers Were Aimed At." (Fee required). Chicago Tribune. February 28, 1907. Retrieved December 14, 2010.
13. Sellers, James H. (1981). Accounting Student Perceptions of Business and Professional Ethics. University of Mississippi. p. 1.
14. Vogel, David (April 27, 1987). "Manager's Journal: Could an Ethics Course Have Kept Ivan From Going Bad?" (Registration required). The Wall Street Journal. Retrieved May 17, 2009.
15. Loeb, Stephen E. (2007). "Issues Relating to Teaching Accounting Ethics: An 18 Year Retrospective". Research and Professional Responsibility and Ethics

## A STUDY ON LOCAL BODY ELECTIONS IN TAMIL NADU

**S. Mohan,**

Research Scholar

Department of Political Science

Madurai Kamaraj University

Madurai

**Dr.D. Ramakrishnan**

Associate Professor & Head,

Department of Political Science,

Madurai Kamaraj University

Madurai

## INTRODUCTION

Developmental administration is the main objective of these local bodies. They are effected by the means of bodies Urban and Rural local. They are responsible for the implementation of various centrally sponsored, state-funded, and externally aided schemes for provision of basic amenities and other services to the people. Elections are held to elect the representatives for local body council in respective urban and rural areas every five years. Ministry of Municipal Administration and Rural Local Bodies in Tamil Nadu constitute the three tier administration set-up in the South Indian state of Tamil Nadu. It is a system of local government which forms the last level from the Centre. Chennai Corporation in the Madras Presidency, established in 1688, is the oldest such Local Body not only in India but also in any commonwealth nations outside United Kingdom. Developmental administration is the main objective of these local bodies. They are effected by the means of Urban and Rural local bodies. They are responsible for the implementation of various centrally Development, Government of Tamil Nadu is the state government governing body for local bodies which is headed by a Minister who is an elected member of the Tamil Nadu Legislative Assembly. Tamil Nadu Panchayats Act, 1994 was enacted according to the 73rd and 74th Constitutional amendments of India in May 1994 which paved way for the creation of Tamil Nadu State Election Commission. But, the first election to the Local Bodies of Tamil Nadu was conducted in October 1996. Consecutive elections were then conducted in October 2001, October 2006 and October 2011 successfully.

### HISTORY

The history of local bodies in Tamil Nadu could be dated back to the Ancient period wherein the village administration was taken care by a Village assembly known as *Sabai* in every village. Further, each village was divided into several *wards* known as *mandalams*. This is evident from the epigraph inscriptions found in Vaikuntha Perumal Temple near Uthiramerur. They used the Pot-ticket system of election (*Kudavolai Murai*) to elect the representatives to the assembly. Later came the British rule in India in which the centralization of governance was enforced. People in the interior of the villages had to walk up to the central authorities for their obligations and grievances. Anyhow this system faded out as the British government realised the pitfalls in this system. Laudable efforts of Lord Ripon brought legislation in this aspect which created *unions* in small towns and villages, to facilitate proper sanitation and lighting. Later, councils were constituted in this regard for which the members are directly elected by elections. Councils were made accountable to an Inspector and Chairman. Though urbanisation was less prevalent those days, Chennai had the honour of having such Municipal Corporation status even in 1688. Urban local bodies known Municipalities were in existence. A department named *Local and Municipal Department* was functioning in the then Secretariat from 1916 and it had Local, Municipal, Plague, Medical and Legislative Branches. Independent India heard many voices for the revival and strengthening of the Village panchayats, Mahatma Gandhi insisted upon this for achieving Swaraj completely covering all the corners of this country. Later, a committee set up by Government of India, popularly known Balwant Rai Mehta Committee suggested the formation of three-tier Panchayati Raj system. From then, there came many legislation to ensure effective system of Local governance in Tamil Nadu. Notable legislative orders to Local Bodies by the centre-state governments include:

1. Article 40 of Indian Constitution
2. Madras Village Panchayat Act, 1950
3. Tamil Nadu District Municipalities (Amendment) Act, 1950
4. Tamil Nadu Panchayats Act, 1958
5. Tamil Nadu District Development Councils Act, 1958

6. Tamil Nadu Panchayats Act, 1994 (ratification to 73rd and 74th Amendment of the Constitution of India)

#### **A BRIEF HISTORY OF THE EVOLUTION OF PANCHAYATS IN TAMIL NADU**

The village councils, the precursors to present-day Village Panchayats, were institutions of very ancient origin in Tamil Nadu and they functioned very much like little republics enjoying a great deal of local autonomy and powers, including the power of taxation. The village artisans and agricultural labour were thrown out of employment and they migrated in large number to the emerging towns. Consequently, the rural economy was greatly upset. The administration also became highly centralized during the British rule. The administration of justice in rural areas was taken over by civil and criminal courts; the Police department took over functions of maintaining peace in villages; and the administration of land revenue was vested in separate department of Government. The self-reliance with which the villagers had always managed their affairs had gradually disappeared and the Village Panchayats which remained as useful rural institutions sank into insignificance. There came a situation where people looked up to the central authorities for carrying out even simple local works. In course of time, the futility of too much centralization was realized even by the British administration. They felt that Village panchayats were an excellent remedy for the imperfections of a bad form of Government. They realised it imperative to foster voluntary co-operation among the people for carrying out public objects. The credit for realising the importance of shaping new measures towards that direction goes to Lord Rippon. His resolution of 1882 regarding association of non-officials in the administration of local institutions led to the passing of the Madras Local Boards Act, 1884.

This provided for the constitution of “unions” in small towns and large villages mainly for sanitation and lighting. The members in each union were nominated after the visit of the Royal Commission on Decentralization and the Government of Madras decided to increase the number of these unions and to introduce therein the principles of election. They also decided to constitute informal Panchayats, under the control of the Collectors, with the local village head men as ex-officio chairmen. About 1,000 of these informal Panchayats were formed but their position was weak and unsatisfactory. They also did not have any connection with district or taluk boards. The Royal Commission on Decentralization laid stress on the necessity of the statutory backing. The Madras Village Panchayats Act was accordingly passed and brought into force in 1920. The Act enfranchised all men over 25 years of age and provided for the election of all members of the Panchayats. By 1930, the number of panchayats increased, and the panchayats were placed on the same footing as the “unions” formed under the Madras Local Boards Act, and were vested with more powers. Their supervision and control were subsequently vested with Inspector and Municipal Chairman under Local Board Act.

#### **POST INDEPENDENCE METHOD OF ELECTION**

The significant stage in the beginning of the post-independence period was the passing of the Madras Village Panchayat Act, 1950. The Act was enacted in the implementation of Article 40 of the Constitution. Throughout the Independence movement, Gandhiji had been advocating the revival of the Panchayati Raj Institutions with adequate powers so that the villagers could have a real sense of ‘Swaraj’. The insistence of Gandhiji resulted in the introduction of Article 40 (Organisation of Village Panchayats) in the Constitution of India. The Madras Village Panchayats Act of 1950 provided for the creation of Village Panchayats in every Village or hamlet with a population of 500 and above. The Village Panchayats were entrusted with certain obligatory civic functions and a host of discretionary functions. But not all the villages were covered by the Panchayats. Subsequently, with the launching of a nation-wide community development programme, the need for an effective institutional mechanism to involve the local communities in the process of development was felt. The study team on Community Development and Panchayati Raj (popularly known as the Balwantrao Mehta Committee), constituted in the late fifties, recommended the establishment of a three-tier Panchayati Raj. The middle tier, namely, the Panchayati Samiti (Panchayat Union in the case of Tamil Nadu), was the key level in the scheme of decentralization. The Panchayat Union’s jurisdiction was to be co-terminus with that of a Community Development Block. At the district level there was a Zilla Parishad, essentially an advisory body. The Village Panchayat would constitute the lowest level in the three-tier structure.

The Tamil Nadu Panchayats Act, 1958 was enacted immediately following the Balwantrai Mehta Committee Report. This paved the way for the formation of Village Panchayats through the length and breadth of Tamil Nadu. About 12,600 such panchayats came into existence. Villages which were acquiring urban character were classified as Town Panchayats. All the Village Panchayats and the Town Panchayats within a community development block were grouped together to form a Panchayat Union and 385 such Panchayat Unions were originally formed.

#### **ELIGIBILITY CRITERIA-QUALIFICATION FOR AN ELECTOR**

##### **Rural / Urban Local Bodies:**

The electoral roll of a Rural / Urban Local Body shall be the same as the current electoral roll of the Tamil Nadu Legislative Assembly pertaining to the area covered by the Rural / Urban Local Body, as prepared and revised in accordance with the provisions of the Representation of People Act 1950 and the Registration of Electors Rules, 1960 (vide Sections 14, 23 and 30 of the said Act.) This means that a person whose name finds a place within a Rural / Urban Local Body area in the electoral roll of the concerned Legislative Assembly Constituency is automatically included in the Rural / Urban Local Body electoral roll and consequently gets qualified to vote in the elections to that Rural / Urban Local Body.

The following are the conditions for registration of a person as an elector in the Legislative Assembly Electoral rolls:

- (1) he/she should be a citizen of India;
- (2) he/she should not be less than 18 years of age on the qualifying date  
i.e., he should have completed 18 years of age on the first January of  
the year in which the electoral roll is prepared;
- (3) he be should ordinarily a resident of the constituency area
- (4) he should not have been declared as of unsound mind by a competent  
court;
- (5) he should not have been disqualified from voting under the provisions of any law relating to corrupt practices  
and other offences in elections (Sections 16 & 19 of the Representation of People Act, 1950).
- (6) a person shall not be entitled to have his name registered in the electoral roll of more than one place. (Sections  
17 and 18 of Representation of People Act 1950).

The provision in Section 35 and 36 of the Tamil Nadu Panchayat Act, 1994 Section 44, 47 and 60 of the Tamil Nadu District Municipalities Act, 1920 and relevant provisions of other Urban Acts stipulate the following conditions for a voter to exercise his/ her franchise.

- (1) he should not have been convicted of an offence punishable under chapter IX-A of Indian Penal Code and under  
any law for the time being in force for the purpose of election to the Legislative Assembly of the State or is  
disqualified by or under any law for the time being in force shall be disqualified from voting in any election;
- (2) He should not have been disqualified under Section 36 of Tamil Nadu Panchayats Act, 1994 (Rural) and  
Section 47 of the Tamil Nadu District Municipalities Act, 1920 (Urban) and relevant provisions of other Urban  
Acts. He should not have been convicted of an electoral offence punishable under the Sections 58 to 71 of the said  
Tamil Nadu Panchayat Act, 1994 and Sections 56 to 56M of the Tamilnadu District Municipalities Act, 1920 and  
relevant provisions of the other Urban Acts.
- (3) No person who is of unsound mind and declared so by a competent court and no person who is disqualified for an  
electoral offence shall be disqualified to vote so long as the disqualification subsists.
- (4) As per Sec.44(1-B) of the Tamil Nadu District Municipalities Act, 1920 no person shall be entitled to be  
registered in the electoral roll for any Municipality more than once or to be registered in the electoral roll for another  
municipality, panchayat or city.

##### **URBAN LOCAL BODIES**

The urban local bodies act as platform between the people in the urban areas and the administration. According to 2011 census of India, Tamil Nadu has about 48.45% of total population living in urbanized areas. Depending on the population and income of the urban local bodies, they are further classified into three categories.

1. City Municipal Corporations
2. Municipalities



### 3. Town Panchayat

Larger cities of Tamil Nadu are governed by City Municipal Corporations. Tamil Nadu has 12 municipal corporations: Chennai, Coimbatore, Madurai, Tiruchirappalli, Tiruppur, Salem, Erode, Tirunelveli, Vellore, Thoothukudi, Dindigul and Thanjavur. These cities alone house one-third of urban population of the state. Corporation consists of a council of elected councilors from each ward and a presiding officer, Mayor who is also an elected representative. Apart from them, an executive authority referred as Corporation Commissioner is also vested with administrative powers. Municipalities fall next to the city corporations. There are about 125 Municipalities in Tamil Nadu. Municipalities have four categories based on their annual income and population. These include 17 special-grade municipalities, 31 selection-grade municipalities, 33 grade I municipalities, 44 grade II municipalities.<sup>[11]</sup> Their elected representatives include ward councilors and a presiding officer, Municipal Chairperson. Municipal Commissioner is the executive authority. Town panchayat is the body of government for areas in transition from 'rural' to 'urban'. Tamil Nadu is the first state to introduce such a classification in urban local bodies.<sup>[12]</sup> The state has 529 town panchayats. Town panchayats are upgraded to Grade III municipalities if they are found to be eligible. They are categorized in a similar way to that of Municipalities depending on the income criteria and population. Town panchayat council include elected ward councilors and their presiding officer, Town panchayat chairperson. Executive Officer is the executive authority as in case of Town panchayats.

### RURAL LOCAL BODIES

Rural local bodies include the panchayat raj institutions of this state. There are three levels in this system as follows.

1. Village Panchayats
2. Panchayat Unions (*co-terminus with Blocks*)
3. District Panchayats in this state.

Village Panchayats form the grass-root level of democracy as they form the local government for the basic building blocks of our country - villages. It is set up in villages where the population is less than 300. There are about 12,524 Village panchayats in this state. Gram Sabha is a part of Village panchayat which consists of elected ward members and Village panchayat president. Village panchayat president himself/herself is an executive authority here. They must meet for minimum of four times a year. Panchayat Unions (*co-terminus with Blocks*) is the group of Village panchayats. They serve as the link between the villages and the district administration. They form the local government at the Taluk level. Tamil Nadu has 385 panchayat unions. Panchayat Union council consists of elected ward members from the villages. It is headed by a panchayat union chairperson, who is elected indirectly by the ward members of the council.

District Panchayats in this state form the cream of the panchayat raj system. They take the top slot with mainly advisory powers to the rest. Developmental administration of the district in rural areas are in its hands. It consists of ward members elected from various villages in its jurisdiction. It is presided by district panchayat chairperson, who is indirectly elected by its ward members. There are 31 district panchayats in this state except for the district of Chennai as it is an *urban district*. District collector is the ex-officio chairman of the District rural development agency.

### ELECTIONS

Elections to the local bodies in Tamil Nadu, held once in five years, are conducted by Tamil Nadu State Election Commission. Both direct and indirect elections apply for local bodies. Direct election posts include:

- **Urban Bodies**
  1. Corporation Mayor
  2. Municipality/Town Panchayat Chairperson
  3. Corporation/Municipality/Town Panchayat Councilor
- **Rural Bodies**
  1. Village Panchayat President
  2. District Panchayat Ward Member
  3. Panchayat Union Ward Member
  4. Village Panchayat Ward Member



Indirect election posts include Chairpersons of District panchayats and Panchayat unions, Deputy Mayor of corporations, Vice-Chairpersons of Municipalities and Town panchayats. Various statutory/standing committees are also elected by the way of indirect elections.

#### **FUNCTIONS**

Local bodies are completely responsible for the developmental administration in the state. Maintenance of clean environment, primary health facilities gain the foremost importance. Apart from them water supply, roads and buildings, storm-water drains, street lighting, solid waste management, sanitation and bus-stands cum commercial complexes etc. are the prime duties of the local bodies. Centrally sponsored schemes like Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS), Indira Awaas Yojana (IAY), Member of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS), etc., and State-funded Schemes like Tamil Nadu Village Habitation Improvement Scheme (THAI), Member of Legislative Assembly Constituency Development Scheme (MLACDS), Self-Sufficiency Scheme, Solar-Powered Green-House Scheme are also undertaken by the local bodies.<sup>[20]</sup> Source of revenue for these local bodies are mainly from centre-state governments. Local bodies also have the power of taxation which include House Tax, Profession Tax, Property Tax etc. Apart from these they levy fees for specific building plan and layout approvals, Water charges, Sewerage charges etc.

#### **TAMIL NADU STATE ELECTION**

All Local Body elections of Tamil Nadu are conducted by this Commission. The conduct of elections to Rural and Urban bodies of Tamil Nadu are held by both Commission is an autonomous, independent Constitutional and Statutory authority of Tamil Nadu. It was formed under the Constitution of India as per the provisions of the 73rd and 74th Amendments Acts of 1992 on 15 July 1994 direct and indirect elections. The sole controlling authority vests with the Tamil Nadu State Election Commission. Elections to the various posts are held by this commission by direct and indirect election. Electoral rolls as per the electoral rolls of Tamil Nadu Legislative Assembly constituency are prepared by this commission. Polling stations are then identified based on the rolls. Followed by which is the notification for elections. Similar norms followed for the assembly elections are adhered here.

#### **CONCLUSION**

Local Self-Government in India is said to be the boon of British legacy. The English East India Company was established by a Royal Charter. The Charter was renewed at the expiry every two decades. At the time of every renewal of the Charter the Company was instructed to follow certain guidelines in its administration. It so happened that by a Charter of 1687 the Company was to make provisions for the civic administration of certain Principal areas under its control. According to this Charter Act the 'Madras City Municipal Corporation' was instituted in 1688 on the British model. Municipal Government had its 'Mayor' nominated, Aldermen, and Justice of Peace with demarcated powers and functions. Apart from it neither the system of Village Self-Government that prevailed in earlier times in India nor the method of Town-Government' that was then in existence in the European countries, periodically elected and responsible to the electorate, was planted in India by the British Government. The Britishers started Local Self - Government in India only later on as a representative organization responsible to a body of electors, enjoying wide power of administration and taxation and functioning both as a school for training in responsibility and as a vital link in the chain of organisations that made up the Government of the country.

#### **REFERENCES**

1. *Brief Note on Corporation Of Chennai*
2. *"The first corporation". The Hindu. April 2, 2003. Retrieved December 6, 2011.*
3. *"Ancient Epigraphical Inscription on elections". Tamil Nadu State Election Commission. Retrieved November 13, 2011.*
4. *"A Brief History of the Evolution of Panchayats in Tamil Nadu". Tamil Nadu State Election Commission. Retrieved November 11, 2011.*
5. *"About Us". Municipal Administration and Water Supply Department, Govt. of Tamil Nadu. Retrieved November 13, 2011.*
6. *"Post Independence Method of Election". Tamil Nadu State Election Commission. Retrieved November 13, 2011.*



- 
7. *"Districts Statistics"*. Government of Tamil Nadu. Archived from the original on November 4, 2011. Retrieved November 13, 2011.
  8. *"Presentation on Census"* (PDF). Directorate of Census Operations, Tamil Nadu. Retrieved November 13, 2011.
  9. *"Urban Local Bodies"*. Commissionerate of Municipal Administration, Govt. of Tamil Nadu. Retrieved November 13, 2011.
  10. *"List of Municipalities in Tamil Nadu Gradewise"*. Commissionerate of Municipal Administration, Govt. of Tamil Nadu. Archived from the original on 28 September 2012. Retrieved November 13, 2011.

## The Effectiveness Of E- Banking Environment In Customer Life Service An Empirical Study

**Author** : J Murali Krishnan

**Qualification** : M.Com., MBA., M.Phil, JAIIB, ICWA (Inter)

**Designation** : Research Scholar (PhD – Part time), Madras University, (Guide: Mr.Tameem Sherif,  
Assistant Professor, New College, Chennai)

**Institute** : Associate Vice President, Religare Finvest Limited.

**Email** : muralikrishnan.j@religare.com

**Contact No.** :9176251869

### Abstract

Advanced technology allows the banks to enhance its operations with cost cutting effectively and efficiently in order to handle daily banking affairs via online banking channel. Customers are being facilitated by reducing their visits in banks and doing their transactions via internet or ATM machines instead of personally visiting the branches. The purpose of this study is attempts to investigate the effective factors of facilitate using ebanking services for customers. This study is approached by using survey method to examine the relationship between independent and dependent variables. Data were collected through questionnaires which were attached by a letter explaining the purpose of study and assuring respondents of the confidentiality of their answers, those participants were online banking users in India. Statistical tools were used to test hypotheses and achieve the objectives, thus the research is descriptive and as a result quantitative methods have been used. The findings indicate that the entire hypotheses are supported positively the effectiveness of e-banking environment in customer service, and provide valuable information for banking industry, hopefully.

**Key words:** E-banking, online banking, service quality and security

### Introduction

Banking industry is one of the major users of information and communication technologies in business life. Since the new millennium, millions of dollars have been spent in developing online banking infrastructures; therefore internet banking has transformed traditional banking practice and looking on online services as the next technology in many countries. Today, through online banking, customers could conduct a wide range of banking services electronically, anytime and anywhere. By offering internet banking services, traditional financial institutions seek to offer lower operational costs, improve consumer banking services, retain consumers and expand share of customer. In the new banking environment, internet banking is increasing managed as an operational activity and an important component of a multi-channel strategy. Traditional banks have the main role for providing financial services as well as the electronic method is still growing up confidently. The majority of banks now offer some form of online services banks which are running to expect more clients in the next years. Internet users and consumers in more developed countries exhibit similar traits, and there is a link between the decision to open an online account and the perceived level of security of internet transactions. The advancement of technology especially the internet has changed the way how organizations run their business.

Nowhere has the revolution of internet been more apparent than in the banking and financial services industry. Many firms adapt rapidly to changes in internet and technology by improving their business efficiency and service quality via new applications in the internet, and attracting new customers. Banks have become increasingly interested and concerned about online banking services and are seeking methods to provide high quality service that exactly fulfills the requirements or preferences of their customers, they also developing differentiated service quality strategies to effectively retain their competitiveness or even obtain competitive advantage in this rapidly growing virtual market, especially given the deep impact of the internet on daily life during the past few years and the apparently assured growth of online banking in the financial service industry. Service quality has identified as an overall evaluation similar to attitude; expected service quality is a consumer desire; and perceived service quality indicates consumer perceptions of a firm's performance in providing a service. Online banking has known in different names such as Cyber bank, Internet banking, Virtual banking, Internet-based e-banking, and e-banking. Hence, the technology acceptance model (TAM) may also be influences in user adoption of technologies, suggested that usefulness refers to "the degree to which a person that using a particular system would enhance or improve his or her job performance" and ease of use refers to "the degree to which a person that using a particular system would be free from effort", likewise has also defined ease of use as "the consumer's perception that online banking involves minimum effort". Therefore, if the system that does not help people perform their jobs is not likely to be received favorably. As online banking continues to grow, banks need to meet these consumer demands in order to create a product that better serves the customer. Therefore in this research, if the bank enhances online user's productivity, it is more likely to be positively enhancing customer life service.

### **E-banking**

It's defined that provision of information and services by a bank to its customers via electronic wired or wireless channels, also have other definition of ebanking as internet portal, through which customers can use different kinds of banking services. In other words, some researcher cited that e-banking is an umbrella term for the process by which a customer may perform banking transactions electronically without visiting a brick-and-mortar institution, and it has become a one stop service and information unit that promises great benefits for both banks and consumers. Websites provide not only a direct contact between the organization and its customers but also present an opportunity for innovation in delivery/sell of products. It has categorized the website of online banking into three different ways namely the informational websites, communicative websites and transactional websites. Some factors such as internet accessibility, awareness, attitude towards change, computer and internet access costs, trust in one's bank, security concerns, ease of use and convenience have significant effect on e-banking industry. Furthermore, online banking provides a best way of low-cost channel for both transactions and building relationships. Therefore bank web sites that offer only information on their pages without possibility to do any transactions are not qualified as online banking services. The measure of this online service is this system satisfies customers need or not? If it's satisfy

then we can call that this system success. There are four basics services for online banking according to

- 1) View account balance with transaction history.
- 2) Paying bills, traffic violation and residence fees.
- 3) Transferring funds between accounts (locally and globally).
- 4) Online purchasing and request credit card advance.

Online Banking has made life much easier and banking much faster and more pleasant, for customers, it allows customers to do their banking outside of bank hours and from anywhere where internet access is available. In most cases a web browser is utilized and any normal internet connection is suitable. No special software or hardware is usually needed. Banks have to improved quality services to their customers to survive in this vulnerable environment among other things, banks must understand who specially adopting commercial technology and why. A primary benefit for the bank is cost savings because its use cheapest delivery channel and reduce number of service staff; and, for the consumer, a primary benefit is convenience with self-service. The advantage of operating online banking in term of bank and customer, respectively, which it shows in (Table 1) below.

**Table1. The advantage of operating online banking**

Operating online banking	Advantage
Bank	<ul style="list-style-type: none"><li>-Improved market image</li><li>-Reduce transaction cost</li><li>-Rapid response to the market changes &amp; customer needs</li><li>-Increased market penetration</li><li>-Advertise/Sell new product</li></ul>
Customer	<ul style="list-style-type: none"><li>-Reduce cost in accessing and using the bank service</li><li>-Increase comfort and time saving(transaction can be made 24 hours a day)</li><li>- Facilitate services &amp; speed of transaction</li><li>-Better administration of funds</li></ul>

#### **Personal device /Availability of internet**

Personal device such as “computers, laptops and smart-phones” is important tool in almost all the business transactions that are made today/has to be connected to the internet all day, therefore it would readily available, unless the user has personal device; it is unlikely to consider using internet banking. The internet as a medium for information consumption underpins consumer adoption of internet banking; internet allows companies to easily reach millions of customers around the world at a very low cost. On other hand, Internet as a marketing channel considered with three main functions namely providing information, conducting transactions, and extending self- help. Hence, the internet is changing the global marketplace, including the banking industry; the use of the internet is lowering entry costs and removing barriers to entry for many businesses. The lowering of barriers has led to a flood of banks entering the industry, ultimately increasing competition and providing increased value to potential customers. Moreover, internet can be used



to facilitate development by taking advantage of its easy access to information and the transfer of technology, also increased competition in the banking sector and customer demand is forcing banks to provide their services online. Unless the user has availability of internet at home or at work; it is unlikely to consider using internet banking. Thus, the future success of financial institutions will depend on how well they understand the market environmental changes position themselves to adapt to the new internet age.

### **Convenience**

The main impulse for internet banking to be convenience in terms of 24/7 access and time savings, and was found the main reason why American consumers selected the internet channel for news services. In most cases a web browser is utilized and any normal internet connection is suitable, which means no special software or hardware is usually needed. People will choose the cheaper method to transact when choosing between electronic or traditional services. Internet access in the expectation that many services and other needs fulfillment would be more convenient through its use. Means mostly described in terms of lifestyle, workplace use, household use, not having to travel, personal safety, not having to wait , 24/7 access and saved time.

### **Security**

It's defined as user's perception of protection against threats when transmitting private information over the internet banking and it is important matter regardless of age group, education and income level in online banking environment. The reliability of internet connections and internet banking applications are considered, users who have a technical background and understood security technology have higher levels of confidence in internet security than others and trust can indeed be a powerful force, but users still concerns about internet security, privacy and trust. Similarly, cited that hackers may access to customer's internet account if the internet banking security is weak, therefore customers need to be aware and up-to-date with the latest safety programs such as firewalls, virus programs.

### **Research Framework**

In particular, customers now enjoy unlimited access to any bank via the internet and thus have a wide range of choices in selecting banks, without geographical limitation. For example, a customer in India may have a savings account in Germany and a credit card from a bank in France. The research framework for the study is shown in (Figure1), based on the literature review, a model of e- banking was developed, and the major objective of the study was to examine the effective factors of facilitate using e-banking services for customers in India; whereby, the independent variables of those factors are (personal device , availability of internet, convenience and security ); are taken the sequential order carefully depends on the importance of each factor to facilitate service for customer, and the dependent variable represented by e-banking services.



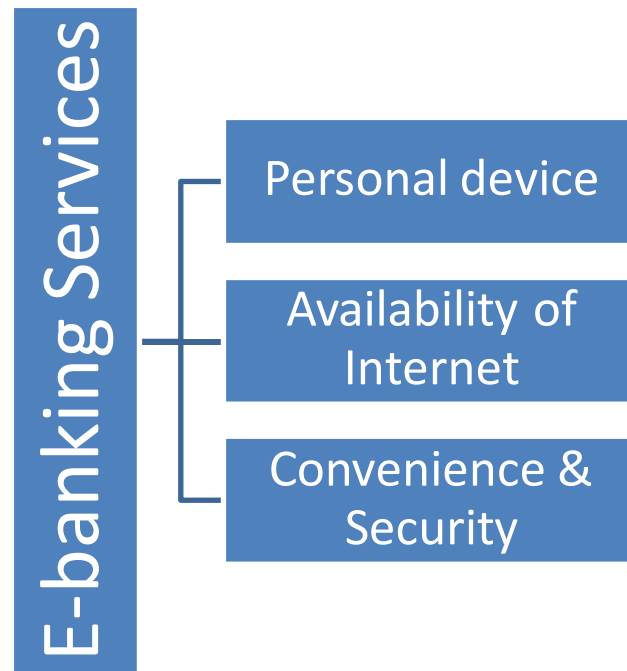


Figure 1. Model of e-banking

#### **Research hypotheses**

In order to achieve the objectives designed for this study, the following research hypotheses are stated and concerning the effective factors of facilitates using ebanking services for customers. Four hypotheses will be tested as follows:

H1: A significant relationship exists between personal device and e- banking service.

H2: A significant relationship exists between availability of internet and e-banking service.

H3: A significant relationship exists between convenience and e- banking service

H4: A significant relationship exists between security and e-banking service.

#### **Research objective**

The main purpose of this study is to evaluate the effectiveness of e-banking environment in customer life service. In order to meet this objective, the following objectives taken up under consideration.

- To find out the effective factors of e-banking facilitation to customer service.
- To enhance online services and meet beyond the expectation.
- To contribute in useful direction for future research.

#### **Methodology**

The main purpose of this study is to investigate effective factors of facilitates using e-banking services for customers in India. Since the questionnaire is one mechanism of data collection which is very famous among researches, a self-administered questionnaire was constructed and developed based on previous literatures, in order to test the above mentioned hypothesis. By using survey method, five-point Likert scales with ranging from “strongly disagree” to “strongly agree” were used to examine participants responses ,as well as, tested the main factors of facilitates using e-banking services for customers. The questionnaire will be handed out directly to the sample and will be collected back after specific time that already determined to ensure the

validity and accuracy as well as credibility of data. As such, the survey was targeted e-banking users in India. From the 220 questionnaires have distributed, 171 responses were received, which yielded response rate of about 77%. Out of 171 responses, 5 samples were eliminated from the analysis due to incomplete data.

#### **Data collection methods**

Primary data were collected by using a questionnaire, while secondary data were obtained from previous researches and literatures. The questionnaires were distributed randomly, whereby; the respondents will be from a different level. The distribution and collection process took about four week's period. The questionnaire consisted of two major parts, the first part was designed to collect demographic data and the second part was designed to measure the study variables. The questionnaire was prepared in English; it is composed of 22 items measuring the independent variables and dependent variable of the study, personal information such as name, mobile number, address etc is avoided in questionnaire.

#### **Sample Profile**

The demographic profile of the survey respondents is presented in (Table 2), which includes gender, age, level of education and etc. The gender distribution of the survey respondents shows that (54.2%) were males, while (45.8%) of them were females. The results also show that majority of the respondents fall into the age group of 31-40 years (35.6%) while only (11.4 %) are above 40 years old. Out of all the respondents, (74.7 %) were graduated; which indicates that respondents were composed of well-educated people. Furthermore, all the respondents have a personal device (computer/laptop) and internet availability at home and work, as well (80%) they logged onto the internet up to 8 hours daily.

**Table2.Demographic Profile of Responses**

Classification	Item	Number of e-banking users	Percentage (%)
Gender	Male	90	54.2
	Female	76	45.8
Age	Below 25	38	22.9
	26-30	50	30.1
	31-40	59	35.6
	Above 40	19	11.4
Level of education	Graduated	124	74.7
	Under-Graduated	40	24.1
	High school	2	1.2
Owing Personal device	Computer	29	0.17
	Laptop	137	0.83
Internet usage	1-4 times a day	52	0.31
	5-8 times a day	80	0.49
	9 times a day	34	0.20

Internet availability	Home	99	0.60
	Office	67	0.40

### **Reliability test**

The reliability test concerned with stability and consistency measurement to access the goodness of a measure, as well as reduce the possibility of getting error result. Data were entered and analyzed using statistical SPSS to obtain the Variance and reliability estimate of each variable. Based on the analysis, the results of variance have measured in the range from (0.6154 to 0.7267), which has exceeded the recommended value (0.5). Furthermore, the reliability of variables are in the range from (0.7123 to 0.7654) considered as acceptable and stable, in other word, the Cronbach's alpha values are above acceptance value ( $>0.7$ ), thus indicating content consistency within the questions related to each factor.

### **Pearson correlation test**

It's a measure of the strength and direction of the linear relationship between two variables to obtain the result of reject or accept the hypothesis. As well as, how well the variables are related. Hypotheses tested are shown as:

#### **H1: A significant relationship exists between personal device and e- banking service.**

As shown in (Table 3), the result of correlation between personal device and ebanking service indicates that there is a significant result between them. Pearson correlation value is ( $r=0.715$  at  $p<0.01$ ). Thus, the correlation between independent variable and determinant of e-banking service has high correlation value. Meaning that Personal device has a very good significance to support and reinforce the ebanking service among online customers positively. Therefore, H1 is accepted. However, Personal device is represented a heart tool of operating the online service from banks and use it by customers.

#### **H2: A significant relationship exists between availability of internet and e-banking service.**

As shown in (Table 3), the result of correlation between availability of internet and e-banking service indicates that there is a significant result between them. Pearson correlation value is ( $r=0.698$  at  $p<0.01$ ). Thus, the correlation between independent variable and determinant of e-banking service has high correlation value. Meaning that availability of internet has a very good significance to support and reinforce the e-banking service among online customers positively. Therefore, H2 is accepted.

#### **H3: A significant relationship exists between convenience and e- banking service**

As shown in (Table 3), the result of correlation between convenience and e-banking service indicates that there is a significant result between them. Pearson correlation value is ( $r=0.683$  at  $p<0.01$ ). Thus, the correlation between independent variable and determinant of e-banking service has high correlation value. Meaning that convenience has a very good significance to support and reinforce the ebanking service among online customers positively. Therefore, H3 is accepted.

#### **H4: A significant relationship exists between security and e-banking service.**

As shown in (Table 3), the result of correlation between security and e-banking service indicates that there is a significant result between them. Pearson correlation value is ( $r=0.549$  at  $p<0.01$ ). Thus, the correlation between independent variable and determinant of e-banking service has

good correlation value. Meaning that security has a good significance to support and reinforce the e-banking service among online customers positively. Therefore, H4 is accepted. Generally, from the above of all results of personal correlations have a very good value, which means all hypotheses are positively supported to concentrate and develop those factors to facilitate the service of e-banking to their customers.

**Table 3. P-correlation test**

Variables	E-banking service	Personal device	Availability of internet	Convenience	Security
Personal device	0.715**	1.000			
Availability of internet	0.698**		1.000		
Convenience	0.683**				1.000

\*\*Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

### Summary

In sum, e-banking process could be defined as "a customer who is using a personal device (computer/laptop), with doing all the online transactions 24/7 offered by the bank website". Unless the user has personal device and availability of internet; it is unlikely to consider using internet banking at all. The internet can play a profound role in maintaining and developing a high level of customer service, the amount of services in the internet is already enormous and more services are evolving. The paper aims to investigate the effective factors of facilitate using e-banking services for customers in India through, have been tested (personal device, availability of internet, convenience and security); hence, the result proved that they have a strong influence of facilitating customer life service easily and comfortably. A new result has appeared as an advantage of e-banking services to their customers" customer can do different types of transactions ; whenever he /she wants to, not bound to the bank's opening /closing hours and avoiding traffic jam or upon weather condition, it is more private and feels safer to do it at home or work". Whereby, the results provide valuable information for practitioners and online Banking systems developers and bank service providers when formulating online banking services. Furthermore, online banking has numerous advantages over traditional banking, for example, reaching far more people in cheap cost, offering more content than a brick-and-mortar branch, enabling easy access to desired services anywhere and anytime 24/7, avoiding the need to wait in lines, and so on. Future research needs to find out more factors could be effective for enhancing and facilitating of using online services coming from banks to their customers, as well As compare e-services with traditional interpersonal services to identify the differences in term of customer life services .However; respondents were sampled only from banks in India, which implies that the general of the study is limited. More studies in European countries are definitely needed. Accordingly, online banking truly changes the environmental methods and the roles of banks in servicing customers, and with the rapid growth of online banking services and large consumers shifting to banking online more empirical research are needed. The researcher also hoped that developers of online technique factors should consider this sentence "how to make online services of banks become easier to their customers".

### References

- 
- [1]. Alexander S, Online banking, OC Metro, 8, 2005, 50–51.
- [2]. Bergsten J.B., Keeping competitiveness in cyberspace, Bank Marketing, 32(2), 2000,34–37.
- [3]. Bielski L., Online banking yet to deliver, American Bankers Association, 92(9), 2000,6–8.
- [4]. Black N.J., Lockett A., Ennew C., Winklhofer H., and McKechnie S., Modeling customer choice of distribution channels: an illustration from financial services, International Journal of Bank Marketing, Vol. 20, No. 4/2002: 161-173.
- [5]. Boot, Arnoud, Relationship Banking: What Do We Know?,Journal of Financial Intermediation, 9/2000, 7–25.
- [6]. Chwirot-Zakrzewska, Ocenawielokanałowegomodeludstrybucjiusługbankowych wPolsce, in e-Finanse, 4/2009.
- [7]. Daniel E., Provision of electronic banking in the UK and the Republic of Ireland, International Journal of Bank Marketing, 17(2)/1999: 72-82.
- [8]. Davis F. D., Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology, MIS Quarterly, 13(3)/1989, 319-340.
- [9]. Degryse Hans and Steven Ongena, The Impact of Bank Competition on Bank Orientation, Journal of Financial Intermediation, 16(3)/2007, 399-424.
- [10]. Fairlamb D., Telecoms and banks tie the knot: They're rushing to make online banking a reality, Business Week, 23(1)/2000, 44–47.
- [11]. Gefen, D., Karahanna E. and Straub D.W., Trust and TAM in Online Shopping: An Integrated Model, MIS Quarterly, Vol. 7, No. 1, 2003: 51-90.
- [12]. Gerrard P. and Cunningham J.B., The diffusion of internet banking among Singapore consumers,International Journal of Bank Marketing, 21(1)/2003: 16-28.
- [13]. Hua G., An Experimental Investigation of Online Banking Acceptance in China, Journal of Internet Banking and Commerce, 14(1)/2009.
- [14]. Huang, J.S., Customer Choice Between Electronic and Traditional Markets: an Economic Analysis, in Proceedings of 35<sup>th</sup>Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2002), IEEE Society Press.
- [15]. LaithTalalKhrais and Gaafar Mohamed Abdalkrim, The Impact of Strategic planning on online banking an empirical study in (Saudi environment), American Journal of Business and Management, Vol. 2, No. 1, 2013, 53-58.
- [16]. Liao Z., & Cheung M.T., Internet-based e-banking and consumer attitudes: An empirical study, Information & Management, 39(2)/2002, 283–295.
- [17]. Mathieson K., Predicting user intentions: Comparing the technology acceptance model with the theory of planned behaviour. Information, Systems Research, 2(3)/1991: 173-191.
- [18]. Mayer Davis &Schoorman., An integrative model of organizational trust, Academy of Management Review, 20(3)/1995, 709–734.
- [19]. Meuter M.L., Ostrom A.L., Roundtree R.I. and Bitner M.J., Self-service Technologies: Understanding Customer Satisfaction with Technology-based Service Encounters, Journal of Marketing, Vol. 64/2002: 50-64.
- [20]. Nath Ravi and Schrick Paul and Parzinger Monica. Bankers, Perspectives on Internet Banking, E-Service Journal, 1-1/2001.



- 
- [21]. Nysveen H., Pedersen P.E. and Thornbjornsen H., Intentions to use mobile services: Antecedents and cross-service comparisons, *Journal of Academy of Marketing Science*, 33(3)/2005: 330-346.
- [22]. Parasuraman A., Zeithaml V.A., & Berry L.L, SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality, *Journal of Retailing*, 64(1)/1988, 2–40.
- [23]. Pew, Public More Critical of Press, But Goodwill Persists: Online Newspaper Readership Countering Print Losses, Pew Internet and American Life Project, 2005, Retrieved from World Wide Web on 5 February 2006 at <http://peoplepress.org/reports/display.php3?ReportID=248>.
- [24]. Pikkarainen T., Pikkarainen K., Karjaluoto H. and Pahnla S., Consumer acceptance of online banking: An extension of the technology acceptance model, *Internet Research*, 14(3)/2004: 224-235.
- [25]. Polasik M. and Piotr Wisniewski T., Empirical analysis of internet banking adoption in Poland, *International Journal of Bank Marketing*, Vol. 27 No. 1/2008.
- [26]. Sathye, Adoption of Internet banking by Australian consumers: an empirical Investigation, *International Journal of Bank Marketing*, Vol. 17, No. 7/1999:324-334.
- [27]. Sohail M.S. and Shanmugham B., E-Banking and customer preferences in Malaysia: An empirical investigation, *Information Sciences*, 150(1)/2003: 207-217.
- [28]. Sonja G.K. and Rita F., Consumer acceptance of internet banking: The influence of internet trust. *International Journal of Bank Marketing*, 26(7)/2008: 483-504.
- [29]. Tan M. and T.S.H. Teo, Factors influencing the adoption of Internet banking, *Journal of Association of Information Systems*, Vol. 1, No. 5/2000: 1-42.
- [30]. Uppal R.K., Customer Perception of E-Banking Services of Indian Banks: Some Survey Evidence, The Icfai University Press.2008



## महाराष्ट्र राज्यातील दुग्धव्यवसाय : एक अभ्यास

वर्षा दामोदर शिंदे

अर्थशास्त्र विभाग,

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ,  
औरंगाबाद.

मधुकर पिराजी शेळके

अर्थशास्त्र विभाग,

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ,  
औरंगाबाद.

प्रस्थावना :

भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. भारताची अर्थव्यवस्था ही कृषीवर अवलंबून असून ७० टक्के लोक हे ग्रामीण भागात राहतात. तसेच ६२ ते ६५ टक्के लोक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या शेतीवर अवलंबून आहे. भारतात प्राचीन काळापासून शेतीच्या मशागतीसाठी गाय बैल यासाराख्या प्राण्यांच्या वापर केल्या जात असल्याने प्राणी व शेती यांचा पुरातन काळापासून अतुट संबंध आहे. गाय, म्हैस, बकरी, मेंढी यासांरख्या प्राण्यांच्या मदतीने शेतीला पुरक साधने प्राप्त झाली असून त्यांच्या पासून मिळणाऱ्या दुधामुळे दुग्धव्यवसायात वाढ होऊन शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत तसेच राहणीमानात वृद्धी झाली.

भारत हा देश दुध उत्पादनात जगात प्रथम क्रमांकावर असून दुध उत्पादनाचे प्रमाण जगातील दुध उत्पादनाच्या १३ टक्के आहे. विविध कृषी पूरक व्यवसाय हे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळून देतात. जागतीक पर्यावरणाच्या सततच्या बदलांमुळे शेती व्यवसाय हा बेभरवशाचा बनत चालला असून शेती व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्या लोकांच्या समोर सतत नवनवीन अडचणी निर्माण होऊ लागल्या आहेत. याचवेळी देशातील सहकारी दुध व्यवसायाच्या माध्यमातून आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे एक साधन मिळाले आहे.

महाराष्ट्रातील मुंबई शहरात लोकानां स्वच्छ दुध मिळण्याच्या उद्देशाने 'आरे' दुध वसाहतीची स्थापना सन-१९४७ साली करण्यात आली. आरे दुध वसाहतीत ३२ गोठे स्थापन करून तेथे मुंबई शहरातील १६ हजार म्हशीचे स्थलांतर करण्यात आले. व १९५२ मध्ये शहरातील नागरीकांना निर्जंतुक दुध मिळण्याच्या उद्देशाने आशियातील पहिली दुधशाळा स्थापन करण्यात आली. या सर्व घडामोठीमुळे सहकारी दुध व्यवसाय देशामध्ये शेतीला पुरक तर काही ठिकाणी पर्याय म्हणून वाढीस

लागला आहे. जनावारांपासून मिळणारे दुध हे पौष्टिक असल्याने मानवाच्या सर्वांगीण वाढीसाठी खुप महत्त्वाचे आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या दुध व्यवसाय विभागाने दुध व्यवसाय या जोडधंद्याकडे विशेष भर देण्याचे ठरवलेले असून त्यानुसार राज्य शासनाने १९५८ साली. स्वतंत्र अशा दुध व्यवसाय विकास विभागाची स्थापना केली. आणि राज्यामध्ये वेगवेगळ्या दुध डेअर्यांची स्थापना होऊन त्यांचा विकास झाला व त्याचे एक प्रभावी साधन म्हणून महत्त्व प्राप्त होऊ लागले. मुंबई, ठाणे व नवी मुंबई ही देशाती सर्वात मोठी दुधाची बाजारपेठ निर्माण झाली. तेथे दररोज ७३ लाख लिटर दुधाची विक्री होते. त्यापैकी ५० लाख लिटर पिशवीबंद दुध विकले जाते. सन-१९६० मध्ये राज्यातील प्रतीदीन सरासरी दुध संकलन १ लाख लिटर्स इतके होते ते सन-२०१५-१६ या वर्षामध्ये ११४ लाख लिटर्स प्रति दिन इतके वाढले आहे. सन-१९९५-९६ साली शासन आणि सहकार मिळून एकूण ३१.४० लाख लिटर प्रतिदिनी पर्यंत होते. ते २००५-०६ साली ४०.०० लाख प्रतिदिनी पर्यंत वाढले होते. शासनाचे दुध वितरण सन-१९९५-९६ साली ८.५९ लाख लिटर प्रतिदिन एवढे होते. ते २००५-०६ मध्ये ६.६८ लाख लिटर प्रतिदिन एवढे कमी झाले. दरम्यान या काळामध्ये सहकारी संघाचे वितरण वाढत होते.

केंद्र सरकारने अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत “दुध व्यवसाय उद्योजक विकास योजना” लागू करून या योजनेसाठी २५० कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली होती. त्याचबरोबर १२ व्या पंचवार्षिक योजनेत कार्यरत असलेल्या ३ योजना सधन दुग्धविकास प्रकल्प, स्वच्छ दुध उत्पादन योजना, व संघाचे पुनर्वसन यांचे समायोजन करून राष्ट्रीय प्रकल्प पशु पैदास व दुध डेअरी विकास (NPBBDP) योजना तयार करण्यात आली या योजनेची अमलंबजावणी २०१४ पासून करण्यात आली होती.

#### संशोधन पध्दती :

सदर संशोधन हे दुय्यम साधन सामग्रीवर आधारीत आहे.

### संशोधनचे अद्दिष्ट :

१. महाराष्ट्रातील दुध व्यवसायाचा अभ्यास करणे.

### संशोधनाचे गृहित :

१. महाराष्ट्रातील दुध उत्पादनात वाढ होत आहे.

### दुध व्यवसायाची प्रगती :

१९७० नंतर दुधाच्या उत्पादनात झालेली वाढ ही धवल क्रांती किंवा श्वेत क्रांती म्हणून ओळखली जाते. १९७० मध्ये जो महत्त्वकांक्षी कार्यक्रम सुरू करण्यात आला तो "दुधचा महापूर" म्हणून ओळखला जाऊ लगला.

महाराष्ट्र शासनाच्या दुधव्यवसाय विकासाच्या प्रगतशील धोरणामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रगती झाल्याचे दिसून येते. ग्रामीण व तालुका पातळीवर शीतकरण केंद्रे उभारण्यात येऊ लागले असून राष्ट्रीय दुध विकास महामंडळ आणि मदर डेअरी यांच्या माध्यमातून दुध उत्पादन वाढीसाठी विदर्भ आणि मराठवाडा विभागातील दहा जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली होती. सद्यास्थितीमध्ये महाराष्ट्र राज्यात १३७३५ प्राथमीक सहकारी दुध संस्था, २१ जिल्हा सहकारी दुध संघ व ४६ तालुका सहकारी दुध संघ कार्यरत आहे. त्याचबरोबर सहकारी दुध महासंघाची 'महानंद' डेअरी, कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दुध उत्पादक संघ, कोल्हापूर जवळील 'वारणा' सहकारी दुध उत्पादक संघ, अकलूजचा 'शिवामृत' सहकारी दुध उत्पादक संघ अशा प्रकारे महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या ठिकाणी दुध महासंघ कार्यरत आहेत. या दुध उत्पादक महासंघामुळे शहरात मोठ्या प्रमाणात दुध पुरवठा होत आहे.

### देशातील व राज्यातील दुध उत्पादन :

भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणातील लोकसंख्या व त्यामानाने दुधाळ गुरांची कमी प्रमाणातील उत्पादनक्षमता बघता स्वातंत्र्यापूर्वी दुध व्यवसायाच्या प्रगतीस मार्यादा असल्याचे दिसून येते. मात्र स्वातंत्र्यानंतर दुध व्यवसायात दिवसेंदिवस प्रगती होतांना दिसून येते.

खालील तक्त्यात देशातील व राज्यातील दुध उत्पादनाची आकडेवारी दर्शवण्यात आलेली आहे.

तक्ता क्र. १

(दशलक्ष मेट्रिक टन)

अ. क्र.	वर्ष	देश	राज्य
१	१९७३-७४	२२.५००	१.०२३
२	१९८०-८२	३४.३००	१.७५६
३	१९८५-८६	४२.३००	२.४६६
४	१९८८-८९	४८.४००	२.८००
५	१९९०-९१	५४.९००	३.४६६
६	१९९५-९६	६६.०००	३.८५०
७	१९९७-९८	७२.९२८	५.१९३
८	२०००-०१	८०.६०७	५.८४९
९	२००५-०६	९७.०६६	६.७६९
१०	२००९-१०	११६.४२५	७.६८९
११	२०१२-१३	१३२.४३१	८.७३४
१२	२०१३-१४	१३७.०७	९.१००

स्रोत : शेतकरी मासिक (२०१६), सुवर्णमहोत्सवी विशेषांक, जानेवारी पृ.५५.

वरील तक्ता क्र. १ वरून असे दिसून येते की, १९७३-७४ मध्ये देशात २२.५०० दशलक्ष मेट्रिक टन तर राज्यात १.०२३ दशलक्ष मेट्रिक टन दुध उत्पादन झाले होते यात सतत वाढ होत जाऊन २०१३-१४ मध्ये देशात व राज्यात अनुक्रमे १३२.४३१, ९.१०० दशलक्ष मेट्रिक टन दुध उत्पादन झाले होते.

**दुध व्यवसाय विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजना :**

१. सधन दुग्ध विकास प्रकल्प :

ही योजना केंद्रपुरस्कृत असून या मध्ये डोंगराळ व मागासवर्गीय जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. दुध माहापूर योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्यासाठी परंतु ५० लाखा पेक्षा कमी तरतुद असलेल्या जिल्ह्याचा यात समावेश केला जातो. ही योजना केंद्रशासनाच्या कृषी पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागामार्फत राज्यातील डोंगराळ, अविकसीत व आदिवासी भागासाठी आहे. हा प्रकल्प १०० टक्के अनुदानावर राबविण्यात येतो.

२. स्वच्छ दुध उत्पादन योजना :

सदर योजना केंद्रशासन पुरस्कृत असून या योजनेतर्गत केंद्र शासन ७५ टक्के व संबंधित जिल्हा अथवा तालुका २५ टक्के हिस्सा या तत्वावर संरचनेचे बळकटीकरण व स्वच्छ दुध उत्पादन योजना राबविण्यात येते.

३. संघाचे पर्ववसन :

सदर योजना केंद्र व राज्य पुरस्कृत असून या योजनेतर्गत आजारी असलेल्या जिल्हा दुध सहकारी संघ व राज्य दुध सहकारी संघ यांना पुर्नजीवित करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

४. राष्ट्रीय कृषी विकास योजना :

या योजनेतर्गत विविध कार्यक्रम राबविण्यात येतात ते खालील प्रमाणे

१. इंटिग्रेटेड डेअर पार्क योजना : या योजनेतर्गत कोकण, मराठवाडा व विदर्भ या विभागातील २३ जिल्ह्यात प्रति २ या प्रमाणे एकूण ४६ प्रकल्प राबविले आहेत.
२. वेगवर्धक दुग्धविकास कार्यक्रम : राज्यामध्ये दुध व्यवसायाला चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे तसेच या योजनेतर्गत सहकारी संघाचे बळकटीकरण करण्यासाठी वेगवर्धक दुग्धविकास कार्यक्रम शासनामार्फत राबविण्यात येत आहे.
३. राष्ट्रीय ग्रथिने पूरक अभियान (NMPS) : या योजनेतर्गत दुध पावडर निर्मिती प्रकल्प अभाषणी करणे म्हणजेच दुध उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पादीत झालेले सर्व दुध संकलीत करून त्यापासून पावडर निर्माण करणे त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या दुधाचे होणारे नुकसान टाळणे.

समारोप :

महाराष्ट्रातील दुध व्यवसायाचा अभ्यास करतानां असे दिसून येते की, १९७० नंतर म्हणजेच स्वतऱ्यप्राप्तीनंतर दुध उत्पादनात दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसत आहे. विशेषतः ग्रामीण व शहरी भागात ही वाढ होताना दुध उत्पादनाचे महत्त्व लक्षात येते. महाराष्ट्र शासनाने यामध्ये विविध योजना राबवून दुध व्यवसायाला मोठी बाजारपेठ निर्माण करून देण्यात मोलाचा हातभार लावला आहे. विविध योजना राबवितांना शासनाने काही उद्दिष्टे सादर करण्यासाठी दुध महापूर योजना, संरचनेचे बळकटीकरण व स्वच्छ दुध उत्पादन योजना, संघाचे पूर्णवसन, सधन दुध विकास प्रकल्प, राष्ट्रीय

कृषी विकास योजना, राष्ट्रीय पूरक प्रथिने अभियान, राष्ट्रीय पशु पैदास व डेअरी विकास इंटिग्रेट डेअरी फार्म प्रकल्प, सुधारीत दुध प्रक्रिया सुविधा विकास प्रकल्प, वेगवर्धक दुग्धविकास कार्यक्रम इत्यादी योजनांची अंमलबजावणी करण्यात आली व त्याचा परिणाम होऊन दुधाची गुणवत्ता व परिमाण यांच्यात चांगल्या प्रमाणत वाढ दिसून येते त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीमध्ये वाढ व्हावी यासाठी भारत सरकारने २०२२ पर्यंत पूरक व्यवसायाची योजना राबविणार असल्याचे दिसून येते. शेतमजूर व बेरोजगारांना या व्यवसायाच्या माध्यमातून नवीन संधी निर्माण झाल्या आहेत. तसेच ग्रामीण भागातील दुध उत्पादन वाढवून शहरी भागातील दुधाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी शासनाने राबविलेल्या विविध योजनेमुळे शासनाने ठरविलेले उद्दिष्ट साध्य होताना दिसत आहे.

#### संदर्भ :

१. केरुरे वाय.ए. (२०१६), "महाराष्ट्रातील दुग्धोत्पादन : सद्यस्थिती व वाव", शेतकरी मासिक, स्ववर्णमहोत्सवी विशेषांक, जानेवारी २०१६.
२. भोसले विस्वास (२०१६), "पशुसंवर्धन विभागाचे सिंहावलोकन व भविष्यातील दिशा", शेतकरी मासिक, जानेवारी २०१६.
३. पशुधन ऐश्वर्य (२०१५), पशुसंवर्धन विभागाचे मासिक, पशुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
४. dairy Maharashtra.gov.in 16/05/2017.
५. <http://www.nic.in/dand> 16/05/2017.



## महाराष्ट्रातील दारिद्र्य-एक आढावा

ज्योती मच्छिंद्र कांबळे

अर्थशास्त्र विभाग,

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा

विद्यापीठ, औरंगाबाद.

### १) प्रस्तावना :-

मानवास जीवन जगताना अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण व आरोग्य या मूलभूत गरजांची पूर्तता करावी लागते. या सर्वांची पूर्तता करण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीस उत्पन्न प्राप्त करणे आवश्यक असते. मात्र या जीवनावश्यक मूलभूत गरजांची पूर्तता करू न शकणाऱ्या व्यक्तीस दरिद्री म्हणून ओळखले जाते.

दारिद्र्य हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोरील एक मोठे आव्हान आहे. मिलेनियम डिव्हलपमेंट २००० जाहीर होऊनही आज पंधरा वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला असताना देखील जगाला दारिद्र्य निर्मूलन या ध्येय प्राप्तीच्या दृष्टीने अपेक्षित यश प्राप्त झालेले दिसून येत नाही. उच्च दरडोई उत्पन्न असूनही उच्च मानव विकास साधण्यात अपयश येण्यामागे जी कारणे आहेत, त्यातील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे दारिद्र्याचे वाढते प्रमाण होय. आर्थिक नियोजनाचा स्विकार करून ६५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ जाऊनही देशात ३२ टक्के पेक्षा अधिक लोकसंख्या दारिद्र्यात जीवन जगत आहेत. किमान उपभोग पातळी ज्यांना उपभोगता येत नाही अशा व्यक्ती दारिद्र्यात जीवन जगत असतात. अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी मोठा अडथळा ठरणारा दारिद्र्य हा घटक दूर करण्यासाठी चौथ्या पंचवार्षिक योजनेत व्यापक प्रयत्न करण्यात आले आहेत. त्यामुळे दारिद्र्य नष्ट करण्यासाठी नियोजनाच्या माध्यमाने प्रयत्न करणारा भारत हा जगातील पहिला देश ठरला. सर्वसाधारणतः जगातील सर्व विकसनशील किंवा अविकसित देशांमध्ये दारिद्र्य आढळून येते. वाढती लोकसंख्या, रोजगार वृद्धीचा दर कमी, शहरीकरणाचा मंद विकास, औद्योगिक व सेवाक्षेत्राचा विकास संथ गतीने त्यामुळे बेकारीचे जास्त प्रमाण, कमालीची उत्पन्न विषमता, अशातच वारसा हक्काने जमिनीचे तुकडीकरण या सर्वांचा परिणाम म्हणून देशातील दारिद्र्याच्या संख्येत भर पडताना दिसून येते. भारतातील अनेक महत्त्वाच्या समस्यांपैकी दारिद्र्य ही एक महत्त्वाची समस्या आहे. दारिद्र्य हे केवळ गरीब किंवा विकसनशील देशातच आढळत नाही तर ते अमेरिकेसारख्या विकसित देशातही दिसून येते.

### २) संशोधन पद्धती :

प्रस्तुत संशोधनासाठी दुय्यम साधनांचा वापर करण्यात आला आहे.

### ३) संशोधनाची उद्दिष्ट्ये :

महाराष्ट्रातील वाढत्या दारिद्र्याचा अभ्यास करणे.

**४) संशोधनाची गृहतके :**

महाराष्ट्रातील दारिद्र्याच्या प्रमाणात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.

**५) दारिद्र्याची संकल्पना :**

दारिद्र्य हा शब्द संपत्तीचा अभाव किंवा कमतरता या अर्थाने वापरला जातो. ज्या व्यक्तींना आपल्या उत्पन्नातून किमान आवश्यक गरजाही पूर्ण करता येत नाही किंवा त्या व्यक्तीजवळ तुटपुंजी संपत्ती असेल अशा व्यक्तींना गरीब किंवा दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्ती असे म्हणतात. देशातील समाजाचा एक मोठा हिस्सा किमान जीवनमान पातळीपासून वंचित राहत असेल तेव्हा समाजात व्यापक दारिद्र्य अस्तित्वात असते. म्हणून समाजाचा एक भाग आपल्या जीवनावश्यक गरजा पूर्ण करू शकत नसेल तर त्यास दारिद्र्य म्हणतात.

दारिद्र्याची संकल्पना त्या-त्या देशाच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार बदलत जाते. अर्थतज्ज्ञांच्या मते अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य व शिक्षण या मूलभूत गरजांची उणीव म्हणजे दारिद्र्य होय. भारतामध्ये दारिद्र्याचे आकलन पर्याप्त मात्रेमध्ये (उष्मांक) उपभोगाच्या क्षमतेच्या आधारावर केले जाते. म्हणजे त्याच व्यक्तीला दारिद्र्य रेषेखाली समजते जाते जो की, ग्रामीण भागामध्ये प्रतिदिन २४०० उष्मांक आणि शहरी भागामध्ये २१०० उष्मांक जेवनातून मिळविण्यास असमर्थ आहेत. दारिद्र्य हे सर्वच देशात दिसत असले तरी दारिद्र्य विभाजन हे समाज आणि व्यक्ती परत्वे भिन्न असल्याचे दिसून येते.

रॅग्नर नर्वर्स यांच्या मते, कमी उत्पादकतेमुळे लोकांचे उत्पन्न कमी असते. कमी उत्पन्नामुळे वस्तुंची मागणी कमी असते. वस्तुंच्या मागणीतील कमतरतेमुळे गुंतवणुकीतून पुरेसा नफा न मिळाल्याने जी थोडीशी बचत होते ती गुंतवणुकीसाठी वापरली जात नाही. गुंतवणुक कमी झाल्याने कामगारामागे सरासरी भांडवल कमी राहते आणि त्यातून कामगारांची उत्पादकता कमी राहून उत्पन्नाची पातळी कमी राहते.

दारिद्र्य या संकल्पनेचा विचार करताना सापेक्ष दारिद्र्य आणि निरपेक्ष दारिद्र्य या दोन्ही संकल्पना विचारात घ्याव्या लागतात.

**सापेक्ष दारिद्र्य :**

जेव्हा एकाच देशातील उच्च उत्पन्न आणि न्यून उत्पन्न असणाऱ्या लोकांच्या उत्पन्नाची आणि उपभोगाची तुलना केली जाते तेव्हा सापेक्ष दारिद्र्य या संकल्पनेचा उपयोग केला जातो.

**निरपेक्ष दारिद्र्य :**

ज्या व्यक्तीस आपल्या प्राप्त उत्पन्नापासून किमान गरजा भागविणे ही शक्य नसते तेव्हा त्यास निरपेक्ष दारिद्र्य असे म्हटले जाते.

**६) दारिद्र्याची व्याख्या :**

१) अमर्त्य सेन यांच्या मते, व्यक्तीने जोपासलेल्या मूल्याप्रमाणे जगता न येणे म्हणजे दारिद्र्य होय.

२) जीवन जगण्यासाठी किमान आवश्यक गरजा भागविता येत नसल्याच्या परिस्थितीला दारिद्र्य असे म्हणतात.

**७) महाराष्ट्रातील दारिद्र्य :**

महाराष्ट्रात ग्रामीण आणि शहरी या दोन्ही भागात दारिद्र्याची समस्या असल्याचे दिसून येते. ओला व कोरडा दुष्काळामुळे महाराष्ट्रातील दारिद्र्याचे प्रमाण वाढता दिसून येते. लोकसंख्येचे वाढते प्रमाण व याचा परिणाम म्हणून बेरोजगारीची वाढती समस्या गोष्टींमुळे दारिद्र्य दिवसेंदिवस वाढत जाताना दिसून येते. बेरोजगारीमुळे माणसाला आपल्या मूलभूत गरजा अन्न, वस्त्र, निवारा हे सुद्धा भागवणे शक्य होत नाही व या गरजा पूर्ण न झाल्यामुळे दारिद्र्यात वाढ होत आहे. महाराष्ट्रात २०११-१२ मध्ये २४.२२ टक्के ग्रामीण भागात तर ९.१२ टक्के शहरी भागात म्हणजे एकूण १७.३५ टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली होती.

महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीपासून दारिद्र्य निर्मूलन हे विकासात्मक नियोजनाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट्ये राहिले आहे. सन २०११-१२ साली अखिल भारतीय स्तरावरील दारिद्र्यरेषा ग्रामीण भागासाठी ८१६ रुपये प्रतिव्यक्ती प्रति महिना आणि शहरी भागासाठी १००० रु. प्रति व्यक्ती प्रति महिना अशी निश्चित करण्यात आली. महाराष्ट्राकरिता ग्रामीण भागासाठी ९७६ रुपये प्रतिव्यक्ती प्रति महिना आणि शहरी भागासाठी ११२६ रुपये प्रतिव्यक्ती प्रति महिना अशी ठरविण्यात आली. खालील तक्त्यावरून महाराष्ट्रातील दारिद्र्याचे प्रमाण स्पष्ट होईल.

**महाराष्ट्रातील दारिद्र्याचे प्रमाण (१९७३-७४ ते २०११-१२)**

वर्ष	शिरगणतीचे गुणोत्तर (%)	व्यक्तींची संख्या (लाखात)
१९७३-७४	५३.२	२८७.४
१९८३	४३.४	२९०.४
१९९३-९४	३६.९	३०५.२
२००४-०५	३८.२	३९२.२
२०११-१२	१७.४	१९७.९

**संदर्भ :** महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१३-१४

उपरोक्त तक्त्यात महाराष्ट्रातील दारिद्र्याचे प्रमाण दिले आहे. सन १९७३-७४ मध्ये महाराष्ट्रातील दारिद्र्याचे प्रमाण ५३.२ टक्के होते. सन २०११-१२ मध्ये तेच प्रमाण १७.४

टक्क्यांवर आले आहे. तसेच १९७३-७४ मध्ये व्यक्तींची संख्या २८७.४ लक्षावर सन २०११-१२ मध्ये १९७.९ लक्षांवर आली आहे.

वरील तक्ता पाहता आपल्या असे लक्षात येते की मागील चार दशकात दारिद्र्याच्या प्रमाण घट झालेली दिसून येत असले तरी मात्र आजही महाराष्ट्रातील दोन कोटी जनता दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगत असल्यामुळे महाराष्ट्रातील दारिद्र्याची व्याप्ती मोठी असल्याचे दिसून येते.

#### ८) दारिद्र्याचे मोजमाप केलेल्या समित्या :

भारतात आजपर्यंत अनेक विचारवंतांनी दारिद्र्याचे मोजमाप करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

##### १) पी.डी. ओझा :

यांच्या मते, दररोज सरासरी २२५० उष्मांक मिळून देण्यासाठी ग्रामीण भागात दरडोई माणसी ८ ते ११ रुपये आणि शहरी भागात १५ ते १८ रुपये उपभोग खर्च आवश्यक आहे. परंतु हा उपभोग खर्च करण्याएवढे उत्पन्न नसलेली ग्रामीण भागातील ५१.८ टक्के आणि शहरी भागातील ७.६ टक्के लोकसंख्या सन १९६०-६१ मध्ये दारिद्र्यात होती. १९६७-६८ मध्ये ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखाली लोकसंख्येचे प्रमाण ७० टक्के होते. म्हणजेच ग्रामीण भागातील दारिद्र्यात वाढ झालेली दिसून येते.

##### २) डॉ. दांडेकर व निलकंठ रथ :

१९६०-६१ च्या किंमतीनुसार २२५० उष्मांक असलेला आहार मिळविण्यासाठी दरडोई दरवर्षी ग्रामीण भागात १८० रुपये आणि शहरी भागासाठी २७० रुपये आवश्यक आहेत. सन १९६८-६९ च्या किंमतीनुसार ग्रामीण भागासाठी ३२४ रुपये व शहरी भागासाठी ४८६ रुपये खर्च येतो. त्यांच्या मते १९६८-६९ मध्ये ग्रामीण भागातील ४० टक्के आणि शहरी भागातील ५० टक्के अशी एकूण ४१ टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यात होती.

##### ३) बी.एस. मिन्हास :

यांच्या मते, ग्रामीण भागासाठी दरडोई २४० रुपये उपभोग खर्च आवश्यक आहे. असे मानल्यास सन १९५६-५७ मध्ये ग्रामीण भागातील दारिद्र्याचे प्रमाण ६५ टक्के तर १९६७-६८ मध्ये दारिद्र्याचे प्रमाण ५०.६ टक्के होते. म्हणजे दारिद्र्यात घट झालेली दिसून येते.

##### ४) डॉ.पी.के. वर्धन :

१९६०-६१ च्या किंमतीनुसार ग्रामीण भागात दरडोई मासिक १५ रुपये उपभोग खर्च आवश्यक आहे. यांच्या मते, ग्रामीण भागात सन १९६०-६१ मध्ये ३८ टक्के तर १९६८-६९ मध्ये ५४ टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यात होती असे दिसून येते.

वरील समित्यांच्या अभ्यास केला असता सर्व समित्यांच्या मोजमापामध्ये तफावत असल्याचे दिसून येते.

९) समारोप :

भारत देशाकडे जगातील उगवती महासत्ता म्हणून पाहिले जाते. या दृष्टिकोणातून व्यवहरचनात्मक धोरणांचा स्वीकार करून दारिद्र्य निर्मुलनासाठी प्रामाणिक प्रयत्नांची गरज आहे. तसेच दारिद्र्य निर्मुलनाची समस्या दूर करण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरच नव्हे तर स्थानिक पातळीवर देखील प्रयत्न केला गेला पाहिजे. आपल्या देशात आजही ग्रामीण भागात शहरी भागापेक्षा जास्त प्रमाणात दारिद्र्य असल्याचे आढळून येते. दारिद्र्यासाठी शिक्षणाचा अभाव, भ्रष्टाचार, जातिव्यवस्था, आर्थिक असमानता या गोष्टी जबाबदार आहेत. दारिद्र्य कमी करण्यासाठी सरकारने शिक्षणाची सक्ती करणे, रोजगार निर्माण करणे, लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण करणे या सर्व गोष्टींची अंमलबजावणी केली तरच देशातील दारिद्र्य संपुष्टात आणण्यास मदत होईल व आपला देश दारिद्र्याच्या दृष्टचक्रातून बाहेर येईल.

संदर्भ :

- १) प्रा. मदनुरे व्यंकटेश, काळूराम, २०१०, योजना, पृ. क्र. ५० ते ५२
- २) कांबळे कृष्णा शिवाजी, २०१२ लघु शोध प्रबंध, रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाद्वारे दारिद्र्य निर्मुलन एक अभ्यास, पृ. क्र. ५ ते ७
- 3) Shodhankan, 21st Century World : Present Scenario and challenges, Dr. Pandit Nalawade.
- ४) दत्त रूद्र व सुंदरम (२०१०), भारतीय अर्थव्यवस्था, एस.चंद्र अँड कंपनी, नई दिल्ली.

## महाराष्ट्रातील रोजगार व स्वयंरोजगार निर्मितीत अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे योगदान

विलास आबासाहेब नरवडे

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा

विद्यापीठ, औरंगाबाद.

Email: narwadevilas158@gmail.com

### प्रस्तावना :

महाराष्ट्र राज्यात बेरोजगारी ही एक जटील व गंभीर समस्या बनली आहे. हा मुलतः आर्थिक व सामाजिक स्वास्थाचा प्रश्न आहे. महाराष्ट्र राज्याने सन २००० मध्ये रोजगार आणि स्वयंरोजगाराबाबत घोषित केलेल्या धोरणानुसार सुशिक्षित स्वयंरोजगार योजनांप्रीत्यर्थ आवश्यक निधी देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाने उचलली आहे. स्वयंरोजगार योजनांची उद्दिष्ट्ये व त्याची यशस्वीता योग्य लाभार्थ्यांच्या निवडीवर अवलंबून आहे. रोजगार व स्वयंरोजगार योजनांची उद्दिष्ट्ये ही केवळ इष्टांकपूर्तीसाठीच न राहता या योजनांमुळे योग्य लाभार्थ्याला खरोखरच लाभ होण्यासाठी या योजना सुलभ व पारदर्शीपणे राबवणे आवश्यक आहे. स्वयंरोजगारासाठी सामान्यपणे कोणतीही व्यक्ती सहसा प्रवृत्त होत नाही. कारण त्या व्यक्तीस भविष्यात आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होण्याची खात्री वाटत नाही. स्वयंरोजगाराकरीता समाजात अनुकूल बदल घडवून आणावयाचे असतील तर स्वयंरोजगार करणाऱ्यास त्याचे भविष्यकाळासाठी आर्थिक स्थैर्याची शाश्वती मिळवून देण्याची आवश्यकता आहे.

या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील बेरोजगार उमेदवारांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतर्गत असलेल्या महामंडळामार्फत स्वयंरोजगार इच्छुक उमेदवारांना स्वयंरोजगारीकरीता प्रोत्साहन तसेच कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते.

राज्यातील बेरोजगारीची तिब्रता कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विविध प्रकारच्या स्वयंरोजगार योजना सुरु केल्या आहेत. या अनुषंगाने स्वयंरोजगार योजना सुरु केल्या आहेत. या स्वयंरोजगाराच्या कर्ज योजनांची पारदर्शी आणि प्रभावी अंमलबजावणी होऊन उमेदवारांना स्वयंरोजगाराकरीता कर्ज उपलब्ध करून देणे सुलभ व जलद होण्याकरीता स्वयंरोजगार वेब पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे.

स्वयंरोजगार म्हणजे काय :



शिक्षणानंतर सर्वच जण स्वयंरोजगाराच्या शोधात असतात. पण पुष्कळदा तुम्हाला तुमच्या शैक्षणिक योग्यतेची नोकरी मिळत नाही अशा परिस्थितीत स्वयंरोजगार हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो.

स्वयंरोजगार या शब्दाचा अर्थ स्वतःच स्वतःसाठी रोजगार उपलब्ध करणे आणि त्याद्वारे अर्थार्जन करणे असा होतो. नोकरी न करता स्वयंरोजगाराचा मार्ग पत्करणे म्हणजे स्वयंरोजगार होय.

#### रोजगार व स्वयंरोजगार संचालनालय :

महाराष्ट्र राज्याच्या कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता संचालनालयाकडे दरवर्षी लाखो बेरोजगार युवक युवती नोंदणी करीत असतात. परंतु या बेरोजगारांच्या हातांना काम देण्यास संचालनालय कुचकामी ठरले आहे. २०१५-१६ च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार २०१५ साली केवळ ७० हजार बेरोजगारांना रोजगार मिळाला आहे.

#### रोजगार व स्वयंरोजगाराचा दृष्टीकोन :

युवकांना नोकरीकरीता सहाय्य आणि स्वयंरोजगाराकरीता मार्गदर्शन करून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी व उत्पन्न वाढविण्यासाठी त्यांना उद्युक्त करणे.

#### उद्देश :

उमेदवारांना आश्वासित, पारदर्शक व विकेंद्रीत रोजगार, स्वयंरोजगारांची सेवा ई-प्रशासनाच्या माध्यमातून मिळवून देणे, उमेदवारांना रोजगार मिळण्याची क्षमता वाढविणे, उद्योजकांना रोजगार व स्वयंरोजगार विभागांतर्गत उमेदवार होण्यासाठी उद्युक्त करणे व त्याद्वारे युवकांचा सामाजिकस्तर वाढविणे.

#### कार्य :

- १) बेरोजगार उमेदवारांची नोंदणी करणे व त्यांना नोकरी मिळविण्यासाठी मदत करणे.
- २) असंघटीत क्षेत्रातील सेवा देणाऱ्या व सेवा घेणाऱ्यांसाठी पाठबळ व मदत करणे.
- ३) अपंग उमेदवारांसाठी विशेष रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्र.
- ४) कौशल्य विकास कार्यक्रम.

#### संशोधन पध्दती :

प्रस्तुत संशोधन पध्दती दुय्यम आधार सामुग्रीवर आधारित आहे.

#### उद्दिष्ट्ये :

१. महामंडळाने स्वयंरोजगार निर्मितीत दिलेल्या योगदानाचा अभ्यास करणे.

#### गृहित :

१. महामंडळाने राबविलेल्या विविध योजनेमुळे बेरोजगारांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होत आहे.

#### रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाची बदलती भूमिका :

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना दिनांक २७/११/१९९८ रोजी कंपनी कायद्यांतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या सर्वांगीन विकासासाठी करण्यात आली. लाभार्थ्यांच्या सर्वांगीन विकासासाठी स्वयंरोजगार एक पर्याय म्हणून उपलब्ध करून दिल्यास त्यामुळे लाभार्थ्यांच्या उन्नतीचा मार्ग मोकळा करता येईल. प्रत्येक विभागाने आपल्या क्षेत्रासाठी व स्वयंरोजगार निर्मितीचे व्यापक धोरण व अंमलबजावणीची जबाबदारी उचलणे आवश्यक आहे. या सर्व व्यापक धोरणाची अंमलबजावणी योग्यरितीने व प्रभावीपणे होत आहे हे पाहण्याचे काम करणे ही आवश्यक आहे. याकरीता रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाने एका प्रभावी समन्वयकाची (नोडल एजन्सी) भूमिका बजावावी. रोजगार व स्वयंरोजगार योजनांच्या धोरणांचा, अंमलबजावणीचा आणि त्यास येणाऱ्या अडीअडचणींचा आढावा घेवून त्यातून योग्य मार्ग काढावा.

#### अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाबद्दल :

राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी राज्य शासनाने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना दिनांक २७/११/१९९८ रोजी केली.

राज्यात आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकांचा आर्थिक विकास करणे आवश्यक आहे. त्याकरीता विशेष करून मराठा समाजातील बेरोजगार युवकांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याकरीता या महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाद्वारे मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व दारिद्र्य रेषेअंतर्गत जीवन जगणाऱ्या व्यक्तींना त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. सध्या महामंडळाचे भाग-भांडवल रुपये २०० कोटीचे असून २०१६-१७ या वर्षात महामंडळाला रुपये ५०.०० कोटी भाग-भांडवल शासनाकडून मिळाले आहे. म्हणजेच महामंडळाचे भाग-भांडवल हे पहिले रुपये १५० कोटी वरून रुपये २०० कोटी झाले आहे.

#### महामंडळाची उद्दिष्ट्ये :

- १) आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकापर्यंत विशेष करून बेरोजगार तरुणांपर्यंत रोजगार योजना पोहचवून त्यांना सक्षम बवविणे.
- २) योजना राबवून रोजगाराच्या व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
- ३) आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांचा सामाजिक विकास घडवून आणणे.

#### महामंडळाच्या विविध योजना :

##### १. बीज भांडवल कर्ज योजना :

महामंडळ राबवित असलेल्या बीज भांडवल कर्ज योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी समान संधी मिळावी या दृष्टीने दर वर्षी महामंडळाकडून जिल्हानिहाय समान लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट सर्व जिल्हा कार्यालयांना वाटप करण्यात येतात. या उद्दिष्टांच्या किमान तिप्पट कर्ज प्रकरणे बँकेकडे मंजूरीसाठी पाठविण्याच्या सुचना प्रत्येक जिल्ह्यांना देण्यात येतात.

बीज भांडवल कर्ज योजनेअंतर्गत वितीय संस्थांचा सहभाग हा ६० टक्के असल्यामुळे या महामंडळाकडून कर्ज घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना बऱ्याच अडचणींना सामोरे जावे लागते. बऱ्याच वेळी बँक लाभार्थ्यांचे बचत खाते नसल्यामुळे कर्ज प्रकरण नाकारते. तसेच जी गावे बँकेने दत्तक घेतलेली आहेत, त्यापैकी कर्ज घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना बँकेकडून चांगला प्रतिसाद मिळत नाही. यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये निराशा उत्पन्न होवून त्यांची स्वयंरोजगाराची आवड कमी होत जाते.

बीज-भांडवल कर्ज योजना (शासन निर्णय) जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार कार्यालयामार्फत राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत अर्जदारास रुपये ५ लाखापर्यंत प्रकल्प मर्यादा असलेल्या व्यवसायाकरीता अर्थसहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते. यामध्ये राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित बँकेचा सहभाग ६० टक्के असून अर्जदारास ५ टक्के रक्कम स्वतःचा सहभाग म्हणून भरावयाची आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांनी मंजूर केलेल्या प्रकल्प रकमेच्या ३५ टक्के रक्कम महामंडळामार्फत बीज भांडवल म्हणून देण्यात येते. महामंडळाच्या मंजूर रकमेवर द.सा.द.शे. ४ टक्के व्याज आकारण्यात येते. परतफेडीचा कमाल कालावधी ५ वर्षांचा असून त्यासाठी वसूली ही मासिक, त्रैमासिक, सहामाही, वार्षिक याप्रमाणे करण्यात येते.

## २. महामंडळाची थेट प्रकल्प योजना :

महाराष्ट्रातील ही योजना जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्रामार्फत राबविली जाते. सुशिक्षित बेरोजगार युवक, युवतींना रुपये ५००/- ते ५०,०००/- पर्यंत कर्ज दिले जाते. या योजनेअंतर्गत कर्ज घेणाऱ्यांची शैक्षणिक पात्रता इयत्ता ४ थी पास आवश्यक आहे. यासाठी वयोमर्यादा १२ ते ४५ वर्ष एवढी आहे. एकूण कर्ज रक्कमेतून ९५ टक्के रक्कम महामंडळाकडून मंजूर केली जाते. व्याजदर ६ टक्के द.सा.द.शे. राहिल. या महामंडळाचा लाभ घेण्यासाठी खालील अटींची पूर्तता करावी लागते.

१) सदर योजनेसाठी दोन सक्षम जमीनदार देणे आवश्यक आहे.

२) कर्जातून व्यवसायासाठी यंत्र साधनसामुग्री घ्यावयाची असेल तर ती तारण म्हणून महामंडळाकडे ठेवली पाहिजे.

सारांश :

नवयुवक तरुणांना स्वतःची क्षमता आणि ताकद याबाबत जागरूक करण्याची आज गरज आहे. ज्यामुळे ते समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ शकेल. त्यांना नवीन नवीन कौशल्य विकास योजनांची माहिती द्यावी लागेल. जेणे करून तरुण पिढी बेरोजगार राहणार नाहीत. यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे.

**संदर्भसूची :**

- १) रोजगार व स्वयंरोजगार मंत्रालय, मुंबई.
- २) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ पुस्तिका (२००० ते २०१४), मुंबई.
- ३) रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग, मुंबई. (५ नोव्हेंबर २०००).
- ४) जिल्हा रोजगार आणि स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, (२६ मे २०१५),

## ANALYSIS OF PARLIAMENTARY ELECTIONS (2014) IN PUNJAB

**Dr. Neeru Sharma**

Associate Prof. & Head Political Science,  
B.D. Arya Girls College, Jalandhar Cantt.  
Email-neerusharma15@gmail.com,  
Mobile no: 9463284185

### **Abstract**

*The Great Indian General Elections, the biggest ever democratic process in the country's history were conducted from April 7 to May 12. Elections were conducted in nine phases on April 7, 9, 10, 12, 17, 24, 30, May 7 and 12 (2014). It is over six decades that democracy has been in action in India. Our greatest positive achievement has been that we have survived as a democratic nation. In India, representative democracy calls for a system of choosing representatives of the people. Although every election in itself is very important yet Lok Sabha elections are important in the sense that these are held all over India and decide the destiny of the government of country. Therefore, the whole process right from the notification of elections to the declaration of results remains very interesting. Every state has to play important role in sending its representatives to the Parliament. Reputation of candidates, the image of the ruling party, state ruling party's performance, core issues, factors at play and other non-political issues vary from state to state. Keeping this in view, a modest attempt has been made in this paper to analyse the outcome of Lok Sabha elections 2014 in the state of Punjab. The requisite data for this study has been obtained from newspapers, journals, magazines and websites.*

### **Keywords:**

*AAP, Akalis, Badals, Elections, Lok Sabha, Punjab, SVEEP.*

In 1947, the province of Punjab was partitioned between India and Pakistan. Again under the Punjab Reorganisation Act, a Punjabi speaking state was carved out in 1966. The present Punjab is organized into 5 divisions, 22 districts, 81 subdivisions tehsils, 81 sub-tehsils and 145 development blocks. The state has total area of 50,363 sq km. Punjab boasts of an average growth rate of 10%, which is almost highest in the country. Agriculture is the biggest contributor to Punjab's Gross Domestic Product (GDP). The region is ideal for wheat growing. In fact, Punjab is known as the granary of India or "India's bread basket"<sup>1</sup>.

Geographically, Punjab is divided into three regions-Majha, Malwa and Doaba. Majha is a historical region of the Punjab comprising the modern district of Amritsar, Gurdaspur and Taran Taran. Malwa is a region between Sutlej and Yamuna river. Barnala, Bathinda, Faridkot, Firozpur, Ludhiana, Mansa, Ropar, Moga, Anandpur Sahib, Muktsar, Patiala, Sangrur and Fatehgarh Sahib district form the Malwa region. Doaba is the region of Indian Punjab surrounded by Beas and Sutlej rivers. It is one of the fertile regions of Punjab. Jalandhar, Hoshiarpur, Kapurthala, Nawasahar (now Shaeed Bhagat Singh Nagar) are important areas of this region<sup>2</sup>. As per 2011 census, Sikh population is 63.60%, Hindu 34%, Muslim 2%, Christian 1.2% and Jain 0.16%<sup>3</sup>.

### **Politics in Punjab: Background**

Politics in Punjab has been dominated by a handful of families since independence. Although these clans have been opposing each other politically, most of them are closely connected. The Badal family has been dominating the state politics. Parkash Singh Badal is active in State politics since the late 50s. While he is serving the fifth term as Chief Minister, his son Sukhbir

Singh Badal is Deputy Chief Minister. Politics has created split in the Badal family. Former Finance Minister Manpreet Badal (nephew of Parkash Singh Badal) Contested election against Harsimrat kaur Badal (Daughter in-law of Parkash Singh Badal.) Sukhbir Badal's brother in Law Bikram Singh Majithia's family has been active in politics since 1920. Adesh Partap Singh Kairon, son-in-law of Parkash Singh Badal, belong to a family which is active in politics since 1930s and his grandfather Partap Singh Kairon remained Chief Minister of Punjab for about a decade. The royal family of Patiala is another dominating force in the State Politics. Captain Amrinder Singh's family members had served in different capacities in Punjab politics<sup>4</sup>.

From 1947 to 1966, INC was dominant party in undivided Punjab. In 1967, following the division of Punjab, Shiromani Akali Dal (SAD) came to power and remained in office till 1971. In the elections held in 1972, Indian National Congress (INC) led by Zail Singh obtained majority and came back to power. In the 1977 elections, SAD led by Parkash Singh Badal emerged victorious. Since then INC has won the 1980, 1992 and 2002 elections while SAD has formed government after in 1985, 1997, 2007 and 2012 elections. Punjab has been under the President rule on eight occasions<sup>5</sup>.

Punjab has always played an important role in the formation of all Central governments. State has given the nation its Prime Minister I.K. Gujral, who successfully contested from the Jalandhar seat on Janta Dal ticket supported by the Akalis in 1989. Since the parliamentary elections in 1967- the first after Punjab was divided on linguistic basis (1966), state has recorded a high percentage of voter turnout, ranging between 50 per cent and over 70 percent. The 1992 elections were the only exception when Punjab recorded 23.96 per cent polling on account of a boycott call by the SAD. Every party had fluctuating fortunes here. In 1977 and 1988, the Congress was wiped out with no seat, but in 1980 and 1992 it won 12 seats. Similarly, the best performance of the Bhartiya Janta Party (BJP) earlier Jan Sangh has been in 1967, 1977, 1998 and 2004. But it scored a duck in 1971, 1980, 1985, 1989 and 1996. The Communist Party of India (CPI) won two seats in 1971 and one in 1999, while the Communist Party of India Marxist (CPM) won a seat in 1977. The Janta Dal won a seat in 1989 and I.K. Gujral became PM. In the same year, the (SAD Mann) won six seats. The BSP also has had its occasional successes in Punjab, even though Punjab has one of the largest numbers of schedule caste populations. The BSP won a seat in 1992 and three in 1966. Among the regional parties, the SAD had its best performance in the post-emergency era when it won seven seats in 1985, six in 1987, and eight seats each in 1996, 1998 and 2004. In the 2009 elections, it won four seats, the BJP one and Congress eight<sup>6</sup>.

### **From Nominations to Campaign: Factors at Play**

The Election Commission of India decided that Lok Sabha elections in Punjab for 13 seats would be held in single phase<sup>7</sup>. The process of filing of the nominations started on 2 April 2014 and the last date for filling of nominations was 9 April 2014. 11 and 12 April 2014 were fixed for withdrawing nominations. A total of 253 candidates were left in the election fray as 27 candidates withdrew their nominations on the last day of withdrawing. 455 nominations were filled by 350 candidates which were reduced to 280 after scrutiny. Out of total 50 candidates



fielded by the SAD-BJP. Congress, Bahujan Samaj Party (BSP) and Aam Aadmi Party (AAP) for 13 seats in the state, six women were left in the fray<sup>8</sup>.

**Table: No. of voters and candidates**

Constituency	No. of voters (Lakh)	No. of candidates
Gurdaspur	14,92,000	13
Amritsar	17,90,885	23
Khadoor Sahib	15,75,926	17
Jalandhar (R)	15,48,088	24
Hoshiapur (R)	14,85,286	17
Anandpur Sahib	15,57,188	18
Ludhiana	15,59,851	22
Fatehgarh Sahib (R)	13,96,954	15
Faridkot (R)	14,50,423	19
Ferozepur	14,98,366	15
Bathinda	14,55,075	29
Sangrur	14,24,743	21
Patiala	15,73,687	20

**Source :** The Tribune, 17 April 2014, PP. 12-13. Jalandhar, Ajit 29 April 2014, P.2, Jalandhar. Earlier in Punjab it had always been a direct contest between SAD-BJP alliance and the Congress. For the first time in the state there was a credible third contender in the fray in the form of Aam Aadmi Party (AAP). The entry of AAP in Punjab's electoral arena after its success in the Delhi Assembly Polls spiced up the electoral battle in many constituencies. SAD and BJP having alliance in Punjab with Akali candidates contested from 10 seats and BJP from 3 seats. Out of 13 Lok Sabha seats Jalandhar, Hoshiarpur, Fatehgarh Sahib and Faridkot were reserved for schedule caste candidates. This time it was triangular competition between SAD/BJP, Congress and AAP. Instead of Modi wave it was AAP wave in Punjab, especially among the youth<sup>9</sup>. Manpreet Badal was the only regional leader being supported by two national parties. Though the people's Party of Punjab (PPP) he founded in 2011, floundered in the state's choppy political waters, Manpreet Badal was supported by Congress and the Communist Party of India<sup>10</sup>.

**Table: Lok Sabha Candidates: Punjab, Three Main Parties**

Constituency	Congress	BJP/SAD	AAP
Amritsar	Captain Amrinder Singh	Arun Jaitley	Dr. Daljeet Singh
Anandpur Sahib	Ambika Soni	Prem Singh Chandumajra	Himmat Singh Gill
Bathinda	Manpreet Badal (PPP) Support of Congress	Harsimrat Kaur Badal	Jasraj Singh Longia
Faridkot	Joginder Singh	Paramjit Kaur Gulshan	Prof. Sadhu Singh
Fatehgarh Sahib	Sadhu Singh Dharamkot	Kulwant Singh	Harinder Singh Khalsa

Ferozepur	Sunil Kumar Jakhar	Sher Singh Ghubaya	Satnam Paul Kamboj
Gurdaspur	Partap Singh Bajwa	Vinod Khanna	Sucha Singh
Hoshiarpur	Mohinder Singh Kaypee	Vijay Sampla	Yamini Gomar
Jalandhar	Santokh Singh Chaudhary	Pawan Kumar Tinu	Jyoti Mann
Khadoor Sahib	Harminder Gill	Ranjit Singh Brahampura	Baldeep Singh
Ludhiana	Ravneet Singh Bittu	Manpreet Singh Ayali	H.S. Phoolka
Patiala	Preneet Kaur	Deepinder Dhillon	Dharamvir Gandhi
Sangrur	Vijay Inder Singla	Sukhdev Singh Dhindsa	Bhagwant Mann

**Source:** [www.Punjabdata.com](http://www.Punjabdata.com), MP list 2014 candidates.

Different political parties started its election campaign by inviting its star campaigners in different election rallies. Narendra Modi addressed four rallies in Punjab for BJP. Besides Modi, Rajnath Singh, Preety Sapru, Sunny Deol, Hema Malini, Shatrughan Sinha, Akshay Khanna addressed BJP rallies for Vinod Khanna (BJP candidates from Gurdaspur) and Arun Jaitley (BJP candidate from Amritsar). Rahul Gandhi addressed two Congress rallies in Ludhiana and Bathinda, Captain Amrinder Singh addressed in Ferozepur Bathinda and Khandoor Sahib for Congress candidates. Sachin Pilot addressed a rally in Garshankar for Congress candidate<sup>11</sup>.

Scores of celebrities came out in support of BJP candidate Arun Jaitley. Shatrughan Sinha BJP MP, Vivek Oberoi, Kirron Kher, Poonam Dhillon, Preeti Sapru and Suniel Shetty and Manoj Tiwari campaigned for Jaitley. Cricketers Gautam Gambhir, Madan Lal and Chetan Chauhan also campaigned for Jaitley. Noted Santoor maestro Pandit Shiv Kumar Sharma, Yog guru Baba Ramdev, noted journalists Kuldeep Nayyar, Swapan Dasgupta and M. J. Akbar also canvassed for Jaitley in the city<sup>12</sup>.

During elections in Punjab in various constituencies, core issues took back seat. Both Congress and BJP have come down to personal vituperation and hardly fall short of calling names. Both Captain Amrinder Singh and Parkash Singh Badal kept criticizing each other and real issues were lost in their mutual rivalry. Amritsar and Bathinda seats were centre of allegations and counter allegation. Akali leader Bikram Singh Manjinder used indelicate words against BJP leader Arun Jaitley. In Bathinda it was a family war of Harsimrat Kaur Badal and Manpreet Singh Badal<sup>13</sup>.

Cuss words dominate Punjab's election. Alien, Liar, Feudal, Maverick, Mercenary, *goonda*, *chor* hypocrite and ruthless were the words used in political vocabulary. Punjab Revenue Minister Bikram Singh Majithia made the remark "*dhaun naap deyange*" (we will hold him by the neck) against Amarinder Singh. Former Chief Minister and Congress leader Rajinder kaur Bhattal called the Akali Dal candidate from Anandpur Sahib seat, Prem Singh Chandumajra a "*chor*" (thief) and "*daaku*" (dacoit). Captain Amrinder Singh called Mr. Arun Jaitley an "outsider" and an "alien"<sup>14</sup>.

The major issues that have emerged in this election were new taxes and high power tariff imposed by the cash-strapped state government; rising inflation due to poor policy planning by the central government; and the 'Caterlisation' of sand mining, liquor and transport business<sup>15</sup>. In

Amritsar both SAD and BJP have strong presence. Poor civil conditions, delayed and halted projects led to resentment. The seat became a victim of ego clash between Sidhu and the Badals. Bathinda seat became a war in the Badal family for claiming a political legacy. The region lacks good institute to treat cancer patients. Water in the region carried heavy metals. Known as cotton belt it faced crisis as many farmers and labourers committed suicide<sup>16</sup>. The closing of Hussainiwala joint check post for trade after the 1971 Indo Pak war proved to be the death knell for local residents, especially traders in Ferozepur, became a key factor in poll campaign<sup>17</sup>. In Khadoor Sahib, Congress candidate Harminder Singh Gill brought 'Drugs' as the key issue to the centre stage. Sand shortage and drug issue became main factors in Faridkot. Besides, Poor civil amenities, unemployment, poor rail and road connectivity and lack of infrastructure were other issues which became key factors during elections<sup>18</sup>. Both the BJP and AAP assured the farming community to fix Minimum Support Price (MSP) so as to ensure minimum 50 percent profit. With farm distress taking a toll in this region, ensuring a minimum profit margin has been a long standing demand of the farmers. The contribution of agriculture to the Punjab's gross state domestic product has fallen sharply and is only 18 percent<sup>19</sup>.

### **Punjab's Harvest of Intoxicants**

Even a casual observer of the election scene in Punjab understood how drugs had emerged as main source of election campaign. In constituency after constituency, candidates of ruling Akali Dal- BJP combine as well as the Congress were faced with the questions from angry people about what measures will be taken to arrest the problem that threatens the State's youth.

In the 2012 Assembly Elections, the Akali Dal-BJP alliance promised to eradicate the drug problem. Barely two years later, a drug lord who was arrested named cabinet minister Bikram Singh Majithia, the brother-in-law of deputy Chief Minister Sukhbir Badal, as the kingpin of flourishing drug racket. A retired Punjab police officer-turned-crusader against drugs, Shashi Kant Sharma, has on the directions of Punjab and Haryana High Court informed the Election Commission that there is a widespread use of drug money in elections. As against the 322 kilograms of heroin recovered from the Punjab border in 2013, more than 250 kilograms have been seized in the first four months of 2014, prompting the Ministry of Home Affairs and the EC to take note of the problem<sup>20</sup>.

In 2012, Jim Yardley, a reporter for New York Times, commented on the issue of drug abuse in Punjab, saying, "Throughout the border state of Punjab, whether in villages or cities, drugs have become a scourge. Opium is prevalent, refined as heroin or other illegal substances. He further wrote that even though around 60% of all illicit drugs confiscated in India were seized in Punjab, during the Punjab State elections of 2012, candidates rarely spoke about drug abuse, and that India's Election Commission indicated that some political workers were actually giving away drugs to buy votes<sup>21</sup>.

When Rahul Gandhi (Congress), quoting from a survey, said in 2012 that 70 percent of Punjab's youth are addicted to drug, the ruling combine had reacted with fury. All candidates across the state faced uncomfortable questions over the perceived involvement of political machinery in the distributing of drug. Bhagwant Mann (AAP candidate from Sangrur) has based his entire election

campaign on drugs. A brand of AAP youth organize street plays that show drugs being transported in the ruling party leaders' official vehicles<sup>22</sup>.

Bathinda is the worst affected district in Punjab when it comes to drug abuse. According to the data compiled by the department of health and family welfare, among all 22 districts, Bathinda, has the maximum number of drug addicts. The other worse-affected districts are Amritsar, Moga, Tarn Taran, Nawanshahr, Muktsar, Mansa and Ludhiana<sup>23</sup>.

### **Role of Election Commission**

Following the strict directions from Election Commission of India, Punjab State Election Commission took various pungent measures to conduct free and fair elections. During 16<sup>th</sup> Lok Sabha elections, EC launched a nationwide campaign Systematic Voter's Education and Electoral Participation (SVEEP) to lure young voters to use their right to vote. About 5 Lakh first-time voters were registered in Punjab. Irked with corruption, communalism and unemployment, the youth brigade came forward in Punjab with a vision for all round development. On January 25, National voters Day was celebrated at all polling booths where election identity cards were distributed to voters. For this purpose EC sought help from educational institutions. This year's State Award winner teacher Rajinder Pal Singh Brar, launched a campaign against the use of drugs and money in elections. The hoardings were titled: "stay alert, leaders are coming to seek votes; if you find none of the candidates worthwhile, press NOTA(None of the Above) on the machine; never vote for candidate who dares to influence you by distributing drugs or money<sup>24</sup>".

To increase voting percentage District Electoral Officer told all government employees across the state to vow on April 15 to vote in the Lok Sabha elections. A circular was sent to the heads of various departments. To ensure that no employee is left out of the pledge, returning of all signed documents to the district election office had been made compulsory. All educational institutions were issued instructions to take the pledge to vote<sup>25</sup>.

The EC also announced that any outsider or political official, who was not enrolled as a voter in particular a parliamentary constituency, cannot stay there on the day of polling, but the candidates contesting elections have been exempted from the order. Chief electoral officer VK Singh also announced a ban on organizing parties in homes, especially in which liquor and lavish food is served, on April 28 and 29, 48 hours before the polling. The EC also decided that all 22,022 polling booths be covered by either micro-observer, webcasting, Videography or with presence of Paramilitary forces<sup>26</sup>.

It arranged 22,060 polling stations and 24,300 Electronic Voting Machines(EVMs) for smooth and fair elections<sup>27</sup>. The EC banned advertisement of political nature on any building or space owned by the government or public sector bodies even if space had been rented out to private contractors<sup>28</sup>. EC also launched a unique Short Messaging Service (SMS) 'Voter queue Information Service', to inform voters about the queue status and this was aimed to check the trend of lack of interest for voting and ensure that people voted<sup>29</sup>. EC deputed 40 observers in the state and 18 expenditure observers. For a fair poll, all the observers were from Central Services such as the Indian Revenue Service(IRS), the Indian Police Service(IPS) and the Indian Administration Service(IAS)<sup>30</sup>. V.K. Singh Chief Election Officer (CEO) ordered transfer of

three officers on complaints filled by different parties which included two officers from PUDA and Mandi Board and one excise officer<sup>31</sup>.

It is well known that the police and civil administration in Punjab is deeply politicized. Officers are handpicked by ruling politicians for key posts, particularly of Chief Secretary, DGP, DC and SSP. Barring some, officers court politicians for favours and do their bidding in the hope of getting remunerative postings, protection from punitive action and post retirement assignments. EC took a tough stance and transferred nearly half a dozen senior officers following complaints that they had sided with the ruling Akali Dal-BJP. Punjab government forwarded a panel of three IPA officers to the Election Commission for consideration to be posted as the State Police Chief as Punjab Director-General Police Sumedh Singh Saini proceeded on leave. Congress had made persistent demands for his removal. So that elections could be held in free and fair manner<sup>32</sup>.

The Election Commission served notice to SAD-BJP candidate Deepinder Singh Dhillon as he claimed to be the DPC (District Planning Committee) chairman on his Facebook page even though he had resigned. EC also issued notice to Congress candidate Preneet Kaur and District Congress Committee President P K Puri for distributing an eight-page booklet to promote Preneet Kaur without taking the EC's permission<sup>33</sup>.

The Election Commission restricted the movement of Punjab Revenue Minister Bikram Singh Majithia to his polling station area in Majithia Assembly constituency till the campaign period was over<sup>34</sup>. The EC served a notice on Punjab CM Parkash Singh Badal for having admitted that crores were spend in electioneering. Addressing a meeting on April 12 at Jalandhar he said: 'Crores are spent on campaigning, though we show less in expenditure detail. Give quietly, don't give openly'. The EC notice cities Rule 90 of the conduct of Election Rules, 1961, which prescribes the maximum limit of expenditure. The EC has warned that the expenditure in contravention of the rules is a corrupt practice which is a ground for setting aside the election of the returned candidates<sup>35</sup>. The commission reminded CM of section 77 of the Representation of the people Act, 1951 which prescribes that every candidate shall keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him<sup>36</sup>. For all these efforts, CEO Punjab VK Singh deserves appreciation.

## Polling

The state went to poll on 30 April, 2014 (7th phase of elections). Punjab recorded 70.89% polling, second after West Bangal's 81.35%. In 1999 Lok Sabha elections this voting percentage was 56.11%, in 2004 it was 61.59%, in 2009 it reached 70.04% and now 70.89%. Till now the highest-ever Lok Sabha polling recorded in Punjab was 71.13% in 1967. In terms of percentage, more women voted in the Lok Sabha polls in Punjab. While 70.7% male voters exercised their right to vote, among women it was 71.1%. There were less female voters as compared to male voters in the state. Out of six women candidates, only one woman could win the election<sup>37</sup>.

**Table : Poll Percentage Constituency Wise**

Constituency	2014	2009
Gurdaspur	70.22%	71%
Amritsar	68.51%	66%
Khadoor Sahib	68%	71%



Jalandhar (R)	67.25%	67%
Hoshiapur (R)	65.29%	65%
Anandpur Sahib	70%	68%
Ludhiana	70.27%	65%
Fatehgarh Sahib (R)	74.05%	69%
Faridkot (R)	71.44%	72%
Ferozepur	72.79%	71%
Bathinda	77.44%	79%
Sangrur	77.48%	74%
Patiala	71.21%	70%

**Source:** Hindustan Times, 2 May 2014, P. 4, Jalandhar

The lowest turnout was recorded in Hoshiarpur (65.29) followed by Jalandhar and Khadoor Sahib (67.5% & 68). Punjab's chief electoral officer VK Singh said that polling was by and large peaceful. As compared to 44 cases of violence where FIRs were registered in 2012 Punjab Assembly elections there had been very few incidents this time. Aam Aadmi Party's Patiala candidate Dr. Dharamvir Gandhi was punched in the face, slapped repeatedly and abuse by a group of men led by local councilor Rajinder Virk at Rasoolpur village in the Patiala (rural) assembly segment. Besides there were reports of clashes between SAD and Congress workers at different places<sup>38</sup>.

More than 90 percent soldiers registered as voters exercised their right to vote. This large turnout was the outcome of the Supreme Court directions to the electoral authorities to ensure that serving armed forces personnel and their families were registered as general voters. All senior officers at the corps Headquarters were nominated to oversee polling by soldiers. Punjab has a huge population of serving armed forces personnel. Besides 10 corps at Bathinda and 11 corps at Jalandhar, 1 Armoured Division at Patiala, 7 Infantry Division at Ferozpur, 15 Infantry Division at Pathankot, numerous other formation and unit are based in the state. Punjab also has four major Air Force station at Halwara, Bathinda, Adampur and Pathankot<sup>39</sup>.

### People's Verdict and AAP Surge in Punjab

In exit poll predictions News 24, declared 5 seats for SAD-BJP, 3 for Congress and 5 for AAP ABP News Exit Poll declared 5 seats for SAD-BJP, 7 for Congress and 1 for AAP. But the actual results declared were quite different<sup>40</sup>. Defying the 'Modi Wave' Punjab emerged as the saving grace for Arvid Kejriwal's Aam Aadmi party (AAP) in the 2014 Lok Sabha elections. It is the best performance ever by any non-Congress and non-SAD-BJP entity in Punjab. It firmly established the AAP as a formidable third force in the historically bipolar politics of Punjab. The rookie party, whose candidates were relative greenhorns to Punjab's brutal power politics cut both ways. It came as a bolt from the blue for SAD/BJP and Congress. Though together with ally BJP, which contested three seats, the SAD secured 35% of vote share. In the seat tally AAP was on par with the SAD-four each. As for the Congress despite 33% vote share it was pushed to the third slot and a tally of just three. In 2009, Congress vote share was 45.23% with 8 seats<sup>41</sup>.

**Table : Punjab Lok Sabha Poll Results 2009 to 2014**

2009



Party	Vote share	Seats
Congress	45.23	8
SAD	33.85	4
BJP	10.06	1

Source: The Tribune, 27 April 2014, P.11, Jalandhar.

#### 2014

Party	Vote share	Seats
Congress	33.1%	3
SAD	26.3%	4
BJP	8.7%	2
AAP	24.4%	4

Source : Hindustan Times, 17 May 2014, P.2, Jalandhar.

Congress Veteran Capital Amrinder Singh from Amritsar with assets worth Rs 86.35 crore emerged as the richest winner from Punjab. 13,582 was the lowest winning margin in Punjab for BJP's Vijay Sampla against Congress' Mohinder Singh Kaypee in Hoshiarpur. The highest victory margin was secured by its Sangrur Candidate, Bhagwant Mann, who won more than 2 Lakh votes. His victory with 49% votes was highest in the state. Punjab is the only state where AAP made a dream debut, while drawing blank elsewhere in the country. AAP won four seats from Sangrur, Faridkot, Fatehgarh Sahib and Patiala. It stood second in Ludhiana and third in 8 constituencies of Punjab. Four Congress Stalwarts were swept away by the AAP's 'broom' as it pocketed over a Lakh votes against Punjab Congress Chief Partap Singh Bajwa (Gurdaspur), leader of opposition in the assembly, Sunil Jakhar (Ferozepur), former Union Minister Ambikar Soni from Anandpur Sahib and Congress working Committee (CWC) member Mohinder Singh Kaypee. In Jalandhar, AAP's virtually unknown candidate Jyoti Maan got over, 2 Lakh votes, which contributed to the SAD's Pawan Kumar Tinu losing to Congress' Santokh Singh. Jyoti Mann and Yamini Gomar candidates from (Jalandhar and Hoshiarpur) even cut into the vote bank of the BSP in two reserved constituencies in Doaba region<sup>42</sup>. About 58,754 voters pressed NOTA button to express their anger<sup>43</sup>.

**Table : Punjab Parliamentary Election Results**

Constituency	Winning Candidate	Winning Party	Votes of Winner
Gurdaspur	Vinod Khanna	BJP	482114
Amritsar	Amrinder Singh	Congress	482876
Khadoor Sahib	Ranjeet Brahmampura	SAD	467332
Jalandhar	Santokh Chowdhry	Congress	380467
Hoshiarpur	Vijay Sampla	BJP	346643
Anandpur Sahib	Prem Chandu Majra	SAD	347394
Ludhiana	Ravneet Bitu	Congress	300459
Fatehgarh Sahib	Harinder Singh	AAP	367293
Faridkot	Prof. Sadhu Singh	AAP	450752
Ferozpur	Sher Singh Gubaya	SAD	487932

Bathinda	Harsimrat Kaur Badal	SAD	514727
Sansarpur	Bhagwant Mann	AAP	533237
Patiala	Dharamveer Gandhi	AAP	365671

**Source:** Dainik Saveria, 17 May 2014, P.1, Jalandhar and Verdict 2014, Hindustan Times, 17 May 2014, P.2, Jalandhar.

The Pan-India Modi magic failed to click in Punjab, as the Bharatiya Janta Party's Arjun Jaitley suffered a humiliating defeat at the hands of capital Amrinder Singh. The Amritsar triumph has dramatically resurrected Amrinder Singh's political fortunes that had hit the nadir after the Congress under his leadership, had suffered a stunning successive defeat in the 2012 Assembly polls. Despite having carved a niche for herself as the Shiromani Akali Dal (SAD) flag bearer in the Lok Sabha, Harsimrat Kaur Badal barely managed to retain her seat by a margin of 19,939 votes. While the SAD nominee polled 5.14 Lakh votes, the Congress candidate bagged 4.94 Lakh votes and AAP clearly ruined the chances of Congress by bagging 87,600 votes<sup>44</sup>. Apparently had it been the direct contest, Manpreet Badal could have caused huge embarrassment to the deputy CM Sukhbir Singh Badal. Three factors worked to the captain's advantage. First, the Sikh card as Jaitley was pitched against the electoral history of Amritsar which with 63% Sikh population has mostly swung in favour of the Sikh face. His protest resignation against the army operation struck a chord with the Sikh population. The second factor was a groundswell of anti-incumbency ire against the seven-year ruling of SAD. Third, Majithia scored the worst self-goal in the last leg of the campaign by distorting a hymn of Guru Granth Sahib while projecting Jaitley's victory as a foregone conclusion<sup>45</sup>.

Aam Aadmi Party (AAP) opened its account in Lok Sabha by winning four of the 13 seats. The rookie AAP burst into the state's political scene as a formidable third force with 25% vote share, damaging both the Congress and the SAD-BJP alliance. Comedian-turned-political Bhagwant Singh Mann, led the AAP surge by defeating Akali Stalwart Sukhdev Singh Dhindsa and sitting Congress MP Vijay Inder Singla in Sangrur.

### **Poll analysis: Some concluding observations**

- The emergence of AAP has made the electoral battle so complex that it became difficult to prejudge the outcome.
- Aam Aadmi Party played a major role in ensuring defeat of Congress on most seats by eating into its vote bank.
- PPCC President Partap Singh Bajwa was confined to his constituency, Gurdaspur, and was unable to campaign for party candidates.
- The Bathinda verdict is a clear indication of palpable anti-incumbency and anger of electorate against the ruling family (Badals).
- The verdict given by Punjab's voters is a wake-up call for deputy Chief Minister Sukhbir Singh Badal, who is the SAD Chief and a brutal blow to the prestige of ageing Chief minister Parkash Singh Badal.
- Despite having won four seats- Bathinda, Ferozepur, Anandpur Sahib and Khadoor Sahib-on its own and two going to ally BJP, it will take more than the customary huddle for the SAD to put things back on track.

- Widespread drug menace in Punjab had virtually turned the voters against the Panthic party. Sand and liquor mafia spreading its wing in the state under the patronage of some Akali leaders had not gone down well with the voters.
- The senior leadership's arrogance and overconfidence of winning the elections by poll management of Akali Dal cost the party dearly.
- Poor governance of Public service delivery system and strong anti incumbency were another factors responsible for low performance of SAD.
- A democracy should not merely be a five yearly ritual of voting, but a continuous process of national deliberation.

Punjab has been slipping in the ranking of Indian States in the last few decades. The growth rate of Punjab has suffered over the years and per capita income of Punjab is no more the highest in the country. The per capita income of Kerala, Gujarat, Maharashtra, Haryana, Himachal Pradesh, Sikkim, Tamil Nadu and Uttarakhand exceeds that of Punjab<sup>46</sup>.

Agriculture accounts for nearly one fourth of the gross state domestic product (GSDP) in Punjab which is in sharp contrast to that of Gujarat, Tamil Nadu, Maharashtra, Sikkim, Kerala, Uttarakhand where agriculture account for less than 10 per cent of GSDP. In Haryana the service sector is nearly four times that of agriculture, while in Punjab it is just about two times. The fiscal position of Punjab continues to deteriorate. The gross fiscal deficit of Punjab is higher than that of other states. This is also reflected in the higher debt-to-state GDP ratio and higher interest payment as compared to other states in India<sup>47</sup>.

The formation of the new Parliament has given new hopes. People expect a lot from their leaders and representatives. Hope our elected representatives will raise crucial issues of Punjab in the Parliament. The state has lost its lead position in per capita income. The recruitments in various government departments remain suspended. Punjab has been left behind in education sector. A large section of population remains uneducated in rural areas. The Punjab health infrastructure is strongly underutilized for want of availability of doctors and paramedical staff. Farmers and labourers felt alienated and this led many to commit suicide. A large number of young people are leaving Punjab. Another section of youth is falling prey to drug addiction. A matured and experienced leadership can ensure good governance and help regain glory of the Punjab. Let's hope for that.

### References:

1. Official website of Punjab Government, <http://Punjabgovt.nic.in> accessed on 12 November 2014.
2. Rattan Singh Jaggi, Sikh Panth Vishavkosh, Part II, Guru Rattan Publishers, PP.972, 1418, 1424. 1982.
3. The Tribune, 27 April 2014, P.11, Jalandhar.
4. The Tribune, 19 April 2014, P.9, Jalandhar.
5. [www.mapsofindia.com/parliamentaryconstituencies/punjab](http://www.mapsofindia.com/parliamentaryconstituencies/punjab) accessed on 17 November 2014.
6. The Tribune, 27 April, op.cit.
7. The Tribune, 6 March 2014, P.2, Jalandhar.

8. The Tribune, 13 April 2014, P. 3, Jalandhar.
9. The Tribune, 17 April 2014, PP. 12-13, Jalandhar.
10. The Hindu, 25 April 2014, P.9, Mohali.
11. Dainik Bhaskar, 19 April 2014, P.6, Jalandhar.
12. The Tribune, 28 April 2014, P.3, Jalandhar.
13. Ajit, 1 April 2014, P.5, Jalandhar.
14. The Hindu, 15 April 2014, P.3, Mohali.
15. The Tribune, 27 April, op.cit.
16. Hindustan Times, 20 April 2014, P.2.
17. Hindustan Times, 23 April 2014, P.2, Jalandhar.
18. Hindustan Times, 19 April 2014, P.2, Jalandhar.
19. The Tribune 8 April 2014, P.8, Jalandhar.
20. Chander Suta Dogra, "Punjab's Harvest of Intoxicants", The Tribune, 29 April 2014, P.7.
21. Manjit S. Kang, "Elections Lack Substantive Agenda". The Tribune, 4 April 2014, P.11, Jalandhar.
22. Chander Suta Dogra, op.cit.
23. Vishav Bharti, "Drug Abuse: Bathinda Worst Hit", Hindustan Times, 27 November 2014, P.4, Jalandhar.
24. The Tribune, 9 April 2014, P.7, Jalandhar.
25. The Tribune, 14 April 2014, P.2, Jalandhar.
26. Hindustan Times, 24 April 2014, P.4, Jalandhar.
27. Ajit, 26 April 2014, P.5, Jalandhar.
28. The Tribune, 14 April, op.cit.
29. Ibid.
30. The Tribune, 8 April, op.cit.
31. The Ajit, 26 April, op.cit.
32. The Hindu, April 4, 2014, P.2, Mohali.
33. The Tribune, 1 April 2014, P.4, Jalandhar.
34. The Hindu, 29 April 2014, P.3, Mohali.
35. The Tribune, 1 May 2014, P.1, Jalandhar.
36. [www.ndty.com](http://www.ndty.com), 14 May 2014, 2.41 IST, Accessed on 15 November 2014.
37. Hindustan Times, 2 May 2014, P.4, Jalandhar.
38. Ibid.
39. The Tribune, 1 May 2014, P. 3, Jalandhar.
40. Hindustan Times, 17 May 2014, P.2, Jalandhar.
41. Ibid.
42. Ibid.
43. Ibid, P.4.
44. Ibid.
45. Ibid.
46. Charan Singh, "Deteriorating Growth in Punjab". The Tribune, 3 May 2014, P.10.

## महिला सशक्तिकरण : गांधी जी के विचार

डॉ० राजीव कुमार  
एसोसिएट प्रोफेसर  
राजनीति विज्ञान विभाग  
आर०एस०एस० (पी०जी०) कॉलेज, पिलखुवा

समकालीन समय में महिला सशक्तिकरण समाज विज्ञानों में विमर्श का ज्वलंत मुद्दा एवं अकादमिक बहसों का केन्द्रीय बिन्दू है। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तब हमें गाँधी जी के दृष्टिकोण की गम्भीरता से पड़ताल करनी होगी जिन्होंने न सिर्फ भारतीय नारी बल्कि सम्पूर्ण नारी जाति को नई प्रतिष्ठा दी और समाज तथा राजनीति में नये सिरे से प्रतिष्ठित किया। यद्यपि उनके पूर्व भी स्त्रियों के उत्थान की दिशा में प्रयास हो रहे थे। भारतीय नारी जागरण के इतिहास में गाँधी युग स्वर्ण युग है। उन्होंने नारी में छिपी महती मातृशक्ति के दर्शन किये, उन्होंने देखा कि नारी त्याग की प्रतिमा है, उसके स्वभाव में ही दान है, प्रेम है, अहिंसा है।<sup>1</sup> इसलिए अहिंसात्मक जागरण की दिशा में कोई वास्तविक कार्य कर सकना तब तक संभव नहीं, जब तक सुसुप्त नारी शक्ति को उसकी पूर्ण गरिमा तक जागृत न कर दिया जाय। गाँधी जी ने भारतीय नारी के अन्दर छिपी त्याग वृत्ति और इसकी महती दान परम्परा को गृह की चारदीवारी के बाहर निकाला और समाज तथा देश के व्यापक हितों में उसका विनियोग किया। उपरोक्त संदर्भ में इस शोधपत्र में गाँधी जी के दृष्टिकोण का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

नारी सशक्तिकरण के संदर्भ में गाँधी का दृष्टिकोण व्यापक है। उन्होंने नारी को जागृत किया और सभी प्रकार के बलात् आरोपित बंधनों से उसे बाहर निकालने का महती प्रयास किया। सभी प्रकार की कुरीतियों एवं भय वर्जनाओं के बीच उसे आश्वस्त किया, उसे बन्दिनी से विद्रोहिणी बनाया एवं वहीं उन्होंने उसकी मर्यादा भी स्थापित की। उन्होंने उससे एक ही आश्वासन की मांग की कि वह अपने को निम्न भोग-वृत्तियों की पुतली न बनने देगी, वह वासनाओं की झंझा में अपनी आत्मा का दीपक बुझने न देगी, क्योंकि इसी भोग वृत्ति से उसकी दासता की शृंखला का निर्माण होता है।<sup>2</sup> गाँधी जी ने उसे पुकार कर कहा— तुम पुरुष की क्रीड़ा और भोग-लालसा का अस्त्र बन कर नहीं जियोगी, तुम उसे धर्म और नीति के गौरव शिखर की ओर ले जाने वाली जीवन संगिनी और पथ प्रदर्शक बनोगी।<sup>3</sup>

गाँधी जी ने सार्वजनिक जीवन में, गृह जीवन में, समाज जीवन में सर्वत्र नारी को मुक्ति की दीक्षा दी है। वह दासी नहीं है, स्वाभिमानी है, वह दिल बहलाव की वस्तु नहीं, जीवन की निरन्तर साधना में प्रेम और साहचर्य की दीप-शिखा है, पुरुष के मुक्त विलास पर संयम का प्रतिबन्ध है।<sup>4</sup> उसके जीवन का गहरा तात्पर्य है— अधोवृत्तियों के शमशान नर्तन में करुणा का समाहार है। इस प्रकार स्पष्ट है कि गाँधी जी के चिंतन में नारी को उसके पूर्ण गौरव तक उठाया गया है।

वास्तव में गाँधी जी की नारी पुरुष का बंधन नहीं, मुक्ति है। कन्या के रूप में, भगिनी के रूप में, पत्नी के रूप में एवं माता के रूप में सर्वत्र उसका एक ही नियुक्त कार्य है पुरुष की सद्वृत्तियों को जागृत करना। उसे निरन्तर धर्म पथ पर, संस्कार के मार्ग पर ले चलना, उपदेश से नहीं, प्रेममय थपकियां देते हुए सेवा और त्याग के द्वारा। इसीलिए जहाँ उन्होंने नारी को जगाया और उसे निर्बन्ध किया वही उसे पाश्चात्य सभ्यता की भोगवृत्ति की ओर जाने से रोका भी।<sup>5</sup> अनेक विदुषी नारियों को उन्होंने भारतीय परिवेश में रंगने में सफलता हासिल की। उनकी आदर्श नारी आज श्रृंगार विलास में बह रही, प्रत्येक दिशा में विद्रोहिणी, किसी भी नियम बंधन या संयम को न मानने वाली नारी नहीं है, वरन् वह गृह को सम्भालने वाली, बच्चों का निर्माण करने वाली, दाम्पत्य में स्नेह को सिंचित करने वाली, समाज के हित के लिए निजी हितों एवं स्वार्थों का त्याग करने वाली है।

गाँधी जी ने नारी जीवन की विविध समस्याओं का गहरा अध्ययन और चिंतन किया है। विवाह सम्बन्धी समस्याओं पर भी उन्होंने खूब प्रकाश डाला है। विवाहित जीवन में पति-पत्नी के बीच उठने वाले कितने ही प्रश्नों का सुलझाव उनकी रचनाओं में मिलता है। पुरुष नारी पर जो अन्याय करता है, उन सबका वे घोर विरोध करते हैं, परन्तु नारी से भी यह कहते हैं कि कोरे विरोध से कुछ न होगा, जब तक नारी में स्वयं अपने गौरव का बोध नहीं आयेगा, तब तक उनकी कृत्रिम विवशता बनी रहेगी।<sup>6</sup> जब तक वह गहनों, कपड़ों में पुरुष द्वारा प्रदत्त श्रृंगार बहुल सामग्रियों की लालसा में लिपटी रहेगी, उसका शोषण होता ही रहेगा।

गांधी जी का यह भी मानना था कि जब तक वह अपने शरीर के आकर्षण का प्रयोग पुरुष को आकर्षित करने में करती रहेगी, तब तक वह प्रमुखतः भोग्य बनी रहेगी। जब वह शरीर एवं मत की प्रेम-वृत्तियों का प्रयोग पुरुष के एवं अपने सह-जीवन को उच्च संस्कारों से प्रेरित एवं पूरित करने के लिए करेगी, तब वह समाज जीवन के उच्चादर्शों से अनुप्राणित हो उठेगी और मानव की अन्तर्निहित आध्यात्मिक प्रेरणाओं का उद्घाटन करेगी तभी वह अपने एवं पुरुष दोनों के जीवन को सार्थक करेगी।<sup>7</sup> कुल मिलाकर गाँधी जी नारी को समस्त कुरीतियों और अनिष्ट परम्पराओं के बंधन से मुक्त कर उसे उच्च आदर्शों की ओर प्रेरित करते हैं। वह उसे परम्पराओं की अनुगामिनी नहीं बनाना चाहते, यद्यपि उसे पुरातन उच्चादर्शों एवं परम्पराओं से विरहित देखने को भी तैयार नहीं है।

जहाँ तक विवाह का सम्बन्ध है, गाँधी जी उसे आवश्यक नहीं मानते थे।<sup>8</sup> किन्तु जिन स्त्री-पुरुषों का अपनी कामनाओं पर नियन्त्रण नहीं है, उन्हें अन्दर-अन्दर घुटते रहने की अपेक्षा, वह विवाह की छूट देते हैं। उनके लिए विवाह, धर्म एवं श्रेय के मार्ग पर चलने वाले स्त्री-पुरुष का समाहार है। वे दुःख, सुख में एक-दूसरे को धर्म के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए साहचर्य की शपथ लेते हैं और इस जीवन तथा पारलौकिक जीवन के लिए भी एक दूसरे से सम्बद्ध होते हैं। विवाह शरीर के माध्यम से दो आत्माओं का मिलन है।



नारी सशक्तिकरण के नाम पर आजकल विवाह को स्वच्छन्द प्रेम की परिणिति के रूप में स्वीकार करने का चलन है। बल्कि 'बेलेन्टाइन डे' आदि के नाम पर विवाह के पूर्व की स्वच्छन्दता का चलन हो गया है। आज वहाँ नई पीढ़ी प्रणय को ही विवाह का मुख्य कारण मानती है। वह पारस्परिक आकर्षण और प्रेम को प्रथम स्थान देती है वहीं गाँधी उसे अन्तिम छोर पर रखते हैं। वह आध्यात्मिक उन्नति को प्रथम स्थान पर रखते हैं, इसके बाद समाज और देश सेवा, फिर कौटुम्बिक और व्यावहारिक सुविधा। इसका अर्थ यह हुआ कि जहाँ इन तीन शर्तों का अभाव हो, वहाँ पारस्परिक प्रेम को स्थान नहीं मिल सकता। अगर प्रेम को प्रथम स्थान दिया जाय, तो वह सर्वोपरि बन कर दूसरों की अवमानना कर सकता है, और करता है।<sup>9</sup>

गाँधी जी ने सत्याग्रह और अन्य अहिंसक आन्दोलनों के माध्यम से स्त्री-शक्ति को घर से बाहर निकाला, जिससे सैकड़ों वर्षों बाद उनको एक नई पहचान मिली आत्म सम्मान और आत्म बल मिला। भारत में नारी जागरण में योग देने वाला कोई भी घटक इतना शक्तिशाली नहीं हो सका, जितना भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व के विरुद्ध छिड़े 'स्वतन्त्रता संग्राम' में गाँधी जी द्वारा स्त्रियों की सहभागिता को प्रेरित किया गया। इस सहभागिता से सैकड़ों हजारों स्त्रियों को अपनी चारदीवारियों में घिरे घरों से निकालकर अग्नि परीक्षा के सामने निर्भीकता पूर्वक खड़ा कर दिया। इसने इस तथ्य को पूर्णतः सिद्ध कर दिया कि स्त्रियाँ बुराई या आक्रमण का सामना करने में पुरुष से किसी तरह पीछे नहीं हैं।<sup>10</sup>

महिला को सबल और शक्तिमान बनाने के लिए गाँधी जी ने स्त्री-शिक्षा पर विशेष बल दिया है। उनका कहना है कि भारतीय पुरुषों ने भारतीय स्त्रियों को बहुत पिछड़ा हुआ रखा है। वे कहते हैं कि बालाओं! आपके सीखने के लिए तो बहुत है। सुई और कतरनी का प्रयोग आपका काम है। घर को साफ, स्वच्छ किस प्रकार रखा जाय, यह आपको जानना है, घर की साज-सज्जा ठीक होगी तो उसकी बात बाहर फैलेगी और घर के समान ही गाँव भी बन जायेगा। पैसे का क्या उपयोग किया जाये यह भी आपको सीखना है। आप एक दिन माता बनेंगी, आप पर बच्चों की जिम्मेदारी होगी। केवल पढ़ना, लिखना भर सीख लेना आपके लिए पर्याप्त नहीं है। अपने मन का संस्कार जरूरी है, क्योंकि बच्चों की सच्ची शिक्षा देने वाली तो उनकी माता ही होती है।<sup>11</sup> इस प्रकार कहा जा सकता है कि उनकी दृष्टि में सही मायने में यही महिला सशक्तिकरण है।

गाँधी जी का स्पष्ट मत था कि बिना महिला भागीदारी के हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उनका कहना था कि हमने अपनी स्त्रियों को अपने आन्दोलन से अलग रखा, इससे हम पक्षाघात के शिकार हो गये। जनता एक पाँव से चल रही है। यही कारण है कि उसके सारे कार्य अधूरे और आधे होते देखे जाते हैं।<sup>12</sup> इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि सभी आन्दोलनों में, घर में, समाज में, उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाय।

गाँधी जी का मानना था कि पुरुष अपेक्षाकृत अविचारी, उतावला और सदैव नवीनता की खोज में लगा रहने वाला होता है। स्त्री गम्भीर, धैर्यवान और अधिकतर पुरानी वस्तुओं से चिपककर रहने वाली होती

है।<sup>13</sup> उनका कहना था कि स्त्रियों में नवीन भावनाओं के सृजन की तथा उनको व्यवहार में लाने की जो शक्ति विद्यमान है, वह पुरुषों में नहीं है।<sup>14</sup> उनका कहना था कि स्त्री और पुरुष का दर्जा समान है, पर वे एक नहीं हैं। वह ऐसी अनुपम जोड़ी हैं, जिसमें प्रत्येक दूसरे का पूरक है। वे एक दूसरे के लिए आश्रय रूप हैं। यहाँ तक कि एक के बिना दूसरे की हस्ती की कल्पना नहीं की जा सकती। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिस बात से एक का भी दर्जा घटेगा, दोनों की बराबर बर्बादी होगी।<sup>15</sup> उनका कहना था कि स्त्री और पुरुष में चरित्र की दृष्टि से स्त्री का आसन अधिक ऊँचा है, क्योंकि आज भी वह त्याग, मूक तपस्या, नम्रता, श्रद्धा और ज्ञान की मूर्ति है।<sup>16</sup> इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब नारी शक्ति की बात की जाती है तब हमें केवल महिलाओं के अधिकारों पर ही बल नहीं देना है, बल्कि कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करनी है, जिससे महिला और पुरुष दोनों आपस में सहयोग करते हुए शक्तिशाली बनें और सुन्दर समाज की रचना में सहभागी हों।

न सिर्फ सुन्दर परिवार और समाज की रचना बल्कि अपने राजनीतिक आन्दोलन की दृष्टि से भी महिलाओं को वे महत्वपूर्ण मानते थे, और उनकी शक्ति को पहचानते थे। उनका मानना था कि स्त्रियाँ स्वभाव से ही बहुत सहनशील होती हैं। यही कारण है कि उनके लिए अहिंसा बहुत सुगम हो जाती है।<sup>17</sup> वे कहते हैं मेरी आशा स्त्रियों पर लगी है। मैं हमेशा कहता आया हूँ कि वे अहिंसा और आत्म त्याग की जीती जागती मूर्ति हैं। त्याग के बिना अहिंसा कभी सत्य रूप में सफल नहीं हो सकती।<sup>18</sup>

इसी तारतम्य में स्त्रियों के राजनीति में भाग लेने के सम्बन्ध में गाँधी जी कहते हैं कि आजकल बहुत कम स्त्रियाँ राजनीति में भाग लेती हैं, और जो भाग लेती भी हैं, उनमें अधिकांश स्वतंत्र विचार नहीं रखतीं। जैसा माता-पिता या पति कहते हैं, वैसा ही वे करती हैं। फिर पराधीनता महसूस कर वे स्त्रियाँ खास अधिकारों की मांग करती हैं। वे कहते हैं कि यदि तमाम स्त्रियों के नाम मतदाताओं की सूची में दर्ज करा दें, उनको व्यावहारिक शिक्षा दिला दें या दिलाएं, उन्हें स्वतन्त्र रीति से विचार करना सिखायें, उन्हें जात-पात की जंजीरों से छुड़ाएं और ऐसी हालत पैदा कर दें, जिससे पुरुष ही उनकी शक्ति और त्याग को पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाए। यदि कार्यकर्त्रियां इतना करें तो वे आज के गंदे वातावरण को शुद्ध कर देगी<sup>19</sup> और तभी उनकी शक्ति को पहचान मिल सकेगी। उनका कहना था कि जो स्त्री मृत्यु से नहीं डरती, उसकी बेइज्जती करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता।<sup>20</sup> वे कहते हैं कि मैं औरतों और मर्दों में कोई भेद नहीं करता, औरतों को भी मर्दों की तरह आजादी महसूस करनी चाहिए। बहादुरी मर्दों की बपौती नहीं है। अपनी हिफाजत अपने आप करने की कला किसी बाहरी मदद की गरज नहीं रखती।<sup>21</sup> इसके लिए उन्हें हर प्रकार का डर मन से निकाल देना चाहिए। आधुनिक युग में जुड़ो-कराटे का प्रशिक्षण स्त्री सुरक्षा हेतु इस प्रकार का एक उपचार है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि महिला सशक्तिकरण की आधुनिक व्याख्या गाँधी जी ने प्रस्तुत की। इस सम्बन्ध में उनके विचारों से कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।

- 1— महिला और पुरुष दोनों में कोई प्रतिद्वन्द्विता नहीं हो सकती, ऐसा होने पर दोनों का नुकसान होगा। आपस में प्रेमकार और सहयोग से ही नारी शक्तिवान होगी।
- 2— महिला की स्वाभाविक प्रकृति यथा सरलता, कोमलता, क्षमा, शीलता आदि ही उसे शक्तिमान बनाती है। इस स्वाभाविक प्रकृति को छोड़ना उसके लिए अहितकर है।
- 3— महिला का बाहरी आवरण, ढकोसलों और दिखावे पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि एक व्यक्तित्व के रूप में अपने को स्थापित करना चाहिए।
- 4— नारी को यह बात मन से निकाल देनी चाहिए कि सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए उसे किसी आश्रय की जरूरत है। वह उसी प्रकार पूर्ण है जैसे पुरुष। लेकिन सम्पूर्णता दोनों को मिलाकर ही होती है।
- 5— उसको पश्चिम के चकाचौंध से बचना होगा। भारतीय पर्यावरण, वातावरण में ऐसे सभी तत्व मौजूद हैं, जो नारी को देवी रूपी शक्ति बनाने के लिए पर्याप्त है।

### संदर्भ सूची

1. सुमन, श्री रामनाथ, समाज सुधार : समस्याएँ और समाधान (गाँधी जी), गाँधी साहित्य प्रकाशन, इलाहाबाद, 1969, पृष्ठ 15.
2. वही, पृष्ठ 15
3. वही, पृष्ठ 15
4. वही, पृष्ठ 15
5. वही, पृष्ठ 16.
6. वही, पृष्ठ 16
7. वही, पृष्ठ 16
8. वही, पृष्ठ 19.
9. हरिजन सेवक, 15.5.1937.
10. कृपलानी, सुचेता का लेख 'नारियों के नेता और शिक्षक', महात्मा गाँधी 100 वर्ष, सर्वोदय साहित्य प्रकाशन, वाराणसी, 1969.
11. इण्डियन ओपीनियन (गुजराती), 19.1.1907 में उद्धृत.
12. वही, 3.11.1917, गोधरा में प्रथम गुजरात राजनीतिक परिषद में अध्यक्ष पद से दिये गये भाषण से उद्धृत.
13. सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय, भारत सरकार का प्रकाशन, भाग-14, अगस्त 1965 संस्करण, पृष्ठ 85.
14. वही, पृष्ठ 85
15. महात्मा गाँधी विचार सृष्टि से, बम्बई भगिनी समाज में दिये गये भाषण का अंश, 20.2.1918, सुमन, श्रीरामनाथ, वही में उद्धृत, पृष्ठ 98.
16. यंग इण्डिया, 15.9.1921.
17. हरिजन सेवक, 5.5.1946.



- 
18. वही, 23.3.1947.
  19. वही, 21.8.1946.
  20. हरिजन, 3.11.1946.
  21. हरिजन सेवक, 12.1.1947.

## पंचायतराज व्यवस्थेमधील महिलांची स्थिती : एक आढावा

प्रा.डॉ. राजेंद्र सदाशिव मुद्दमवार  
राज्यशास्त्र विभागप्रमुख  
श्रीशिवाजी कला, वाणिज्य व विज्ञान  
महाविद्यालय, राजुरा, जि. चंद्रपूर  
rajmuddamwar@rediffmail.com

### प्रास्ताविक :

जगातील सर्वच देशात सर्वच समाजात लिंगभेदावर आधारीत स्त्री-पुरुष विषमतेची समाज रचना आढळून येते. भारतात स्त्री अजूनही पुरुषांच्या दायित्वातून सुटलेले नाही. कारण भारत हा खेड्यांचा देश असून त्यात जुनाट, पुराण्या संस्कृतिना बांधल्या गेलेला आहे. म्हणूनच स्त्रियांच्या मुक्ततेसाठी आता स्त्रियांच पाऊले उचलणे गरजेचे आहे. जगातील इतरही देशांचा विचार केल्यास असे लक्षात येते की, स्त्री-पुरुष समानता दिसून येत नाही. परंतु आज आधुनिक काळात भारतात व इतर आशियाई देशांमध्ये स्त्रियांनी महत्वाची पदे भुषविली आहेत. उदा. स्व. इंदिरा गांधी, बेनझीर भुट्टो, शेख हसीना वाझीद, सिमिमाओभंडारनायके, प्रतिभाताई पाटील, मिराकुमार इ. असे असले तरी जगातील इतर देशांच्या तुलनेत पंचायतराज व्यवस्थेमधील स्त्रियांचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे.

स्त्रिने लहानपणी वडिलांच्या अधिपत्याखाली, तारुण्यात (लग्नानंतर) पतीच्या अधिपत्याखाली, पतीच्या निधनानंतर तिने मुलाच्या अधिपत्याखाली राहावे अशीच परंपरा दिसून येते.

महिलांचा विकास व्हावा हे ध्येय समोर ठेवून शासनाने सुध्दा महिलांच्या विकासाच्या दृष्टीने पंचवार्षिक योजना सुरू केली. यामध्ये केंद्रीय सामाजिक कल्याण मंडळाची स्थापना 1953 मध्ये केली. यामध्ये केंद्रीय सामाजिक कल्याण मंडळाची स्थापना 1953 मध्ये केली. तसेच तिसऱ्या व चवथ्या योजनेमध्ये स्त्रियांच्या शिक्षणावर भर देण्यात आला. इतकेच नव्हे तर स्त्रियांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, तिच्यात आत्मविश्वास व जाणीव जागृती निर्माण व्हावी यासाठी सातवी पंचवार्षिक योजना (1985-90) निर्माण करून महिलांना सर्वच स्तरावर स्थान प्राप्त होईल यावर प्रकाश टाकण्यात आला.

स्वातंत्र्या नंतरच्या काही काळानंतर 1992 साली 73 व्या घटना दुरुस्तीनुसार स्त्रियांना आरक्षण देण्यात आला. तरी पण आजही 21 व्या शतकात महिलांना पंचायतराज व्यवस्थेत पाहिजे तसे स्थान मिळाले नाही.

### महिलांची जागतिक स्थिती :

20 व्या शतकात जगाच्या राजकारणात फार मोठ्या प्रमाणात बदल घडून आले. याच काळात दोन महायुद्धे झालीत. तिसऱ्या जगातील अनेक देश स्वतंत्र झालीत. जगातील सर्वच पीडित व शोषित समाजामध्ये एक नवी लोकशाहीवादी जागृती निर्माण झाली. 19 व्या शतकापर्यंत स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार नव्हता. अमेरिकेसारख्या देशात 1918 नंतर स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार प्राप्त झाला. तर स्वित्झर्लंडसारख्या देशात हा अधिकार 1970 मध्ये स्त्रियांना मिळाला. 20 व्या शतकात स्त्री स्वातंत्र्याची चळवळी सुरू झाल्या आणि खऱ्या अर्थाने राजकारणात महिलांचा सहभाग फार मोठ्या प्रमाणात वाढू लागला.

### पंचायत राज्याची स्थापना :

भारतात लोकशाही विकेंद्रिकरणावर जोर देण्यासाठी त्रिस्तरीय योजना अंमलात आणली. त्याला 'पंचायतराज योजना' असे संबोधिल्या जाते. त्यासाठी बलवंतराय मेहता समिती (1958) वसंतराव नाईक समिती, व्ही.टी. कृष्णमाचारी समिती, ल.ना. बोंगीरवार समिती, अशोक मेहता समिती, जी.व्ही.के. राव समिती, प्राचार्यपी.बी. पाटील समिती अशा अनेक समित्या स्थापन करण्यात आल्या व या समित्यांच्या शिफारशीनुसार पंचायतराज व्यवस्था स्विकारण्यात आली. यशवंतराव चव्हाण यांनी 'महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा 1961' नावाचा कायदा करून सत्तेच्या विकेंद्रिकरणावर भर दिला.

### 73 व 74 वी घटनादुरुस्ती :

ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थेसंबंधी तरतूद करण्यासाठी 73 व्या घटनादुरुस्तीने 'पंचायत' या शिर्षकाखाली 'भाग-9' हा नवा भाग राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आला. त्यामध्ये कलम 243 ते 243-ओ या कलमात महिलांसाठी राखीव जागांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

त्यानंतर 22 डिसेंबर 1992 ला लोकसभेने व 23 डिसेंबर 1992 ला राज्यसभेने हे विधेयक मंजूर केले. त्यावेळचे पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांनी 24 एप्रिल 1993 ला राष्ट्रपतीच्या स्वाक्षरीसह 73 वी आणि 74 वी घटनादुरुस्ती अस्तित्वात आणली. व या नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली.

**पंचायतराज मधील महिलांचा सहभाग :**

लोकसभेत गेल्या 50 वर्षात स्त्रियांचे प्रमाण सरासरी 6 टक्के राहिले आहे. 1977 साली झालेल्या लोकसभेच्या निवडणूकीत सर्वात कमी 19 महिला होत्या, तर 1999 ला स्थापन झालेल्या 13 व्या लोकसभेत सर्वाधिक 48 महिला होत्या. तसेच महाराष्ट्राच्या विधिमंडळातील प्रमाण अत्यंत कमी होता. 1995 पर्यंत काँग्रेस पक्षामार्फतच जास्तीत जास्त महिला निवडून आल्या असल्याचे दिसून येते.

विधान परिषदेवरील सर्वाधिक 12 स्त्रिया पदव्युत्तर आणि उच्चतांत्रिक शिक्षण घेतलेल्या आहेत. दहावी ते पदवी आणि व्यावसायिक व डॉक्टरेट प्रत्येकी 1 अशा शैक्षणिक पात्रता असलेल्या स्त्रिया विधानपरिषदेवर गेल्या आहेत. वैवाहिक स्थितीनुसार 37 महिला विवाहीत आहेत. 29 सामाजिक कार्यकर्त्या, 5 शिक्षिका प्रत्येकी 2 शेतकरी आहेत.

आधुनिक काळात महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण, कौटुंबिक सक्षमीकरण, राजकीय सक्षमीकरण, शैक्षणिक सक्षमीकरण, सामाजिक सक्षमीकरण अशा प्रत्येक क्षेत्राच्या महिला सहभागी होत असल्याचे अनेक उदाहरणे दिसून येतात.

**सारांश :**

पंचायतराज संस्थांमध्ये महिलांना 33 टक्के राखीव जागा मिळून स्त्रियांना राजकीय सहभागाची संधी प्राप्त झाली आहे. आज महिलांना संघटीत कार्यकत्याचे पाठबळ लागत असल्याने त्यांच्यामध्ये मुलींचे शिक्षण, स्त्रियांचे आरोग्य, व्यसनमुक्ती, भ्रष्टाचार निर्मुलन, अंधश्रद्धा निर्मुलन अशा अनेक क्षेत्रात अनेक महिला जबाबदारी पार पाडीत आहे. अनेक महिला गावातील सरपंच पदावर पोहचले आहे. तसेच पंचायत समितीस्तरावर सभापतीपदी तर जि.प. चे अध्यक्ष पद भुषविल्याचे अनेक उदाहरणे दिसून येत आहे. यामुळे समाजातील पुरुषांचा तसेच नेतेमंडळींचा व राजकीय पक्षांचा महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदललेला आहे. हे पंचायतराज व्यवस्थेमुळे शक्य झाले आहे.

**संदर्भ :**

- 1) ग्राम संवाद जलस्वराज्य वार्तापत्र, फेब्रुवारी, मार्च 2005 (महिला विशेषांक)
- 2) किता
- 3) चोरमारे विजय, स्त्री सत्तेची पहाट
- 4) नांदेडकर व्ही.जी., पंचायतराज
- 5) पाटील व्ही.बी., पंचायतराज व्यवस्था
- 6) विधिमंडळ ग्रंथालय



## शैक्षणिक तंत्रज्ञान : शैक्षणिक गुणवत्ता विकासाचे प्रभावी साधन

श्री. प्रफुल एस. सिडाम  
जि. प. प्राथमिक शाळा, खेडी  
ता. धानोरा जि. गडचिरोली  
मो.नं. 8275215248  
ई-मेल : prafulsidam@gmail.com

### सारांश :

आजचे युग हे विज्ञानयुग आहे आणि विज्ञानयुगात तंत्रज्ञानाला फार महत्वाचे स्थान आहे. तंत्रज्ञानाच्या विविध शाखा आहेत त्यापैकी शैक्षणिक तंत्रज्ञान ही एक प्रचलित शाखा आहे. त्याचा प्रभावी वापर आज शिक्षणक्षेत्रात केला जात आहे आणि त्याचा सकारात्मक परिणाम आपल्याला दिसत आहे. प्रत्यक्ष अध्ययन अध्यापनात E- Learning, M- Learning, Enternate, इत्यादी साधनांचा वापर होत असल्याने विद्यार्थ्यांना उच्च गुणवत्ता प्राप्त शिक्षण मिळण्यास मदत होत आहे. शिक्षणप्रक्रियेत शिक्षक विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढून शाळेतील गडतीचे प्रमाण कमी झाले आहे. शैक्षणिक तंत्रज्ञानाचा वापर प्रत्यक्ष शिक्षणप्रक्रियेत केला गेल्याने विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढिस मदत मिळत आहे. शैक्षणिक समस्यावर उपाययोजना करण्यास्तव शैक्षणिक तंत्रज्ञान सहाय्यक ठरत आहे.

### प्रस्तावना :

करू तंत्रज्ञानाचा उपयोग,

शैक्षणिक विकासाचे जुळून येतील योग.

धरू उत्कृष्टतेची आस,

होईल देशाची प्रगती झकास.

रोज सकाळी शेतकरी रानाकडे जातो. व्यापारी धनाकडे जातो. विद्यार्थी ज्ञानाकडे जातो. थोडक्यात काय तर माणूस आपल्या जगण्याकडे जातो. माणूस जगत असताना सतत नाविन्याचा ध्यास घेत असतो. त्यासाठी विविध तंत्रांचा शोध घेत असतो. अगदी अनादी काळापासून तो नाविन्याचा शोधात आहे. अशा नाविन्यातून नवं तंत्रज्ञान विकसित होत असते. याच तंत्रज्ञानाचा उपयोग शैक्षणिक क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात होत आहे आणि ती आधुनिक भारताची गरज आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांचे डिजिटल इंडियाचे स्वप्न सत्यात उतरविण्यासाठी ते आवश्यक आहे.

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राचे सर्वत्र वारे वाहत असतांना त्याच्या पूर्ततेसाठी एक नवा विचार उदयास आला. तो म्हणजे शिक्षणक्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग. या नवविचाराने संपूर्ण महाराष्ट्रभर वादळ निर्माण झाले आणि याचे लोन संपूर्ण देशात पसरायला सुरुवात झाली. शैक्षणिक क्षेत्रात नविन शैक्षणिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर वाढला असल्याने शैक्षणिक गुणवत्तेत निश्चितच वाढ होत आहे.

### तंत्रज्ञान म्हणजे काय ? :

तंत्रज्ञान (Technology) म्हणजे अवजारे, यंत्रे, यापासून बनलेल्या प्रणाल्या (System) यांचे संकल्पना, निर्मिती आणि उपयोजन अभ्यासणारी तसेच त्यात सुधारणा घडवून आणण्यासंबंधीची विद्याशाखा होय. प्राचिन काळापासून माणव तंत्रज्ञानाचा विकास व

त्याचा वापर करित असून. त्यातूनच आज छापाईचे यंत्र, टेलीफोन, इंटरनेट इत्यादी तंत्रांपर्यंत माणवाने तंत्रज्ञानाचा विकास साधला आहे.

तंत्रज्ञान म्हणजे " वैज्ञानिक व इतर सुसंघटीत ज्ञानाचे प्रत्यक्ष जीवनात आवश्यक प्रात्यक्षित, कृतीना सोपे व सहज करण्याचे उपयोजन "

#### **शैक्षणिक तंत्रज्ञान :**

शिक्षणाचे ध्येय व उद्दिष्ट निश्चित करून ती साध्य करण्यासाठी विविध यंत्रे, तंत्रे पद्धती इत्यादींचा शोध घेणे, त्याची परिणामकारकता तपासणे, मूल्यमापन करणे व त्याचे उपयोजन करणे याचा समावेश शैक्षणिक तंत्रज्ञान या संकल्पनेत होतो.

E. E. Haddan:-

Educational Technology is that branch of educational theory And practice which is concerned primarily with the design and use of messages which control the learning process.

शैक्षणिक तंत्रविज्ञान ही शैक्षणिक विचार आणि प्रयोगाची अशी शाखा आहे की, जी त्या निर्देशांच्या प्रकाराबरोबरच प्रयोगाबरोबर प्रारंभिक रूपात जोडली गेली आहे, ज्यामुळे शिक्षण प्रक्रियेला नियंत्रित केले जाऊ शकते.

G. O. M. Leith :-

Educational Technology is the systematic application of scientific knowledge about teaching , learning and conditions of learning to improve the efficiency of teaching and training.

शैक्षणिक तंत्रज्ञान हे शास्त्रीय ज्ञानाचे सुनियोजित उपयोजन आहे. अध्ययन अध्यापन व प्रशिक्षण यांची परिणामकारकता वाढवून विकास साधणारी उपयोजित शाखा आहे.

NCERT:-

" शिक्षण आणि प्रशिक्षण त्यांच्या गरजांचा पूर्तिसाठी लागणाऱ्या आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कौशल्यांशी शैक्षणिक तंत्रज्ञानाचा संबंध आहे. यांमध्ये अध्ययन प्रक्रियेला सहज सोपे बनविणे, यासाठी पद्धती साधनांचा उपयोग करणे व अध्ययन परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणे याही गोष्टींचा समावेश होतो."

" तंत्रे आणि पद्धती आणि प्रणाली यांचा विकास, उपाययोजना आणि मूल्यमापन म्हणजे शैक्षणिक तंत्रज्ञान असून ते मानवी अध्ययनाच्या क्षेत्रास मदत करते."

#### **शैक्षणिक तंत्रज्ञानाचे उद्दिष्टे :**

- ❖ अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया अधिक मनोरंजक करणे.
- ❖ शिक्षणप्रक्रियेत शिक्षक – विद्यार्थ्यांना नविन तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करता येणे.
- ❖ शिक्षकामध्ये तंत्रज्ञान विषयक आवड निर्माण करणे.
- ❖ अध्ययन प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढविणे.
- ❖ शिक्षणाची उच्च गुणवत्ता प्राप्त करणे.
- ❖ खडू-फडा विरहित मुलांचे दपतराचे ओझे कमी करणे.
- ❖ विद्यार्थ्यांचा अध्ययनाचा वेग अनेक पटीने वाढविणे.
- ❖ विद्यार्थ्यांमध्ये शाळेविषयी आवड निर्माण करून गडतीचे प्रमाण कमी करणे.

**शैक्षणिक तंत्रज्ञानातील नविन संकल्पना :**

आज अध्ययन अध्यापन प्रभावी करण्यासाठी माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा वापर विविधतेने करण्यात येत असल्याचे आढळून येतो. माहिती तंत्रज्ञानात जसजशी प्रगती घडून येते, तसतसे शिक्षण क्षेत्रातील त्यांच्या वापराबद्दल बुद्धीमंथन घडून येते. आजमितीस अनेक अत्याधुनिक संकल्पना शिक्षण क्षेत्रात वापरल्या जात आहेत.

**M लर्निंग :**

आज मोबाईल माणसाची गरज बनली आहे. तेव्हा त्याचा वापर शिक्षणक्षेत्रात न होईल तर नवलच आज 3 Dतंत्रज्ञान, नवनविन शैक्षणिक Application, Educational Blog, Webside चा वापर मोबाईलने आपल्या अध्ययन अध्यापनात सहजतेने व कल्पकतेनेकरता येतो. Teacher Whats Up Group चा वापर करून शैक्षणिक माहितीची देवानघेवान खुप मोठया प्रमाणात होत असल्याचे आढळून येते.

**E लर्निंग :**

अध्ययन अध्यापनातील एखादया क्लिष्ट संकल्पना इंटरनेटचा वापर करून सहजतेने स्पष्ट करू शकतो. अभ्यासकमावर आधारितSoftwareचा प्रत्यक्ष वापर आज शिक्षणक्षेत्रात खुप मोठया प्रमाणात होत असल्याचे आढळते यामुळे शिक्षण सोपे होते, शिक्षणप्रक्रियेत विद्यार्थी सहभाग वाढतो आहे.

**डिजिटल स्कूल :**

प्रत्यक्ष शाळेत डिजिटल साधने ( स्मार्ट बोर्ड, कंप्युटर, लॅपटॉप, प्रोजेक्टर, स्मार्ट टिव्ही, एल.सि.डी टिव्ही, साउंड सिस्टीम, टॅब ) इत्यादीचा वापर करून अध्ययन अध्यापन करणे म्हणजे डिजिटल शाळा होय. महाराष्ट्रात डिजिटल शाळेची चळवळ विस्तारीत आहे. यातुन विद्यार्थीना आंतरक्रियात्मक ( Interactive ) शैक्षणिक कृती मध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करून कमीत कमी किमतीत शिक्षणाची उच्च गुणवत्ता प्राप्त करणे शक्य होत आहे.

**संगणक शिक्षण :**

संगणक शिक्षण हा आता एक विषय म्हणून ओळखला जातो. जवळजवळ बहूतेक शाळात संगणक शिक्षण शिकविले जाते. विद्यार्थीना संगणकाच्या मदतीने दर्जेदार शिक्षण दिले जाऊ शकते.

**डिजिटल शैक्षणिक साधने :**

ही शैक्षणिक साधने शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी आणि उत्साही करण्यास मदत करतात. शिक्षक विविध साधनाचा वापर करून विद्यार्थीना अधिक ज्ञान देऊ शकतात. हे शैक्षणिक तंत्रज्ञान उदयोन्मुख ट्रेंड आहेत. महाराष्ट्रात शैक्षणिक साधनांची देवाणघेवाण करण्यासाठी मित्रा(Mitra)सारखे उपयुक्त वेबसाईडडिजिटल शैक्षणिक साधनांच्या निर्मिती, प्रसारासाठी कार्य करित आहे. आज शिक्षणासाठी बहुसंख्य वेबसाईड, ब्लॉग, शैक्षणिक अप्लीकेशन तयार केलेल्या आहेत. नविन शैक्षणिक संकल्पना इतरापर्यंत पोहचविण्यासाठी वेबसाईड, ब्लॉगचा वापर होतांना दिसतो आहे. महाराष्ट्रातील असंख्य शिक्षक वेबसाईड, ब्लॉग च्या माध्यमातुन नविन शैक्षणिक क्रांतीघडून आणण्याचा प्रयत्न करतांना दिसतो आहे.

**गडचिरोलीया मागास व अतिसंवेदनशिल जिल्हात शैक्षणिक तंत्रज्ञानाची यशस्वी अमलबजावणी :**

महाराष्ट्रातील गडचिरोली सारख्या मागास व अतीसंवेदनशिल भागातही शैक्षणिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील एकूण 2023 शाळांपैकी मार्च 2017 पर्यंत सुमारे 1200 शाळा ह्या डिजिटल बनल्या आहेत त्यामुळे दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील माहितीचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातील मार्च 2017 पर्यंत डिजिटल शाळांची स्थिती :

तालुका	एकूण शाळा	जि. प.	ग्रा.प.	सर्व शिक्षा	लोकसहभाग
गडचिरोली	179	95	83	7	56
आरमोरी	135	87	77	7	28
देसाईगंज	75	29	22	6	16
कुरखेडा	176	116	109	6	18
कोरची	135	93	78	4	15
धानोरा	222	64	55	5	5
चामोर्शी	173	147	129	9	52
मुलचेरा	99	52	39	2	2
अहेरी	246	123	115	4	25
एटापल्ली	213	84	73	4	7
भामरागड	106	92	92	2	1
सिरोंचा	164	45	31	2	14
एकूण	2023	1027	903	58	239

गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण सर्व व्यवस्थापनाच्या 2023 शाळा आहेत त्यापैकी ग्रामपंचायतीच्या निधितून 903 शाळा डिजिटल झालेल्या आहेत त्याची टक्केवारी 44.63 टक्के आहे.सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत 58 शाळा डिजिटल तर लोकसहभागानातून 239 शाळा डिजिटल झालेल्या आहेत त्याची टक्केवारी 11.81 टक्के आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड या मागास तालुक्यात 106 शाळा असून त्यातील 95 शाळा डिजिटल झालेल्या आहेत त्याचे प्रमाण सर्वात जास्त आहे. यावरून तंत्रज्ञानविषयक लोक जागृत होत असल्याचे दिसते आणि ते आधुनिक भारत निर्माणसाठी आवश्यकही आहे.

#### **गडचिरोली जिल्हा डिजिटल चळवळीचे यशाचे गमक :**

गडचिरोली जिल्ह्यातिल 100 टक्के शाळा डिजिटल झाल्या पाहिजे याकरिता राज्याचे शिक्षण आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनात चळवळीला प्रारंभ झाला. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनात एक कालबद्ध कार्यक्रम आखला गेला.या उपक्रमास व्यापक स्तरावर प्रसिद्धी देण्यात आली. जिल्हा, तालुका. केंद्र स्तरावर विशेष सभेचे आयोजन करून नियोजन करण्यात आले. ग्रामपंचायतीच्या मदतीने डिजिटल चळवळीविषयी जनजागृती करण्यात आली.ग्रामस्तरावर विशेष सभेचे आयोजन करून गावातील पेसाअंतर्गत, वा इतर योजनेतून डिजिटल साधनाकरिता आवश्यक पैसाची तरतुद करण्यात आली व बहूतेक शाळा डिजिटल करण्यात आल्या यासाठी सामाजिक सहभागही मोठ्या प्रमाणात घेण्यात आला. या सर्वांचा परिणाम जिल्ह्यातिल 60 टक्के शाळा डिजिटल झाल्या आहेत.

या सर्व चळवळीवर नियंत्रण ठेवण्याचे कार्य जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्थेने केले. त्यांच्या मार्फतीने जिल्ह्यातील 3000 शिक्षकांना तंत्रस्नेही प्रशिक्षण दिले गेले असल्याने शिक्षकांनी गरजेनुसार डिजिटल साधनांचा वापर करण्याविषयी कौशल्य प्राप्त केले आहे. गडचिरोलीसारख्या मागास जिल्ह्यात अनेक भाषा बोलल्या जात असल्याने स्थानिक

तंत्रस्नेही शिक्षकाच्या मदतीने स्थानिक बोलीभाषेवर आधारित डिजिटल शैक्षणिक साहित्याची निर्मिती करून प्रत्यक्ष अध्यापनात वापर केला जात आहे त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भाषिक समस्येवर निश्चितच मात करता येईल. या सर्व चळवळीच्या यशस्वितेसाठी गडचिरोली जिल्हातील तंत्रस्नेही शिक्षकटीम अविरत प्रयत्न करित आहे.

**निष्कर्ष :**

- ❖ शैक्षणिक तंत्रज्ञानाच्या वापराने अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया रंजक झाली आहे.
- ❖ अध्ययन अध्यापन प्रक्रियेत नविन तंत्रज्ञानाचा शिक्षक विद्यार्थ्यांकडून प्रभावी वापर वाढला आहे.
- ❖ शिक्षकामध्ये तंत्रज्ञानाची भिती नष्ट होऊन तंत्रज्ञानाविषयी आवड निर्माण झाली आहे.
- ❖ अध्ययन अध्यापन प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढला आहे.
- ❖ विद्यार्थी आधुनिक साधनाचा वापर करून अध्ययन करित असल्याने विद्यार्थ्यांचे दपतराचे ओझे कमी झाले आहे.
- ❖ डिजिटल शैक्षणिक साधनाचा वापर करून विद्यार्थ्यांना उच्च गुणवत्ता प्राप्त शिक्षण मिळण्यास मदत होत आहे.
- ❖ डिजिटल शैक्षणिक साधनाचा वापराने विद्यार्थ्यांचा अध्ययनाचा वेग अनेक पटीने वाढला आहे.
- ❖ विद्यार्थ्यांमध्ये शाळेविषयी आवड निर्माण होऊन गडतीचे प्रमाण कमी झाले आहे.

**संदर्भ सुची:-**

- 1) प्रा. शमसुदिन तांबोडी, महाराष्ट्राचा शैक्षणिक विकास डायमंड पब्लीकेशन पुणे, 1 जानेवारी-2009
- 2) शैक्षणिक माहिती तंत्रज्ञान, फडके प्रकाशन, 2007
- 3) <http://mr.m.wikipedia.org/wiki/aaशिक्षण> प्रणालित तंत्रज्ञानाचा वापर

## आधारभूत संरचनेचे आर्थिक विकासातील महत्व आणि भारतातील ऊर्जा आधार संरचना

- 1) प्रा. एस. एम. कोल्हापूरे, अर्थशास्त्र विभाग, विलिंग्डन महाविद्यालय, सांगली.
- 2) प्रा. डॉ. वाय. एस. गायकवाड, प्रमुख अर्थशास्त्र विभाग, विलिंग्डन महाविद्यालय, सांगली.

देशाच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याचे कार्य आधारभूत संरचना करतात. विकसित देशांचा जलद आर्थिक विकास होण्याचे श्रेय आधारभूत संरचनेस दिले जाते. देशाचा आर्थिक विकास उद्योग व कृषी क्षेत्राच्या विकासावर अवलंबून असतो. तर कृषी व उद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी पाणीपुरवठा, वीज, वाहतूक व दळणवळण, बँकिंग सुविधा अशा विविध घटकांची आवश्यकता असते. या सर्व घटकांना एकत्रितपणे "आधारभूत संरचना" म्हटले जाते. आधारभूत संरचनेमध्ये साधारणपणे वाहतूक, संदेशवहन, ऊर्जा, अधिकोषण, विज्ञान व तंत्रज्ञान, पाणीपुरवठा, सामाजिक सेवा या घटकांचा समावेश होतो.

### संशोधनाची उद्दिष्टे:

1. पायाभूत आधारसंरचनेचे आर्थिक विकासातील महत्व अभ्यासणे.
2. भारतातील ऊर्जा आधारसंरचनेची मागणी व पुरवठा यातील तफावत अभ्यासणे.
3. भारतातील ऊर्जा समस्या सोडविण्यासाठी उपाय सुचविणे.

### ➤ आधारभूत संरचनेचे देशाच्या विकासातील महत्व:

आधारभूत संरचना देशाच्या आर्थिक विकासासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याचे कार्य करतात. उद्योजकांना, व्यापाऱ्यांना, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादक क्रियांसाठी तसेच कौटुंबिक क्षेत्रासाठी दैनंदिन गरजांच्या पूर्ततेसाठी आधारभूत संरचना आवश्यक असतात.

1. आधारभूत संरचना देशातील कृषी क्षेत्राच्या विकासामध्ये महत्वाची भूमिका बजावतात. प्रत्येक अर्थव्यवस्थेमध्ये शेती क्षेत्र महत्वाची भूमिका बजावते. देशातील लोकसंख्येला लागणारे अन्नधान्य आणि कृषिवर आधारित उद्योगांना लागणारा कच्चा माल पुरविण्याचे महत्वपूर्ण कार्य शेती क्षेत्र करते. शेतीमधील शेतमालाचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी जलसिंचन, वीज, वाहतूक यासारख्या पायाभूत सुविधा महत्वपूर्ण असतात.
2. औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी विविध पायाभूत सुविधांची आवश्यकता असते. यामध्ये प्रामुख्याने वीज, पाणीपुरवठा, रस्ते, वाहतूकीची साधने आदींची मोठ्याप्रमाणात आवश्यकता असते. कच्चा माल आणणे व पक्का माल बाजारपेठेत वेळेवर पोहोचविणे यासाठी चांगल्या प्रतीचे रस्ते, रेल्वेमार्गांची गरज असते. याव्यतिरिक्त संदेशवहनाची आधुनिक साधने, बँकविषयक सुविधा, दर्जेदार व कुशल कामगार व प्रशिक्षित व्यवस्थापक, तंत्रज्ञ यांचीही आवश्यकता असते. या सर्व बाबींचा संबंध आधारभूत संरचनांशी येतो. या सुविधा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असतील तर उद्योगांचा विकास जलद गतीने होऊन अर्थव्यवस्थेच्या विकासास गती प्राप्त होते.
3. श्रम, भांडवल, संघटक हे उत्पादनाचे घटक गतिशील असतात. त्यांची गतीक्षमता आधारभूत संरचनांच्या उपलब्धतेशी निगडित असते. संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत वाहतूक व संदेशवहनाचे जाळे पसरलेले असेल तर संपर्कव्यवस्था कार्यक्षम बनते. एका भागातून दुसऱ्या भागामध्ये माहितीची देवाण-घेवाण करणे सुलभ होते. यातून व्यावसायिक संधी व भांडवल गुंतवणूकीची संधी कोठे उपलब्ध होऊ शकते ते समजते. परिणामी उत्पादन घटकांना एका व्यवसायातून दुसऱ्या व्यवसायात आणि एका प्रदेशातून दुसऱ्या प्रदेशात स्थलांतरण करणे शक्य होण्यासाठी मार्गदर्शन प्राप्त होते.



4. आधारभूत संरचना बाजारपेठेचा विस्तार करण्यासाठी सहाय्यभूत ठरते. वाहतूक व दळणवळणाच्या साधनांमुळे देशातील कोणत्याही प्रदेशात वस्तू पोहोचविण्यास मदत होते. बाजारपेठेच्या उपलब्धतेवर वस्तूचे उत्पादन अवलंबून असते. एखाद्या वस्तूस बाजारपेठेचे उपलब्ध होत नसेल किंवा बाजारपेठ उपलब्ध होण्यास विलंब होत असेल तर वस्तूचे उत्पादन करून काहीही फायदा होणार नाही. त्याचप्रमाणे इंटरनेटच्या माध्यमातून जगामध्ये कोणत्याही ठिकाणी एखादी वस्तू असेल तर ती ग्राहकास मिळू शकते. त्याचबरोबर घरबसल्या विविध वस्तू खरेदी करता येतात.
5. प्रादेशिक समतोल प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने आधारभूत संरचना महत्वाचे कार्य करतात. रस्ते, वाहतूकीची साधने, संपर्काची विविध साधने जेवढी विस्तारत जातात तेवढे दोन ठिकाणांमधील अंतर कमी होते. रस्ते, वाहतूकीच्या साधनांमुळे खेडी शहरी भागांशी जोडली जातात. त्यामुळे त्यांचा विकास होण्यास सुरुवात होते. प्रसारमाध्यमांमुळे ग्रामीण भागातील जनतेमध्ये जागृती निर्माण होऊन ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी दबाब निर्माण करण्यास मदत होते. यातून शैक्षणिक सुविधा, पाणीपुरवठ्याच्या सुविधा, वीज उपलब्धता, रस्ते अशा विविध पायाभूत सुविधांच्या विकासांमुळे प्रादेशिक असमतोल दूर होण्यास मदत होते.
6. औद्योगिकविकासाच्या प्रक्रियेत संयोजक या घटकाचे महत्वपूर्ण स्थान आहे. ज्या देशात संयोजकांचा वर्ग उपलब्ध आहे ते देश आर्थिक विकासात अग्रेसर आहेत. हा संयोजक वर्ग निर्माण करण्यास दर्जेदार व्यावसायिक व व्यवस्थापकीय शिक्षण देणाऱ्या संस्थांची आवश्यकता असते.
7. देशामध्ये राष्ट्रीय ऐक्य निर्माण करण्यात आधारभूत संरचनेचे योगदान उल्लेखनीय आहे. वाहतूक व दळणवळणाच्या प्रगत सुविधांमुळे विभिन्न प्रांतातील नागरिकांचा परस्परांशी संपर्क निर्माण होतो. औद्योगिकीकरणाच्या स्थानियीकरणामुळे ग्रामीण भागातील, विविध प्रदेशातील लोक एकत्र येतात. त्यांच्यामध्ये भाषा, परंपरा, सण, उत्सव यांची ओळख होते. परस्परांतील एकात्मिकता वाढीस लागते. यातून मानवी मूल्यांची जोपासना होते. यातूनच राष्ट्रीय एकात्मता वाढते.
8. पायाभूत सुविधांच्या विकासांमुळे संयोजक वर्गाची निर्मिती, संशोधकांची, तज्ज्ञांची निर्मिती होते. हे संशोधक विविध प्रकारचे संशोधन करून नवीन तंत्रज्ञानाची निर्मिती करतात. यातूनच प्रगत तंत्राची उपलब्धता मोठ्याप्रमाणात होऊन देशाचा विकास होण्यास मदत होते.

भारतामध्ये नियोजनाच्या सुरुवातीपासून आधारभूत संरचनेच्या विकासास महत्व दिले आहे. पंचवार्षिक योजनेमध्ये साधारणतः योजना खर्चाच्या 50 टक्के आधारभूत संरचनांवर खर्च करण्यात आला आहे. आधारभूत संरचनांच्या विकासांमुळे पायाभूत उद्योगांच्या उत्पादनामध्ये वाढ होण्यास मदत झाली आहे.

➤ **ऊर्जा : एक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना:**

मानवाच्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजकीय विकासांमध्ये ज्याप्रमाणे चाकाचे महत्व अनन्यसाधारण आहे त्याचप्रमाणे ऊर्जेचे सुद्धा आहे. कार्य करण्यासाठी लागणारी क्षमता म्हणजे ऊर्जा होय. कृषी क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र व सेवा क्षेत्रातील पायाभूत कार्ये करण्यासाठी ऊर्जेची आवश्यकता असते. ऊर्जेच्या उपलब्धतेवर देशाचा आर्थिक विकास अवलंबून असतो. ऊर्जा व विकास यांमध्ये घनात्मक संबंध असतो. यंत्राची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी ऊर्जा महत्वाची असते. अलिकडील काळातील लोकसंख्येतील भरमसाठ वाढ त्याचबरोबर त्यांच्या गरजांमधील वाढ यामुळे ऊर्जेची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. ही ऊर्जेची वाढती मागणी पुढील स्त्रोतांच्या आधारे पूर्ण केली जाते.

**ऊर्जेचे स्त्रोत:** ऊर्जेचे प्रामुख्याने दोन स्त्रोत आहेत. 1. पारंपारिक ऊर्जा स्त्रोत. यांना बिगर व्यापारी स्त्रोत असेही म्हटले जाते. 2. आधुनिक स्त्रोत. यांना व्यापारी स्त्रोत असे म्हटले जाते.

1. **पारंपारीक ऊर्जा साधने:** जळाऊ लाकूड, गोवऱ्या, पिकांचा टाकाऊ भाग.

2. आधुनिक ऊर्जा साधने: अ) विनाशी ऊर्जा साधने:—कोळसा, खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, अणुऊर्जा, औष्णिक ऊर्जा. ब) अविनाशी ऊर्जा साधने:जलविद्युत, सौरऊर्जा, पवनऊर्जा, सागरी ऊर्जा, जैविक वायू (गोबर गॅस)

➤ भारतातील ऊर्जेचे स्रोत:

अ. व्यापारी स्रोत:

1. कोळसा व लिग्नाइट:

भारतामध्ये कोळशाचे एकूण अनुमानीत भंडार 14,879 कोटी टन आहेत. परंतु यापैकी खोदण्यायोग्य भंडार जवळपास 6000 कोटी टन आहे. तमिळनाडू येथील नेवेली भंडारमध्ये जवळपास 330 कोटी टन आहे त्यापैकी 109 कोटी टन प्रमाणित वर्गात मोडतो. वर्तमान प्रक्षेपणाच्या आधारे भविष्यातील मागणीच्यादृष्टीने असा अंदाज वर्तविला जातो की हे भंडार जवळपास 130 वर्षांपर्यंत पुरतील एवढेच आहेत.

2. तेल व गॅस:

अलिकडील अंदाजानुसार तेलाचे शुद्ध भंडार 55 कोटी टन आणि गॅसचे एकूण भंडार अंदाजे 550 अरब घन मिटर आहेत. 2009-10 मध्ये क्रुड तेलाचे उत्पादन 337 लाख टन होते. उपभोगाच्या वर्तमान स्थितीवरून तेलाचे भंडार केवळ 20 ते 25 वर्षांपर्यंतच पुरतील एवढेच आहेत.

3. विद्युत शक्ती:

शासकीय अंदाजानुसार सरासरी 90,000 मेगावॅट जलविद्युत वार्षिक विज उपलब्ध होऊ शकते. यापैकी 18,000 मेगावॅट जलविद्युत निर्मिती क्षमतेचा विकास केला गेला आहे. म्हणजेच एकूण क्षमतेच्या केवळ 20 टक्केच क्षमतेचा विकास केला आहे. उर्वरित क्षमता शेष आहे.

आज एकूण वीज निर्मितीमध्ये जलविद्युत ऊर्जेचे योगदान 17 टक्के आहे. औष्णिक ऊर्जेचे योगदान 80 टक्के आणि 3 टक्के अणुऊर्जेचे आहे. सार्वजनिक वीज युनिटच्या अतिरिक्त बिगर सरकारी क्षेत्रातसुद्धा वीज युनिट आहेत त्यांना 'बद्ध-वीज-प्लांट' किंवा गैर उपयोगिता म्हणतात. यांच्याद्वारे 2009-10 मध्ये 109.7 अरब किलोवॅट तास वीज उत्पादन झाले होते.

देशामध्ये युरेनियमचे भंडार अंदाजे 70,000 टन आहेत. हे भंडार 120 अरब टन कोळशाएवढे आहेत. भारतात थोरियमचे भंडार अंदाजे 3,60,000 टन आहेत. हे थोरियम जेव्हा प्रजनक रिअॅक्टरमध्ये वापरले जातील त्यावेळी ते 600 अरब टन कोळशाबरोबर असतील. हे भंडार कोळशाच्या जवळपास पाचपट आहेत. अणुऊर्जेची दीर्घकालीन क्षमता थोरियमवर आधारित आहे.परंतु अणुऊर्जेद्वारे वीजनिर्मितीस मोठ्याप्रमाणात जनविरोध होत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे अमेरिका व रशियामधील अणुऊर्जा प्लांटची विफलता हे आहे.

मागील सहा दशकांमध्ये उर्जेच्या उत्पादनात महत्वपूर्ण वाढझाली असली तरी वीजेचा अभाव हा प्रश्न कायम आहे. वीजेचा शिखर अभाव 2008-09 मध्ये जवळपास 12 टक्के होता. भारतामधील सर्वच भागांमध्ये व्यापारी उर्जेची साधने समान रितीने विभागलेली नाहीत.

1. कोळसा मोठ्याप्रमाणात उपलब्ध आहे पण हा पूर्वीय क्षेत्रामध्ये एकवटलेला आहे. या क्षेत्रात 70 टक्के पेक्षा अधिक कोळसा आहे.
2. हायड्रोकार्बन 70 टक्के पेक्षा अधिक पश्चिमी क्षेत्रात आहे.
3. देशाच्या एकूण जलविद्युत क्षमतेच्या 70 टक्के पेक्षा जास्त उत्तर आणि उत्तर-पूर्व भागामध्ये उपलब्ध आहे.
4. दक्षिण क्षेत्रात कोळसा केवळ 6 टक्के तर जलविद्युत क्षमतेच्या केवळ 10 टक्के उपलब्धता आहे. परंतु लिग्नाइटचे भंडार जवळपास 100 टक्के उपलब्ध आहे.

वरील ऊर्जा स्रोतांचे वितरण पाहता वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये त्या ऊर्जा स्रोतांचा वापर करून वीज निर्मिती करणे योग्य ठरते. परंतु आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या अभावामुळे व भांडवलाच्या अभावामुळे त्या ठिकाणी तसे उद्योग स्थापन करणे अडचणीचे ठरते.

#### ब. बिगर व्यापारी स्रोत:

##### 1. लाकूड:

ग्रामीण भागात इंधन म्हणून लाकडाचा उपयोग मोठ्याप्रमाणात होतो. इंधन लाकूड समिती (Fuelwood Committee) 1982 च्या मते देशातील इंधनासाठी 5 कोटी टन लाकूड दरवर्षी प्राप्त होते, जे गरीब लोकांचे अन्न शिजविण्याच्या केवळ अर्धे आहे. वर्तमान मागणी व पुरवठा असाच राहिला तर देशातील लाकूडरूपी इंधनाचा दुष्काळ पडेल.

##### 2. वनस्पतींचे टाकाऊ भाग:

शेतीमधून टाकाऊ पदार्थ जसे गवत, वेगवेगळ्या पीकाचे टाकाऊ भाग यांचा वापर इंधन म्हणून ग्रामीण भागामध्ये केला जातो. याच्या वापराबाबत विश्वसनीय अंदाज नाहीत. परंतु इंधनाच्या रूपात यांचा उपभोग 1976-77 मध्ये 410 लाख टन अंकीत केला होता. आता जवळपास 650 लाख टन असेल.

##### 3. गोव्या:

पशूपासून मिळणाऱ्या शेणाचा वाळवून उपयोग इंधनाच्या रूपात ग्रामीण तसेच शहरी भागामध्ये केला जातो. शेणाच्या अनुमानित 32.4 कोटी टन उत्पादनापैकी दरवर्षी जवळपास 7.3 कोटी टन इंधनाच्या रूपात वापर केला जातो.

#### ➤ भारतातील ऊर्जेची मागणी व पुरवठा:

2011 च्या जनगणनेनुसार भारताची लोकसंख्या 121 कोटी आहे. प्रत्येक व्यक्तीला तीच्या जीवनावश्यक गरजा जसे अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि आरोग्य पूर्ण करण्यासाठी ऊर्जेची आवश्यकता असते. लोकसंख्येच्या गरजा अनंत आहेत त्यातच त्या पुन्हा पुन्हा निर्माण होतात. या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मोठ्याप्रमाणात ऊर्जा आवश्यक आहे. त्यामुळे ऊर्जेची मागणीही वाढत आहे. पुढील तक्त्यामध्ये भारतातील ऊर्जेची मागणी दर्शविली आहे.

भारतातील ऊर्जेची मागणी(in Mtoe)

ऊर्जेचे घटक	वर्ष					शेकडा प्रमाण	
	2000	2013	2020	2030	2040	2013	2040
तेल	112	176	229	329	458	23	24
नैसर्गिक वायू	23	45	58	103	149	6	8
कोळसा	146	341	476	690	934	44	49
अणु	4	9	17	43	70	1	4
पुनर्निर्मित	155	204	237	274	297	26	16
1. जलविद्युत	6	12	15	22	29		
2. जैवऊर्जा	149	188	209	217	209		
3. इतर पुनर्निर्मित	0	4	13	35	60		
एकूण	441	775	1018	1440	1908	100	100

Source: India Energy Outlook, World Energy Outlook Special Report, International Energy Agency, 2015.

(Mtoe: million tonnes of oil equivalent)

वरील तक्त्यावरून असे दिसून येते की भारतातील ऊर्जेची मागणी दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे. इ. स. 2000 मध्ये 441 Mtoe असलेली ऊर्जेची मागणी 2040 मध्ये वाढून 1908Mtoe एवढी होण्याचा अंदाज आहे. ऊर्जेच्या मागणीतील ही वाढचारपटीपेक्षाही जास्त आहे.ऊर्जेच्या मागणीमध्ये कोळसा ऊर्जा संसाधनाची मागणी सर्वाधिक आहे. त्यानंतर तेल ऊर्जा संसाधनाची मागणी सर्वाधिक आहे.

**भारतातील ऊर्जेचा पुरवठा (in Mtoe)**

ऊर्जेचे घटक	वर्ष					शेकडा प्रमाण	
	2000	2013	2020	2030	2040	2013	2040
तेल	37	43	35	31	31	8	3
नैसर्गिक वायू	23	29	32	46	75	6	7
कोळसा	131	238	298	443	648	45	58
अणु	4	9	17	43	70	2	6
पुनर्निर्मित	155	204	237	274	297	39	26
1. जलविद्युत	6	12	15	22	29		
2. जैवऊर्जा	149	188	209	217	209		
3. इतर पुनर्निर्मित	0	4	13	35	60		
एकूण पुरवठा	351	523	619	836	1121	100	100
एकूण मागणी	441	775	1018	1440	1908		

Source: India Energy Outlook, World Energy Outlook Special Report, International Energy Agency, 2015.

(Mtoe: million tonnes of oil equivalent)

वरील तक्त्यामध्ये भारतातील ऊर्जेचा पुरवठा दर्शविला आहे. इ. स. 2000 मध्ये 351 Mtoe एवढा ऊर्जेचा एकूण पुरवठा होता. या पुरवठ्यामध्ये 2040 मध्ये वाढ होऊन तो 1121Mtoe एवढा होण्याचा अंदाज आहे. ऊर्जेचा पुरवठा व मागणी यावरून असे दिसून येते की ऊर्जेच्या पुरवठ्याच्या तुलनेत मागणी खूप जास्त आहे. त्यामुळे भारतामध्ये ऊर्जेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

➤ **भारतातील ऊर्जा समस्या दूर करण्याचे उपाय:**

**1. तेलाच्या उत्पादन वाढीस प्रोत्साहन देणे:**

जेव्हा 1973 मध्ये क्रुड तेलाच्या किंमती 2.1 डॉलर प्रति बॅरलवरून 1980 मध्ये 27.30 डॉलर प्रतिबॅरल वाढविल्या, त्यावेळी तेल उपभोगाच्या अतिरिक्त वापरावर निर्बंध घालणे गरजेचे होते ज्यामुळे पेट्रोल आणि पेट्रोलियम पदार्थांच्या आयातीस एका मर्यादेमध्ये ठेवता येईल. त्याचबरोबर देशांतर्गत तेलाचे उत्पादन व त्याची क्षमता वाढविण्यावर लक्ष केंद्रीत करायला पाहिजे होते. ओएनजीसी आणि ओआईएल मार्फत देशांमध्ये पेट्रोलियम तेलाचा शोध घेतला जातो. तेलाचे उत्पादन 1973-74 मध्ये 70 लाख टन होते जे वाढून 1995-96 मध्ये 350 लाख टन झाले. यानंतरच्या कालावधीत यामध्ये घट झाली आणि 2009-10 मध्ये हे 337 लाख टन झाले.

**2. पेट्रोलियमच्या वापरावर नियंत्रण:**

पेट्रोलियम पदार्थांचा उपभोग कमी व्हावा यासाठी सरकारने लावलेली नियंत्रणे पूर्ण यशस्वी झाली नाहीत. 1973 मध्ये पेट्रोलियम उत्पादनांचा उपभोग जवळपास 240 लाख टन होता तो काही कालावधीसाठी स्थिर राहीला परंतु त्यानंतर उपभोगामध्ये वाढहोत गेली. 1979-80 पर्यंत 300 लाख टन, 1995-96 मध्ये 750 लाख टन, 2009-10 मध्ये 1382 लाख टन झाला. या उपभोगातील वाढीमुळे आयातीवर मोठा खर्च होत आहे.

त्यामुळे सरकारने पेट्रोलियम पदार्थांच्या उपभोगावर प्रभावी नियंत्रण प्रस्थापित करावे जेणेकरून त्यांचा उपभोग एका मर्यादेमध्ये सीमित राहिल.

### 3. विद्युतशक्तीचे विस्तारीकरण:

तेलाला एक महत्वपूर्ण पर्याय म्हणजे विद्युत ऊर्जा. जलविद्युत, पवन विद्युत आणि सौरऊर्जा यातून वीज निर्मिती करून काही प्रमाणात ऊर्जा समस्येवर मात करता येऊ शकते. त्याचबरोबर औष्णिक विद्युत, अणुविद्युत याला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण शासनाचे आहे. यासाठी अनेक उपाय योजिले आहेत.

### 4. ऊर्जा बचत किंवा रक्षण:

भारतामध्ये वाणिज्यीक ऊर्जेची जसे कोळसा, पेट्रोलियम, आणि वीज यांची मागणी बिगर वाणिज्यीक ऊर्जेच्या तुलनेत अधिक पटीने वाढत आहे. कोळशाची मागणी दरवर्षी 4 ते 5 टक्क्यांनी वाढत आहे, पेट्रोलियम पदार्थांची मागणी 6 टक्क्यांनी वाढत आहे. तर वीजेची मागणी 9 ते 10 टक्क्यांनी वाढत आहे. यामुळे भारत सरकारने पेट्रोलियम पदार्थांच्या बचतीसाठी काही उपाय केले आहेत. त्यामध्ये इंधन कुशलता वाढविणाऱ्या उपायांचा उपयोग, औद्योगिक क्षेत्रातील जुनी मशिनरीचे नवीन मशिनरीद्वारे प्रतिस्थापन, इंधन कुशल सिंचन पंपसेटसूचे प्रमाणीकरण इ. उपाय केले आहेत.

### 5. नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांच्या वापरास प्रोत्साहन:

ऊर्जेच्या अपारंपारीक स्रोतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने विविध उपाय योजिले आहेत. भारतात जैव ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, पवन ऊर्जा इ. मोठ्याप्रमाणात उपलब्ध आहे. यांच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकारने अनेक उपाय योजिले आहेत. जैव ऊर्जा निर्मितीसाठी सरकारने 33 लाख जैव ऊर्जा प्लांट स्थापन केले आहेत. साखर उद्योगातून वीज निर्मितीस प्रोत्साहन दिले आहे. देशात 420 साखर कारखान्यांतून 5300 मेगावॉट वीज निर्माण होऊ शकते.

थोडक्यात भारताची वाढती ऊर्जेची गरज पूर्ण करण्यासाठी शासनाने प्रबळ प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. कोळसा, तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, लाकूड यांच्या वापराऐवजी अक्षय ऊर्जा साधनांपासून ऊर्जेची गरज पूर्ण करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. भारतामध्ये सौरऊर्जा, पवनविद्युत, जलविद्युत, सागरी ऊर्जा यांच्या विकासासाठी मोठा वाव आहे. तसेच भारतामध्ये हे घटक मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असल्याने या अक्षय ऊर्जा साधनांच्या सहाय्याने ऊर्जेची गरज पूर्ण करण्यावर भर दिला पाहिजे.

### संदर्भ:

1. गौरव दत्त आणि अश्विनी महाजन, "दत्त एवं सुन्दरम भारतीय अर्थव्यवस्था", एस. चंद एन्ड कंपनी प्रा. लि., नवी दिल्ली.
2. मिश्र पुरी, "भारतीय अर्थव्यवस्था", हिमालया पब्लिशिंग हाउस, नवी दिल्ली.
3. India Energy Outlook, World Energy Outlook Special Report, International Energy Agency, 2015.
4. Energy Statistics 2016, Central Statistics Office, Ministry of Statistics, and Programme Implementation, Government of India.



## SOCIAL MEDIA MARKETING

Dr. H. M. Kamdi,

Adarsh Arts & Commerce College, Desaijanj(Wadsa)

[E-mail-h.kamdi@yahoo.com](mailto:E-mail-h.kamdi@yahoo.com)

### Abstract

*Social media marketing is the use of social media platforms and websites to promote a product or service. Most of these social media platforms have their own built-in data analytics tools, which enable companies to track the progress, success, and engagement of ad campaigns. Companies address a range of stakeholders through social media marketing including current and potential customers, current and potential employees, journalists, bloggers and the general public. On a strategic level, social media marketing includes the management of the implementation of a marketing campaign, governance, setting the scope (e.g. more active or passive use) and the establishment of a firm's desired social media "culture" and "tone". To use social media effectively, firms should learn to allow customers and Internet users to post user-generated content (e.g. online comments, product reviews, etc.), also known as "earned media", rather than use marketer prepared advertising copy. While social media marketing is often associated with companies, as of 2016, a range- of -not -for- profit organizations and government organizations are engaging in social media marketing of their programs or services.*

**Keywords: Social Media, Twitter, Face book, Google+, Blog, LinkedIn**

### Introduction

Social networking websites allow individuals businesses and other organizations to interact with one another and build relationships and communities online. When companies join these social channels, consumers can interact with them directly. That interaction can be more personal to users than traditional methods of outbound marketing and advertising<sup>[6]</sup> Social networking sites act as word of mouth or more precisely, word of mouth. The Internet's ability to reach billions across the globe has given online word of mouth a powerful voice and far reach. The ability to rapidly change buying patterns and product or service acquisition and activity to a growing number of consumers is defined as an influence network. Social networking sites act as word of mouth or more precisely, word of mouth. The Internet's ability to reach billions across the globe has given online word of mouth a powerful voice and far reach. The ability to rapidly change buying patterns and product or service acquisition and activity to a growing number of consumers is defined as an influence network. Social networking sites and blogs allow followers to "rewet" or "repost" comments made by others about a product being promoted, which occurs quite frequently on some social media sites. By repeating the message, the user's connections are able to see the message; therefore reaching more people. Because the information about the product is being put out there and is getting repeated, more traffic is brought to the product/company. Social networking websites are based on building virtual communities that allow consumers to express their needs, wants and values, online. Social media marketing then connects these consumers and audiences to businesses that share the same needs, wants, and values, Through social networking sites, companies can keep in touch with individual followers. This personal interaction can instill a feeling of loyalty into followers and potential customers. Also, by choosing whom to follow on these sites, products can reach a very narrow target audience. Social networking sites also include much information about what products and services prospective clients might be interested in. Through the use of new semantic analysis



technologies, marketers can detect buying signals, such as content shared by people and questions posted online. An understanding of buying signals can help sales people target relevant prospects and marketers run micro-targeted campaigns.

#### **Importance and Objectives of the Study:**

The greater promotional impact for retailers and manufacturers today is knowledge and insight. In order to maximize promotional effectiveness, organisation need to know what categories and what brand are being promoted, by whom, at what price point and how often they are changing. In this context, the following objectives are laid for studying the role of social media in promotional and marketing strategies.

- To present the various common social media components
- To know about the social marketing strategies
- Conclusion for effective social media marketing

#### **Material Method:**

This is the descriptive research paper base on secondary data. The literatures is collected from various journal, books, magazines, periodicals, various reports, publications of recent research papers available in different websites.

#### **Social Media Marketing Components**

**Twitter :-** Twitter allows companies to promote their products in short messages known as tweets limited to 140 characters which appear on followers. Home timelines. Tweets can contain text, Hash tag, photo, video, Animated GIF, Emboli, or links to the products' website and other social media profiles etc. Twitter is also used by companies to provide customer service. Some companies make support available 24/7 and answer promptly, thus improving brand loyalty and appreciation.

**Face book :**Face book pages are far more detailed than Twitter accounts. They allow a product to provide videos, photos, and longer descriptions, and testimonials as other followers can comments on the product pages for others to see. Face book can link back to the product's Twitter page as well as send out event reminders. As of May 2015, 93% of businesses marketers use Face book to promote their brand. A study from 2011 attributed 84% of "engagement" or clicks to Likes that link back to Face book advertising. By 2014, Face book had restricted the content published from businesses' and brands' pages. Adjustments in Face book algorithms have reduced the audience for non-paying business pages (that have at least 5000,000"Likes") from 16% in 2012 down to 2% in February 2014.

**Google+:** Google+, in addition to providing pages and some features of Face book, is also able to integrate with the Google search engine. Other Google products are also integrated, such as Google Ad words and Google Maps. With the development of Google Personalized Search and other location-based search services. Google+ allows for targeted advertising methods, navigation services, and other forms of location-based marketing and promotion. Google+ can also be beneficial for other digital marketing campaigns, as well as social media marketing. Google+ authorship was known to have a significant benefit on a website's search engine optimization, before the relationship was removed by Google. Google+ in one of the fastest growing social media networks and can benefit almost any business.

**LinkedIn :** LinkedIn, a professional business-related networking site, allows companies to create professional profiles for themselves as well as their business to network and meet others. [48] Through the use of widgets, members can promote their various social networking activities, such as Twitter stream or blog entries of their product pages, onto their LinkedIn profile page. LinkedIn provides its members the opportunity to generate sales leads and business partners. Members can use “Company Pages” similar to Face book pages to create an area that will allow business owners to promote their products or services and be able to interact with their customers. Due to spread to spam mail sent to job seeker, leading companies prefer to use LinkedIn foremployee’s recruitment instead using different a job portal. Additionally, companies have voiced a preference for the amount of information that can be gleaned from a LinkedIn profile, versus a limited email.

**Whatsapp:** WhatsApp was founded by Jan Koum and Brian Acton. WhatsApp joined Facebook in 2014, but continues to operate as a separate app with a laser focus on building a messaging service that works fast and reliably anywhere in the world. WhatsApp started as an alternative to SMS. Whatsapp now supports sending and receiving a variety of media including text, photos, videos, documents, and location, as well as voice calls. WhatsApp can read or listen to them. Whatsapp has a customer base of 1 billion people in over 180 countries. It is used to send personalised promotional messages to individual customers. It has plenty of advantages over SMS that includes ability to track how Messages Broadcast Performs using blue tick option in Whatsapp. It allows sending messages to Do Not Disturb (DND) customers. Whatsapp is also used to send a series of bulk messages to their targeted customers using broadcast option. Companies started using this to a large extent because it is a cost effective promotional option and quick to spread a message. Still, Whatsapp allow businesses to place ads in their app.

**Yelp :** Yelp consists of a comprehensive online index of business profiles. Businesses are searchable by location, similar to Yellow Pages. The website is operational in seven different countries, including the United States and Canada. Business account holders are allowed to create, share, and edit business profiles. They may post information such as the business location, contact information, pictures, and service information. The website further allows individuals to write, post reviews about businesses, and rate them on a five-point scale. Messaging and talk features are further made available for general members of the website, serving to guide thoughts and opinions.

**Foursquare :** Foursquare is a location - based social networking website, where users can check into locations via a Swarm app on their smart phones. Foursquare allows businesses to create a page or create a new/claim an existing venue.

**Instagram :** In May 2014, Instagram had over 200 million users. The user engagement rate of Instagram was 15 times higher than of Face book and 25 times higher than that of Twitter. According to Scott Galloway, the founder of L2 and a professor of marketing at New York University’s Stern School of Business, latest studies estimate that 93% of prestige brands have an active presence on Instagram and include it in their marketing mix. When it comes to brands and businesses, Instagram’s goal is to help companies to reach their respective audiences through captivating imagery in a rich, visual environment. Moreover, Instagram provides a platform where

user and company can communicate publicly and directly, making itself an ideal platform for companies to connect with their current and potential customers.

**YouTube :** YouTube is another popular avenue ;advertisements are done in a way to suit the target audience. The type of language used in the commercials and the ideas used to promote the product reflect the audience's style and taste. Also, the ads on this platform are usually in sync with the content of the video requested, this is another advantage YouTube brings for advertisers. Certain ads are presented with certain videos since the content is relevant. Promotional opportunities such as sponsoring a video is also possible on YouTube," for example, a user who searches for a YouTube video on dog training may be presented with a sponsored video from a dog toy company in results along with other videos." YouTube also enable publishers to earn money through its YouTube Partner Program. Companies can pay YouTube for a special "channel" which promotes the companies products or services.

**Blogs :** Platforms like LinkedIn create an environment for companies and clients to connect online. Companies that recognize the need for information, originality/ and accessibility employ blogs to make their products popular and unique / and ultimately reach out to consumers who are privy to social media. Studies from 2009 show that consumers view coverage in the media or from bloggers as being more neutral and credible than print advertisements, which are not thought of as free or independent. Blogs allow a product or company to provide longer descriptions of products or services, can include testimonials and can link to and from other social network and blog pages. Blogs can be updated frequently and are promotional techniques for keeping customers, and also for acquiring followers and subscribers who can then be directed to social network pages. Online communities can enable a business to reach the clients of other businesses using the platforms. To allow firms to measure their standing in the corporate world, sites enable employees to place evaluations of their companies. Some businesses opt out of integrating social media platforms into their traditional marketing regimen. There are also specific corporate standards that apply when interacting online. To maintain an advantage in a business-consumer relationship, businesses have to be aware of four key assets that consumers maintain: information, involvement, community, and control.

**Timber :** Blogging website Timber first launched ad products on May 29, 2012. Rather than relying on simple banner ads, Timber requires advertisers to create a Timber blog so the content of those blogs can be featured on the site. In one year, four native ad formats were created on web and mobile and had more than 100 brands advertising on Timber with 500 cumulative sponsored posts.

### **Benefits of Social Media Marketing**

1. **Increased Brand Recognition :** Every opportunity you have to syndicate your content and increase your visibility is valuable. Your social media networks are just new channels for your brand's voice and content. This is important because it simultaneously makes you easier and more accessible for new customers, and makes you more familiar and recognizable for existing customers. For example, a frequent Twitter user could hear about your company for the first time only after stumbling upon it in a newsfeed. Or, an otherwise apathetic customer might become better acquainted with your brand after seeing your presence on multiple networks.

2. **Improved brand loyalty :** According to a report published by Texas Tech University, brands who engage on social media channels enjoy higher loyalty from their customers. The report concludes “Companies should take advantage of the tools social media gives them when it comes to connecting with their audience. A strategic and open social media plan could prove influential in morphing consumers into being brand loyal.” Another study published by Convince & Convert found that 53% of Americans who follow brands in social are more loyal to those brands.
3. **More Opportunities to Convert :** Every post you make on a social media platform is an opportunity for customers to convert. When you build a following, you’ll simultaneously have access to new customers, recent customers, and old customers, and you’ll be able to interact with all of them. Every blog post, image, video, or comment you share is a chance for someone to react, and every reaction could lead to a site visit, and eventually a conversion. Not every interaction with your brand results in a conversion, but every positive interaction increases the likelihood of an eventual conversion. Even if your click-through rates are low. The sheer number of opportunities you have on social media is significant. And as I pointed out in my article, “The Four Elements of Any Action. And How To Use Them In Your Online Marketing Initiative,” opportunity” is the first element of any action.
4. **Higher conversion rates :** Social media marketing results in higher conversion rates in a few distinct ways. Perhaps the most significant is its humanization element: the fact that brands become more humanized by interacting in social media channels. Social media is a place where brands can act like people do. And this is important because people like doing business with other people: not with companies.

### Conclusion

Social media marketing (SMM) is a form of Internet marketing that utilizes social networking websites as a marketing tool. The goal of SMM is to produce content that users will share with their social network to help a company increase brand exposure and broaden customer reach. One of the key components of SMM is social media optimization (SMO). Like search engine optimization (SEO), SMO is a strategy for drawing new and unique visitors to a website. SMO can be done two ways: adding social media links to content, such as RSS feeds and sharing buttons -- or promoting activity through social media by updating statuses or tweets, or blog posts. SMM helps a company get direct feedback from customers (and potential customers) while making the company seem more personable. The interactive parts of social media give customers the opportunity to ask questions or voice complaints and feel they are being heard. This aspect of SMM is called social customer relationship management (social CRM). SMM became more common with the increased popularity of websites such as Twitter, Facebook, MySpace, LinkedIn, and YouTube. In response, the Federal Trade Commission (FTC) has updated its rules to include SMM. If a company or its advertising agency provides a blogger or other online commenter with free products or other incentives to generate positive buzz for a product, the online comments will be treated legally as endorsements. Both the blogger and the company will be held responsible for ensuring that the incentives are clearly and conspicuously disclosed, and



that the blogger's posts contain no misleading or unsubstantiated statements and otherwise complies with the FTC's rules concerning unfair or deceptive advertising.

**References:**

*Barwise, Pratik; Meehan, Sean (2010), \_New social media possibilities, Harvard Business Review, Vol 88 I*

*Boyd, D. M. and Ellison, N B (2008), \_ Social networks Sites: Definition, History and Scholarship, Journal of computer –Mediated Communication 210-230*

*Mangold G. W. and Faulds David, J. (2009), \_Social media: The new hybrid element of the promotion mix, Business Horizons 52, 357-365*



## SYMBOLIC APPLICATIONS ON LEGACY DATA IN LIBRARIES

**Prof. Vijay Malekar**

Librarian,  
Janta College of Education,  
Chandrapur

**Dr. D. W. Deote**

Librarian,  
Bar. Sheshrao Wankhede Mahavidyalaya,  
Mohpa, Dist. Nagpur

Today in the Web environment we are surrounded by data. So, if we want to make our data discoverable in the present scenario, we have to make it machine processable and this can be achieved from Semantic Web Technology. A more refined way to this is Linked Data. A large amount of data is available in different file formats other than RDF also known as Legacy Data and this provides a framework to achieve Linked Data. So, we have to convert them to RDF for publishing the as Linked Data. This paper tries to explain the Linked Data technology stack and its working principles, highlighting some of its use cases on bibliographic data. This paper intends to propose an approach to apply these principles on the bibliographic data of Indian Statistical Institute's Hostel Library. Finally it concludes with a comparison of used technique and need for Linked Data in general with particular emphasis for libraries.

### Introduction

The evolution of Semantic Web from Syntactic Web has made data on the Web machine processable. Despite All the progress made, one of the biggest challenges towards the use of semantics is the lack of background knowledge. Capturing this background knowledge is a tough problem to deal with due to the nature of knowledge. Knowledge does not have one uniform description. Everyone has a different perception of a particular knowledge. And here we are trying to capture this multidimensional knowledge, which is vast in terms of size, continuum and dynamic in nature and has diverse source. Moreover, we want it to be of high quality and contextually relevant. Glunchiglia and Dudtta For encountering this difficulty, have proposed and adapted the faceted approach, well-established methodology used in the field of Library Science for knowledge organization in libraries and came up with DERA, a new faceted knowledge representation approach. This provides the solution for the development of Descriptive Ontology, which allows scaling to the ever growing knowledge. So, DERA methodology can be applied in building ontology for domains, as evident from the papers on the subject. But developing ontology from scratch is an extremely time-consuming, costly, error-prone-task and it is therefore fundamental to reuse existing resources. This can be achieved by connecting or linking related concepts or entities from various datasets available as a giant network of interconnected resources, the Linked Open Data Cloud (Linked Data Connect Distributed Data Across the Web, 2014). This enables different applications to interoperate and share their data. However for integrating datasets, purpose should be taken into account and make explicit the semantics (Maltese and Farazi, 2011). Typically it can be achieved by mapping between their terms/concepts.

### Barriers and Motivation

We all understand the importance of data and being a library and information science professional, our job is to make best use of raw data and to make it information. In this dynamic, Web environment the role of libraries is also changing. The bibliographic data



painstakingly created by libraries are highly-structured and of high quality. If we want to make our data visible, reusable and discoverable in the present scenario, we have to make it machine processable. This can be attained by using Semantic Web techniques with Linked Data principles. So, in this paper an approach to apply these principles on the bibliographic data of our Hostel Library by annotating tabular data using Open Refine and publishing legacy data as Linked Data using Linked Media Framework has been taken. The basic assumption behind this is that there is increase in value and usefulness of datasets when interlinked with other dat.

### **Structural Plan of the Document**

This paper is organized as follows: The paper begins with the introduction of the problem of discourse and motivation behind it. Section 2 presents Semantic Web architecture with emphasis on Linked Data and its evolution, need, technology stack and working principles. Section 3 presents the State-of-Art and some of the emblematic use cases of Linked Data in context of libraries. Section 4 will talk about the solution for annotating text as Linked Data and ways of publishing legacy data as Linked Data. Finally, Section 5 will lead to conclusion of the work with future work and final remarks.

### **Semantic Web and Linked Data**

This section will provide a description of the Semantic Web. Here, Semantic means ‘meaning’ and Web means several documents, connected with each other via hyperlinks. These documents are Web pages containing data, understandable and processable by humans. Whereas, Semantic Web means the meaningful Web where data present in the Web pages are also processable by machines. In this way machines would be able to interpret and understand the meaning of data in a Web page and will present the user with the relevant information. As explained “The Semantic Web is not a separate Web but an extension of the current one, in which information is given well-defined meaning, better enabling computers and people to work in cooperation”, so briefly, we can say that, the Semantic Web enables us to express data as well as rules for reasoning about the data.

### **Linked Data**

Linked data is just an addition of one more facet to the Semantic Web, i.e. publishing and connecting data with related data. So, we do not have to search for related concepts; rather machines will provide it for us. This publishing of structured data on the Web is based on a set of guiding principles, to interlink data making a Web of Documents to a Web of Data. In the following sub-sections, we will have the various aspects of Linked Data since its evolution to its working principles.

### **Evolution of Linked Data**

The growth and development of the Linked Data can be traced way back with the invention of Web. Initially, Web has the HTML pages which are mainly made up as ASCII and images. It was syntactic in nature with human clickable hyperlinks which humans have to understand and then click to navigate for one page to the other. This was popularly known as Web of documents. After this came the Semantic Web or Web 3.0, where data becomes machine processable.

Now, machines can understand the data and able to understand Jaugau as an animal and a car. Adding one more facet to Semantic Web, i.e. connecting related data, gave birth to Linked Data.

### **Need for Linked Data**

The rationale behind the Linked Data is the need for enhancing re-usability, fundability and visibility of our data. In order to achieve this several approaches were adopted. Prime among them are Micro formats and Web APIs. But they have some shortcomings like Micro formats were meant to represent data about a small set of various entities. Further, Web APIs were with vendor-locked interfaces and most do not have global unique identifiers for entities, so we cannot set hyperlinks between entities of different Web APIs. Web APIs thus slice the Web into separate data silos making data sets isolated, unconnected but with linked data related concepts can be joined. Moreover, machines would be able to do the processing.

### **Linked Data Working Principles**

Linked Data working principles are a set of best practices that have been designed for publishing and interlinking related data on the Web in a way that it becomes part of a unified global data set. According to these rules by Tim Berners-Lee, every entity must have a Uniform Resource Identifier (URL) that, when followed up should provide useful information, using standards like RDF and SPARQL. Along with these, the entity must be linked to other related concepts so that more entities can be discovered. Now the principles says we must use URIs as names for things, so here we represented people with URLs, then we must provide information using standards like RDF, so here concepts are in the form of triples with subject, predicate and object. Finally, it says to include links to other related entities, so that they can discover more things. To here we have linked it with location of the figures to get more related information.

### **Linked Data vs Linked Open Data**

According to Tom Heath, not all Linked Data will be open, and not all Open Data will be linked. So there is an important difference between these two terms; Linked Data is the data which is linked with other related datasets but is not open to reuse, whereas the Linked Open Data is the data which is linked as well as published under an Open License to reuse.

### **Symbolic Use Cases of Linked Data in Libraries**

This section covers some use cases and case studies from the library community and associated areas collected and analyzed by W3C Library Linked Data Incubator Group. These use cases and case studies reflect the possible benefits of Linked Data technologies in describing library resources with explicit semantics and linking to related entities from other sources. Almost all applications described use, one way or another DBpedia. Use of Linked Data in Libraries can be subdivided into the following groups.

### **Classification Systems**

#### **Dewey Decimal Classification (DDC)**

DDC uses Linked Data principles to provide its data as a small “terminology service”. DDC has used these principles to assign URLs, not only for single classes but for every concept and these

could be de-referenced back to obtain information about concepts in both human-readable as well as machine processable. Data can be accessed through SPARQL endpoints and will be reusable for non-commercial purposes under Creative Commons license. Its classification semantics are encoded using SKOS and are available in different serialization formats (RDF/XML, TSurtle, ISON).

#### **Universal Decimal Classification (UDC)**

The Universal Decimal Classification (UDC) is a multilingual classification scheme for all fields of knowledge with sophisticated indexing and retrieval mechanism. UDC Summary data is available in SKOS (XML/RDF) format. Linked Data has been used to interlink and make cross-references to make it more useful for both humans and computers.

#### **Library of Congress Subject Headings (LCSH)**

LCSH has an extensive list of subject headings available in print as well as Linked Data. Subject authority headings can be accessed through the Library of Congress Authorities and Vocabularies Service.

#### **Eurovoc**

Eurovoc is a multilingual, multidisciplinary thesaurus which covers activities of the European Union, the European Parliament in particular. It covers terms in 24 language.

#### **WorldNet 3.0**

WorldNet is a lexical database of English language for nouns, verbs, adjectives and adverbs which are grouped as a collection of Synsets. Linked Data principles have been applied to interlink Synsets using conceptual-semantic and lexical relation between them. Its Linked Data version has been published by the Vrije Universiteit, Amsterdam.

#### **WorldCat – OCLC**

OCLC WorldCat uses Linked Data to make its catalogue records available through search engines like Google. This has been done by mapping its records with the schema developed by Schema.org and launched by Google, Bing, Yahoo to create and support a common set of schemas for structured data mark-up on Web pages.

#### **BIBFRAME – Library of Congress**

BIBFRAME is a project undertaken by the Library of Congress to better accommodate the future-requirements of the library community. The major focus of the initiative will be determine a transition path for the MARC 21 exchange format to more Web based. Linked Data standards.

#### **Proposal**

This paper intends to propose an approach to apply the principles of Linked Data on the bibliographic data of the Indian Statistical Institute's Hostel Library, by publishing legacy data as Linked Data using OpenRefine and Linked Media Framework. Finally it concludes with comparison of used techniques with an automatic Conversion tool, i.e. Csv2Rdf on the same data set and need for Linked Data in general with particular emphasis for libraries.

#### **Requirements**

This paper is based on the use of Open Source Software to accomplish the desired goal of annotating text and linking legacy data. The software used are as follows :

➤ **Google Refine 2.5**

Google Refine is a free, open source, power tool used for cleaning messy data and linking it to databases like Feedback, DBpedia, and Europeana with the help of respective SPARQL endpoints. It supports several import formats such as CSV, RDF/XML, Notation 3 and export formats like CSV, Excel, HTML Table, RDF/XML. It is available for Windows, Linux and Mac based operating systems.

➤ **Linked Media Framework (LMF) 2.2.0**

Linked Media Framework is a server application which supports central Semantic Web technologies such as : LMF Core. This has the Linked Data Server that allows exposing data following the Linked Data Principles and LMF Modules. It is used to extend the functionality of the Linked Media Server. LMF can be used in publishing Legacy Data as Linked Data and building Semantic : Search Over Data **Solution Architecture for Linking Legacy Data**

To implement the project bibliographic data from our Hostel Library is collected. Data available in CSV format is imported into the Google Refine and the concepts are mapped with the desired data-set. This process of mapping data-sets in Google Refine is known as reconciliation service. Mostly this reconciliation will happen automatically, sometimes manual checking is required if there is any ambiguity due to polysemy and homonymy by opening the hyperlinks and verifying which sense of the Concept is required for the project. After this, data in columns are described and the relationship between them is explicitly established with standard vocabularies in the triple form as Subject, Object and Predicate. Finally, data is exported in the required format.

➤ **Csv2rdf Converter**

Annotating the text using Csv2rdf, an automatic conversion tool can be achieved using below by copying the link location of the CSV file from the Hostel Library website. Then we provide the address of the CSV file to CSV2rdf. After this output, The RDF/XML file is generated and we can publish it in a similar manner using LMF.

**Evaluation Methodology**

The evaluation of the proposed project will be done by comparing the output files of both the adopted techniques for annotating the tabular form of data obtained from the Hostel Library in CSV format. We will examine each output by considering the fact better and the semantics explicitly described using standard vocabularies like OWL, FOAF Dublin Core etc. efficiently the data can be processed by machines. So, that machine can fetch more Linked Data to a concept or resource from the LOD.

**Conclusions**

This paper addresses a vital issue about the nature of data and investigated into several techniques to handle it in the Semantic Web era. As we know bibliographic data painstakingly created by libraries are highly-structured and of high quality. So, if we want to sustain the present scenario, we have to make it machine processable following Semantic Web techniques

with Linked Data principles. The development in this regard is visible from the increasing number of data-sets available on LOD since its inception in 2007 and from various applications developed following Linked Data principles. Applying these Linked Data principles on bibliographic data brings related data available on the LOD. This work draws a comparison between the two techniques used after examining the Output files from both the used techniques; that the RDF/XML files generated by Google Refine though semi-automatic, i.e. need human intervention if any ambiguity arises but is rich in Semantics as it is better described using standard vocabularies, whereas, the csv2rdf lacks this. So, it can be concluded that the machine can process and infer things to fetch Linked Data from LOD in a better way on the result set obtained from Google Refine. Future work would be to extend this technique to enable Semantic Search over data using a SKOS Thesaurus for information Extraction.

### References

1. <http://www.oclc.org/data.en.html>.
2. <http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html>.
3. <http://eurovoc.europa.eu/drupal/>.
4. <http://paanchiweb.blogspot.pt/2012/12/getting-essence-of-semantic-web.html>.
5. <http://www.w3.org/2005/incubator/lld/XGR-lld-usecase-20111025/>.
6. <http://id.loc.gov/>
7. <http://www.loc.gov/bibframe/pdf/maecld-report-11-21-2012.pdf>.
8. <http://linkeddata.org>.
9. <http://dewey.info/>
10. [http://semanticweb.org/wiki/Linked\\_Media\\_Framework](http://semanticweb.org/wiki/Linked_Media_Framework).
11. Ranganathan, S. R. Prolegomena to library Science. Third. New Delhi: Ess Ess, 2006.
12. <http://udcdata.info/>
13. <http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn>

## The Effective Communication Process - The Life Blood Of The Organization

**Dr. Prashant M. Puranik**

Gurukul Arts, Commerce & Science College,  
Nanda, Tal: Korpana, Distt: Chandrapur.  
9860461574 (M)

Email Id : Prashantpuranik1970@gmail.com

### ABSTRACT:

India is a developing country and having three major sectors. First sector is known as Agriculture Sector, Second sector is called as Industrial sector and third sector is called as Commerce or Service sector. From last few decades India is very well known for its immensely developing Industrial growth. So, we are going to make ourselves worthy to make competitions in this cutthroat competition in this global Scenario. For the allover development of the organization, there are various factors due to which we are ready to face these competitions. Some of the important factors are excellent strategic planning, excellent decision making process, excellent selection as well as recruitment process, excellent decision making process, excellent co-operation as well as co-ordination between employees and employer, excellent selection of well educated, talented, skillful and experienced employees, excellent work of the HRD department by providing on the job and off the job training, excellent feedback process from the employees, excellent motivational process etc. But among these all the functions there is one of the major function which is always needed in all the organizations – The function of Effective Communication. It is the most important function among all these functions because in all the management function there must be an effective and two way communication without which it is not possible to convey the messages from Top level To Bottom Level and also from Bottom level To Upward Level. So, effective communication plays an important role in the Success of the Organization

**KEYWORDS:** Resists, Feedback, chalk out, counselling, workforce

### INTRODUCTION:

Today's world is very competitive. There is a tremendous competition in every sphere of the society. Though it should be political, Social or ethical, there is a high competition is going on. There is a tough competition in the different organizations also. As far as the Organizational Structure of any Industry is concerned it is clear that, there are two main pillars on which the whole organization structure is resists – Employees and Workforce or Manpower. These two factors are also called as 'An Asset of the Organization'. Because these factors are directly related with the production as well as administrative process. So it's the duty of the Top Management to maintain better relations with the employees as well as workers. The Communication plays a very important role for this. That's why it is very necessary to know the meaning of 'Communication'.

### CONCEPT OF COMMUNICATION:

'Communication' is a word consists from the latin word 'communicare'. The meaning of communicate is to share. It is an act of conveying message from one group to another. This



message should be either in form of Orders, Instructions, Direction, Feedback, Complaints etc. from one man to another or the one group of persons to another.

#### **ORGANIZATIONAL COMMUNICATION:**

Organization is the governing body consists of various departments viz, Personal Department, Stores Department, Dispatch Departments, Financial Departments, Quality Control Department, Accounts Department, Sales Department, Raw Material Department, Maintenance Department etc. All these departments are directly or indirectly interrelated with each other. These departments have to convey important messages with each other. While conveying these messages they have to follow the orders of the Top Management. This all the process is called as 'Organizational Communication'.

#### **ORGANIZATIONAL COMMUNICATION MEDIA:**

There are lots of small, medium and big groups of working personnel in an Organization. So, it is not possible to give the orders to these groups at once as well as one by one. It is so because all the instructions and orders given to these groups are vary from each other. To convey these information from the different groups, it is necessary to take help of different tools or resources or medias which are so called as 'Organizational Communication Media'.

#### **IMPORTANCE OF EFFECTIVE COMMUNICATION IN THE ORGANIZATION:**

This is a competitive world. In this world there is a cutthroat competition is going on in the every Market, though it may be Rural Market, Urban Market, National Market or International Market. That's why it is necessary for every organization to maintain the excellent co-operation as well as co-ordination between the various departments in the organization. Because due to effective communication its possible to maintain the quality of the production.

Every Organization is having various departments and also having various levels i.e. Top Level, Medium Level and Top level Management. The Top level Management always gives Important Orders to the Down level employees. But it's responsibility of the Top level Management to know the problems of the employees, to identify the depth of the problem and to Chalk out the various solutions for that problem. It's possible only due to Effective Communication.

Due to Effective Communication it's possible to know the exact situation of the Business. Because in an organization every departments are directly or indirectly co-related with each other. That's why whenever the Top Management want to know the current position of the Business, every department has to give the important data to the Accounts and Financial Departments. To collect this information from various departments Effective Communication must be needed. Effective Communication is needed to chalk out the Business Strategies. There are various policies available for this. It's possible to implement the proper strategic planning by the help of Effective Communication.

Every Organization has its predetermined goals. These goals are to be achieved by all levels of management. To achieve these goals it's must be necessary that there should be excellent and Two way Communication in the organization.

Top executives always give important instructions to their subordinate employees. They should expect that, the work should be done properly in specific period. But Sometimes due to their negligence it's possible that there should take long time to complete the particular work. To

complete this work in proper time, Counselling technique should be the exact remedy. For all this process the function of Effective Communication plays a very important role.

Though the Organization should be big, medium or small but, the image or popularity of the organization is depend on its goodwill. But one should not forget the importance of the free Communication process in the organization. Because the free Communication process the doubts of the employees should be rectify which should help them to do their work in a very easy manner. Effective Communication is also useful for the creation of Goodwill of the Organization.

In the organization there are lot of departments having lot of employees and top executives. The top executives always give the lot of orders to the employees. It is a continuous process. There should not be any type of gap in giving these orders. As for the proper use of manpower, it's necessary to convey messages to the employees. Because employees are the main source by which Top Management can fulfill the objectives of the organization.

The Employees and Workforce are the two pillars on which the whole Management Structure is resist. Most of the time due to continuous process it is not possible to get work done from the employees. To get work done from the employees it is very necessary to motivate them. To make them prepare for the motivation it is necessary to maintain effective communication.

#### **CONCLUSION:**

This is a competitive world. Today there are various sectors in which High Competition is going on; i.e. Economic, Social, Political, Industrial, and Ethical etc. But as far as the Organization is concerned, it is very necessary to maintain effective communication. There are various departments available in the organization which is directly or indirectly interrelated with each other. There must be a co-operative relations within these departments. Moreover there are various managerial functions due to which the organizations predetermined goals are to be achieved. Such as Strategic Planning, Co-ordination, Selection and Recruitment, Direction, Reporting, Marketing Research etc. For the fulfillment of all these functions Effective Communication must be needed. So, Communication is the important function of the management by which India can make its effective Industrialization growth and by this India will prove himself as a superpower of the century.

#### **BIBLIOGRAPHY**

1. [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)
2. Samajik Sanshodhan Paddhati : Bodhankar Sudhir, Aloni Vivek, Sainath Prakashan, Nagpur.
3. Industrialization of India : Dr. Muzumdaar Shubhangi, Omkar prakashan, Indore
4. Communication Process : Prof. A. D. Adwani, S. R. Munjekar, Rajani Prakashan, Aurangabad
5. Organizational Communication : Prof. Tyagi Virat, Sur Anupama, Nandini Prakashan, Pune

## स्मरण प्रतिमान व संकल्पनाप्राप्ती प्रतिमानाची माध्यमिक स्तरावर परिणामकारकता –एक प्रायोगिक अध्ययन

आर. एम. माणुसमारे

**संक्षिप्त:-** आजच्या स्पर्धेच्या युगात विद्यार्थ्याला जास्तीत जास्त शिकविलेले घटक आपल्या स्मरणात ठेवून त्याचा वापर योग्य त्या ठिकाणी वेळोवेळी करावा लागतो. माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांना कठीन वाटणारा गणित विषय स्मरणात राहावा याकरिता शिक्षकाला विविध क्लुदया वापराव्या लागतात.त्याकरीताच हॅरी लॉरेन व जेरी ल्युकस यांनी स्मरण प्रतिमानाची निर्मिती केली आहे. या प्रतिमानाच्या आधारे गणित विषयाबद्दलची विद्यार्थ्यांना वाटणारी भिती दूर करून त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणे व गणित विषयाचा निकाल उंचावणे हा प्रमुख हेतु ठेवून त्यांना व्यावहारिक जिवनात यशस्वीरित्या पदार्पण करण्याकरिता प्रोत्साहित करण्याकरीता संशोधन अभ्यासण्याची गरज भासली याकरिता माध्यमिक स्तरावरील इयत्ता 9वी. च्या भूमिती पाठ्यपुस्तकातून त्रिकोणमिती घटक अभ्यासण्याचे ठरविले. संशोधन विषय अभ्यासण्याकरिता प्रायोगिक पद्धती अंतर्गत मार्गदर्शक तथा तज्ज्ञांकडून तपासलेली स्व : निर्मिती पूर्वचाचणी व उत्तरचाचणी संशोधन साधन म्हणून वापरली. माहितीचे संकलन व विश्लेषण सांख्यिकीय प्रविधीद्वारे केल्यावर असे आढळून आले की विद्यार्थी स्मरण प्रतिमानामध्ये पूर्वचाचणीपेक्षा उत्तरचाचणीमध्ये प्रगत आहेत.संशोधनाअंती प्राप्त झालेले मूल्य 8.54 हे 0.01 स्तरावर सार्थक आहे. तसेच संकल्पनाप्राप्ती प्रतिमानामध्ये पूर्वचाचणीपेक्षा उत्तरचाचणीमध्ये प्रगत आहेत. संशोधनाअंती प्राप्त झालेले मूल्य 4.73 हे 0.01 स्तरावर सार्थक आहे.

आजच्या धकाधकीच्या जिवनात प्रत्येक गोष्ट व्यक्तीच्या स्मरणात राहणे अवघड आहे परंतु अशक्य नाही. विद्यार्थी देखील या सर्व परिस्थितीशी सामना करीत असतात. संपूर्ण अभ्यास विषय जास्तीत जास्त चांगल्याप्रकारे लक्षात राहण्याकरिता शिक्षणतज्ञांनी स्मरण प्रतिमानाची रचना केली आहे.

माध्यमिक स्तरावरिल विद्यार्थी हा जिवनाभिमुख असतो त्याला आपल्या व्यवहारात, दैनंदिन जिवनात गणिताचा वापर करावा लागतो. म्हणूनच माध्यमिक स्तरावर गणिताचा फार महत्व दिल्या गेले आहे.

माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या निकालाचे निरीक्षण केल्यावर असे आढळून आले की विद्यार्थी गणित विषयात इतर विषयांपेक्षा मागे आहेत. विद्यार्थ्यांना गणित विषयाची वाटणारी भिती,त्यांना गणित विषयात उदाहरणे सोडवितांना येणा-या समस्या,त्यांना न समजणा-या घटकांचा अभ्यासकरून त्यांच्या मनातील गणित विषयाबद्दल याना असणारी भिती दूर करणे, त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण करण्याची गरज आहे.स्मरण प्रतिमानाद्वारे विद्यार्थ्यांमध्ये गणित विषयात रुची निर्माण करण्याकरिता संशोधन विषय अभ्यासण्याची आवश्यकता वाटली.

**प्रतिमान,** “अध्यापनाची प्रतिमाने म्हणजे वर्गातील अध्यापन व अध्यापनासाठीची वापरण्याचे साहित्य यांचे नियोजन करण्यासाठी वापरलेला आराखडा होय.” ब्रुस जॉयस व मार्शविल या अमेरिकन शिक्षणतज्ञांनी “Models of Teaching ” या पुस्तकात बावीस अध्यापन प्रतिमाने दिलेली आहेत.

स्मरण प्रतिमान हे ज्ञानप्रक्रियाकरण गटातील एक प्रतिमान असून त्याची रचना हॅरी लॉरेन व जेरी ल्युकस यांनी केली आहे. स्मरण म्हणजे स्मृती,आठवण होय.

स्मरण प्रतिमानाची परिणामकारकता माध्यमिक स्तरावरील गणित विषयात अभ्यासायची असल्यामुळे इयत्ता 9 वी.तील गणित विषयातील भूमिती पाठ्यपुस्तकातून त्रिकोणमिती हा घटक अभ्यासासाठी निवडला आहे. या पाठावर पारंपारिक पद्धतीपेक्षा स्मरण प्रतिमानाची प्रभावीकता व परिणामकारकता अभ्यासाची आहे.

**संशोधन विषयाची चले :** – चंद्रपूर जिल्हातील संपूर्ण खाजगी विद्यालयातील इयत्ता 9वी.चे विद्यार्थी हे संशोधन विषयातील स्वाश्रयी चल असून त्यांच्या गणित विषयाच्या अध्यापनात स्मरणप्रतिमानची परिणामकारकता आश्रयी चले आहेत.

**संशोधनाची उद्दिष्टे:** –

1 गणित अध्यापनाचे पारंपारिक पद्धतीने अध्यापन करून पूर्व चाचणीची निर्मिती करणे.

2. स्मरण प्रतिमानावर आधारित इयत्ता 9 वी. च्या भूमिती अंतर्गत त्रिकोणमिती या घटकावर पाठ टाचण तयार करणे.
3. स्मरण प्रतिमानावरिल आधारित पाठाची परिणामकारकता अभ्यासण्यासाठी उत्तरचाचणीची निर्मिती करणे.
4. स्मरण प्रतिमानद्वारे विद्यार्थ्यांच्या संपादनात पडणा-या फरकाचा अभ्यास करणे.
5. संकल्पना प्रतिमानावर आधारित इयत्ता 9 वी. च्या भूमिती अंतर्गत त्रिकोणमिती या घटकावर पाठ टाचण तयार करणे.
6. संकल्पना प्रतिमानावरिल आधारित पाठाची परिणामकारकता अभ्यासण्यासाठी उत्तरचाचणीची निर्मिती करणे.
7. संकल्पना प्रतिमानद्वारे विद्यार्थ्यांच्या संपादनात पडणा-या फरकाचा अभ्यास करणे.
8. स्मरण प्रतिमान व संकल्पना प्राप्ती प्रतिमान यांच्या परिणामकारकतेची तुलना करणे.

**संशोधन परिकल्पना :** - स्मरण प्रतिमान व संकल्पना प्रतीमानाच्या आधारे अध्यापन केले असता विद्यार्थ्यांच्या संपादनात सार्थक फरक पडणार नाही.

**परिक्षेत्र व्याप्ती मर्यादा:** - संशोधन विषयांचे परिक्षेत्र चंद्रपूर जिल्हातील खाजगी माध्य. शाळा असून व्याप्ती मर्यादा 9 वी. च्या गणित अध्यापनातील स्मरण प्रतिमान याची परिणामकारकता पडताळून पाहणे आहे.

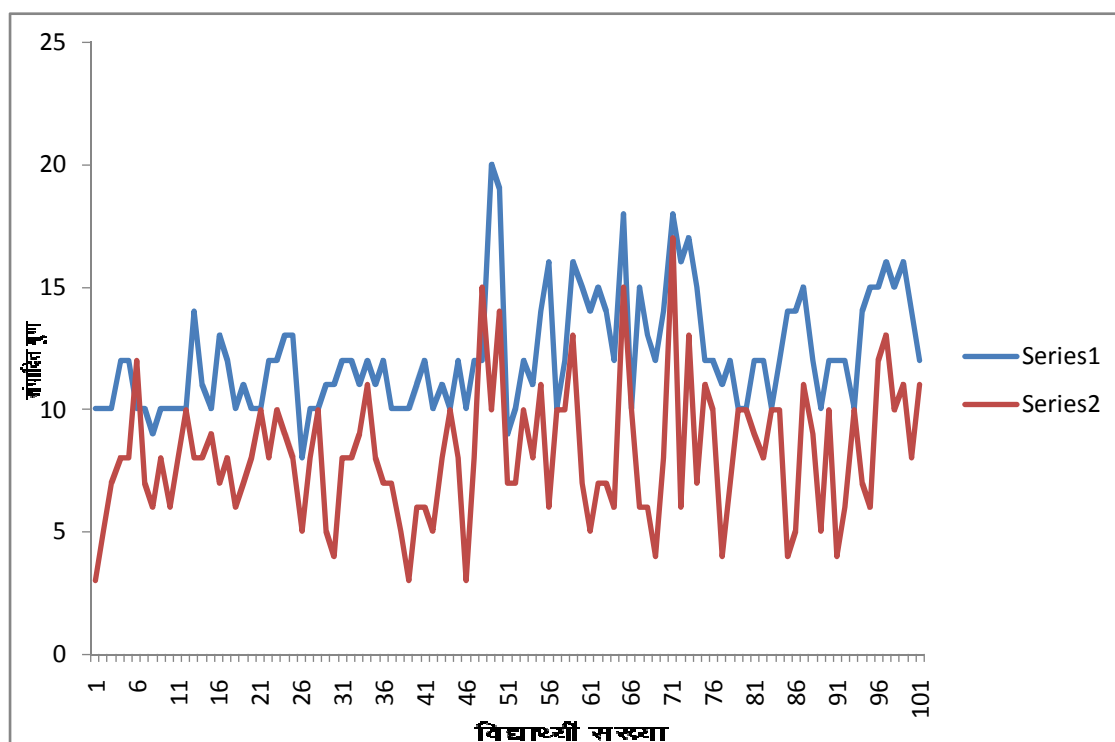
**संशोधन पद्धती व साधने :** - सदर संशोधन विषय अभ्यासण्यासाठी प्रायोगिक पद्धतीचा उपयोग केला असून स्व:निर्मित साधने मार्गदर्शक यांचे कडून तपासून वापरली आहे.

**जनसंख्या:** - ; चंद्रपूर जिल्हातील लॉटरी पद्धतीने निवडल्या गेलेल्या दोन खाजगी माध्य.विद्यालयातील इयत्ता 9वी.तील संपूर्ण विद्यार्थ्यां संशोधनाची जनसंख्या आहेत.

**न्यादर्श:** - विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक संपादनाच्या आधारे एकूण 100 विद्यार्थ्यांचा न्यादर्श म्हणून समावेश केला आहे.

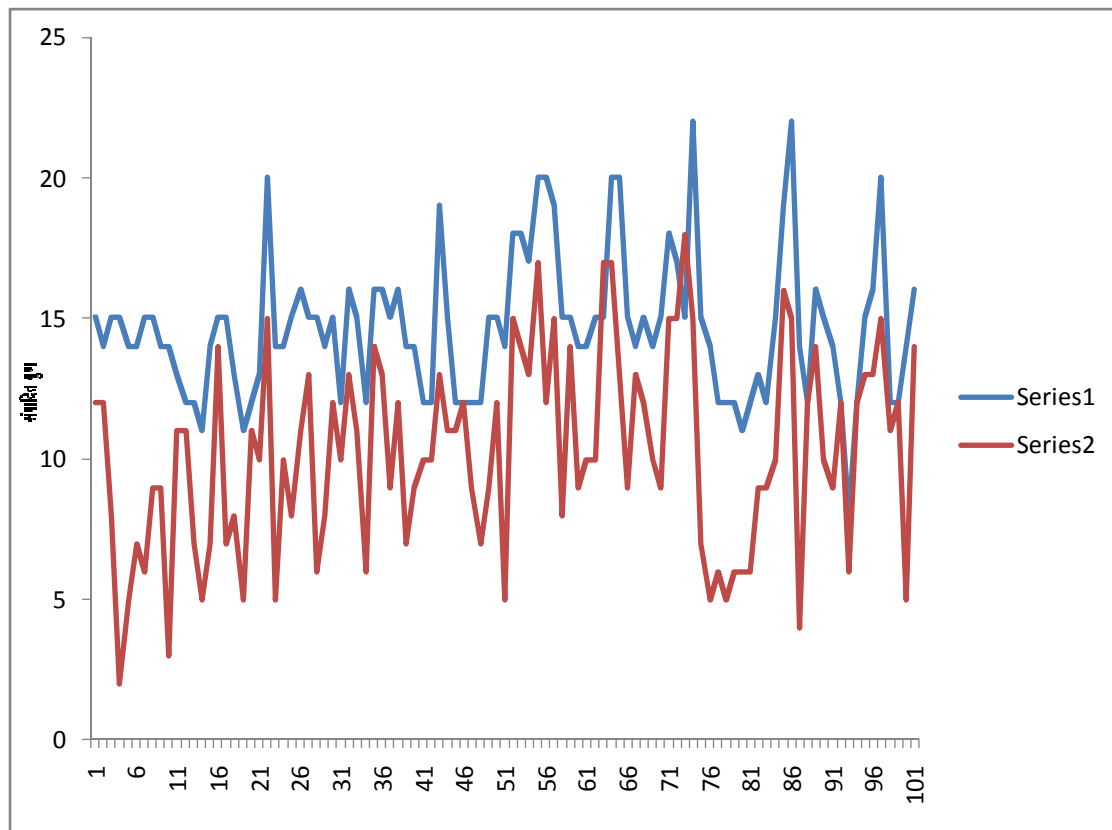
**संकलित माहितीचे विश्लेषण :** - संकलित माहितीचे विश्लेषण करण्याकरिता मध्यमान( $m$ ) व फरक( $t$ ) सांख्यिकीय प्रविधीद्वारे काढला आहे.

स्मरण प्रतिमान व संकल्पनाप्राप्ती प्रतिमान यांच्याद्वारे घेतल्या गेलेल्या पूर्वचाचणी द्वारे विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या गुणाकावरून खालील आलेख प्राप्त झाला.



### स्मरण प्रतिमान व संकल्पनाप्राप्ती प्रतिमानाची पूर्वचाचणीतील तुलना

स्मरण प्रतिमान व संकल्पनाप्राप्ती प्रतिमान याच्याद्वारे घेतल्या गेलेल्या उत्तरचाचणी द्वारे विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या गुणाकावरून खालील आलेख प्राप्त झाला.



स्मरण प्रतिमान व संकल्पनाप्राप्ती प्रतिमानाची उत्तरचाचणीतील तुलना

### निष्कर्ष : -

1. स्मरण प्रतिमानाची पूर्व चाचणी व उत्तर चाचणी यांची तुलना केली असता.प्राप्त मुल्य हे सार्थक आढळले. हा फरक सार्थक असल्यामुळे परिकल्पनेचा त्याग करण्यात येतो.
2. संकल्पनाप्राप्ती प्रतिमानाची पूर्व चाचणी व उत्तर चाचणी यांची तुलना केली असता, प्राप्त मुल्य सार्थक आढळले. हा फरक सार्थक असल्यामुळे परिकल्पनेचा त्याग करण्यात येतो.

### संदर्भ ग्रंथ सुची

आगलावे, प्रदिप (२००१)“ संशोधन पध्दती व तंत्रे ”

नागपूर,विद्या प्रकाशन

डॉ. वामन रंगनाथ पाटील, (डिसेंबर‘गणित ;अध्यापन शिक्षण पदविका’द्व

प्राचार्य ज्य. वा. भागवत २००५ )पुणे,नूतन प्रकाशन २१८१,सदाशिवपेठ

डॉ. फाडके वासंती(१९८८)“ अध्यापनाची प्रतिमाने ”

पुणे,नूतन प्रकाशन २१८१,सदाशिवपेठ

विद्या बेलसरे,(नोव्हेंबर “गणित(शालेय विषय :आशययुक्त अध्यापन ) ”

सतोष फुले २००५)पुणे, संविचार प्रकाशन मंडळ ४६१ / ४ सदाशिवपेठ



प्रा.सोहोनी शं. कृ.( १९९३ ) “ शैक्षणिक टिपा कोष ”  
पुणे, हिन्दुस्थान मुद्रनालय १४८२ शुक्रवारपेठ मंडई रस्ता, ४११०२  
डॉ. सप्रे , निलिमा, (फेब्रु. २००२) “ अध्यापनाची प्रतिमाने ”  
प्रा. पाटील , प्रीती कोल्हापूर , फडके प्रकाशन.  
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त — “ संकल्पनाप्राप्ती प्रतिमान ”  
विद्यापीठ, नाशिक  
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त — “ स्मरण प्रतिमान ”  
विद्यापीठ, नाशिक

Maharashtra State Board of 1<sup>st</sup> Edition “ Geometry ”  
Secondary & Higher Secondary 2006 ( Standard IX )  
Education, Pune – 411005 Reprint 2007  
Maharashtra State Board of 1<sup>st</sup> Edition “ Algebra ”  
Secondary & Higher Secondary 2006 ( Standard IX )  
Education, Pune – 411005 Reprint 2007  
Government College of Vol.3, “ GCTE JOURNAL  
Teacher Education, Research Issue ( 2 ) OF RESEARCH AND  
Centre In Education, Univ of July 2008 EXTENSION IN  
Kerala , Thycad , EDUCATION  
Thiruvananthapuram – 695014

Edutrack's	Feb. 2003	Jyoti Sharma
Edutrack's	Sept. 2003	Marlow Ediger
Edutrack's	April. 2004	S. Uma
Edutrack's	June 2004	Dr. P. Vimala Devi
Edutrack's	July 2004	Samson Chandradoss

### **Websites**

[http : // www.inflibnet.ac.in.,](http://www.inflibnet.ac.in.)  
[http : // www.infolibrarian.com.,](http://www.infolibrarian.com.)  
[http : // www.academicjournals.org/err/;](http://www.academicjournals.org/err/)  
[http : // www.ncte.org.,](http://www.ncte.org.)



## Chronic Mass Poverty in India - a Social Perspective

**Balasaheb A. Sarate**

Research Student in Economics  
Dr. Babasaheb Ambedkar  
Marathwada University  
Aurangabad (Maharashtra)

**Key Words :** Chronic mass poverty, Absolute Poverty, Tendulkar Committee, Rangarajan Committee, Democratic needs.

### Introduction:

The economic history of India, is actually the history of Planning Commission of India. Planning Commission was the Nodal Agency for estimation and eradication of poverty in India. The Approach Paper of Twelfth Plan<sup>1</sup> (2012-2017) speaks about the chronic problem of poverty as; "Reducing poverty is a key element in our inclusive growth strategy and there is some progress in that regard". The poverty in India is perpetuated since centuries ago. Hence, it can be called as the chronic poverty. Further, poverty in India is not individual, but it is a collective phenomenon. The segments, social groups, localities, communities are deprived of their minimum basic needs which constitute the masses under poverty. Since the appropriateness of the poverty line was questioned in some quarters, the Government appointed an Expert Committee under the Chairmanship of the Prof. Suresh Tendulkar. This Committee recommended a recalibration of the rural poverty line to make it more comparable with the urban poverty line, which it found to be appropriate. The Eleventh Plan (2007-12) and Twelfth Plan (2012-17) had set a more ambitious target of reduction in poverty ratio at least of 2 percentage points per year. However, the recent poverty estimates of Rangarajan Committee mentions as, there were 29.50 percentage (363 million) people of India living under the guise poverty. Thus, there is serious problem of chronic Mass poverty in India.

### Objectives Of the Study:

1. To study the methods of poverty estimation in India adopted by the Planning Commission.
2. To understand the nature and status of the chronic poverty in India.
3. To examine the approaches and policies of the Government for alleviation of poverty.
4. To suggest the practical remedial solutions for reduction in poverty in India.

### Methodology :

This paper contains an analytical study of the nature and status of poverty in India mainly based on the secondary data sought from the authentic reports of Planning Commission of India and from some renowned Books on Indian Economy available in public domain. In addition to that various Research Articles of Research Scholars are also referred for writing this Research Article.

### Meaning of Poverty:

Poverty means inability to fulfill even basic economic needs of life. When any individual, family or any group becomes unable to satisfy their basic needs due to lack of sufficient income

or resources. It means the people are deprived of means of Consumption and resources or income for a long time. When such situation arises frequently over a longer period, it becomes more critical to eradicate. If substantial segment of Society is deprived of the minimum stand of living is treated as Mass Poverty. Unfortunately, Indian masses come under the category of mass poverty. The Poverty in India is chronic in the case of the same segments of Society.

Indian economy has been facing the problem of 'chronic mass poverty' since centuries ago. The nature of poverty is chronic because the particular families, communities and segments of the people at large have been living under the poverty since many generations. Their poverty is determined by their place of birth in certain families, communities or areas. These masses remained poor because their forefathers were poor. Hence, it is termed as the chronic or unending poverty for those families, communities and segments of the people whose life is bound by continuous deprivation of basic human needs. The masses living in the hill areas, forest areas, boarder areas, rural areas and slum areas in the cities and towns have been the victims of poverty in India. Hence, it is the poverty of masses characterized by the place of birth and hereditary living conditions. In this situation, there is need to examine the utility of rapid GDP growth for legitimate reduction in such a chronic mass poverty.

C. Rangrajan (2014)<sup>2</sup>, in his preface to the report of the expert group, has stated that, "Growth is not the sole objective of economic policy. It is necessary to ensure that the benefits of growth accrue to all sections of the society. Eradication of poverty is thus an important objective. Human beings need a certain minimum consumption of food and non-food items to survive. However the perception regarding what constitutes poverty varies over time and across countries. Nevertheless there is need for a measure of poverty. Only then, it will be possible to evaluate how the economy is performing in terms of providing a certain minimum standard of living to all its citizens. Measurement of Poverty has, therefore, important policy implications".

It is stated in the Annual Report<sup>3</sup> (2013-14) that, "The Planning Commission ass the nodal agency for estimating the number and percentage of people living below the poverty line at the National Level and at State levels for rural and urban areas separately. It was estimating the poverty based on the large sample survey on Household Consumer Expenditure carried out by the National Sample Survey Office (NSSO) at an interval of five years. The methodology for estimation of poverty has been reviewed from time to time". (p.23)

The Annual Report<sup>4</sup> (2013-14) also states that, "The Planning Commission constituted an Expert Group under the Chairmanship of Prof. Suresh Tendulkar in Dec. 2005 which submitted its report in December, 2009. As per the Tendulkar Committee report, the national Poverty line at 2004-05 prices has been fixed as monthly per capita consumption expenditure of Rs.446.68 in the rural areas and Rs.578.8 in urban areas. These poverty lines vary from state to state because of price differentials. The poverty lines and poverty ratios for the year 2011-12 have been updated as per recommendations of the Tendulkar Committee using NSS 68th round (2011-12) data of Household Consumer Expenditure Survey and released poverty estimates for 2011-12 on 22nd July, 2013. According to these estimates, poverty line at all India level is estimated as Monthly per-capita Consumption Expenditure of Rs. 816 for rural areas and Rs. 1000 for urban areas in the year 2011-12". (p.23)

The Annual Report<sup>5</sup> (2013-14) further states that, “Based on the latest estimates of poverty released by the Planning Commission, poverty in the country has declined by 2.2 percentage points per year between the years 2004-05 and 2011-12. The incidence of poverty, or in other words, the percentage of people living below poverty line in the country declined from 45.3 per cent in 1993-94, to 37.2 per cent in 2004-05, and further to 21.9 per cent in 2011-12. During the 11-year period 1993-94 to 2004-05, the average rate of decline in the poverty ratio was 0.74 percentage points per year which further accelerated up to 2.18 percentage points per year, during the 7 years period from the year 2004-05 to 2011-12. This implies that the rate of decline in the poverty ratio during the most recent 7 years period 2004-05 to 2011-12 was almost about three times' that experienced in the 11-year period 1993-94 to 2004-05”. (p.23)

However, as per the report of Tendulkar Committee<sup>6</sup> (2009), the per cent of poverty for the years 2009-10 was 29.80 per cent and for the year 2011-12, the poverty was 21.90 per cent. Thus, the rate of declination of poverty from 2004-05 to 2009-10 was 1.48 per cent per annum and for the last two years the rate of declination was shown as 3.95 per cent per annum which was unbelievable itself. Therefore, questions were raised on the methodology of estimation of Poverty by Tendulkar Committee and thereby adjusting the Poverty line at very lowest level for the year 2011-12. Therefore, in June 2012, Planning Commission had constituted an Expert Group under the Chairmanship of Dr. C. Rangarajan to 'Review the Methodology for Measurement of Poverty'. The Expert Committee submitted its Report in June, 2014.

Mishra and Puri<sup>7</sup> (2015) states that, “The Tendulkar Committee (2009) has pointed out that the concept of Poverty is associated with socially perceived deprivation with respect to basic human needs. These basic human needs are usually listed in the material dimension as the need to be adequately nourished, the need to be decently clothed the need to be reasonably sheltered, the need to escape avoidable diseases, the need to be, at least) minimally educated and the need to be mobile for the purposes of social interactions and participation in economic activity. This shows that the concept of poverty is *multidimensional*. However, while measuring the actual Poverty line, the focus generally has been on the material dimensions and even in this respect, the focus is often on the terms of minimum consumption requirements”.(p.202).

Misra and Puri<sup>8</sup> (2015) have further stated that, “The all India Rural and Urban Poverty lines, anchored in the per capita calorie norms of 2400 (for Rural) and 2100 (for Urban), were originally defined in terms of per capita total consumer expenditure (PCTE) at 1973-74 market prices. The all India Poverty line so defined in 1973-74 was Rs. 49.63 for Rural areas and Rs. 56.64 for Urban areas. The all India Poverty line for 2004-05 adjusted for prices was Rs. 356.30 for Rural areas and Rs. 538.60 for Urban areas. For the year 2011-12 the Planning Commission has defined the Poverty line as Rs. 27.20 per capita per day in Rural areas and Rs. 33.33 per capita per day in Urban areas. This translates to Rs. 816/- per capita per month in Rural areas and Rs. 1000/- per capita per month in Urban areas”. (p.202).

There are two types of poverty - absolute (*Nirapexa*) poverty where a *certain* criteria of estimation are defined and applied for a segment or whole society. This method is universally applicable. It has no bar of time, place, segments or geographical area. The poverty in India is the absolute poverty. The another type is relative or comparative poverty where comparison between

level of two countries or segments are considered for estimation. The comparative method of estimation is not applied in India. According to the Planning Commission, the main determinants of poverty are (i) lack of income and purchasing power attributable to lack of productive employment and considerable underemployment and not to lack of employment per se; (ii) a continuous increase in the price of food, especially food-grains which account for 70-80 per cent of the consumption basket; and (iii) inadequacy of social infrastructure, affecting the quality of life of the people and their employability. (9<sup>th</sup> plan, Vol.1)

**Table - 1 : Planning Commission's Estimate of Poverty**

Year	No. of Persons in rural (lakh)	Per cent of Rural Poverty	No. of Persons in urban (lakh)	Per cent of Urban Poverty	Total No. of Persons (lakh)	Per cent of Total Poverty
1973-74	2613	56.4	600	49.0	3213	54.9
1977-78	2642	53.1	647	45.2	3289	51.3
1983	2520	45.7	709	40.8	3229	44.5
1987-88	2319	39.1	752	38.2	3071	38.9
1993-94	2440	37.3	763	32.4	3203	36.0

Source: Ninth Five Year Plan (1997-02), Vol.1, Planning Commission, Govt. of India.

As stated by Datta and Mahajan<sup>9</sup> (2013), "Planning Commission accepted the Lakdawala methodology for estimation of Poverty with minor modifications. Between the period 1973-74 and 1987-88, there was a decline in Poverty from 54.90 to 38.90, i.e. the fall of 16 per cent in 14 years. But in the subsequent six years period (1987-88 to 1993-94), Poverty ratio declined from 38.90 to 36.00 per cent, i.e. a fall of 2.90 per cent only. The average rate of decline in Poverty ratio during later period was barely 0.48 per cent per annum only. The slowdown in the reduction of Poverty, particularly, in the rural sector, is a matter of serious concern.

### C. Rangarajan Committee Report

In June 2012, the Planning Commission had constituted an Expert Group under the Chairmanship of Dr. C. Rangarajan<sup>10</sup>(2014) to suggest a methodology for measurement of poverty in India. The Expert Group headed by C. Rangarajan submitted their report in June 2014. The terms of reference of the Expert group are summarized as follows:

- To comprehensively review the existing methodology of estimation of poverty.
- To examine the issue of divergence between consumption estimates based on the NSSO methodology and those emerging from the National Accounts aggregates; and to suggest a methodology for updating consumption poverty lines using the new consumer price indices launched by the CSO for rural and urban areas state-wise.
- To review alternative methods of estimation of poverty which may be in use in other countries and indicate whether on this basis, any methodology can be evolved for estimation of poverty in India and across states.
- To recommend how the estimates of poverty, as evolved above, should be linked to eligibility and entitlements for schemes and programmes under the Government of India".

**Table 2: Poverty Estimates by Tendulkar Committee and Rangarajan Committee**

	Tendulkar Committee		Rangarajan Committee	
	1993 - 94	2004 - 05	2009 - 10	2011 - 12
Rural Poverty Line (Rs. Per capita per month)	--	447	801	972
Urban Poverty Line (Rs. Per capita per month)	--	579	1198	1407
Rural Poverty (%)	50.10	41.80	39.60	30.90
Urban Poverty (%)	31.80	25.70	35.10	26.40
All India Poverty (%)	45.30	37.20	38.20	29.50
Poor Persons - Rural (Lakh)	3286.00	3263.00	3259.30	2605.20
Poor Persons -Urban (Lakh)	745.00	808.00	1286.90	1024.70
Poor Persons - <b>India</b> (Lakh)	4037.00	4071.00	4546.20	3630.00

Sources:

1. Tendulkar Committee Report to Review the Methodology for Estimation of Poverty, (November 2009), Planning Commission, Government of India.
2. Press Note on Poverty Estimates (Jan. 2011), Planning Commission of India.
3. Press Note on Poverty Estimates (July 2013), Planning Commission of India.
4. Rangarajan Committee Report (June 2014), (Report of Expert Group to Review the Methodology for Measurement of Poverty, Planning Commission, Govt. of India.

The Table 2 reveals that, the analysis presented in the Report, monthly per capita consumption expenditure of Rs. 972 in rural areas and Rs. 1407 in urban areas is treated as the poverty line at the all India level. This implies a monthly consumption expenditure of Rs. 4860 in rural areas or Rs. 7035 in urban areas for a family of five at 2011-12 prices. This has to be seen in the context of public expenditure that is being incurred in areas like education, health and food security. The actual 'well- being' of the household will be higher than what is indicated by the poverty line. Based on the methodology outlined in the Report, the poverty ratio at all India level for 2011-12 comes to 29.5 per cent. Working backwards this methodology gives the estimate for 2009-2010 at 38.2 per cent. This is in contrast to 21.9 per cent as estimated by Tendulkar methodology for 2011-12 and 29.8 per cent for 2009-10. (Preface of the report)

Generally there are various Methods of estimation of Poverty - the average level of living of society, Minimum level of living and reasonable level of living. In India , a large segment of the population is continuously deprived of minimum level of living for a quite long time. Hence it is Mass Poverty. Therefore, only minimum level of standard of living is considered for estimation of Poverty. Reasonable level of estimation means the average level of standard of living of all the people. But it is mere a wishful thinking in India as the minimum level is also difficult to achieved yet. May take many more decades to consider Minimum Level of standard of living for all the people. The Poverty in India is mass Poverty. A big segment of the population is living under poverty even after independence of the Nation.

#### Why Poverty became so Chronic ?

1. **Theory of Exploitation :** The Poverty in India is generated through the theory of exploitation based on social hierarchy. Mahatma Jyotiba Phule writes in the preface of his booklet '*Shetkaryach Asud (Cultivator's Whipcard)*' as " Without knowledge



*intelligence was lost, Without intelligence morality was lost, Without morality was lost all dynamism ! Without dynamism money was lost, Without money the shudras were sank, All the misery was caused by lack of knowledge !!*" It was the true reasoning of the Poverty in India. Karl Marx had described that the Capital does not create any value. Surplus value of commodity is created by labor. But the Capital holder gets all the surplus value as profit. That system of earning profit was declared as the exploitation of the labour by Karl Marx. In the same way, in India, the Shudra, Atishudra and Women create the wealth through their labour. But all the benefits are enjoyed by the upper class Brahmin community. Alike Karl Marx Mahatma Phule propounded the theory of exploitation in India.

There are four factors Industrial production – Land, Labour, Capital and Entrepreneur. In that system of production, the true producers are labour only. The Land and Capital are non- living factors. It means the Land and Capital are passive factors. Only Labour and Entrepreneurs are the living factors of production. In fact, the Entrepreneurs do not take part in actual Production. Only labour is the true Producer. On the same line, in India, there were four factors of production as Shudra, Vaishya, Kshetriya and Brahmin. In this Fourfold Indian society- Shudra was foundation of Production. In India, all the productive activities were in the hands of Shudra only.

Actually, as like, Entrepreneurs the Brahmin factor did not take part in any productive activity. But gradually, through the religious theories and rituals, the Brahmin started exploitation of the Shudras. Further, more social strata were created by the Brahmins in the name of the Religion and Rituals. Indian social system has become too rigid to get changed. This fact was well described by Mahtma Phule. It is very clear that roots of Poverty of Indian masses are in the Social system. Without making some preventions to such exploitation the upper class people, the Poverty in India can not come to end. Poverty is the sin of a few & curse for masses and hence, will remain forever.

2. **Economic Inequalities:** India is not a poor country. India has ample Assets of production. The per capita income of India is not very low. Presently India's per year per capita income is more than Rs. 70,000/-. It is sufficient to live better life in India. But, due to economic Inequalities, the rich are becoming rich and the poor are becoming poor in India. Because of social stratification, the means of production and assets are not distributed proportionately. Therefore, the poor and their successors are poor forever. On the other hand the rich and their successors are becoming more rich day by day. The policy of Economic Reforms, Liberalization, Privatization and Globalization has caused to further increase in the Economic Inequalities in India. Due the Economic Inequalities, the Poverty of Masses is becoming chronic day by day.
3. **Unemployment :** Since the Economic Reforms started, every body speaks for the GDP Growth rate. Is is always contended by the economists that only high GDP Growth rate can reduce Poverty. But actual experience shows that the highest GDP Growth rate of more than 9 per cent could not help to reduce poverty in India. With manipulation of the figures, the Government of India is claiming that the rate of Poverty is reduced. But in



Reality the rate of Poverty and the Population under Poverty is not reduced during the last decade. Because, the Growth theory is not Scientifically checked and challenged on the basis of the facts and experience. The theories of Higher Growth rate can not help to reduce Poverty in reality. Because the actual Industrial Production, Agricultural productions are showing negative growths. Therefore, the rate employment generation is minus during last decade. Those who are getting employment are not getting suitable wages. In short, low wages, unemployment, irregular employment, in secured working conditions are leading to increase in the poverty.

4. **Population not the main Reason :** It is always stressed that the Poverty in India is due to population growth. But in 1950 to 1960 the population of India was  $1/4^{\text{th}}$  of today's population. The resources were more or less same which are as today. Even then there was poverty more than 55 per cent in 1950s. The population may be a reason of Poverty. But it is not the main reason. Even today the per capita income is more than Rs. 70,000/- per year. This is quite sufficient in India to live life without poverty. But it is average Income. It means Upper 10 per cent of Indian population is getting very high share of income. On the other hand, the 80 per cent population constituting masses, are getting very low income. The lowest 10 per cent of the masses are getting no income. Thus the distribution of income is the main problem behind the Poverty in India.
5. **Corruption and Black Money :** The corruption and Black money is the main cause of the Poverty in India. The corruption in Policy making and Implementation is rather serious, so far as the Poverty is concerned. The Black money is also a cause for poverty in India. The Black money leads to low tax collection and the increase in inflation. Due to increase in inflation, the real income in the hands of poor get automatically reduced. The inflation rises, but the income of the masses does not rise. With the same quantity of money the masses have face the inflation. Thus, the Corruption, Black Money and Inflation are also the causes of the Poverty in India.

#### Conclusions:

There is a need to redefine the criteria of poverty as per the democratic spirit of the Nation. The Basic Needs like Food, clothing, air, water are the survival Needs. In addition to that suitable residence, hygienic locality & bringing up of children, education, skill & social needs productive, creative work & reasonable income, Timely treatment and health, hygiene must be considered as fundamental needs of life. Neglecting Agriculture and priority to service sector in free economy has been unsuitable models for our country. Further, benefits of economic growth are not reaching to needy people. Employment is offered on subsistence wage and sufficient wages are not paid. Suitable work, reasonable wages, redistribution of assets, wealth and income, equal opportunity to progress by democratic system are necessary for reduction in poverty. There is a need to make estimation of poverty sensitively with sympathy and compassion. There are Socio-cultural factors which make poverty eternal. The GDP growth centric economic policies should be changed, labour intensive techniques of production and employment oriented policies must be adopted for reduction in the poverty in India.

#### References :



1. An Approach to the Twelfth Five Year Plan (Oct. 2011), Planning Commission, Government of India, New Delhi.
2. Report of C. Rangarajan Committee Report (June 2014), (Report of Expert Group to Review the Methodology for Measurement of Poverty, Planning Commission, Govt. of India.
3. Annual Report (2013-14), Planning Commission, Government of India, New Delhi.
4. Ibid.
5. Ibid.
6. Tendulkar Committee Report to Review the Methodology for Estimation of Poverty, (November 2009), Planning Commission, Government of India
7. Misra S.K., Puri V.K. (2015), Indian Economy, Himalaya Publishing House Pvt. Ltd, Mumbai.
8. Ibid.
9. Datta Gaurav, Mahajan Ashwani, Datt & Sundharam Indian Economy (68<sup>th</sup> Ed, 2013), S.Chand & Company Ltd, New Delhi, (p.397).
10. Op. cit. C. Rangarajan Committee Report (June 2014).

## कुसुमाग्रजांच्या प्रेमकाव्यातील अंतरंग

प्रा. संतोष सदाशिव देठे

मराठी विभाग प्रमुख

श्री शिवाजी कला, वाणिज्य व विज्ञान

महाविद्यालय, राजुरा, जि. चंद्रपूर

कुसुमाग्रज उर्फ वि.वा. शिरवाडकर हे अग्निसंप्रदायी कवी म्हणून ओळखले जातात. क्रांतीकारी आणि क्रांतीपूजक कविता लिहिणारे कवी म्हणून कुसुमाग्रज आपणांस सुपरिचित आहे. ओजस्वी भाषा, प्रखर आवेश, राष्ट्रीयत्व, विश्वबंधुत्व इत्यादी वैशिष्ट्यांनी त्यांच्या कविता परिपूर्ण आहे. 'विशाखा', 'जीवनलहरी', 'किनारा', 'मराठी माती', 'स्वगत', 'हिमरेषा' यासारख्या काव्यसंग्रहांनी मराठी काव्यक्षेत्रात कुसुमाग्रजांनी मानाचे स्थान मिळविले. कथा, कादंबरी, नाटक आणि कविता इत्यादी वाङ्मय प्रकार कुसुमाग्रजांनी समर्थपणे लिहिले असले तरी कवी आणि नाटककार म्हणूनच ते जास्त रसिकमान्य आहेत. कवी कुसुमाग्रजांची प्रतिभा कुळातच काव्यात अंतर्भूत आहे. या प्रतिभेला भव्य, रम्य आणि उज्ज्वल अशा कल्पकतेचे देणे लाभले आहे. उत्तुंग कल्पनावैभव आणि नाट्यात्मकता तसेच मानवतेवरील प्रेम, विषमतेची चीड इत्यादी गुणांनी त्यांच्या कविता सजलेल्या आहेत. कुसुमाग्रजांचे सर्वच काव्य भावोत्कट आहे. कुसुमाग्रजांची कविता जे व्यक्त करते ते इतके रेखीवपणे असते की ते पाहताच डोळ्याचे पारणे फिटते.

कवी कुसुमाग्रजांनी काव्यलेखनाला १९३१-३२ मध्ये प्रारंभ केला. त्यांच्या प्रेमळ स्वभावामुळे ते कोणालाही आपलेसे वाटतात. कविजनांच्या बैठकीत रंगून जाणे हा तर त्यांच्या स्वभावाचा स्थायीभावच म्हणता येईल. प्रेम ही मानवी जीवनातील मुलभूत भावना आहे. प्राचीन मराठी संत कवितेत व मध्ययुगीन कवितेत प्रेम या भावनेचे आविष्कारण होत नव्हते. केशवसुतांनी प्रथम मानवी जीवनातील लौकीक भावभावनांचे आविष्कारण केले. त्यांच्या प्रेमकवितेत प्रेमाचा आर्त व उत्कट भाव दिसून येतो. त्याचप्रमाणे गोविंदाग्रजांच्या भावकवितातही आपणास प्रेमाची संकल्पना अधिक आर्त, कोमल व उत्कट झालेली आहे. कुसुमाग्रजांची प्रेमकविता ही रसिक हृदयाला स्पर्श करून जाणारी आहे. कुसुमाग्रजांच्या प्रेमकविता अभ्यासल्यानंतर त्या कविता आपणांस प्रेमाचे अनेक वळणे घेणाऱ्या वाटतात. कवी कुसुमाग्रजांजवळ अभिजात व अष्टपैलू कल्पकता असल्यामुळे 'पृथ्वीचे प्रेमगीत', 'स्वप्नाची समाप्ती', 'तरीही कंधवा', 'शेवटचे पान', 'प्रतिक्षा', 'भावमोहन', 'आश्वासन', 'प्रीतीविण', 'कुतूहल' इत्यादी प्रेमकविता कुसुमाग्रज लिहू शकले. त्यांची प्रीतीगीते विपूल नसली तरी त्यात विविधता आहे. त्यात विरहाची तळमळ आहे. प्रीतीने पराक्रमाच्या आड येवू नये ही उत्कट इच्छा आहे. प्रियजनाकरिता त्यागाची तयारी आहे. कुसुमाग्रजांच्या कविता वाचतांना आपणांस एक गोष्ट लक्षात येते की, ती म्हणजे त्यांचे व्यक्तिमत्व अभिजात, सुसंस्कृत प्रामाणिक व संपन्न कवीचे आहे. वि.स. खांडेकर म्हणतात, "टिळक जसे फुलामुलांचे कवी होते, किंवा गोविंदाग्रज जसे कल्पनारम्य प्रणयाचे कवी होते तसे कुसुमाग्रज हे मानवतेचे कवी आहेत. कुसुमाग्रज प्रेमानुभव उत्कटपणे व्यक्त करू शकत नाही. कारण त्यांच्या मनाचे केंद्र समुहभावनांचा आविष्कार करणारे आहेत. समुहमनाच्या भावना ते जितक्या सहजतेने व्यक्त करताना रमून जातात तितके ते स्वतःचा प्रेमानुभव व्यक्त करताना रमत नाही".

'स्वप्नाची समाप्ती' ही कुसुमाग्रजांची लोकप्रिय प्रेमकविता आहे. या कवितेत कुसुमाग्रजांच्या कल्पकतेबरोबर त्यांची सौंदर्यवेधकता, भावोत्कटता, विचारशीलता आणि वास्तवाचे भान अशा कितीतरी गुणांचा आपणास प्रत्ययास येतो. 'काढ सखे गळ्यातील तुझे चांदण्याचे हात, क्षितिजाच्या पलीकडे उभे दिवसाचे दूत' या कडव्यात स्वप्न आणि वास्तव यांची विदारकता मोठ्या संयमाने हाताळली आहे. शुक्रतारा मंद होणे म्हणजे प्रकाशाच्या पावलांची चाहूल स्पष्ट होते. आता स्वप्नाला आवर घातल्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. ही प्रियकराची जाणीव विलक्षण सौंदर्यवेधी वृत्तीने टिपलेली आहेत. एकीकडे प्रियकराला समाजाचे भान तर दुसरीकडे आपल्या प्रेयसीची समजुतही घालतो. कवीने प्रेयसीच्या हातांना 'चांदण्याचे हात' संबोधले आहे. चांदण्याचे हात म्हणजे नाजुकपण, आनंद देणारा स्पर्श असे सूचन कवी करतो. त्यामुळे कवीची कल्पना अतिशय तरल वाटते.

‘विषमता दाटलेली दिशांतून’ आणि ‘जमू लागलेले दव गवतांच्या पातीवर। भासते भू तारकांच्या आसवांनी ओलसर!’ या प्रतिमांतून कवीची मनःस्थिती सहज लक्षात येते.

ध्येय प्रेम आशा यांची  
होतसे का कधी पूर्ती।  
वेड्यापरी पूजितो या  
आम्ही भंगणाच्या मूर्जी।

अशा शब्दांतून प्रियकराची मानसिक अवस्थेचा परिचय होतो. प्रस्तुत कवितेच्या संदर्भात वि.स. खांडेकर म्हणतात, ‘अतिसुंदर प्रेमगीत म्हणजे कुसुमाग्रजांच्या कल्पकतेने काठोकाठ भरलेला अमृतकलश आहे’ ह्यावरून ही प्रेमकविता किती सरस आहे याची आपणास साक्ष पटते.

‘पृथ्वीचे प्रेमगीत’ या कवितेत प्रियकर-प्रेयसीचे रूपक योजताना भौगोलिक सत्याचा आधार घेतला. भौगोलिक सत्यावर जी कल्पना कुसुमाग्रजांनी केली ती उत्तुंगच म्हणावी लागेल. सुर्याच्या अस्तित्वाची कल्पना असतांनाही त्यांच्यावर जीव ओतणारी पृथ्वी किती निष्ठावंत आहे याची कल्पना येते. या कवितेत पृथ्वी पौढ आहे. सावित्रीसारखी निष्ठावंत आहे. बाहेरून शांत दिसली तरी तिच्या अंतःकरणातील प्रेमज्योत जळती, जागती आहे. चंद्र, तारे, शुक्र, मंगळ, ध्रुव आणि धुमकेतू आपापल्या परीने आणि आपापल्या स्वभावानुसार तिचे मन जिंकण्याचा प्रयत्न करतात. पृथ्वीला आपलस करण्यासाठी ज्या ज्या घटकांनी प्रयत्न केले ते पूर्ण होत नाही हे कवी कुसुमाग्रजांनी अत्यंत रेखीव आणि प्रत्येकाच्या स्वभावाला, मनाला विचार करायला भाग पाडणारेच आहे.

परी भव्य ते तेज पाहून पूजून  
घेऊ गळ्याशी कसे काजवे?  
नको शुद्र शृंगार तो दुर्बळांचा  
तुझी दुरता त्याहूनी साहवे!

कवी कुसुमाग्रजांची ही प्रेमकविता समर्थ प्रेमाचा साक्षात्कार घडवण्याच्या दृष्टीने अप्रतिम वाटतेच, पण त्याचबरोबर ग्रहगोलाविषयीच्या आपल्या शास्त्रीय ज्ञानाचा कलादृष्ट्या किती उपयोग करून घेता येतो हे तिकेचमहत्वाचे आहे. शृंगाराला उदात्ताची इतकी उत्तुंग बैठक आणि तीही इतक्या कलापूर्ण रीतीने देणारी दुसरी कविता दुर्मिळच म्हटली पाहिजे.

कवी कुसुमाग्रजांची ‘उषःकाल’ या कवितेतून पटाटेचे वातावरण चित्रित करून सखीला उठविण्याचा प्रयत्न केला आहे.

स्वप्नांचा वा खजिना होऊनि लगबगिने रात्र  
गेली, चुकोनिया मात्र  
उषास्वप्न हे उरले मागे तुजसाठी रमणी  
झाला उषःकाल राणी!

इथे कवीचा प्रियकर किती शालीन, संयमीवृत्तीचा आहे. तो आपल्याबरोबर इतरांचीही काळजी करणारा आहे. हे आपणास लक्षात येते. या कवितेतला प्रियकर आपल्या सखीला सांगत आहे. या स्वप्नाचा प्रसन्न गारवा, उत्साहवर्धक तजेला आणि विस्मयकारक अपूर्वाई यांनी चित्राला दीर्घकाळ भूरळ घालावी अशा दृष्टीने येथील सर्व प्रतिमा एकमेकांशी संवाद साधतात हे या कवितेचे खरे मर्म आहे. ह्यानंतर कवी कुसुमाग्रजांची ‘भावमोहन’ ही कविता सुंदर प्रेमकविता म्हणून वाचकाच्या मनात घर करून बसते. प्रियसीने प्रीतीच्या संदर्भात बोलू नये. मौन धारण करण्यातच खरी प्रीती आहे. अबोल प्रेम प्रियकराला सुखमय वाटते.

तुझ्या पापण्यांच्या आत, काय साठले दाटले  
दोन ओठांच्या दलात, दव कोणते गोठले  
नको सांगुस कधीही, काय सांगायचे आहे  
अशा भाव मोहनाचा, अंत अक्षरात आहे

इथे प्रियकराला वाटते की, प्रेमाचे भाव हे बोलण्यापेक्षा कृतीतून व्यक्त होणे चांगले असते. ते शब्दांतून व्यक्त झाले तर प्रेमाचा, भावनाचा अंत होईल. कुसुमाग्रजांनी या कवितेत प्रियकरांच्या भावना किती नाजूक व तरल आहे हे सांगितले आहे.

‘प्रीतीसाठी प्रीती’ ही कविता प्रेमाचे महत्व विशद करणारी आहे. ही कविता इतर प्रेमकवितापेक्षा वेगळी आहे. ह्या जगात सर्वच अशाश्वत व क्षणभंगूर आहे. आपणही प्रीतीला अशाश्वत व क्षणभंगूर मानले पाहिजे. असा आशय व्यक्त करणारी आहे. ‘उपास्वप्न’ या कवितेत कवी कुसुमाग्रजांना असे वाटते की, प्रीतीचे एक तरी स्वप्न जिवाभावे सांभाळावे ‘स्वप्नाची समाप्ती’ या कवितेत प्रीतीला आवर घालून वास्तवाची जाणीव ठेवणारा प्रियकर आपणास दिसतो तर ‘उपास्वप्न’ या कवितेत प्रियकराची वृत्ती बदलेली दिसते. ती म्हणजे प्रीती शाश्वत काय म्हणून मानायची?

विश्वाची हि फुले गळून पडती आकाशगंगेमध्ये

प्रीतीलाच कसा चिरंतनपणा जी जन्मली नश्वर (प्रीतीसाठी प्रीती)

प्रीतीचा पूरेपूर आनंद लुटायचा असेल तर प्रत्येक मानवानी एकच गोष्ट लक्षात ठेवायला पाहिजे. जो क्षण आपल्या वाट्याला आला आहे त्याचा पूरेपूर फायदा घेवून प्रीतीचा खराखुरा आनंद उपभोगला पाहिजे. आपण भूत व भविष्यकाळाचा विचार न करता वर्तमान काळाचा विचार करावा. असा उदात्त विचार कवींनी या कवितेत मांडला आहे.

‘तुझे गीत’ या कवितेत कवी व्यवहारातील पोळलेल्या जीवाला ती व्यथाच सुखाची शिंदरी होऊन बसते. हा मधूर भाव कवीने व्यक्त केला. तुझ्या गीतांनीच माझ्या जीवनात आनंद प्राप्त होते. तुज गीतच आपल्या जीविताच जीवन आहे.

तुझे नितळ नाजूक, गीत आले हे कुटून

परीप्रमाणे कोणत्या, फुलामधून उठून

तुझ्या गीतांच्या संगती, आला श्रावण समोर

माझ्या वैशाख चैत्रात, झाले हिरवे काहूर

‘आहे ती व्यथेची’ या कवितेत कवींनी प्रेमाचे नवे रूप आकारलेले आहे. प्रेम करित असताना सुख मिळत असले तरी ह्या सुखाबरोबर दुःखही झेलावे लागतात. हे दुःख भोगण्याची तयारी माणसानी ठेवली पाहिजे.

प्रीती ना आपूली

संतोष सुखाची

सारंगी बिनाची

आहे ती व्यथेची, गहन दुःखाची

अथांग मौनाची!

कवीला या कवितेत हेच सुचित करायचे आहे की, माझी प्रीती म्हणजे सामान्य गोष्टीसारखी व मनोरंजक नाही. ‘नाही’ या कवितेत कवी कुसुमाग्रजांनी प्रियकरांच्या व्याकुळ व्यथा व्यक्त केल्या आहे. प्रियकरांचे शब्द वाचकाच्या मनाला चटका लावून जातात. प्रीतीच्या वेदना मी एकटाच सहन करीन, तुला त्याचा स्पर्श होऊ देणार नाही. हे सहन करण्याची शक्ती माझ्या प्रेमाचीच मला दिली.

काही बोलायचे आहे, पण बोलणार नाही

देवळाच्या दारामध्ये, भक्ती तोलणार नाही

तुझ्या कृपाकटाक्षाने, झालो वणव्याचा धनी

त्याच निखान्यात कधी, तुला जाळणार नाही

या कवितेतील प्रियकर किती सहनशील मनाचा, प्रेमळ भावनेचा आहे हे दिसून येते. या प्रियकराच्या संयमामुळे प्रीतीला भक्तीचा जो गहिरेपणा आला आहे आणि त्याच्या आत्म्याला जो डौल लाभलेला आहे त्यांच्यामुळे तर हे उदार रसिकाच्या मनात दीर्घकाळ घर करू राहतात. ‘स्मरण’ या कवितेत प्रीतीच्या दिव्याग्नीने दोन जीव चार क्षण उल्कासारखे एकमेकांना अंतराळात भेटतात. पृथ्वीवर कोसळल्यानंतर त्यांना मातीची अवकळा येते पण दिव्य भावांनी नटलेले हे चार क्षण जीवनाला आयुष्यभर बिलगून राहतात. त्यानंतर कुसुमाग्रजांच्या ‘मुर्ती’ या कवितेत प्रियकर आपल्या सखीला म्हणतो, की तुझी घडण

मुळातच संगमरवरी शिल्पासारखी आहे. मी मात्र त्यात उगीच तऱ्हेतऱ्हेचे कोमल भाव वाचले आणि अहंकाराला वश होऊन स्वतःची फसवणूक करून घेतली. तुझ्या देवळातला मी एकमेव भक्त नाही. ह्या कवितेत कवींनी तिचे लावण्य, तिची भावनिकता व स्वतःची फसवणूक याचे सुरेख वर्णन केले. 'निराकार' या कवितेत कुसुमाग्रजांनी प्रियकरांचे दुःख व्यक्त केले आहे. प्रेमाची उपेक्षा व अवहेलना झाल्यावर दुःखाला कुठल्याच प्रकारचा आकार उरत नाही. दुःखाला शब्दांत पकडण्याची प्रियकरांची धडपड आहे. प्रियकराचे शब्द असूनही त्यालाच ओळखता येत नाही.

कुसुमाग्रजांच्या प्रेमकाव्यांचे वैशिष्ट्ये म्हणजे त्यांच्या कवितेतून दृग्गोचर झालेली प्रेमी जीवांची शब्दचित्रे, त्यांची प्रीती जीवन समजावून घेण्यास उपयोगी पडते. त्यांची प्रीती विरहभावनेतून देखील उफाळून येते. प्रीतीचा डाव हराण तरी कुसुमाग्रजांचे प्रेमिक डोके हरवून बसत नाही. शांतपणे एकमेकांचे निरोप घेतात. वेलीच्या पानाआड दडलेल्या पुष्पासमान त्यांची प्रीतीभावना सुगंधाने दरवळत असते. यातना हाच कुसुमाग्रजांच्या प्रीतीभावनेचा स्थायीभाव आहे. रणांगणावर फुलणारी, भव्यतेचा वेध घेणारी, स्वप्नशील वातावरणात रमणारी, विरहातून वाट शोधणारी, जीवनाची नवी क्षितीजे पाहणारी, रुपकातून निनादणारी, कल्पकतेचा साज देणारी, संयमाचे वरदान अभिमानाने मिरविणारी, नेत्रात एकाचवेळी कोमलभाव अन् निश्चयीपणा धारण करणारी अशा कीर्तीतरी प्रीतीच्या भावना कवी कुसुमाग्रजांच्या कवितेतून विविधप्रकारे आढळून येतात. याशिवाय त्यांची प्रेमकविता निसर्ग प्रतिमातून आपल्या एकाकीपणाच्या भावना, दुःख व्यक्त करताना दिसते. व्यक्तिगत मानवी प्रीतीपेक्षा सामाजिक जाणीवेला, ध्येयाला, कर्तव्याला श्रेय देणारी अशी कुसुमाग्रजांची प्रीतीविषयक संकल्पना आहे. कुसुमाग्रजांची प्रीती नाट्यात्मकता प्रगट करते तेव्हा ती ध्येयवादाला जवळ करते. आपणास जेव्हा तिचा उत्कट आत्माविष्कार दिसतो. तेव्हा तिच्यातील भावानुभव अधिक आर्त व तरल वाटू लागते. आणि ही प्रीती भाष्य व्यक्त करते तिथे मात्र त्यांची प्रेमकविता अधिक सबळ बनते.

संदर्भ ग्रंथ :

- १) 'रसयात्रा', संपादक बा.अ. बोरकर, शंकर वैद्य
- २) 'मराठी कविता : जुनी आणि नवी', वा.ल. कुलकर्णी



---

## MAHARASHTRA: A GLOBAL HEALTH DESTINATION

Mrs. Rupali M. Patil  
Research scholar  
[rupali.patil48@gmail.com](mailto:rupali.patil48@gmail.com)

Prof .Dr. SadashivLaxmanShiragave  
M.Com.M.A,M.Phil,D.H.E,L.L.B,Ph.D  
Arts & Commerce College, Daund, Dist-Pune  
[sadashiv.shiragave@gmail.com](mailto:sadashiv.shiragave@gmail.com)

### ABSTRACT

Medical Tourism is the fastest growing industries in the world, combining with healthcare & tourism. India is one of the top destinations in the medical tourism industry. Globalization of the health care sector in India leads tremendous growth in Health care industry.

Maharashtra has emerged as the major destination of health care in the medical map of the world. Maharashtra has wide scope and opportunities in medical tourism in the coming years not only metro cities but also in small cities like Nagpur, Aurangabad, Pune, Kolhapur, Sangli, Solapur. So, travel and tourism industry is growing vastly in India in domestic level as well as international level. Maharashtra provides world class facilities with hospitals & specialized multi specialty health center.

Paper highlights the potential of Medical Tourism industry in India. Maharashtra has a potential global health destination for analyzing the potential and significance of Medical Tourism in India. The data has been gathered through secondary sources which includes Books, Magazines, Journals, E-Journals & websites etc. After the analyzing all the facts in can be concluded that Maharashtra is in an advantageous position to tap global opportunities in the Medical tourism sector.

**Key Words:** Medical Tourism, Domestic Tourism, Out Bound Tourism, Inbound Medical  
Tourism, Intra-bound Medical Tourism.

### I. Introduction

The concept of Medical Tourism is not new one, it is actually thousands of years old. After the globalization, peoples are travel globally. Currently millions of people are travelling to tourist destinations seeking health care. The main purpose of travel is for healthcare, afterwards the conventional tourism experience related to leisure and relaxation in tourist places.

In recent years, growing need for better health care which has led to an increasing number of countries starting to promote medical tourism. The recent trend is for people to travel from developed countries to developing countries for medical treatments because of cost consideration, quick response, and expert healthcare services. The countries like Malaysia, Singapore, India, Jordan, Philippines provide medical tourism. India is one of the best destinations for medical tourism due to the availability of specialized doctors and world - class hospital and medical treatments, low treatment costs, technological advancements. India has become a global leader in medical tourist most preferable and least expensive choices among

medical tourism destinations. Medical tourism market is estimated to be around USD 3 billion in 2015 & is expect to reach USD 8 billion in 2020. (Figures from Ministry of Health & Medical Tourism Association Report) Inflow of medical tourists is expected to cross 3.2 million by 2015 compared to 0.85 million in 2012. The International Healthcare Research Center made survey finds that India is the 5<sup>th</sup> country in most attractive destinations.

### **I. OBJECTIVES OF THE STUDY**

1. To know the growth of medical tourism in India.
2. To know the potential of medical tourism in Maharashtra.

### **II. RESEARCH METHODOLOGY**

This paper is prepared on the basis of secondary data from different sources like Medical Tourism Index, Reports, Journals, Websites, Books.

### **III. WHAT IS MEDICAL TOURISM?**

Medical Tourism is also known as Medical Travel, Health tourism, Surgical tourism, overseas medical, wellness tourism. In Tourism industry, medical tourism is a promising concept and growing phenomenon. Medical Tourism can be defined as provision of 'cost effective 'personal health care or Private medical care in association with the tourism industry for patients needing Surgical heart care and other forms of specialize treatment. Medical tourism includes outbound, inbound and Intra-bound medical tourism.

Outbound Medical Tourism - Refers to patients travelling out of a country.

Inbound Medical Tourism - Refers patients coming into a country.

Intra-bound Medical Tourism- Refers to patients travelling within a country. It is also called as domestic medical tourism.

### **IV. MEDICAL TOURISM A CURRENT GLOBAL SCENARIO**

Medical tourism has increased significantly in the last several years with the explosion of complex communication techniques and transportation technologies. Global medical tourism industry faced tremendous competition so, healthcare, hospitality and travel providers are attempting to improve their own services to become more attractive to the customers.



The global medical tourism industry was estimated at USD 10.5 billion in 2012. It is expected to grow at a CAGR of 17.9% from 2013-2019 to reach USD 32.5 billion in 2019 (Business standard 2<sup>nd</sup> Dec. 2013)

## **V. MEDICAL TOURISM IN INDIA**

Tourism sector is one of the booming sector in India and also largest foreign exchange earners. Government of India implemented 'Incredible India Campaign' in 2002 and 'AthithiDevoBhava' in the year 2008. The Minister of Finance Government of India took initiatives for develop and promoting medical tourism destinations in 10<sup>th</sup> 5 year plan. Further 12<sup>th</sup> 5 year plan (2007-2012) clearly emphasized the importance of sustainable development and growth of medical tourism to India along with promoting India as a world class quality and high-tech healing destination providing low cost medical surgeries and treatment with less waiting time. The 12<sup>th</sup> plan focuses on providing universal healthcare, strengthens healthcare infrastructure, promoting R & D and enacting strong regulations for the healthcare sector. The NITI Aayog has allocated USD 55 billion under the 12<sup>th</sup> 5 year plan.

Superior quality healthcare, coupled with low treatment costs in comparison to other countries, is benefiting Indian medical tourism which has, in turn, enhanced the prospects of the Indian Healthcare Market. Yoga, Meditation, Ayurveda, Allopathy and other traditional methods of treatment are major service offerings that attract medical tourists from European Nations and the Middle East to India. According in industry estimates, the size of the medical tourism industry stands at Rs.1,200-1,500 crores. Currently Indian Healthcare Market is at Rs.15 billion and growing at over 30% every year.

## **VI. MEDICAL TOURISM IN MAHARASHTRA**

### **A. Profile of Maharashtra**

Maharashtra is the third largest State in the country and populous state with a population of 96.75 million. It is also economically developed state. Maharashtra has the highest level of urbanization among major states in India 43% of the population residing in urban areas. The density of population is 314 persons per square kilometer. It has largest industrial economies in the country. Maharashtra is abounds in numerous tourist attractions like ancient cave temples, forests and wildlife, unique hill stations, beaches, ancient forts & monuments, pilgrimage centers, tradition of festivals. Maharashtra is the commercial and financial state of India is now coming up as the most suitable destination for medical tourism within the country.

## B. MAHARASHTRA INFRASTRUCTURE

Maharashtra State has a well developed infrastructure. It has good road, rail and port and air connectivity. There are 3 international and five domestic airports. Maharashtra ranks first amongst all the Indian states in terms of GSDP. The rail transport system of Maharashtra is well developed. Indian Railways headquarters in Mumbai. The state is well connected to its six neighboring states and other parts of India through 18 National Highways.

## C. MAHARASHTRA TOURISM MARKET

Maharashtra State ranked 1<sup>st</sup> in foreign tourists arrivals. It received nearly 4.8 million tourists, Tamil Nadu 3.4 million welcomed people and New Delhi welcomed 2.2 million foreigners, 5<sup>th</sup> ranked in domestic tourist arrivals. Maharashtra received 66.3 million domestic tourists. (India Tourism Statistics 2013)

### Top 10 destinations in Maharashtra

#### Domestic Destinations

1. Shirdi
2. Ellora
3. Gateway of India
4. JuhuChowpathi
5. Tadoba Tiger Project
6. Elephanta Caves
7. Mahalakshmi Temple, Mumbai
8. Mahalakshmi Temple, Kholapur
9. Lonavala
10. Khandala

#### Foreign Destinations

1. Gate way of India
2. JuhuChowpathi
3. Tadoba Tiger Project
4. Elephanta Caves
5. Marine Drive
6. Ellora
7. Lonavala
8. Khandala
9. Haji Ali
10. Aghakhan Palace

## D. MEDICAL TOURISM IN MAHARASHTRA

Maharashtra has been in the forefront of healthcare development in the country. The Indian healthcare delivery system is categorized into two major components public and private.

In recent years Maharashtra is top most health care destination. Medical facilities in Maharashtra is well advanced with world class health facilities zero waiting time & most importantly one tenth of medical costs spent in the US or UK. One of the main reason, Maharashtra's geographic location which is easily accessible & well connected with all the parts of not only India but with

rest of the world also. Majority of foreigner's come for cardiac surgery, joint replacement, plastic surgery, in- vitro fertilization, knee surgery.

Maharashtra has the best qualified professionals in each & every field is one of the strength of increasing Share of medical tourism. Now, Maharashtra is creating a new identity by offering best health services to tourist.

The specialized Allopathy and Ayurvedic Clinics and hospitals gaining popularity through word of mouth and this is contributing to the inflow of medical tourists. The facilities and equipment available at the hospitals are comparable with the best hospitals in the country seven in the world. Recently with an objective of 'To deliver 'value for money' healthcare with a "Human Touch" FICCI and the Govt. of Maharashtra have joined hands to provide best available services to the patients coming from other parts of the country and world at the reasonable price with qualitative services.

Mumbai is the most preferred medical tourist distinction. Medical cancer and Research institute receive lot of inquiries from foreign countries specially from NRI's. The major hospital of Mumbai are mainly Bombay Hospital and Medical Research center, Asian Heart Institute, Wockhardt Hospital, P.D. Hinduja Hospital and Medical Research Center, Breach Candy Hospital, Tata Memorial Centre, Apollo Hospital, Leelavati Hospital.

Pune is second preferred medical tourist destination. The major hospitals are Ruby Hall Clinic, Sancheti Institute for Orthopedics and Rehabilitation, Aditya Birla Memorial Hospital and Jeghanir Hospital. Around Pune many wellness centers like Kaivalyadham, International yoga centre. Apart from metro cities, small cities have potential to attract people from across the world. These are the sunshine cities Maharashtra that is Nashik, Kholapur, Aurangabad, Nagpur, Solapur, Sangli. Maharashtra is one of the best emerging medical tourism destination and also better scope in medical tourism in the coming years in yoga, Ayurveda, Homeopathy, Unani, Allopathic medicines.

#### **E. Some of the Key Growth Facilitators for Advantage Maharashtra are**

1. Specialized hospitals and clinics.
2. Well qualified suspended and experienced professional doctors, surgeons with respective fields.
3. Hospitals as highly equipped with latest life saving technological equipments.

4. Doctors are serving in various international projects and making valuable and important contribution in international assignments.
5. Low cost delivery.
6. Knowledge of English Language
7. Well connected with base metros like Delhi & other parts.
8. Most attractive state for medical foreign tourist.
9. Zero waiting periods for all patients.
10. One tenth to one twentieth of the costs involved for medical treatment in USA or UK.
11. Good roads and infrastructure compared to other states of India.

Table 1 : Cost comparison of charges

Procedure	Abroad	India (Other states)	Maharashtra
Total Hip Replacement	6.50 Lakh	2.60 Lakh	1.30 Lakh
Total knee Replacement	7.50 Lakh	3.50 Lakh	2.30 Lakh
Simple Spine Surgery	3.20 Lakh	210 Lakh	1.00 Lakh
Spine Surgery with Implant	9.60 Lakh	2.40 Lakh	1.30 Lakh
Simple Brain Tumor	1.92 Lakh	50,000	30,000
Open Heart Surgery	8.40 Lakh	2.50 Lakh	1.50 Lakh
Deformity Correction	1.50 Lakh	60,000	30,000

( Webmed Central > Research article)

Cost effectiveness is one of the most important factor for Medical tourist to attract people from across the world. From the above Table ,In the state of Maharashtra cities like Mumbai, Pune, Nashik, Aurangabad, Nagpur, Kholapur, Sangli, Solapur the cost of treatment is very low compare to abroad and other states in India.

#### **F. CHALLENGES IN FRONT OF MAHARASHTRA**

1. Standardization of services & accreditation of hospitality.
2. Co-ordination between the healthcare and tourism sectors.
3. Increasing visibility of Maharashtra on the world map.
4. Lack in PPP (Public Private Partnership)
5. Lack of Unified Pricing.
6. Poor Marketing strategies.



7. Lack of Mechanism to deal with medical insurance related cases.
8. Need to be Simple and transparent medical procedure.
9. Need to improve the air connectivity within and outside state.

India is a huge magnet for attracting foreign patients for medical treatments. The Maharashtra State Govt. has announced a medical tourism policy 2016, which will be helpful for providing better health care facilities & give exposure to the medical fraternity. The policy is also expected to give a lot of revenue to the government

A part from the medical Tourism council, the IMC chamber of commerce & Industry is also Looking into creating a task force which will put together its suggestions for drafting the necessary and appropriate policies for the promotion of medical tourism in the state (speech : IMC President Deepak Premnarayan).

## **VII. CONCLUDING REMARKS**

Medical tourism is the provision of "Cost effective" private medical care in collaboration with the tourism industry for patients needing surgical & other forms of specialized treatment.

The growth in medical tourism has the potential to change the economic scenario of the country receiving tourists Maharashtra is most developing state has opened new opportunities for medical tourism. Mumbai is one of metro city and vast flow of medical tourist coming from all over the world. Maharashtra is one of the top most destinations for foreign tourist. After ward Pune, Aurangabad, Nashik, Nagpur, Kholapur, Solapur cities also lot of potential to grab foreign medical tourists as well as Domestic medical tourists.

## **REFERENCE**

1. Anil P Bankar, "Potential for promoting Medical Tourism in Maharashtra" Webmedcentral.com
2. Dr. R. Kumar, Dr. Raj Bahadur, "Medical Tourism in India management & promotion" Deep & Deep Publication Pvt.Ltd., New Delhi-2008
3. NiramalDubey, "Hospitality, Tourism & Hotel Management", Sonali publications- New Delhi-2001
4. Percy K. sing, "Medical Tourism - global outlook & Indian Scenario" Kanishka Publishers and distributors, New Delhi-2008
5. Rajpal K. Tayade, Dr. Varsha S. Sukhadev "The growth simpact of M.T. in India", I JARTIE Vol-2 Issue - 3 2017 Page No. 20-09-2013



- 
6. Sabyasachi Bose, "A study on problems & prospects of Medical Tourism in India with strategic implications." A PJMNR, Vol. 3 (11), Nov (2014) PP-1-13.
  7. India Brand Equity Foundation Healthcare report Jan - 2016
  8. Medical Tourism Magazine Page 73 Global NTT 2016

**WEBSITE**

[www.ibef.org](http://www.ibef.org)  
[www.health-tourism-india.com](http://www.health-tourism-india.com)  
[www.india.gov.in](http://www.india.gov.in)  
[www.medicaltourisminindia.net](http://www.medicaltourisminindia.net)  
[www.medicaltoursimindex.com](http://www.medicaltoursimindex.com)  
[www.webmedcentral.com](http://www.webmedcentral.com)  
[www.ijariie.com](http://www.ijariie.com)

---

**A STUDY ON WORK-LIFE BALANCE OF MARRIED WORKING WOMEN WITH  
REFERENCE TO CO-OPERATIVE BANKS, SOLAPUR**

**Ms. Pedda Nagaratna S.**  
Research Scholar  
Sangameshwar College, Solapur

**Prin. Dr.S. K. Patil**  
B.P. Sulakhe College of commerce, Barshi

**1.2 INTRODUCTION :**

The role of working women has changed throughout the world due to economic conditions and social demands. This has resulted in a scenario in which working women have tremendous pressure to develop a career sustaining active engagement in personal life. This affects the person's physical, emotional and social well-being. Thus, achieving work life balance is a necessity for working women to have a good quality life.

The attempt of working women to integrate, organize and balance the various problems and activities in their different roles simultaneously put them under tremendous pressure. Women of the early centuries were mostly confined to their kitchens and those who were employed worked in factories, organization, farms or shop works. As working women get married, they have additional responsibilities and when they become mothers, they have to manage the primary care of children and extend family and are thus, under greater pressure to continue on a career path. Working mothers of today try to remain fully involved in their careers coping up with the competing demands of their multiple roles.

The concept of work-life balance is attracting increasing attention at both the national and international level. Rising levels of employment among women were a consequence not only of changes in the attitudes and values of women, but also of developments in the wider economy. The traditional approach to addressing work-family issues has been challenged in the press and is not fully compatible with current patterns of the twenty-first century workforce.

Evolving work relationships, placing more pressure on organizations, as well as on individuals balancing multiple domains of their lives, illustrate the need both heuristically and theoretically to expand the conceptualization of work-life balance issues. The proposed difference between the work and family spheres has been strengthened by the continuous reduction of time spent at the workplace and the resulting increase of free time.

The boundaries between time spent at the workplace and the time set aside for private life may vary in each individual case and need to be continually re-determined.

This project report is an attempt to explore the tough challenges faced by working women in maintaining a balance between their personal and professional life. The various factors affecting the work-life balance of married working women have been examined in this study.

**1.2 OBJECTIVES OF THE STUDY**

- To find out present practices followed by women employees for work-life balance.
- To study the work-life balance problem among working women.
- To study the various factors affecting women's work-life balance.
- To study the effect of work-life balance on the quality of life of married working women.

### 1.3 SCOPE OF STUDY:

#### 1.3.1 Geographical Scope:

The scope of the study was limited to the married working women of Solapur city from Banking sectors only. The two co-operative banks are considered for study.

- Lokamangal co-operative bank, Solapur
- Sidheshwar co-operative bank, Solapur

#### 1.3.2 Conceptual Scope:

The study is concern with the challenges faced by working women in balancing professional life as well as personal life. The study also put a light on present practices followed by women employees for work-life balance.

### 1.4 LIMITATIONS OF STUDY:

- The project is only related to work life balance issues of female employees employed in co-operative banks only.
- It excludes the females who are employees in other sectors i.e. manufacturing.
- The study is carried out in limited time period.
- Conclusions are drawn on the assumption that data provided by them is true and correct.

### 1.5 RESEARCH METHODOLOGY:

#### Data Collection Method:

Primary Data- For this study Primary data was collected through interviewing the Married Working Women from two co-operative banks by using structured questionnaire.

Secondary Data- For this study Secondary data was collected from secondary sources:

- Reference books
- Online resources etc.

#### Sampling Plan :

- **Sample Unit**- Married working women from Lokamangal

Co-operative bank, Solapur and Sidheshwar co-operative bank, Solapur

- **Sample Size** - 50 women
- **Sampling Technique** - Convenience sampling method
- **Research Instrument** - Structured questionnaire was framed on the basis of objectives of the study.

### 1.5 THEORETICAL ASPECTS:

**THE CONCEPT OF WORK LIFE BALANCE** The term work life balance (Work Life Balance) was coined in 1986 in response to the growing concerns by individuals and organizations alike that work can impinge upon the quality of family life and vice-versa, thus giving rise to the concepts of “family- work conflict” (FWC) and “work-family conflict” (WFC). The former is also referred to as work interferes with family” (WIF) while the latter is also known as “family interferes with work” (FIW). In other words, from the scarcity or zero-sum perspective, time devoted to work is construed as time taken away from one’s family life.

“Work-life-family balance is a self-defined state of well-being. It allows one to effectively manage multiple responsibilities at work, home, and in the community; it supports physical, emotional, family, and community health.”

Work-Life Balance does not mean an equal balance. It means the capacity to schedule the hours of professional and personal life so as to lead a healthy and peaceful life.

Vijaya Mani (2013) has revealed the major factors influencing the Work Life Balance of Women professionals in India such as role conflict, lack of recognition, organizational politics, gender discrimination, elderly and children care issues, quality of health, problems in time management and lack of proper social support.

K.Santhana Lakshmi et al, (March 2013) have examined that the Educational institutions should address the Work Life Balance related issues among their staff, specifically women and take a holistic approach to design and implement the policies to support the teaching staff to manage their WLB. KumariK.Thriveni et al, (2012) have studied and analyzed the significant relationship between the demographic variables and WLB. Shalini and Bhawna 2012 reported in their study, Quality of work life is being used by the organizations as a strategic tool to attract and retain the employees and more importantly to help them to maintain work life balance with equal attention on performance and commitment at work

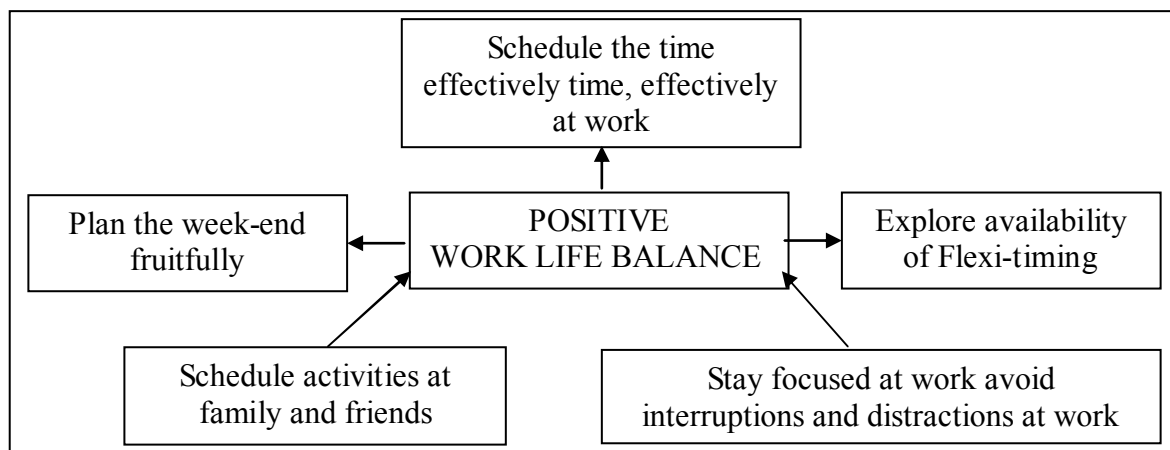
### WORKING WOMEN AND WORK LIFE BALANCE

Work life balance of women employees has become an important subject since the time has changed from men earning the family living in today's world both men and women equally share the responsibility of earning for the betterment of their family life. Hence it is for the betterment of their family life. In the initial stages, women had to struggle a lot to establish their identity in this competitive world, both in the society as well as in the professional life. But with the advancement in educational and training institutions, things have improved to a great extent.

With the increasing of industrialization and education, employment opportunities for women have also increased. And with increasing economic conditions, it has become a necessity that both husband and wife need to work to have a normal life.

In this fast growing and competitive world, as every possible opportunity for employment is increased, the organization needs to create a congenial atmosphere where employees can balance their professional and personal life. Only when an employer has a positive work life balance she can be productive and give her best to her organization. Hence industries are working out schemes which can attract as well as retain their employees.

To achieve a positive work-Life Balance, women should be pro-active and plan her professional and personal schedules well in advance so that both are equally balanced and the end result is satisfaction. The below figure represents few strategies to strike a positive Work Life Balance.



## ABOUT CORPORATIVE BANK

Co-operative banks are an integral part of the Indian financial system. They comprise urban co-operative banks and rural co-operative credit institutions. Co-operative banks in India are more than 100 years old. UCBs mobilizesavings from the middle and lower income groups and purvey credit to small borrowers, including weaker sections of the society. Scheduled UCBs are under closer regulatory and supervisory framework of the RBI. Rural cooperative banks operate mainly for the benefit of rural areas, particularly the agricultural sector.

The Indian cooperative movement was initiated by the government. It spread and diversified with the encouragement and support of the government. Its present condition is also to a great extent because of the intrusive involvement of, and interference by the government.

The Indian corporative banks are growing up in there different phases from the beginning of 20<sup>th</sup> century–

The First Phase	:	1900-1930
The Second Phase	:	1930 – 1950
The Third Phase	:	1950 – 1990

## PROFILE OF LOKMANGAL CO-OPERATIVE BANK

“**Lokmangal Co-operative Bank**” started is the well-known and reputed bank in the Solapur situated in the heart of Solapur city.“**Lokmangal Co-operative Bank**” started in the year 1998 i.e. on dated 28<sup>th</sup> April, 1998. The bank is registered under RBI Act as SUR/BNK (O) 129/1997-1998. RBI license No. UBD-NAH-1543P/Date 2<sup>nd</sup>Feb.1999.

“**Lokmangal bank**” started with the blessing of god “Siddheshwar” and the honest members and promoter/ founder chairman Mr. SubhashSureshchandraDeshmukh.Lokmangal bank is a developing bank in the Solapur city. The bank paid dividend @ 15% p.a.to its members.

### Working staff

Lokmangal Co-operative bank today has total 20 staff members out of which 1 is manager, 2 Accountants, 3 Senior Officers, and 3 Peons. The management expenditure of the bank is 2.50% of its working capital.

## PROFILE OF SOLAPUR SIDDESHWAR CO-OPERATIVE BANK LTD

### Establishment of bank and foundation

- Bank Establish -18/11/1974.
- Bank Working Start - (6/2/1976)
- Total Members -13601
- Audit Class - A (2011-12)

### ISO-9001-2008

**Staff:**37officers 45, Clark, 25 peons its administration cost is 1.73% bank gives 8.33% bonus & various facilities of medical allowance, Home loan, leave salary, Grecia vehicle loan.

**Other activities:**Bank have group who held lecture a time of “Navratra” by well-known speaker save baby girl, poster, banner, Prizes for girls child pennant,Blood Donation camp, and health camp.

## DATA ANALYSIS



**TABLE NO: 4.1:**Table showing respondents satisfaction towards their working hours and whether it is fit with their private life.

Attributes	No. Of Respondents	Percentage
Strongly Satisfied	11	22%
Satisfied	19	38%
Neutral	14	28%
Strongly Disagree	6	12%
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

**TABLE NO: 4.2:** Table showing whether respondents are working for long hours or overtime and even work on holidays.

Attributes	No. Of Respondents	Percentage
Frequently	11	22%
Occasionally	19	38%
Neutral	14	28%
Strongly Disagree	6	12%
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

**TABLE NO: 4.3:**Table showing for whether respondents have any stress on their workplace or not.

Attributes	No. Of Respondents	Percentage
YES, Very High	5	10%
YES, Moderate	29	58%
Not at all	16	32%
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

**TABLE NO: 4.4:**Table showing for whether respondents ability towards balancing their life as well as work.

Attributes	No. Of Respondents	Percentage
Very Well	14	28%
Somewhat	22	44%
Not Balanced	14	28%
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

**TABLE NO: 4.5:**Table showing whether respondents are missing out any quality time with their family or friends because of pressure of work.

Attributes	No. Of Respondents	Percentage
Most of the time	9	18%
Sometimes	21	42%

Rarely	7	14%
Never	13	26%
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

**TABLE NO: 4.6:**Table showing whether respondents are able to get time for their hobbies and other personal activities.

**TABLE NO: 4.7:**Table showing that which factor affects more in balancing respondents work

Attributes	No. Of Respondents	Percentage
Always	10	20%
Sometimes	14	28%
Rarely	11	22%
Never	15	30%
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

life and their family life.

Attributes	No. Of Respondents	Percentage
Working Hours	7	14%
Overtime	14	28%
Work from Home	8	16%
Work on Holiday	11	22%
Target	8	16%
More travelling for work	2	4%
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

**TABLE NO: 4.8**Table showing which factor is more important in balancing work life.

Attributes	No. Of Respondents	Percentage
More flexible hours	9	18%
Work from home	9	18%
Time of during holiday	3	6%
Family supports	27	54%
Other	2	4%
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

**TABLE NO: 4.9:** Table showing respondents opinion towards' the biggest challenge of working women Work-Life-Balance.

Attributes	No. Of Respondents	Percentage
------------	--------------------	------------

YES	46	92%
NO	4	8%
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

## PERSONAL INFORMATION

**TABLE NO: 4.10:** Table showing respondents according to their Age.

Attributes	No. Of Respondents	Percentage
20-30	17	34%
31-40	12	24%
41-50	12	24%
Above 50	9	18%
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

**TABLE NO: 4.12:** Table showing that respondents according to their No. of children.

Attributes	No. Of Respondents	Percentage
None	16	32%
One	13	26%
Two	14	28%
Three or more	7	14%
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

**TABLE NO: 4.13:** Table showing respondents according to their Family Type.

Attributes	No. Of Respondents	Percentage
Joint	27	54%
Nuclear	23	46%
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

## FINDINGS AND SUGGESTIONS

### FINDINGS:

The findings of this survey reinforce the perceived importance of balance between both work and personal aspects of one's life to enable greater success to be achieved in every area of life – including professional matters. With increasing working population and changes in perceived company commitment and loyalty, Work and personal life balance is a real issue for employers and employees.

1. Maximum respondents are satisfied with their working hours and it is fit with their private life.
2. It is found that 30% of the respondents occasionally work for long hours, overtime and even on holidays.
3. 50% of the respondents have moderate and only 10% and of the respondents have very high work stress.

4. It is found that some respondents are able to balance their work life properly.
5. It is found that maximum respondents are missing their quality time with their family and friends because of work pressure.
6. Maximum respondents are not able to find the time for their hobbies and other personal activities because of their work load.
7. Overtime, target, working hours, working on holidays are the factors that affect more in balancing respondents work life.
8. Family support is the most important factor apart from flexible hours which helps them in balancing their work life.
9. It is found that work life balance is the biggest challenge for working women as per 92% of the respondents.

#### **SUGGESTIONS:**

Based on data analysis and interpretation the following suggestions are drawn in favor of working women, which help them to balance work-life balance.

##### **• Suggestions to working women's:**

1. There is a need to drop the activities that may sap the time and energy of women.
2. They have to set the priorities for every task so that they can able to manage their time properly.
3. They have to leave their work stress at office only and should not need to bring it at home.
4. They always need family support so that they can able to manage or balance work life properly.
5. They need to give sometime for their health and mental relaxation.

##### **• Suggestions to organization:**

1. Organizations have to avoid as far as possible the long hours of work for women employees.
2. Organizations have to organize training and development programs for working women.
3. Organizations have to take an initiative to nominate WLB champions for better balanced working women.
4. Organization need to provide child care centers at work place.
5. There is a need to make workplace more women friendly, reducing communication gap between women and boss, provide basic amenities and facilities like; security, canteen facility, toilet rooms, separate rest rooms for women etc.

#### **REFERENCES**

- [1] Mani V. Work Life Balance and Women Professionals. Global Journal of Management and Business Research Interdisciplinary 2013; 13(5): 2013.
- [2] Santhana Lakshmi K, SujathaGopinath S. Work Life Balance of Women Employees with reference to Teaching faculties. International Monthly Refereed Journal of Research in Management and Technology 2013; II.
- [3] Kumari KT, Devi VR. Impact of Demographic Variables on Work Life Balance of Women Employees (with special reference to Bangalore City). International Journal of Advances in Management and Economics 2012; 1(6): 226-229
- [4] P. Subba Rao "Personnel and Human Resource Management"

---

## INFORMATION NEED AND ACCESS PATTERN OF HOMOEOPATHIC TEACHERS OF BHARATESH HOMOEOPATHIC MEDICAL COLLEGE: A STUDY

**Mrs. Sunita S. Patil**

Research Scholar,  
Rani Channamma University, Belagavi.

**Dr. Maranna .O.**

Asst. Professor,  
Dept. of Library and Information Science,  
Rani Channamma University, Belagavi.

### ABSTRACT:

All libraries are established and maintained for users, so users are treated as the most important components, irrespective of type and size. An effort has been made in this study to identify the information need and access pattern of homoeopathic faculty of Bharatesh Homoeopathic Medical College library, Belgaum, Karnataka. The main objective of this research study is to analyze the information access pattern of teachers in the field of Homoeopathic medical science. The survey was conducted to look more closely at specific areas of the study for an in depth examination of trends and patterns in searching information. It is found that almost all teachers are using print material than non print material for study purpose.

**KEYWORDS:** Information needs, Access pattern, Homoeopathy, users seeking behavior.

### 1. INTRODUCTION

Twenty first century is the century of information explosion. The information needs of the users are also increasing day by day to have an access to the widest possible range of literature. Under these circumstances the medical college libraries have to play their role as real centers of intellectual activity and to disseminate knowledge. The information need for physicians has become complex and problematic due to the tremendous publications and interdisciplinary researches that are being undertaken at higher level. The librarians working in those medical institutions need to pay sincere attention to acquire appropriate and need- based literature in these subjects up to the utmost satisfaction of physicians. In this critical situation, librarians should have a clear understanding of their users' needs and their professed information seeking behavior.<sup>1</sup>

### 2. INFORMATION NEED AND USE PATTERN

The homoeopathic medical science teachers of today need more efficient and effective access to information as and when new techniques are developed around the world. Compare to the electronic resources most of the homoeopathic teachers gives first preference towards print resources. Because there are less homoeopathy books in electronic form. In India there is need for designing and development of homoeopathic information resources. The main purpose of information need of homoeopathic teachers is for three purposes namely for teaching, research & for clinical practice for patient care. The teachers which are involved in homoeopathic research need information from source books so they depend on the library only. The teachers give first preference to source books then classical homoeopathy and third priority to the journals. Most of the teachers use departmental library for their current information need.

A doctor always needs latest information. A group of users with same level of education may be working on the same subject at the same time but they use the information in different patterns. Some of the group may feel a part of information is relevant but others may not. It may also happen that some of them may scan and absorb the vast quantities of material while others may read only a part of it. Thus, every individual has his own patterns while collecting or gathering information.

### 3. NEED FOR THE STUDY

This study is restricted to the Information Need and Access Pattern of teachers of Bharatesh Homoeopathic Medical College Belgaum- A study. The main aim of the study is to measure the success and failure of the reading habits and the variety of interests of the teachers in their fields such as general and subject oriented.

#### 4. REVIEW OF LITERATURE

**Umesh and Divyananda (2016)** examined the Use Pattern of Library and Information Centre by Medical Practitioners in Medical Research Institutes at Bangalore. Author examined the medical practitioners approach to the different type of information sources, their current information need, problems and difficulties faced by the doctors. It was found that practitioners visit library once in a week. Most of the time they visit library for various purpose like reference of books & journals, access web resources and prefer print along with e- resource. Practitioners stated that they are partially satisfied from the library collection. The survey revealed that medical practitioners were well aware of library resources and services. They use web resources for the clinical practice. In another study undertaken by **Perera (2014)** it was reported that information seeking purpose of faculty was for teaching, research, updating knowledge and writing articles. Most of the lecturers used information for preparation of exams. HINARI was the most used database, whereas Medline-PUBMED the most used resource. Study has also been found those faculties are using personal collections of resources than visiting library.

**Pareek and Rana (2013)** conducted a study to find out the information seeking behavior and library use by research scholars at the Banasthali University. Study reported that central library and internet are the most reliable sources for seeking information. Whereas other library are less used by the researchers. Study also revealed that library has lack of information materials according their need, and library opening hours are also not sufficient, researchers don't know to search documents in library. It has been suggested to give training for researchers and to do

marketing library services. **Ocheibi and Buba (2003)** in their respective research contend that medical doctors need information to keep up current development in their chosen field. Study also revealed that doctors spend longer time in library, because of non availability of electronic media such as databases, both online and CD-ROM and also internet facility.

#### 5. OBJECTIVES OF THE STUDY

The main objectives of this research study are:

1. To identify the information needs of homoeopathic teachers.
2. To identify the frequency of visit to library by the teachers.
3. To identify the purpose of the teachers visit.
4. The level of satisfaction on the access and services provided in the library
5. The level of satisfaction of infrastructure, working time, procedures of the library.
6. To know the impact of IT on information seeking behavior of teachers.

#### 6. BHARATESH HOMEOPATHIC MEDICAL COLLEGE: A Profile

Bharatesh Homoeopathic Medical College & Hospital is situated in Belgaum. This college is one of the premiere institutes in Karnataka state rendering quality education in Homoeopathy. The college was established in 1982 and has grown to great heights and achieved excellence in imparting Homoeopathic education. It has well equipped laboratories, independent departments and other infrastructure as per the Government norms. The real strength of the institute is the well experienced and dedicated staff, well established hospital as well as peripheral OPD with all required facilities. Since beginning of this college it is providing quality education and producing renowned homoeopathic practitioners all over the country.

#### 7. LIBRARY AN OVERVIEW:



The Library of Bharatesh Homoeopathic Medical College was established in the year of 1982. The College central library has 9093 volumes covering more than 2341 titles. The Library subscribes to various Indian and International Periodicals, Journals and Magazines. Library is partially automated using NewGenLib Library software. Circulation of the books takes place through automation. All the books in library are bar-coded for transaction. The Online Public Access Catalogue system is provided for the benefit of the users. BHMCH has subscribed e-Journals, e books and Databases under HELINET consortium of Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore to motivate the researchers, students and faculty. In this way the library is providing all the UG & PG students the required facilities for their best education.

#### 8. METHODOLOGY:

The present study is based on primary data collected from the faculty members through a well designed questionnaire. In addition, secondary data have been collected from the sources of journals, reference books and conference proceedings. The data collected were tabulated and analyzed.

#### 9. SCOPE AND LIMITATION OF THE STUDY:

The scope of the study is restricted only to the faculty members of Bharatesh Homeopathic Medical College, Belgaum: A study. The target population for data collection was all 46 (100%) teachers of the Homeopathic College.

#### 10. DATA ANALYSIS AND FINDINGS

The questionnaire was distributed among all the homoeopathic teachers to obtain various types of information with regard to their needs and seeking patterns. A total No. of 46 questionnaires were circulated among the teachers and received 41 (89.13%) respond.

##### 10.1 Designation and Gender Wise Distribution

The designation and gender wise distribution of the respondents has been summarized in the form of table No.10.1

**Table – 10.1**  
**Designation and Gender Wise Distribution**

Sl. No	Gender	Designation				Total %
		Professors	Asso. Professors/ Reader	Asst. Professors/ Lecturer	Guest Faculty	
1	Male	12 (40%)	08 (26.66%)	08 (26.66%)	02 (6.66%)	30 (73.17%)
2	Female	04(36.36%)	03(27.27%)	03 (27.27%)	01 (9.09%)	11 (26.82%)

Above table shows designation and gender wise distribution of teachers, 30 (73.17%) respondents are male in that 12 (40%) are professors 16 (53.33%) are Associate Professors and Assistant Professors and guest faculty are only 2(6.66%). 11(26.82%) are female respondents.

**Table – 10.2 Implementation of Automation**

Sl. No	Level of Satisfaction	No. of Samples	%
1	Fully Satisfied	36	87.80
2	Not Satisfied	05	12.19
	Total	41	100

Table – 10.2 shows that the 87.80% teachers are satisfied with the implementation of library Automation; where as 12.19% of teachers are not satisfied.

**Table No. 10. 3 Frequencies of Borrowing Books from the Library**

Sl.No	Frequencies of Borrowing Books	No. of Respondents	%
-------	--------------------------------	--------------------	---

1	Daily	08	19.51
2	Every alternate day	06	14.63
3	Once in a week	03	7.31
4	Once in 15 days	02	4.87
5	Once in a month	04	9.75
6	As & when required	18	43.90
	Total	41	100

From the above Table no. 10.3 it is observed that 44% teachers are borrowing books from as an when required, whereas 20% of the teachers borrow books daily and 15% of the teachers borrow the books every alternate day. 7% of the teachers visit library once in a week and 5% of the teachers visiting library to borrow the books once in 15 days, whereas 10% of the teachers visit the library once in a month.

**Table – 10.4 Purpose of visiting Library**

Sl.No	Purpose of visiting Library	No. of Respondents	%
1	Preparing Lecture notes	09	21.95
2	Preparing questions for Periodical test	05	12.19
3	Setting assignment for students	03	7.31
4	Guide to students for Seminar	03	7.31
5	Prepare articles for publications, conference	04	9.75
6	Reading News paper and Journals	05	12.19
7	Enriching knowledge in subject Area	08	19.51
8	Research work	04	9.75
	Total	41	100

Table no.10.4 shows the purpose of visit by the teachers for accessing of information. 22% of the teachers visit the library for preparing lecture notes. 12.19% for preparing questions for periodical test and for reading news paper. 7.31% for setting assignment for students. 7.31% visit to guide to students for seminar. 10% of teachers visit library for preparing articles for conference and publications and for research work. 19.51% visit library for enriching knowledge in their subject area.

**Table –10. 5 Subject Books Available in the Library**

Sl.No	Books Available in the Library	No. of Respondents	%
1	Very Few	7	17.07
2	Few	05	12.19
3	Sufficient	25	60.97
4	Many	04	9.75
	Total	41	100

It is known from the above table no.10.5 that 60.97% of the teachers express that the books available in the library are sufficient. 17.07% express that very few and 12.19% express that few subject books are available in the library. 10% of the teachers express that many books are available in the library

**Table – 10.6 Users Satisfaction of the Library Services**

Sl.No	Library Services	No. of Respondents	%
1	Circulation	10	24.39
2	Reference	19	46.34
3	Photo copying	03	7.31
4	CAS Services	04	9.75

5	Internet	05	12.19
	Total	41	100

Table no. 10.6 indicates that the teachers are satisfied cent percent with reference service and circulation service 71%. 29% of the teachers are satisfied with photo copying, current awareness service and internet service.

#### **FINDINGS**

1. In relation to 41 teachers 36(87.80%) teachers are satisfied with the implementation of library Automation; whereas 5(12.19%) teachers are not satisfied.
2. The majority of teachers 18(44%) are visiting library to borrow the books as a when required.
3. About 41 teachers 9(22%) teachers visits the library for preparing lecture notes and 8(20%) visit library for Enriching knowledge in their subject Area
4. Majority of the teachers 25(61%) expressed that the books available in the library are sufficient.
5. Teachers are satisfied with library services with reference and circulation services 29(71%).
6. Due to the departmental library and location of the library on the top floor of the building visiting of the teachers is very less.

#### **SUGGESTIONS**

- There should be fully automated services to accelerate the retrieval and dissemination of information.
- The library should send alerts regarding information to all the departments.
- The librarian should encourage the teachers to visit the library.
- The library location should be in center place in the college building.

#### **CONCLUSION**

The teachers in this study area have different levels of knowledge on information services. Due to the departmental library visiting percentage decreased. Majority of the teachers are utilizing the library only for preparing lecture notes and also for enriching knowledge in their subject area. The study also marked the teachers visiting period for borrowing books. Based on the use pattern of the college libraries, care has been taken to attract the teachers to visit library more frequently and spend their valuable time in the library to make use of the library information resources, services and facilities to meet their needs.

#### **REFERENCES:**

1. Premmit, P.(1990). Information needs of academic Medical Scientists at Chulalongkom University. Bulletin of Medical Library Association, 78(4), 383-387.
2. Padmaja, M. and Kishore (2014). A Perception and Expectation of the users in S.V. Ayurvedic College, Tirupati – A Case Study vol.2(6), 1-5.
3. <https://www.collegedekho.com/colleges/bharatesh-homoeopathic-medical-college-belgaum>
4. Umesh S. D. and Divyananda, K. (2016). Use Pattern of Library and Information Centre by Medical Practitioners in Medical Research Institutes At Bangalore: A Study. International Journal of Information Research and Review, 3 (1), 1691-1699.
5. Perera, P.A.S.H.(2014). Preferences and Pattern of Information Seeking of Academics of Health Related Faculties, University of Peardeniya (UoP). Journal of the University Librarians Association of Sri Lanka, 18 (2), 62-75.
6. Pareek, A.K. and Rana, Madan S. (2013). "Study of Information Seeking Behavior and Library Use Pattern of Researchers in the Banasthali University" Library Philosophy and Practice (e-journal). 887.
7. Ocheibi, J. A, & Buba, A. (2003). Information Needs And Information Gathering Behaviour Of Medical Doctors In Maiduguri, Nigeria. Journal Of Educational Media And Library, 44(4), 417–427.

### शेती विकासातील संबंधीत सार्वजनिक कंपन्या

मार्गदर्शक

प्रा. डॉ. एस.एल. शिरगावे

कला, वाणिज्य महाविद्यालय

दौंड

ता. दौंड, जि. पुणे.

संशोधक विद्यार्थी

शेख कमरुन्निसा अ.हमीद

कला, वाणिज्य व विज्ञान

महाविद्यालय केडगाव

ता. दौंड, जि. पुणे.

9766737394

**सारांश :** भारत हा शेतीवर आधारित देश आहे, शेती शेताचा विकास झाला तरच भारताचा विकास होईल, म्हणून शासनाने शेती क्षेत्राच्या विकासाला योगदान करणाऱ्या सार्वजनिक कंपन्या स्थापन केल्या. यामध्ये प्रामुख्याने N.D.D.B. राष्ट्रीय डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलायझेशन, महाबिज, राष्ट्रीय अन्न महामंडळ, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यासारख्या.

#### प्रस्तावना :

भारत हा कृषी प्रधान देश आहे, पूर्व गोलार्धातील आशिया खंडातील भारत हा एक महत्वाचा देश आहे. भारतात एकूण 26 घटक राज्य आहेत त्यापैकी 'महाराष्ट्र' हे एक महत्वाचे राज्य आहे. 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्राची स्थापना झाली. भारतातील 60 टक्के लोकसंख्या ही कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. शेती क्षेत्रावर आधारित अनेक व्यवसाय कार्यरत आहेत. देशाचा विकास करावयाचा असेल तर व्यवसायाचा विकास करणे आवश्यक आहे. 75 टक्के व्यवसाय हे शेती क्षेत्रावर अवलंबून आहे. म्हणून शेती क्षेत्राच्या विकासाला योगदान करणारे सार्वजनिक उद्योग शासनाने स्थापन केलेले आहेत. त्याचा थोडक्यात माहिती या लेखात मांडली जाणार आहे. अनेक कंपन्या स्थापन केल्या या प्रमुख कंपन्यांची स्थापना उद्दिष्ट या लेखात पाहणार आहोत.

#### 1) राष्ट्रीय दुग्ध विकास महामंडळ :

भारत हा कृषी प्रधान देश असल्यामुळे इतर देशांच्या तुलनेत भारतातील पशुंची संख्या जास्त आहे. देशातील शेतकऱ्यांच्या दुग्ध विकासाला न्याय देण्यासाठी, जनतेची दुधाची गरज भागविण्यासाठी सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी गुजरात येथील 'खेडा' जिल्ह्यात सहकारी समितीची संकल्पना मांडली, सुरुवातीला मुंबई सरकारने त्यास विरोध केला. शेतकऱ्यांनी 15 दिवसांचा बंद राष्ट्रीय दुग्ध विकास महामंडळाची स्थापना 1965 मध्ये गुजरात येथील 'आनंद' या ठिकाणी सुरु करण्यात आली. डॉ. वर्गिस कुरियन हे या महामंडळाचे पहिले चेअरमन होते. राष्ट्रीय दुग्ध विकास महामंडळाने बंद पुकारल्यानंतर मुंबई सरकारने त्यास परवानगी दिली. 1964 मध्ये पंतप्रधान लाल

बहादूर शास्त्री यांनी सहकारी दुग्ध संस्थांना भेट दिली. त्यांनीच 'आनंद' येथे 1965 मध्ये राष्ट्रीय दुग्ध विकास महामंडळाची स्थापना केली.

राष्ट्रीय दुग्ध विकास महामंडळ अंतर्गत ग्रामिण/शहरी भागाचा विकास करण्यासाठी दुग्ध महापूर योजना राबविण्यात आली.

### 1) दुग्ध महापूर योजना 1ली :

1960 ते 1981 या दरम्यान पहिली दुग्ध महापूर योजना राबविण्यात आली. या योजनेचे महत्वाचे 2 उद्दिष्टे असे होते की, सहकारी संस्थांची स्थापना करणे आणि त्या सहकारी संस्था भारतातील चार महानगरांशी जोडणे की ज्यामुळे सहकारी संस्थांची वाढ होईल आणि सर्वसामान्य जनतेपर्यंत दुधाची गरज पूर्ण करता येईल.

### 2) दुग्ध महापूर योजना 2री :

1981-85 या कालावधीत आहे.

### 3) दुग्ध महापूर योजना 3री :

1985-86 या दरम्यान दुग्ध महापूर योजना 3री राबविण्यात आली.

दुग्ध महापूर योजनेनंतर मात्र दुग्ध उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली ग्रामिण भागातील दुग्ध उत्पादन वाढले. महाराष्ट्रातील 36 शहरांमध्ये शासकीय दुग्ध योजना अंमलात आणली गेली. त्यामुळे जिल्हा व तालुका पातळीवरील सहकारी संस्थांचा विकास होण्यास मदत झाली.

दुग्ध उत्पादनातील वाढीमुळे भारतात अनेक नविन डेअरी प्रकल्प स्थापन झाले या प्रकल्पांतर्गत दुग्ध व्यवसायात झपाट्याने वाढ झाली, दुधावर प्रक्रिया करून दुग्धजन्य पदार्थ तयार केले जाऊ लागले. त्याची विक्री भारतातील प्रत्येक शहरी व ग्रामिण भागात करण्यात येऊ लागली.

राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्ड यांच्या अधिनियम कायदा 1987 नुसार ही संस्था दुग्ध व्यवसाय व शेतीवर आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देते.

राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्ड :

- शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी नवनविन योजना आखते.
- दुग्ध सहकारी संस्थांच्या स्थापनेस परवानगी देते.
- दुग्ध सहकारी संस्थांना कर्ज उपलब्ध करून देते.
- पशुंच्या आहारातील घटक हा पोषकयुक्त असावे म्हणून प्रयत्न करते.
- पशुंच्या आहारासाठी नवनविन यंत्रे कशी वापरावित यासाठी प्रशिक्षण देते.
- आहारावरील खर्च कमी करण्यासाठी नविन यंत्राचा उपयोग कसा करावा यासाठी त्यांना प्रशिक्षण देते.

- चारा उत्पादन व आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रम या विषयावर प्रशिक्षण दिले गेले.
- निवड केलेल्या 120 गावांमध्ये हिरव्या चान्याचे संरक्षण कसे करावे यावर प्रशिक्षण देण्यात येते.
- पशुंची देखरेख करणे, त्यांना खाऊ घालणे, दुग्ध करणे यासाठी आधुनिक पद्धतीच्या मशिनरींचा उपयोग कसा करावा यासाठी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येते.
- ग्रामिण भागात जावून दुधारू पशुंना लसीकरण करण्यात येते. लसीकरणात कोणतीही चूक होवू नये म्हणून त्यांच्या कानावर टॅग लावण्यात येते.
- N.D.D.B. ने 12 राज्यात 19 विर्या केंद्राची स्थापना केलेली आहे.
- विर्या केंद्रामुळे कृत्रिमरित्या पशु पैदाईश केली जाते की ज्यामुळे चांगल्या चांगल्या दुभत्या जातीचे पशु कृत्रिमरित्या विर्यामुळे तयार केले जाते.

## 2) राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलायझेशन :

देशाचा सर्वांगिन विकास हा शेती क्षेत्रावर अवलंबून आहे, म्हणून शेतीसाठी आवश्यक प्रत्येक घटक हा दर्जेदार असणे आवश्यक आहे. जर शेतीला पूरक साधने दर्जेदार असतील तरच शेती सुद्धा दर्जेदार होईल ही बाब शासनाने ओळखली आणि म्हणूनच राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलायझेशन <sup>तत्त्व</sup>ची स्थापना शासनाने केली. आलीबाग येथील 'थळ' येथे 1967 साली देशातील सर्वात मोठा आकाराचा खत निर्मितीचा प्रकल्प शासनाने सुरु केला.

## R.C.F. राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलायझेशन ची कार्यपद्धती :

- 1967 साली सर्व प्रथम 'सुफला' हे खत बाजारात आणले.
- शेतीक्षेत्रासाठी आवश्यक उच्च दर्जाचे खत तयार करणे की ज्यामुळे शेतीक्षेत्रातून उत्पादित होणाऱ्या वस्तू दर्जेदार असतील.
- शेतकऱ्यांना दर्जेदार खते कमी किंमतीत शासनाकडून प्राप्त होतील, म्हणून शासन वेळोवेळी प्रयत्न करते.
- शेतकऱ्यांनी खते कसे वापरावित, किती प्रमाणात वापरावित, कोणती वापरावी, कोणत्यावेळेत वापरावी या विषयीचे माहिती देणारे प्रदर्शन भरविण्याचे काम <sup>तत्त्व</sup>कडून केले जाते.
- <sup>तत्त्व</sup>च्या माध्यमातून भारतातील प्रत्येक राज्यातील तालुका पातळीत शेतकी कार्यालयात खताचा पुरवठा केला जातो. तसेच रासायनिक औषधे, खते हे प्रत्येक ग्रामिण भागातील खत विक्रेता दुकानातून शेतकऱ्यांना खते आणि रासायनिक औषधे उपलब्ध करून देण्यात यावी.
- मार्च 2015 मध्ये R.C.F. ला 'नवरत्न' पुरस्कार प्राप्त झाला.

## 3) महाबिज :



भारत सरकारने प्रमाणित बी-बियाणांच्या पुरवठ्यासाठी राष्ट्रीय बियाणे महामंडळाची स्थापना केली.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना बियाणांचा पुरवठा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळाची स्थापना 1975-76 मध्ये करण्यात आली. महाराष्ट्रातील अकोला या ठिकाणी महाबिजचे मुख्यालय आहे.

शेतकरी कर्ज काढण्यात बी-बियाणे खरेदी करतात, त्या बियाणांच्या आधारे शेतात अन्न धान्य उगवतात. परंतु जर बियाणे दर्जेदार नसतील तर शेतकऱ्यांचा वेळ, श्रम, पैसा यांचे नुकसान होते. म्हणून शेतकऱ्यांना दर्जेदार बी-बियाणे मिळावीत म्हणून महाबिजची स्थापना करण्यात आली.

#### महाबिज ची उद्दिष्टे :

- शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्न देणारे बी-बियाणे मिळावेत.
- शेतकऱ्यांना कमी किंमतीत दर्जेदार बी-बियाणे मिळावेत.
- शेतकऱ्यांना बियाणांबरोबरच किटकनाशक औषध मिळावेत.
- शेतकऱ्यांना सुधारीत बी-बियाणांबरोबरच जंतूनाशक फवारणी कशी करावी, किटक पक्षी, यांच्यामुळे शेतमालाचे नुकसान होवू नये म्हणून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे इ. महत्वपूर्ण काम महाबिज अंतर्गत केली जातात.
- शेतकऱ्यांना तालुका शेती कार्यालयामार्फत महाबिजची सुविधा शासनाने उपलब्ध करून दिलेली आहे.
- तालुका शेती विभागामुळे कोणत्या तालुक्यातील किती शेतकरी महाबिज मार्फत खरेदी करतात याची नोंद कार्यालयाकडे असल्यामुळे शासनाला त्याचा फायदा होतो.

#### भारताचे अन्न महामंडळ :

शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात अन्न धान्य खरेदी करून ते देशातील नागरीकांना पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देण्याची महत्वपूर्ण जबाबदारी भारताचे अन्न महामंडळ स्विकारत आहे. 70 टक्के भारतीयांच्या रोजगाराचे साधन शेती हे आहे, अन्न धान्याचे उत्पदान करणारा भारत हा एक मोठा देश आहे, आणि तरीही अन्न धान्यासाठी इतर देशावर अवलंबून राहणे ही एक लाजीरवाणी बाब आहे. तसेच ही बाब फार धोकादायक आहे. म्हणून देशातील प्रत्येक नागरीकाला पोटभर अन्न मिळावे, कोणीही उपाशी राहू नये, या भूमिकेतून केंद्र शासनाने 1969 मध्ये भारताच्या अन्न महामंडळाची स्थापना केली.

हे अन्न महामंडळ हे अन्न धान्याची खरेदी करणे, साठवणूक करणे, वाहतुक करणे, वाटप करणे, आणि विक्री करणे ही महत्त्वपूर्ण कार्ये करते.

**अन्न महामंडळाची उद्दिष्टे :**

- देशातील प्रत्येक नागरीकाला पोटभर अन्न मिळावे.
- गरजू व गरीब लोकांना सवलतीच्या दराने अन्न धान्य मिळावे.
- शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करणे.
- सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून संपूर्ण देशात खाद्य अन्नाचे वितरण करणे.
- शेतकऱ्यांना त्यांच्या वस्तूची कायदेशीर किंमत प्राप्त करून देणे.
- अन्न धान्याची व्यवस्थित वाटप करणे.
- अन्न धान्याच्या वाढीसाठी शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करणे.
- अन्न धान्याच्या गैरव्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणे.

भारतीय अन्न महामंडळाचा मोठ्या प्रमाणात विकास होत गेलेला आहे, भारतीय अन्न महामंडळ, अफगानिस्थान, यमन येथे गहू, तांदूळ यांची निर्यात करते.

वरील सार्वजनिक संस्था व्यतिरिक्त इतर भारतीय द्राक्ष महामंडळ, आरे यासारख्या अनेक संस्था आहेत की, ज्या शेतीच्या विकासात योगदान करतात. तसेच शासनाच्या माध्यमातून कृषी प्रदर्शन भरविणे, शेतकऱ्यांना नवनवनि तंत्रज्ञान, नविन पिके, आधुनिक शेती, शेतीस पूरक उद्योग यांची माहिती दिली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळते.

**संदर्भ साहित्य.**

- भारतीय अर्थ व्यवस्था
- व्यवसायिक अर्थशास्त्र
- 'शेतीमित्र साप्ताहिक'
- 'अॅग्रोवन' साप्ताहिक'
- Agricultural and Rural Economics
- [www.mahabeej.com](http://www.mahabeej.com)
- [www.nddb.com](http://www.nddb.com)
- [www.rcf.com](http://www.rcf.com)
- [www.ifc.com](http://www.ifc.com)
- [www.agroone.com](http://www.agroone.com)

## कुसुमाग्रजांच्या कवितेतील सामाजिकता

प्रा. संतोष सदाशिव देते

मराठी विभाग प्रमुख

श्री शिवाजी कला, वाणिज्य व विज्ञान

महाविद्यालय, राजुरा, जि. चंद्रपूर

वि.वा. शिरवाडकर यांचे खरे नाव गजानन रंगनाथ शिरवाडकर. दत्तक गेल्यामुळे त्यांचे नाव विष्णू वामन शिरवाडकर झाले. २७ फेब्रुवारी १९१२ साली त्यांचा जन्म पुणे येथे झाला. प्राथमिक शिक्षण पिंपळगाव व माध्यमिक शिक्षण नाशिक येथील न्यू इंग्लिश स्कुल येथे पूर्ण झाले. १९३४ मध्ये बी.ए. परीक्षा उत्तीर्ण केली. १९४४ मध्ये मनोरमा यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला. शिक्षण घेत असतानाच त्यांनी लेखनाला प्रारंभ केला. प्रभा साप्ताहिक, प्रभात वृत्तपत्र, सारथी, धनुर्धरी व नवयुग इत्यादीमध्ये पत्रकारिता केली. त्यांचा आवडता लेखक पी.जी. वुडहाऊस व आवडता नट चार्ली चाप्लिन होता. प्रथम विविध नियतकालिकातून संपादन म्हणून कार्य केले व पुढे लेखक हाच व्यवसाय स्विकारला. १९६४ साली ४५ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे ते अध्यक्ष होते. वि.स. खांडेकरांनंतर त्यांना १९८८ मध्ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाला. १९८६ मध्ये पुणे विद्यापीठाने त्यांना डि.लिट् ही सन्माननीय पदवी प्रदान केली.

कवी कुसुमाग्रजांचे मराठी साहित्यात मोलाचे योगदान आहे. त्यांच्या नावे २४ काव्यसंग्रह, १९ नाटके, १६ कथासंग्रह, ३ कादंबऱ्या, ४ लेखसंग्रह, ५ एकांकिका असं त्यांचं समग्र साहित्य विश्व आहे. त्यांच्या 'मराठी माती', 'स्वगत', 'हिमरेषा' (काव्यसंग्रह) 'ययाती व देवयांनी', 'बीज म्हणाली धरतीला', 'नटसम्राट' (नाटक) इत्यादी साहित्यकृतींना राज्य पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे. तसेच 'नटसम्राट' ह्या नाटकाला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिळाला. १९२० ते १९३० या काळात कवितेच्या प्रांतात 'रविकिरण मंडळ' हे नाव दुमदुमत होते. रविकिरण मंडळातील सामील झालेले जे कवी होते ते आपल्या प्रतिभेने चमकत होते. १९३५ ते १९४५ या कालखंडात एका बाजुने बा.भ. बोरकरांची सौंदर्यवादी कविता बहरत होती, तर दुसऱ्या बाजुने कुसुमाग्रजांची सामाजिक समतेच्या ललकाच्या देणारी आणि राजकीय क्रांतीचा जयजयकार करणारी कविता धगधगत होती. कवी कुसुमाग्रजांच्या कविता इतक्या प्रभावी होत्या की त्या काळात 'ज्योत्स्ना' व 'प्रतिभा' मासिकात केवळ काही कवितांमुळे ते अवघ्या महाराष्ट्राचे लाडके कवी बनले.

कुसुमाग्रजांची बरीचशी कविता ही आरंभापासून आजतागायत सामाजिक जाणीव व्यक्त करणारी कविता म्हणूनच अवतली आहे. 'विशाखा' काव्य संग्रहातील त्यांच्या सामाजिक जाणिवेच्या कविता इतक्या प्रखर नि तेजस्वी आहेत की अनेकांनी त्यांना एकमुखाने केशवसुतांचे उत्तराधिकारी ठरविले. अर्थातच कुसुमाग्रजांच्या सामाजिक कविता केशवसुतांच्या सामाजिक कवितेच्या फार पुढे गेलेली कविता आहे. कारण केवळ सामाजिक जाणीव व्यक्त करून कुसुमाग्रज थांबत नाहीत ते समाजाचे सादपडसाद टिपतात. कुसुमाग्रजांना गरजू व गरीब लोकांबद्दल त्यांच्या मनात खूप कळवळा होता. गोरगरीब लोकांबद्दल जे प्रेम होते ते त्यांच्या कार्यावरून सहज दिसून येते. साहित्य प्रवाहाबरोबर माणूस म्हणून त्यांच्या वेगळ्या व्यक्तिमत्व अभ्यासायचं तर अनेक पैलुनी ते पहावे लागेल. कुसुमाग्रज अग्निप्रदाची कवी म्हणून ओळखले जातात. क्रांतीकारी आणि क्रांतीपूजक कविता लिहिणारे कवी म्हणून कुसुमाग्रज प्रसिद्ध आहे. ओजस्वी भाषा, प्रखर आपेश, राष्ट्रीयत्व, विश्ववर्तुत्व इत्यादी वैशिष्ट्यांनी त्यांच्या कविता परिपूर्ण आहे. 'जीवनलहरी', 'विशाखा', 'किनारा' यासारख्या काव्यसंग्रहांनी काव्यक्षेत्रात त्यांनी मानाचे स्थान मिळविले. कथा, कादंबरी, नाटक आणि काव्य हे सर्व वाङ्मय प्रकार कुसुमाग्रजांनी समर्थपणे लिहिले असले तरी कवी आणि नाटककार म्हणूनच ते जास्त रसिकमान्य आहेत.

कवी कुसुमाग्रजांची प्रतिमा मुळातच काव्यात दिसून येते. त्यांच्या प्रतिमेला कल्पनेचा साज आहे. कुसुमाग्रजांचा पिंड जीवनवादी आहे म्हणून प्रखर जीवननिष्ठा ही त्यांच्या वाङ्मयनिर्मितीची आद्य प्रेरणा आहे. कुसुमाग्रज हे समतेचे निष्ठावंत उपासक असून त्यांच्या विचारांना व भावनांना ध्येयवादाची ओढ आहे. तसेच अन्यायाविरुद्ध झुंज देण्याची तिच्यात एक उग्र जिद्द आहे. त्यांच्या सामाजिक कवितेचा आपण जर अभ्यास केल्यास प्रखर आवेश, विषमतेची चीड, ओजस्वी भाषा,

मानवतेवरील प्रेम, उत्तुंग कल्पनावैभव, नाट्यामकता इ. गुणांनी त्यांच्या कविता सजलेल्या आहेत. कुसुमाग्रजांचे सर्वच काव्य भावीकट आहे. त्यात अग्निची दाहकता आहे. कुसुमाग्रजांची कविता जे व्यक्त करते ते इतके रेखीवपणे व्यक्त झालेले असते की ते पाहताच डोळ्यांचे पारणे फिटते.

केशवसुत व कुसुमाग्रज यांच्या सामाजिक विचारांचे नाते परस्परांशी जुळणारे आहे. सामाजिक विषमतेचा प्रश्न हा केवळ वर्तमान काळातील नाही तर पिढ्या न पिढ्या चालत आलेला सनातन प्रश्न आहे. केवळ महाराष्ट्र वा भारत यापुरता तो मर्यादित नाही तर, श्रीमंत व गरीब, उच्च—नीच, स्पृश्य—अस्पृश्य यांच्यातील संघर्षाच्या स्वरूपातील जगातील देशादेशांत त्यांचे अस्तित्व आहे. ही विषमता निपटून काढावयाची असेल तर, प्रखर आंदोलन उभारून, क्रांती घडवून आणली पाहिजे त्यासाठी बहुजन, दलितानां आपल्यातील ताकद एकत्रित केली पाहिजे असे कुसुमाग्रजांना वाटत होते. त्यांच्या काही महत्वपूर्ण कवितांचा परामर्श घेऊन त्यांच्या कवितेतील सामाजिकमन, सामाजिक बांधिलकी, समाजनिष्ठा किती प्रगल्भ आहे ह्याची कारणमीमांसा आपण करणार नाही तोपर्यंत त्यांच्या सामाजिक जाणीवा आपणास कळणार नाही.

कवी कुसुमाग्रजांच्या कवितेचा पिंड हा व्यक्तिगत जाणिव व्यक्त करण्यापेक्षा समाजमनाच्या आशा—आकांक्षा स्पष्ट करणारा आहे. त्यांच्या सामाजिक कविता व्यक्तिगत जाणिवेपेक्षा सामाजिक जाणिवेशी एकरूप आहे. ‘जीवनलहरी’ या पहिल्या काव्यसंग्रहापासून कवीचे सामाजिक नाते समाजाशी कसे जुळलेले आहे हे सांगतांना कवी कुसुमाग्रज म्हणतो —

हजार हृदये गहिवरली तर  
मन माझेही गहिवरते  
असे हजारसंगे आहे  
जडलेले माझे नाते

प्रस्तुत काव्यपंक्तीतून व्यक्तिपेक्षा समाजमन किती श्रेष्ठ आहे हेच सुचित होते. म्हणून मानवतेची जाणीव त्यांच्या कवितेचा प्राण आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. आपण ज्या समाजात राहतो त्या समाजातील दैन्य, दारिद्र्य व दुःख हे आपले आहे असे कुसुमाग्रज मानतात. यावरून त्यांच्या मनात समाजाबद्दल किती प्रेम आहे हेच दर्शविते. आर्थिक विषमता ही विशिष्ट समाजरचनेमुळे झालेली आहे. कुसुमाग्रजांच्या ‘हिमलाट’, ‘बळी’, ‘लिलाव’, ‘सहानुभूती’ व ‘गुलाम’ इत्यादी कविता वाचल्या म्हणजे त्यांचा समाजवादी पिंड कसा मानवतावादी दृष्टिकोनावर आधारित आहे याचे दर्शन होते.

सामाजिक वास्तवाचे भान सतत बाळगणारे कुसुमाग्रज ‘हिमलाट’ सारखी रूपकात्मक कविता लिहून वास्तवाची जाणीव करून देतात. ही हिमलाट विषमतेची आहे. ज्या विषमतेने गरीबांचे जगणे कठीण होते तीच हिमलाट श्रीमंताच्या मद्यासाठी द्राक्षाचे मळे पिकविले पण जनतेच्या पोटाला लागणारे अन्नधान्याची शेते मात्र उध्वस्त करून टाकते तिचा प्रतिकार करण्यासाठी कवी अग्नीला आवाहन करते.

ज्योतिंतूनी धावत या तेजःकण सारे  
या यज्ञातील अन् सरणातील निखारे  
रेढाळ नभा, तव ते ज्वालामय तारे  
पेटवू ह्या वणवा कणाकणात मशाली

ही शोषणशक्ती नष्ट करावयाची असेल तर सामान्य जनतेने एकत्र आले पाहिजे. इथे कवीच्या मनातील आशावादी वृत्तीचा प्रत्यय येतो. समाजातील शोषणशक्ती सुद्धा हिमलाटेप्रमाणेच गरीबांचे जीणे उध्वस्त करत असते. हा आशय वरील कवितेतून अभिप्रेत आहे.

‘जालियनवाला बाग’ या कवितेत इंग्रज लोकांनी स्वातंत्र्यासाठी लढा देणाऱ्या सैनिकावर कसे अत्याचार केले आहेत या घटनेचे वास्तववादी वर्णन केले आहे. त्यातील हत्याकांड म्हणजे ‘असेल ही वा सैतानाची प्रभूवरी मात’ म्हणजेच इंग्रजांचे हे वर्तन म्हणजे येशुच्या काळजात केलेली नवीन जखमच आहे. उपरोधिक शब्दात कवी स्वतःच्या मनातील चीड व्यक्त करतात. प्रस्तुत कवितेत प्रत्येक शब्दांतून त्यांच्या मनातील चीड प्रखर शब्दांत व्यक्त होताना दिसते. ही चीड म्हणजे त्यांच्या मनातील सामाजिकतेची जाणीव स्पष्ट करणारी वाटते.

पाचोळ्यापरि पडली पाहून प्रेतांची रास  
नयन साकले असशील देवा तु अपुले खास  
या कवितेत माणसाकडूनच माणसाचा कसा संसार झाला ही जाणीव त्यांना व्यथित करते.

‘स्वप्नाची समाप्ती’ ही कुसुमाग्रजांची कविता आशयगर्भ असून प्रेमाची वैयक्तिक भावना व्यक्त करताना प्रियकर सामाजिक भान जपणारा आहे. ह्यावरून तो ध्येयाला जपणारा आहे म्हणूनच ध्येयवादी माणसाला वैयक्तिक जीवनाचे फारसे महत्त्व नसते. कवी म्हणतो,

काढ सखे, गळ्यातील  
तुझे चांदण्याचे हात  
क्षितिजाच्या पलिकडे  
उभे दिवसाचे दुत

आपल्या गळ्यातील करपाश काढण्यास सांगणारा प्रियकर हा समाजजीवनाला किती महत्त्व देणारा आहे याची साक्ष पटते. दिवसा परस्परांच्या करपाशात बद्ध झालेले पाहून लोक आपणास वेडे म्हणतील. आपण अपराधी ठरू याची जाण तो बाळगतो. कवी कुसुमाग्रजांच्या ‘पाचोळा’, ‘माळाचे मनोगत’, ‘बळी’, ‘अहि-नकुल’, ‘आगगाडी व जमीन’, ‘क्रांतीचा जयजयकार’, ‘जालियनवाला बाग’, ‘समाधान’, ‘ध्रुवपद’, ‘विराटवड’, ‘जा जरा पुर्वेकडे’ इत्यादी कवितांतून कवीच्या सामाजिक समकालीन वास्तवाचे प्रखर प्रतिबिंब पडलेले आहे. सामाजिक विषमतेचे चित्रण करताना कवींनी सामान्य कष्टकरी, श्रमिकवर्ग जनतेच्या दुःखाला वाचा फोडलेली दिसून येते.

‘विराट वड’ या कवितेतून कुसुमाग्रजांनी वडाच्या वृक्षाचे प्रथम सामर्थ्य नंतर केविलवाणी स्थिती वर्णन केलेली आहे. आपल्याजवळ कितीही सामर्थ्य, बळ, वैभव, सत्ता, संपत्ती असली तरी तीचा अंत होतोच. प्रारंभी काळावर मात करणाऱ्या वटवृक्षाला गर्व होता पण पुढे हा विजयच नको होता. हा विजय ‘काळाशी झुंजुन राहिला जेता’ या शब्दात व्यक्त केला. प्रारंभी मृत्युला जिंकण्याची भावना वटवृक्षाला सुखावून जात होती, पण आता स्वतःचे जगणे त्याला नकोसे होऊ लागले आहे. आपल्या जवळ सामर्थ्य असले की हजारो लोक आपल्याजवळ येत असतात पण सामर्थ्य नष्ट झाल्यावर साधी विचारपूस करीत नाही. ही समाजाची रीत वरील कवितेतून सुचित होते.

काळाशी झुंजुन राहिला जेता  
विजय परी तो, जाचतो आता  
लोढून काळास, ठाकला धीट  
आजला त्याचीच, पाहतो वाट

कुठपर्यंत आपण समाजाची जुनी, जीर्ण मूल्य जपणार आहोत, संस्कृतीत, समाजात रूढी, परंपरा, जुनी विचारधारा असतात त्या केव्हा ना केव्हा नष्ट होणारच जीवनशक्तीचा न्हास होतो तेव्हा मरणाशिवाय अशा संस्कृतीला पर्याय नसतो हेच कवी कुसुमाग्रजांनी ‘विराट वड’ या कवितेतून सुचित केले आहे.

‘आगगाडी व जमीन’ या कवितेत कवी कुसुमाग्रजांनी सामाजिक शोषणाचे दर्शन घडविले आहे. प्रस्तुत कवितेतील आशय हा शोषितांचा, दलितांचा तसेच अन्याय ग्रस्तांचा आहे. आगगाडी शोषण करणाऱ्या शक्तीचे प्रतीक आहे. तर जमीन ही शोषण, जुलूम सहन करणाऱ्या जनतेचे प्रतीक आहे. या आशयात एक प्रकारची मानवता आहे. शोषण करणाऱ्या शक्तीला नेहमीच आपल्या सामर्थ्याचा अभिमान, वर्ग, घमेंड असतो. आपल्या बळशिवाय त्यांना दुसरे महत्वाचे नसते. शोषित जीव नम्र व सहनशील असतात.

उठला क्षणार्थ, भयाण आक्रोश  
हादरे जंगल, कापले आकाश  
उलटी पालटी, होऊन गाडी ती  
हजार शकले, पडली खालती!

शोषितांच्या जीवावर आपण जगत असतो. त्याचे भान शोषक शक्तीला राहवत नाही. परिणामी दुबळी व भेकड असलेली शोषितांची शक्ती प्रसंगी जागृत होऊन शोषक शक्तीचा बळी घेत असते. म्हणून शोषण शक्तीने कधीही वर्ग करू नये.

‘अहि-नकुल’ या कवितेत एक रूपात्मक योजना करून सामाजिक विषमतेचे चित्रण कुसुमाग्रजांनी केले आहे. प्रस्तुत कविता सनातन संघर्षाचे प्रतिकात्मक स्वरूप आहे. साप आणि मुंगूस यांच्या हाडवैरांच्या माध्यमातून समाज जीवनातील संघर्ष चित्रित केला आहे. समाजजीवनातील गरीब-श्रीमंत यांच्यात निर्माण झालेली खोल दरी दृष्टीपुढे ठेवून कवी कुसुमाग्रजांनी अहि-नकुलाच्या रूपकाने समाजातील शोषक-शोषितांचे स्वरूप स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ही सामाजिक आशय स्पष्ट करणारी कविता ठरते. एकादा मनुष्य कितीही बलाढ्य असला तरी त्याला प्रतिस्पर्धी मिळाला तर तो नतमस्तक होतोच व त्याचा मानवी गर्व चकनाचुर होतो. या कवितेतून अखेर सत्याचाच विजय होतो हेच कवीला सुचित करावयाचे आहे.

‘ध्रुवपद’ ही कुसुमाग्रजांची सामाजिक कविता समुहमनाच्या आशा-आकांक्षा व्यक्त करणारी आहे. समाजातील विविध प्रकारच्या वित्तगतीचे व मानवीमूल्य ढासळल्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या कवीच्या मनःस्थितीचे चित्रण आहे. जगातील दारिद्र्य, दैन्य व दुःख नष्ट होत नाही तोपर्यंत आपल्या कवितेला हे पृथ्वीवरील दुःख नष्ट करण्याचा एकच ध्यास आहे. ‘जा जरा पुर्वेकडे’ या कवितेत जपानने चीनवर युद्धात कसे अत्याचार केले याचे वर्णन कवीने उपहासगर्भ रीतीने केले. माणसेच माणसाला कसे खातात. माणुसकीला कसे पायदळे तुडविले जाते याचे दर्शन प्रस्तुत कवितेत करून आपल्या संस्कृतीच्या ढोंगावर विदारक प्रकाश पाडलेला आहे. त्यांना चीन व जपानच्या युद्धात झालेले राक्षसी अत्याचार लोकांच्या दृष्टीपुढे आनावयाचे होते.

कवी कुसुमाग्रजांच्या सामाजिक कविता विलक्षण प्रतिमेची साक्ष पटविणाऱ्या आहेत. विविधता हे त्यांच्या सामाजिक कवितेचे प्रमुख अंग आहे असे म्हणता येईल. रूपकाचा आधार घेऊन नाट्यमय रीतीने सामाजिक जाणीव व्यक्त करणे हे त्यांच्या कवितेचे खास वैशिष्ट्ये सांगता येईल. अन्यायाविरुद्ध उभे राहणे, इतरांना प्रेरणा देणे, आशावादी वृत्ती जागृत करणे इत्यादी गुणांमुळे वाचकांच्या मनात उतरण्याचे सामर्थ्य त्यांच्या कवितेत आहे. त्यांच्या सामाजिक कविता विशिष्ट पंथ-विचाराशी बांधील नाही तर एकुण मानवता हाच विषय आहे. म्हणूनच सामाजिक भान जपणारी ही कविता मानवतेचे प्रेम, विषमतेची चीड व्यक्त करतांनाही आपली कलात्मकता किंवा काव्यात्मकता हरवत नाही हेच तिचे सामर्थ्यच आहे.

संदर्भ ग्रंथ :

१) ‘रसयात्रा’, संपादक बा.अ. बोरकर, शंकर वैद्य



---

## A Study of 'corporate governance' effectiveness through Board Structure

Dr. Sadashiv L. Shiragave –Research Guide, SP Pune University.

Mr. Sanjay P. Parab- Research Scholar –SP Pune University

### Abstract:

Good governance is the expectations of every stakeholder, especially, shareholder. Governance is related with the efficient controlling of activity of the corporate sector (Fernando, 2009). Indeed, assessment of effectiveness of governance in a firm is challenging and subjective. In past, attempts have been made by few researchers, to quantitatively assess board attributes vis-a-vis performance. The various board attributes represented in terms of board leadership, CEO duality, frequency of meetings, board diversity, representation of independent (outsider director) is been used as an independent variables and its impact on financial performance(ROA, EPS). Few high profile corporate scandals and failures paved way for new studies on same subject in wake of changes introduced in corporate governance norms locally and globally. The content analysis is the technique being used in this study. The present study is exploratory in nature, which covers leading financial and non financial firms and their governance practices. The data is collected by analysing annual reports, company websites and website maintained by the Ministry of Corporate Affairs. The focus of the study is to assess the level of governance through effective and efficient board.

### Key Words:

Board, Board of Directors, Independent Director, Corporate Governance.

### Introduction:

The discussions on Corporate Governance (CG) have succeeded in exerting good deal of public interest because of its perceptible importance for the economic health of a corporate as well as society at large. Governance refers to "all of processes of governing, whether undertaken by a government, market or network, whether over a family, tribe, formal or informal organization or territory and whether through the laws, norms, power or language." It relates to "the processes of interaction and decision-making among the actors involved in a collective problem that lead to the creation, reinforcement, or reproduction of social norms and institutions.

Corporate Governance was brought in limelight through series of corporate failures such as Enron and WorldCorn. These giant corporate collapsed on account of the corporate mis-governance and unethical practices they indulged in. In India, Satyam saga exposed lack of

accountability in the company and raised questions on corporate governance practices of the country.

CG refers to the relationship that exists between the different participants in determining the direction and performance of a corporate firm. A corporate firm is an instrument by means of which capital is acquired and channelised into assets for producing goods and or services and their effective distribution to end users for value consideration (Kumar, 2010). Most of the world economies' major capital force is controlled and managed by few corporations. Few economists describe the corporation as 'a nexus of contracts' leading towards its creation and existence. Corporations are very stronghold of capitalism.

**Cadbury Committee (U.K.), 1992** has defined Corporate Governance as "Corporate governance is the system by which companies are directed and controlled. It encompasses the entire mechanics of the functioning of a company and attempts to put in place a system of checks and balances between the shareholders, directors, employees, auditor and the management."

A level of adherence to CG depends upon the commitment of the management to abide by the principle of integrity, transparency in operations and disclosure of its practices within governance sphere created by the regulator. Few studies undertaken in this field have analysed board effectiveness as a relationship between board attributes in terms of its number strength, quality composition, leadership style and financial performance (RONW, ROE, ROA, Debt to Equity, Market to book value). The present study contributes to the emerging interest in corporate governance by examining the board attributes for effective board management. The study determines the characteristics of Indian public listed firm's board of directors. As the characteristics of all board are distinctive yet in some way alike. But, effectiveness of board may vary depending on a range of various parameters.

Corporate governance principles and codes have been developed in different countries and issued by stock exchanges, corporations, institutional investors or associations with support of government and international organisations. In India, compliance of defined governance recommendations has been mandated by listing agreement or SEBI (Listing Obligations and Disclosure) Requirements, 2015.

### **Significance of Study**

Numerous studies emanating from academic and non-academic platform over the years show that good corporate governance will yield numerous advantages to the investors, company and nation as a whole.

The result of this study is contribute to the interest of business practitioners, investors and academics by providing the picture of corporate governance practices of various Indian listed firms pre and post introduction of newer companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and

Disclosure) Requirements, 2015. The results can be further used by corporate decision maker in order to design the composition of their board. Most of the existing research on corporate governance so far has focused on western countries. As the studies of board effectiveness in the Indian context are still limited. The present study is an attempt to contribute to the body of knowledge in this area through examining the board effectiveness of Indian public firms. Further, the study addresses the Indian corporate governance issues concerning the characteristics of member of board of directors. The study may become useful for helping nomination/ succession committees to select the best criteria while appointing their board members. Finally the outcomes of this study may contribute to Indian regulators for formulating corporate governance policies in India. Eventually, the study may contribute to the overall improvement of Indian corporate governance.

## **Review of literature**

Corporate Governance consists of strategies, process and laws through which a firm is directed and controlled. The board of directors are key instruments through which companies are directed within vacuum of legal framework (Vishny, 1997). The directors of the board possess the ultimate executive power and authority within a firm (Renton, 1994). In the corporate format of management, the stakeholders were in position to elect a manager of a firm to represent their investment (Garratt, 1997). The director's responsibilities are classified into three roles, namely control, services and resource dependence (Kula, 2005). The directors need to monitor functions of managers as custodian of stock holders. The directors are expected to mitigate agency problem and safeguard interest of stakeholders. The director's advice and direct CEO's and top management. Resource dependence role views the board as a means to ease the source management for firm's success. Independent directors are become a paradigm institution of corporate governance and codes across the world. Independent directors are considered as watch dog of governance and they are in a better position to determine whether a particular transaction is in the interest of the Company or not (Nicholoson, 2007). A director might be in conflict of his interest and yet independent and not conflicted and not independent within the board room (Taylor, 2004). In Indian scenario, firms often view independence as a mere statutory obligation and fulfil by appointing people who consider the role as ceremonial. Research by (Vance, 1983) asserted that in past; the board were passive and made modest contribution to the strategic decision of the firm. (Hamilton, 1997), asserted that the role of CEO's remain prominent in firm's decision making. With evolution of governance norms and practices, the roles of board of directors have become more and more challenging. The era of globalisation has created challenges while dealing in global operations coupled with cultural divergence (Rajesh, 2007).

The Firms at global level recognizing that better corporate governance indeed adds significant value to their operational performance in the following ways:

- It enhances strategic thinking at the top through wealth of knowledge of inducted independent directors who bring experience and a host of creative ideas.
- It redefines the management approach towards monitoring of varied risk that a firm faces globally.
- It confines the responsibility of top management, by carefully articulating the decision making process
- It gives comfort as to the integrity of financial reports.
- It has long term reputational effects amid stakeholders, both internally and externally.

## **Objective of Study**

- 1) To understand the nature of corporate governance practices in India.
- 2) To examine the board structure among various Indian corporate and their effectiveness.
- 3) To analyse the characteristics of members of board of directors and their importance for effective board management.
- 4) To examine whether the characteristics of board are harmonious with corporate governance guidelines/ norms set by regulator.

## **Methodology**

The study was founded on the positive theory. The Corporate governance scores have been calculated to find out effectiveness of the board. Various broad parameters of governance have been identified and each parameter is been further fragmented and each fragmented sub parameter has been assigned with standard score/ value, based on its importance in line with clause 49 / SEBI ( Listing Obligation and Disclosure) Regulation, 2015. The identified parameters covers both mandatory, non mandatory and few trend setting practices which are yet not mentioned in any regulation but could be recommendatory by the regulator in future. The purpose of score card computation is to analyse, compact ability of each firm's compliance level by adherence to defined norms or expected industry standards of governance. For the purpose of evaluation of governance practices, scores have been classified based on its pre-defined classification. Firms having score >86 -100, have been rated as Excellent, whereas those score between 71-85 are tagged as Good. Those firms have score between 56-70 are tagged as Average and score below 55 are rated as 'Poor'.

## **Sample Selection**

The study of board effectiveness is carried out for Nifty 50 firms covering period 2009-10 to 2014-15. These are leading firms, identified by NSE, representing different industries, selected on the basis of free float criteria have been considered for this study. The study cover only 46 firms. Data of 4 firms is not considered for study as data not consistent for objective assessment. The companies for study are as under:

Table :1- Nifty Companies covered for Study

Name of the Company	Script Code	Indices Category
ACC Limited	ACC	Nifty - Other
Adani Ports and Special Economics Zones Limited	ADANIPTS	Nifty - Other
Ambuja Cements Ltd.	AMBUJACEM	MNC
Asian Paints Limited	ASIANPAINT	Nifty - Other
Aurobindo Pharma Ltd.	AUOPHARMA	Pharma
Axis Bank Ltd.	AXISBANK	Bank
Bajaj Auto Ltd.	BAJAJ-AUTO	Auto
Bank of Baroda	BANKBARODA	Bank
Bharat Heavy Electricals Limited	BHEL	Nifty - Other
Bharat Petroleum Corporation Ltd.	BPCL	Energy
Bharti Airtel Limited	BHARTIARTL	Nifty - Other
Cipla Ltd.	CIPLA	Pharma
Coal India Ltd.	COALINDIA	Metal
Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	DRREDDY	Pharma
GAIL (India) Ltd.	GAIL	Energy
Grasim Industries Limited	GRASIM	Nifty - Other
HCL Technologies Ltd.	HCLTECH	IT
HDFC Bank Ltd.	HDFCBANK	Bank
Hero MotoCorp Ltd.	HEROMOTOCO	Auto
Hindalco Industries Ltd.	HINDALCO	Metal
Hindustan Unilever Ltd.	HINDUNILVR	FMCG
Housing Development Finance Corporation Ltd.	HDFC	Fin Ser
I T C Ltd.	ITC	FMCG
ICICI Bank Ltd.	ICICIBANK	Bank
Idea Cellular Limited	IDEA	Nifty - Other
IndusInd Bank Ltd.	INDUSINDBK	Bank
Infosys Ltd.	INFY	IT
Kotak Mahindra Bank Ltd.	KOTAKBANK	Bank
Larsen & Toubro Limited	LT	Nifty - Other
Lupin Ltd.	LUPIN	Pharma
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	M&MFIN	Fin Ser
Maruti Suzuki India Ltd.	MARUTI	MNC
NTPC Ltd.	NTPC	Energy
Oil & Natural Gas Corporation Ltd.	ONGC	Energy
Power Grid Corporation of India Ltd.	POWERGRID	Energy
Reliance Industries Ltd.	RELIANCE	Energy
State Bank of India	SBIN	Bank

Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	SUNPHARMA	Pharma
Tata Consultancy Services Ltd.	TCS	IT
Tata Motors Ltd.	TATAMOTORS	Auto
Tata Steel Ltd.	TATASTEEL	Metal
Tech Mahindra Ltd.	TECHM	IT
Ultratech Cement Limited	ULTRACEMCO	Nifty - Other
Wipro Ltd.	WIPRO	IT
Yes Bank Ltd.	YESBANK	Bank
Zee Entertainment Enterprises Ltd.	ZEEL	Media

Table 2 The data for study covers companies representing free float indices –

Free Float Indices Sector	Number of Companies
Auto	03
Bank	08
FMCG	02
Financial Services	01
IT	05
Media	01
Metal	03
Pharma	05
Energy	06
MNC	02
Other (Nifty)	09

### Analysis of Study

Following are the findings of score for period 2010-11 to 2014-15.

**Table 3 – CG Score Frequency Table ( number of firms)**

Score Range (Max 100)	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
86+	0	0	0	0	01
71-85	18	19	23	22	39
56-70	27	25	23	24	06
<55	1	2	0	0	0

Table 1 show that the overall pictures of corporate governance score of 46 leading firms of Nifty 50. It is found that, in FY 2010-10 to 2013-14, no company qualified in highest score category. It is only in 2014-15, Tata Steel Limited, could score highest score indicating, “excellent” level of corporate governance score. More importantly, except in FY 2013-14, more and more companies have qualified in



“good” and FY 2014-15, have almost 84.78% companies in category of good. Except in FY 2010-11 and 2011-12, no company had scored lower or “Poor” mark for its corporate governance practices. Cipla Ltd. and Sun Pharmaceuticals both from Pharma sector were having lower score in FY 2010-11 and 2011-12, respectively. Shockingly, YES Bank was other company in FY 2011-12, with “Poor” score but having average score in other years.

Table 4 – Descriptive Statistics  
N= 46

FY 2010-11	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev
<b>Score</b>	<b>54</b>	<b>83</b>	<b>67.67</b>	<b>20.50</b>
FY 2011-12				
<b>Score</b>	<b>52</b>	<b>83</b>	<b>67.80</b>	<b>21.92</b>
FY 2012-13				
<b>Score</b>	<b>60</b>	<b>83</b>	<b>69.39</b>	<b>16.26</b>
FY 2013-14				
<b>Score</b>	<b>58</b>	<b>83</b>	<b>69.97</b>	<b>17.67</b>
FY 2014-15				
<b>Score</b>	<b>66</b>	<b>87</b>	<b>74.82</b>	<b>14.84</b>

Table 4 show that the score of Indian firms range from 58 to 83.8. Tata Steel has highest score while, Reliance Industries Ltd, TCS, Hindustan Unilever Ltd, Tata Motors and Infosys Ltd. are other companies to attain near excellent score in FY 2014-15. The average mean progressively moves from 67.67 to 74.82 from FY 2010-11 to 2014-15. The Standard deviation shows progressive lower deviation, except FY 2012-13, on account of improved governance level.

## Conclusion

Indian firms have a long way to go, before adhering to corporate governance best practices. Overall, progressive legislative compulsion only making most of Indian firms to adapt to newer level of governance practices. Voluntary adoption of good governance practices is a distinct dream for most of Indian firms. The performance of Indian corporate governance practices is just average. The factors like attendance of directors in board meetings, Annual general meeting, board composition etc are matters of worry. The board members should qualify for their position based on stakeholder’s perspectives rather than promoter driven process for the sake of compliance. Independent directors need to have a clear understanding of their role in corporate governance and be able to exercise sound judgement about the affairs of the Company. The high agenda for objective of effective board is to manage the firm in a legal and ethical manner. Indian firms have to come out with strong governance practices in order to ensure the confidence and trust of investor, society at large and government. There are numerous development taking at

international level, a cue has to be taken by both regulator as well as Indian firms to adhere to those levels. Indian firm need to have detailed study of these developments, to articulate a world –class corporate practices.

## Bibliography

Fernando, A. (2009). *Corporate Governance Principles, Policies, and Practices*. Pearson Education Publication.

Garratt, B. (1997). *The fish rots from the head: the crises in our boardrooms; Developing the crucial skills of the competent directors*. London: Harpen Collins Business .

Hamilton, R. (1997). Corporate Governance in America 1950-2000: Major Changes but in certain benefits. *Journal of Corporate Law* , 25 (2).

Kula, V. (2005). The impact of the Roles, Structures and Process of Boards on Firm Performance: Evidence from Turkey. *Corporate Governance* , 13 (No. 2), 265-276.

Kumar, S. (2010). *Corporate Governance*. (2. Edi, Ed.) Oxford Higher Education Publication.

Nicholason, G. (2007). Can Directors Impact Performance? A Base Based test of Three Theories of Corporate Governance . *Corporate Governacne* , 15 (IV), 585-608.

Rajesh, C. (2007). Corporate Governacne in India Evolution and Challenges. *Journal of Applied Corporate Finance* , 8.

Renton, N. (1994). *Company Directors: Masters or servants*. North Brighton: Wright Books .

Taylor, B. (2004). Leading the Boardroom Revolution . *Corporate Governance* , 12 (4), 415-441.

Vance, S. (1983). *Corporate Leadership: Board, Directors and Strategy*. New York: McGraw Hill .

Vishny, S. a. (1997). A Survey of Corporate Governacne. *Journal of Finance* (52), 737-83.

Appendix

Criteria I	Sub head	Board of Directors	Score	
		Composition of Board of Directors	Assigned	Max
	<b>A</b>	<b>Board Leadership (CE) Duality- [Separation of Chairman &amp; CEO]</b>		<b>08</b>
	1	Promoter Executive Chairman cum CEO/ MD	2	
	2	Non –Promoter Executive Chairman cum CEO/ MD	4	
	3	Promoter Non –Executive Chairman	5	
	4	Non-Promoter Non Executive Chairman	6	
	5	Non –Executive Independent Director as a Chairman	8	
	<b>B</b>	<b>Size of the Board</b>		<b>05</b>
	1	3 to 7	3	
	2	8 to 12	5	
	3	More than 12	4	
	<b>C</b>	<b>Board Balance / Composition (ID)</b>		<b>05</b>
	1	½ for Executive Chairman	2	
	2	1/3 for Non –Executive Chairman	2	
	3	More than ½ for Executive Chairman	3	
	4	More than ½ for Non- Executive Chairman	5	
	<b>D1</b>	<b>% Attendance at the Board Meetings</b>		<b>06</b>
	1	33% to 50%	1	
	2	51% to 80%	3	
	3	81% to 100%	6	
	<b>D2</b>	<b>% Attendance at the AGM's / EOGM's</b>		<b>03</b>
	1	33% to 50%	1	
	2	51% to 80%	2	
	3	81% to 100%	3	
	<b>E</b>	<b>Degree of Diversification of Board composition</b>		<b>02</b>
	1	Only Male Directors	0	
	2	Presence of a female directors in board	2	
	<b>F</b>	<b>Number of Board Meetings</b>		<b>4</b>
	1	Between 4-5	2	
	2	Between 6-8	3	
	3	More than 9	4	
	<b>G</b>	<b>Average Number of Directorship with other Companies</b>		<b>02</b>
		More than 7	0	
		Between 3-5	1	

		Less than 2	2	
II		<b>Board Committees</b>		
	<b>A</b>	<b>Audit Committee</b>		<b>10</b>
		Constitution of Audit Committee ( Minimum Three members)	1	
		Composition of Audit Committee with all independent directors	1	
		Transparency in independence of Audit Committee	1	
		Chairperson with Committee specialised knowledge & Exp.	1	
		Transparency of Independence of AC ( Invitation to experts and CS)	1	
		Compliance with number of meetings in a year (Min 3 – 4)	1	
		Attendance in Audit Committee Meetings (more than 50%)	1	
		Attendance of Audit Committee Chairman at AGM	1	
		Transparency in Qualification and disclosure through AC	1	
		Brief description of terms of reference	1	
	<b>B</b>	<b>Nomination and Remuneration/ Compensation Committee (NRC)</b>		<b>06</b>
		Brief description of terms of reference	1	
		Composition of NR Committee with non-executive directors	01	
	OR	Composition of NR Committee with majority independent directors	02	
	OR	Composition of NR Committee with all independent directors	03	
		Information of number of meetings and other particulars	1	
		Transparency in disclosure as to RPT, nature of interest or office of profit	1	
	<b>C</b>	<b>Investor's / Shareholder's Grievance Committee</b>		<b>03</b>
		Transparency in composition of the Committee	01	
		Information about nature of complaints and queries received and disposed item wise	01	
		Information about number of committee meetings and action taken and investors/ shareholders survey.	01	
	<b>D</b>	<b>Risk Management/ Operations Committee/ management Committee</b>		<b>02</b>
		Brief description of terms of reference	01	
		Information of number of meetings and other particulars	01	
	<b>E</b>	<b>Share Transfer Committee</b>		<b>01</b>
		Brief description of terms of reference and other particulars	01	
		<b>Special Committees</b>		
	<b>F</b>	<b>Health, Safety and Environment Committee</b>		<b>01</b>
	<b>G</b>	<b>Ethics and Compliance Committee</b>		<b>01</b>
	<b>H</b>	<b>Corporate Social Responsibility Committee (CSR)</b>		<b>01</b>
III	<b>A</b>	<b>Disclosure and Transparency of</b>		<b>10</b>



	1	Definition of Independent Director		
	2	The Company's Corporate Governance Philosophy		
	3	Code of Conduct		
	4	Website and Display of Information		
	5	Term of office on non-executive director ( tenure and age )		
	6	Remuneration Policy		
	7	Insider Trading Policy and Disclosure		
	8	Criteria for election of the board and its disclosure in the Annual Report		
	9	Are all pecuniary relationship or transaction of the non-executive director vis-a-vis the company, described in the Annual Report		
	10	Mechanism of internal communication system		
	B	Disclosure and Transparency ( Financial )		10
	1	Basis of Related Party Transaction		
	2	Accounting treatment		
	3	Disclosure of Subsidiary Companies / Joint Ventures/Associate Companies/ Companies under Same Management		
	4	Remuneration to Directors		
	5	Management Discussion and Analysis		
	6	Shareholders Rights and information and Statistical /Graphical Profit/EPS Information as to Performance Index		
	7	Compliance of Corporate governance and qualified certificate		
	8	CEO/ CFO Certification		
	9	Report on Corporate Governance		
	10	Compliance of Corporate Governance and Unqualified Certificate ( Qualified -5)		
IV	A	Non Mandatory provisions		10
		Whistle Blower Policy		
		Training of Board Members		
		Meeting of Independent Director		
		Disclosure of Postal Ballot Resolution/ Proposed Resolution		
		Succession Policy and Criteria		
		Presentation to Media and Investor Meeting		
		Disclosure of Promoter's Shareholding and pledge details (1+1)		
		Disclosure of actions taken by Authorities (-5)		
		Rotation of Auditor		
		Mechanism for evaluation of Non-Executive Board Members		
V	A	Disclosure of Stakeholders Interest		05
		Environment , Health & Safety Measures		
		Human Resources Development Initiative HRD		
		Corporate Social Responsibility (CSR)		
		Industrial Relations		
		Disclosure of policies on EHS, HRD, CSR , IR		



VI	B	Innovative Practices and Trendsetters		05
		Awards/ recognition to the Company		
		Appointment of Independent Lead Manager		
		Functional Website and Transparency of Disclosure		
		Profit related commission to Independent Director		
		Independent Governance Ratings Disclosure / Award for Corporate Governance		



## India's Internal Security : Conceptual Perspective

Dr. ARVIND KUMAR

(GUEST LECTURER) department of Defence & Strategic Studies Allahabad Degree College  
Allahabad.( A CENTRAL UNIVERSITY OF ALLAHABAD ALLAHABAD)

**Abstract:** *internal security in most of the developing countries including india is problematic mainly due to three reasons. First ,they do not conform to the idea of homogeneous socio – political unit, .secondly, they are extremely vulnerable due to their economics weakness and uneven regional development .and finally , they have limited capabilities to deal with internal threats to security.today india rightfully stands at the doorsteps of new geostrategy gateway that will enable it to face the security challenges in new millennium.*

India is a cyclopean nation with myriad languages, a veritable label of tongues, and a plethora of religions and faiths, Unity and diversity in our heritage, and respect for all faiths and religions has been our strength and source of survival against all odds and obduracy. India is a mosaic in which different pieces retain their identity while contributing to a colourful collage from the eternal snows of the Himalayas to the cultivated peninsula of far south, from the deserts of the west to the humid deltas of the east, Indian life styles clearly glorify its geography.

After independence India has emerged as a strong nation in all aspects, viz- technological, economic, defense, education, tourism and the likes. India has embarked upon a high growth trajectory in economic development. It cropped up as a great economy, with a healthy growth rate. Its poverty alleviation is making slow and steady if not a spectacular progress. It's now a day known as a responsible nuclear and missile power. Indian army is third largest in the world, equipping its Jawan with the requisite skills at 15 state of the heart training .

IN THE realm of security, globalization has produced a whole new range of interactive threats and risks . Globalization has also lead to a blurring of the distinction between external and internal threats BY Man Mohan Singh.

While India has established itself in the global arena and registered a phenomenal growth, specter of security threats is haunting the nation. The menace of threats has been increasing over

the years. The multifaceted, perspicuous, consequences of terrorism and security threats need to be known to the world so as to facilitate the formulation of effective plans to ridicule it. The entire growth process will come to a searching half if security concerns are not timely and adequately addressed.

### **Concept of Security**

Vinod saighal stated, if india,s national security aim for second half of the 20<sup>th</sup> century could have been succinctly defined as the preservation of indias unity , the country, s aim for the first half of the 21<sup>st</sup> century could equally succinctly be defined as the preservation of the integrity of the subcontinent , as an essential prerequisite for the global equipoise for the third millennium. His perception is in subjective mode , as an entity that needs to have an aim that change with time changing direction distorts definition. The suggestion therefore could be seen as maximization of the defined concept . it is an important finding . maximization of process is a desired process in its governance by objective when the exact limit is neither known nor can be reached by the very nature of the concept.

While defining the concept security, the most popular answer is, “the security means preservation of the territorial integrity, or in other words, the boundaries of the state. But neither territorial integrity without full sovereignty nor sovereignty without full territorial integrity can be considered to be true security.”

Therefore national security is a function of a country’s external environment and the internal situation, as well as their interplay with each other. So national security refers to the security of a nation that includes protection of its territorial integrity, sovereignty and advancement of vital national interests. And a declaration of an intention or determination to inflict national security is called a threat. On this part, threats are matter of perception. Their assessments take into account capacities not so much intensions of a potential adversary.

What exactly internal security means or should mean is of course disputed. No legally binding definitions exists. In general, the term refers to measures which serve the maintenance of public order, that is which serve to protect against crime and political extremism. In accordance with the concept of a “democracy capable of defending itself” already developed by the German federal constitutional court in 1956. The state has not only the right but also the duty to defend itself against individual persons or parties that actively work for the elimination of the “basic free

democratic order". How far the state may go in this however, is a genuine political question and therefore often itself the object of intense political debate.

Internal security is looked upon not only as a condition of social stability, but also as a kind of state, guaranteed basic social right. This central concept and battle cry replaced the pre-democratic topas of "law and order" in the 1970s and founded a new security model, which in modified form still determined today the fight against international terrorism.

World famous thinker of statehood, Kautilya explains in his famous work 'Arthashastra' that a state could be at risk by four types of threats— internal, external, externally-aided internal, and internally-aided external. He advised that out of these four types, internal threats should be taken care of immediately, for internal troubles, like the fear of the lurking snake, are far more serious than external threats. The most dangerous enemy is the enemy within.

Kautilya's teachings on internal security and his skillful impression of the warp and weft of internal and external security has great relevance in the globalised 21<sup>st</sup> century. Destabilizing a country through internal disturbances is more economical and less objectionable particularly when direct warfare is not an option and international borders cannot be violated. External adversaries, particularly the weaker ones, find it easier to create and aid forces which cause internal unrest and instability. India's history is full of such situation initiated by China, Pakistan and others in the northeast and even in the western sectors of the country since mid 60s. But only after the events of 9/11 the world has started looking these extended internal linkages more seriously.

The politics of internal security has becomes the object of fresh controversies since the attacks of 9/11. The dilemma it presents, remain as before: to guarantee the security of the state and of every individual without endangering democratic freedoms through the "dynamics of an extensive security policy". Internal security is no less threatened or violated by "over-reactions of the state", which provoke to protest and so endanger the domestic place, than by criminals and terrorists. The tense relationship of freedom and security should not be resolved one sided in favour of, for example, and uncontrolled security and surveillance state criticism on the part of civil society is therefore an indispensable corrective to state security policy.

### **India,s Internal Security :**

Internal security has been an important component in India's national security management, right from the day we became independent. Initially, it was confined to maintenance of law and order, containment of communal violence and in very few cases, counter

insurgencies. The internal security became very important from the very beginning, owing to the legacy which we inherited from the British rule. India has partitioned “in the backdrop of large scale communal violence due to reasons” best known to all of us. The background in which the partition was conceived and operationalised, was bound to have consequences like those which were witnessed in many parts of the country after the independence. Therefore, India was perhaps the only country of its kind which faced both an external aggression as well as internal disturbances from the day of its birth. Thus the concept of the internal security came into being simultaneously with the birth of this nation.

The peculiarities of India’s internal security situation arise out of both external and internal factors. The first among significant of these is that the country shares a border and a long history of hostility with the principal locus and source of Islamist extremist terrorism in the world, Pakistan. The wider South Asian region is, more over a region of great instability and global contestation and these impacts directly on India’s own stability. Internally, extreme inequalities and distribution of large proportions of the population combined with abysmal capacities for and quality of governance. The predisposition to political violence, consequently, is great while the capacities to neutralize this predisposition or its eventual manifestations is extremely limited.

India’s internal security challenges acquire a particular urgency, principally, because of the state’s limited capacities and absence of strategy to deal with these, as well as the extraordinarily hostile regional environment, particularly the role of Pakistan, implicitly supported by China in exacerbating every existing tension here. The gravest internal security challenge, in fact is the infirmity of the state. Particularly manifestations of violence only reflect the opportunities exploitation by disruptive elements, internal and external of the vulnerabilities that have been created over decades of political and strategic incompetence.

In an age of Wiki leaks and Balkanization, cohesive nation states like India can become victims of an, as yet, not clearly understood information warfare. Where nation state already under siege by neighbour with religious and geopolitical agendas. The need to provide internal dichotomies against internal insecurity is fast becoming the low cost option for those who see greater profit in it than direct military conflict. India has hitherto managed to stand such assaults on its integrity by the strength of its constitutional institution but even they are to erode and it is time that national debates identify the problems as seek vital solution.

Main challenges to internal security of India are- terrorism in Jammu & Kashmir and North east, Naxal violence, act of subversion, sabotage and terror in the hinterland, communal

violence, corruption, politician-criminal-police(PCP) nexus poor governance, inadequate intelligence and lack of legal/ constitutional coordination between centre and states. At least one third districts of the different Indian states are currently afflicted, at different intensities by various insurgent and terrorist movements. In a shocking disclosure, National security advisor M.K.

Naryanan stated that there are as many as 800 terrorist cells operating in the country with external support.

### **Measures to strengthen the Internal Security**

To understand the complex nature of internal security, a framework of “system” need to be evolved which would assist in assessing and gaining situational awareness. These systems would sustain on political, military, economic, social, infrastructure and information technology aspects. Commanders, organizational leaders, and other military members must think various facts of threat and create operational opportunities. On the back drop of these aspects and situations, the following measures should be taken to strengthen internal security :

- Home Ministry with the help of other concerned departments can effectively manage the internal security. For the governance of the states, an accountable mechanism needs to be built. A strong centre is a must to tackle terror. Internal security may not be a part time job of the Home Ministry, it needs full time attention. For this trained academic politician required having in depth knowledge of the issues.
- Long term national policies and constitutional provisions required to tackle the threats. But, while making these arrangements it should be kept in consideration that these provisions should be guided by our vital national interests. Today new threats to internal security emerging of i.e. drugs trafficking, illicit narcotics trade, smuggling of weapons and explosives, religious fundamentalism, infiltration across the borders and state sponsored terrorism. To tackle these threats effective national policies and constitutional provisions are the need of hour.
- On bureaucratic grounds internal security can be managed. For this, coordination between agencies and ministry is must. About it, Kautilya's suggestions are appreciable that the king's informer should never be his advisor. Having been the former, it would be unfair to expect national security agency to evolve into the latter.

- 
- Diplomatic means itself capable to control by their expertise views, so they should be involved in the process of internal security managements. For this, need to develop a foreign policy road map and time lines to mobilize the world community to ensure action taken.
  - Effective laws enforcement can also play an important role in managing internal security threats. The laws enforcement machinery must be effectively backed by an efficient judiciary system. Courts Trials and Decisions against criminals should not be delayed. So there is a great need of improvements and modification in legal systems of investigations and prosecutions.
  - National Security Council (NSC) can manage internal security effectively only when it enjoys all the powers deliberately without any pressure. NSC should be backed by JIC and NSAS to make accountable.
  - By intelligence including private intelligence agency, internal security threats can be controlled. In India, 25 intelligence agencies including private agencies are dealing with security. They collect informations and performs by the help of joint intelligence committee. JIC is the third tier of national security council.
  - Central Para-military Forces playing important role in the internal security management, so they should be strengthen and well equipped to dealt with the threats.
  - By creating the healthy relations between civil and paramilitary forces internal security threats can be managed. For this conferences, seminars and exercises should be conducted to understand each other's strength, limitation and coordination.
  - Police systems of the states can also play an important role to manage internal security threats. For this adequate training and weapon system should be provided to the police forces.
  - Of course without public support, internal security threats can't be managed. For this, public should be aware with open eyes. They must be alert about every incident which is happening in their neighborhood. They must inform police about suspicious things and persons.
  - Adequate funds allocation is the need of hour to control internal security threats .
  - Responsible media may play vital role to secure internal security as it is assumed that media is the 4<sup>th</sup> pillar of a successful democracy.
  - Cultural integration through exchange programmes between the states to understand each other is of the great importance to enhance internal security.



- Formation of a network of civil defence with residential area so that each individual develops a sense of belonging and a cooperative attitude towards neighbours and a sense of protectiveness and duty towards the locality itself.
- It should be compulsory to serve in the armed forces, a two year stint after school or at the age of 18 for every citizen.
- There should be complete constitutional ban on politician with criminal records.
- Reduce or withdraw the unwanted security for politicians and their families.
- Compulsory education should be implemented at schools level regarding internal security.

India is a study in contrasts, if not contradictions, extreme poverty and lack of opportunities coexist with rapid economic growth and obscene wealth creating what commentators have often conceptualized as “two indias.” these discrepancies, produce enormous potential for discord as well as, a number of enduring conflicts. The internal security problems should not be treated as merely law and order problems. They have to be dealt with comprehensively in their dimension and at all levels- political economic and social as they all are interlinked. At times the required measures will conflict with each other. Going too far in one direction could not be counter-productive. The security requirements have to be met but that does not mean giving the security agencies a free hand. Striking the right balance is the key success in meeting these challenges effectively. We need a comprehensive security system which will be implemented effectively at all levels. In the last we can hope that the govt. machinery, legal aspects and political diplomatic frame work could work in harmony to ensure internal security at national level.

#### REFERENCES:

1. Suri, S “ Political assassination in India, “ The sociological quarterly, (1971).
2. Mehta, P “A functional competition policy for India”. Academic foundation, United Kingdom, (2006).
3. Kujur, R, “ Naxal in India A profile Institute of Peace & conflicts studies India,(2008).
4. India’s war on terror (Gurmeet Kanwal & N. Manoharan)
5. The emerging balance of power in Asia: Conflict or cooperation.



- 
6. Gupta, Anirudha, *Issues in South Asia : Geopolitics or Geoeconomics-International Studies*,34/1, Sage Publications, New Delhi/Thousand Oaks-London, 1997.
  7. Budania, Rajpal, Article "India's Defence Policy: A Conceptual Perspective" U.S.I. Journal, April- June 2007.
  8. India's missile defence programme Threat perceptions and technological evolution.
  9. Daily News Papers- The Hindu, The Tribune and The Times of India.
  10. Consulted various articles from magazines- Strategic Analysis, USI Journal, World Focus, India Quarterly etc.
  11. 11.BRIg sangwan sukhdeep "integrated force projection by india publ.vij books 2011.

## अंगणवाडीत जाणाऱ्या व किंडरगार्डमध्ये जाणाऱ्या मुलांचा भाषाविकासाचा तुलनात्मक अभ्यास

संशोधक

प्रा. सविता आप्पासाहेब लोखंडे  
विमेन्स एज्युकेशन कॉलेज,  
श्रीगोंदा.

मार्गदर्शक

डॉ. बालाजी रंगनाथराव लाहोरकर  
प्राध्यापक एम.एड. विभाग,  
इंदिरा अध्यापक महाविद्यालय,  
सहयोग एज्युकेशनल कॅम्पस,  
विष्णुपूरी, नांदेड.

### प्रस्तावना:-

शिक्षणाची खरी सुरुवात बालक आपल्या कुटूंबातूनच करत असतो. आई हा बालकाचा पहीला गुरु असते. आणि नंतर बालक समाजात येतो. तेव्हा एका ठराविक वयातच मुलांना आपल्या शिक्षणाला सुरुवात करावी लागते. बालक अडीच वर्षांचा झाला की प्रत्येक पालकाला आपल्या पाल्याच्या शाळेची चिंता सतावू लागते. कारण आजच्या आधुनिक समाजाची मागणी लक्षात घेता स्पर्धेच्या युगात टिकून राहण्यासाठी आपल्या पाल्याला उत्कृष्ट शिक्षण पालक देवू इच्छितो. आज आपण पाहतो की कुठे राज्य सरकारच्या अभ्यासक्रमानुसार तर कुठे केंद्रसरकारच्या अभ्यासक्रमानुसार शिक्षण देणे चालू आहे. आपल्या पाल्याचा उत्कृष्ट बौद्धिक विकास व्हावा मुलाला उत्कृष्ट इंग्रजी बोलता यावे म्हणून पालक मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालतात. तर काही पालक आपल्या पाल्याला अंगणवाडीत घालतात.

शिक्षणाच्या संदर्भात वेगवेगळ्या समित्या आयोगाने मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या संदर्भात वेगवेगळ्या शिफारशी केल्या की प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून दिले जावे मुलांच्या भाषाविकासाच्या दृष्टीने हे आवश्यक आहे. आज शिक्षणसंस्थांना व्यावसायिकतेचे रूप आले आहे. उत्कृष्ट शिक्षणाच्या नावाखाली शिक्षणसंस्था मोठ-मोठ्या फीज घेवून मुलांना उत्तम शिक्षण देण्याचे आश्वासन देतात परंतु अंगणवाडीत अशा कोणत्याच पद्धतीची फी घेत नसून मुलांना मोफत पूर्व प्राथमिक शिक्षण देतात. म्हणून पालकांनी जागरूक राहून आपल्या पाल्याचा विकास खऱ्या अर्थाने कोणत्या शाळेत होईल याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

### संशोधनाची गरज व महत्व:-

लहान मुले साधारणपणे ८, ९ व्या महिन्यापासून एक-एक शब्द बोलायला सुरुवात करतात बाबा, पापा, मामा, अशा प्रकारचे घरात जी भाषा बोलली जाते त्याच भाषेतून मुले शब्द बोलायला हळुहळू मुले वाक्यबोलायला शिकतात. त्यांची शब्दसंपत्ती ५०० ते ६०० शब्द झालेली असते. तिसऱ्या वर्षी मुले जवळपास मोठे वाक्य बोलायला शिकतात. परंतु व्याकरणदृष्ट्या ते बरोबरच असेल असे नाही. आपल्याकडे अडीच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर मुलांच्या अंगणवाडी किंवा नर्सरी शिक्षणास सुरुवात

होते मुलांच्या बोलण्याचे अडथळे, शब्द न आठवणे बोलताना अडखळणे असे विविध प्रकारच्या समस्या बोलताना निर्माण होतात याचा शोध घेण्यासाठीच प्रस्तुत समस्येची निवड करण्यात आली.

#### संशोधनाची उद्दिष्ट्ये:-

१. अंगणवाडीत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भाषाविकासाचा शोध घेणे.
२. किंडरगार्डनमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भाषाविकासाचा शोध घेणे.
३. अंगणवाडी व किंडरगार्डनमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भाषा विकासाची तुलना करणे.

#### संशोधनाची व्याप्ती व मर्यादा:-

१. प्रस्तुत संशोधनाची व्याप्ती फक्त श्रीगोंदा शहरातील अंगणवाडी तसेच किंडरगार्डन शाळेपुरतीच असून अंगणवाडीत तसेच KG1, KG2 च्या विद्यार्थ्यांपर्यंत मर्यादित आहे.

#### न्यादर्श:-

प्रस्तुत संशोधनासाठी श्रीगोंदा शहरातील चार अंगणवाड्या व चार इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची निवड करण्यात आली. तसेच यामध्ये शिकणाऱ्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी फक्त ५० विद्यार्थी अंगणवाडीचे व ५० विद्यार्थी किंडरगार्डन मधील KG1, KG2 चे निवडण्यात आले.

#### संशोधनाची साधने:-

प्रस्तुत संशोधनासाठी १.विद्यार्थ्यांचे निरीक्षण २. विद्यार्थ्यांची मुलाखत या साधनाचा वापर करण्यात आला.

#### संशोधनाची पद्धती:-

प्रस्तुत संशोधनासाठी सर्वेक्षण पद्धतीचा वापर करण्यात आला यामध्ये विद्यार्थ्यांसोबतच तसेच शिक्षकांच्या प्रत्यक्ष भेटी घेऊन माहिती गोळा करण्यात आली.

#### कार्यपद्धती:-

प्रत्यक्ष कार्यवाही व माहिती संकलन

१. प्रस्तुत संशोधनासाठी सर्वप्रथम अंगणवाडीमधील व KG1, KG2मधील एकूण विद्यार्थ्यांपैकी ५०-५० विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली.
२. विद्यार्थी निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पालकांसमोर - शिक्षकांसमोर त्यांच्या ज्ञानावर (शब्द संपत्तीवर) आधारीत साधे-साधे प्रश्न विचारण्यात आले.
३. प्रश्नांचे, स्वरूप विद्यार्थ्यांच्या भाषाविकासाचा शोध घेता येईल आशा स्वरूपाचे राहिल याची संपूर्ण काळजी घेण्यात आली. त्यासाठी थोडीफार शिक्षकांची मदत घेण्यात आली.
४. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेत म्हणजे मराठी व नंतर हिंदी व इंग्रजी आश्या तीनही भाषेत सोपे सोपे प्रश्न विचारण्यात आले.

५. प्रश्नांचे स्वरूप काहीसे वैयक्तिक माहिती, घरगुती माहिती, शाळेसंबंधी माहिती तसेच शिक्षणासंबंधी माहिती अशा स्वरूपाचे ठेवण्यात आले होते.

६. सोबतच विद्यार्थ्यांचे शक्य तेथे निरीक्षण करण्यात येऊन, तो विद्यार्थी त्यांच्या मुलांच्या वयोगटात कशा प्रकारे बोलतो याचे त्याच्या नकळत निरीक्षण करण्यात आले.

#### प्राप्त माहितीचे विश्लेषण आणि अर्थनिर्वचन:-

विद्यार्थ्यांना विचारलेल्या प्रश्नांचे स्वरूप विद्यार्थी केंद्रित तसेच त्यांच्या वयाच्या व त्यांच्या एकंदर व्यक्तिमत्त्वाचा विचार करण्यात आल्यामुळे विद्यार्थी प्रतिसादांची आणि त्यांच्या भाषाविकासाच्या नोंदी घेण्यात आल्या त्या पुढीलप्रमाणे.

विद्यार्थ्यांना विचारलेल्या प्रश्नांना प्रतिसाद दर्शविणारी सारणी क्र. १

विद्यार्थ्यांचे शिक्षणचे स्वरूप	अंगणवाडी	KG1	KG2
विद्यार्थी संख्या	५०	१८	३२
प्रतिसाद (होकारार्थी) %	४४ ८८%	१४ ७७.७८%	२९ ९०.६३%
प्रतिसाद नकारार्थी %	३ ६ %	३ १६%	२ ६.२५%
प्रतिसाद अल्प %	३ ६%	१ ५.५०%	१ ३.१३%

भाषा विकास दर्शविणारी सारणी क्र. २

विद्यार्थ्यांचे शिक्षणचे स्वरूप	अंगणवाडी	KG1	KG2
एकूण विद्यार्थी	५०	१८	२२
मराठी भाषेस प्रतिसाद	१३%	८१%	८४%
हिंदी भाषेस प्रतिसाद	१४%	३०%	२५%
इंग्रजी भाषेस प्रतिसाद	१०%	२२%	४०%

#### सारणी क्र. १ चे विश्लेषण -

१. वरील सारणी १ मध्ये विद्यार्थ्यांना विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांना विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या प्रतिसादाची टक्केवारी दर्शविली आहे. यामध्ये अंगणवाडीत शिकणाऱ्या एकूण मुलांपैकी

८८%विद्यार्थ्यांनी प्रत्येक प्रश्नाचे योग्य उत्तर दिले तर ६%विद्यार्थ्यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही. तर ६%विद्यार्थ्यांकडून अल्प प्रतिसाद मिळाला.

२. KG1मधून शिकण्याच्या एकूण १८ विद्यार्थ्यांपैकी ७७.७८ टक्के विद्यार्थ्यांनी होकारार्थी १६ टक्के विद्यार्थ्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही तर फक्त १ टक्के विद्यार्थ्यांनी अल्प प्रतिसाद दिला.

३. KG2मधून निवडण्यात आलेल्या ३२ विद्यार्थ्यांपैकी ९०.६३ टक्के विद्यार्थ्यांनी होकारार्थी २५ टक्के विद्यार्थ्यांनी नकारार्थी तर ३.१३ टक्के विद्यार्थ्यांनी अल्प प्रतिसाद दिला.

सारणी क्र. २ चे विश्लेषण :-

सारणी क्र. २ मध्ये अंगणवाडी KG1आणि KG2मधील विद्यार्थ्यांच्या भाषाविकासाची टक्केवारी दर्शविण्यात आली आहे.

१. यामध्ये अंगणवाडीमधील विद्यार्थ्यांचा मराठी भाषेचा भाषिक विकास तपासण्यात आला असता तो ९३ टक्के इतका आढळून आला. तर हिंदी, इंग्रजी भाषेस १४ टक्के व १० टक्के असा अल्प प्रतिसाद दिसून आला.

२. KG1 आणि KG2मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी ह्या भाषांचा विकास जरी तपासण्यात आला असला तरी मुख्य भर मराठी भाषा म्हणजेच मातृभाषेवर देण्यात आला होता. KG1च्या विद्यार्थ्यांमध्ये ८१ टक्के तर KG2च्या विद्यार्थ्यांमध्ये ८४ टक्के प्रतिसाद आढळून आला तर हिंदी व इंग्रजी भाषेस साधारण प्रतिसाद आढळून आला.

#### निष्कर्ष:-

१. अंगणवाडीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा मातृभाषेचा विकासाचा शोध घेतला असता तो ९३ टक्केइतका आढळून आला. म्हणजेच मातृभाषेतून पूर्वप्राथमिक शिक्षण दिले असता विद्यार्थ्यांचा भाषा विकास अधिक लवकर झपाट्याने होतो. असे दिसून आले.
२. इंग्रजीमाध्यात किंडरगार्डनमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भाषा विकासात इतर दोन भाषा हिंदी व इंग्रजी ह्या अडथळा निर्माण करतात असे दिसून आले.
३. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी असल्यामुळे व शाळेतील विद्यार्थ्यांना अडथळे निर्माण होत होते. अचूक शब्द आठवत नव्हते तर काही विद्यार्थी चुकीचा शब्द प्रयोग करीत होते.
४. मराठी माध्यम म्हणजे अंगणवाडीत जाणारे विद्यार्थी व इंग्रजी माध्यम म्हणजे किंडरगार्डनमध्ये जाणारे विद्यार्थी यांच्या मातृभाषा विकासाचा तुलनात्मक अभ्यास केला असता असे दिसून आले की अंगणवाडीत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भाषेविषयीचे ज्ञान KGच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा चांगले आहे.



५. अंगणवाडीच्या विद्यार्थ्यांना गप्पागोष्टी कहाणी, बालगिते, बडबडगीते हे तोंडपाठ होतात. तर शिवाय त्यांना शिक्षकेशी संभाषणत अडथळा येत नव्हता. तर KGमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी गाणे कथा येत असल्यातरी शिक्षकेसोबत संभाषण करताना भाषेची अडचण जाणवत होती. विद्यार्थी इंग्रजीमध्ये किंवा हिंदीमध्ये किंवा मराठीमध्ये कोणत्याही एका भाषेमध्ये व्यवस्थित बोलू शकत नव्हता.

#### शिफारशी:-

१. विद्यार्थ्यांना पूर्वप्राथमिक शिक्षण शक्यतो मातृभाषेतूनच द्यावे.
२. विविध शिक्षणसमित्यांच्या / आयोगाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करावी.
३. विद्यार्थ्यांना इंग्रजी भाषेतून शिक्षण दिले तरी वेगवेगळ्या भाषांचे त्यांच्यावर दडपण निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
४. इंग्रजी माध्यमातील मुलांना शक्यतो इंग्रजी बोलण्यासाठी दडपण आणू नये. याची दक्षता घ्यावी.
५. तणवमुक्त वातावरणात त्यांचा भाषा विकास होऊ द्यावा.
६. पालकांनी मुलांसोबत भरपूर बोलावे त्यामुळे मुलाचा शब्दसाठा वाढेल.

#### संदर्भ सूची:-

१. बोरुडे, रा.र. (२००५) संशोधन पद्धती शास्त्र पूणे विद्यार्थी ग्रह प्रकाशन
२. भिंताडे वि.शे. (२००५) शैक्षणिक संशोधन पद्धती पूणे नित्यनूतन प्रकाशन.
३. मुळे श. रा. आणि उमाठे वि. तु. शैक्षणिक संशोधन मुलतत्वे १९९८ तृतीय आवृत्ती, विद्या बुक्स प्रकाशन औरंगाबाद.
४. दांडेकर वा.ना. (१९९२) शैक्षणिक मुल्यमापन व संख्या शास्त्र,पुणे, नूतन प्रकाशन.

## ग्रामीण विकासातील महात्मा गांधीजीचे योगदान

डॉ. रामदास तु. कुलसंगे

समाजशास्त्र विभाग प्रमुख

कला व वाणिज्य महाविद्यालय जरुड, जि.अमरावती.

### प्रस्तावना

‘महात्मा गांधीजी आणि ग्रामीण विकास’ यांचा अगदी जवळचा संबंध आहे. त्यांनी सातत्याने ग्रामीणांचा व ग्रामीण क्षेत्राचा विचार केला. या देशाचा खऱ्या अर्थाने विकास करायचा असेल तर खेड्याचा विकासाला प्राधान्यक्रम दिले पाहिजे असे ते म्हणत. गाव स्वयंपूर्ण करणे हे देश विकासाच्या दृष्टीने प्रमुख उद्दिष्टे असायला हवे असे म्हणतांना त्यांना विविध योजना सांगितल्या की ज्यामुळे देशातील सामान्य, कष्टकरी व ग्रामीण, शेतकऱ्यांचा विकास होईल. महात्मा गांधीजींच्या दृष्टीने गाव हा प्रमुख मुद्दा होता. याकरीता त्याचे योगदान अत्यंत मोलाचे आहे. त्याचा आढावा या लेखात घेतला आहे.

### अध्ययनाचे उद्देश

या अध्ययनातील प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे

1. महात्मा गांधीजींच्या विचार कार्याचे अध्ययन करणे.
2. महात्मा गांधीजींच्या ग्रामीण विकासाबाबतच्या योगदानाचे अध्ययन करणे.
3. ग्रामीण क्षेत्रात झालेल्या बदलाचे अध्ययन करणे.

वरील उद्देशाला अनुसरून महात्मा गांधीजींच्या ग्रामीण विकासाबाबतच्या योगदानाचे विश्लेषण येथे केले आहे. ‘गाव’ हा देशाचा घटक समजून त्याकरीता त्यांनी विविध योजनांचे कार्यक्रम सांगितले की, ज्याद्वारा गाव स्वतंत्रपूर्ण व स्वावलंबी करता येईल अशा सर्व मुद्द्यांचे विश्लेषण या लेखात करण्यात आले आहे.

### महात्मा गांधीजीचे ग्रामीण विकासाबाबतचे विचार

ग्रामीण क्षेत्राचा विकास हा त्याच्या जिद्दाळ्याचा विषय होता. त्याकरीता त्यांनी सांगितलेल्या काही मुद्द्यांची मांडणी येथे केली आहे.

सर्वोदयी समाज :

महात्मा गांधीजींच्या काळात एकीकडे भांडवलवादी तर दुसरीकडे साम्यवादी विचारसरणी जगभर गाजत होती. मार्क्सनी सांगितलेला साम्यवादी विचार हा समावता व समान संधीची निर्मिती करून देत असला तरी त्याचा मार्ग हिसेंचा आहे. परंतु महात्मा गांधीजींना मानवाचा विकास करायचा तोही मानवतेच्या नैतिकतेच्या पार्श्वभूमीवर त्यामुळे त्यांना साम्यवादी विचार मान्य नव्हता. भारताबाबत म्हणतात असा भारत घडवायचा आहे की, ज्यामध्ये गरीबांना सुद्धा आपला देश वाटला पाहिजे. ( यंग इंडिया 11.8.1920) याकरीता सर्वांना त्या क्षेत्रातील वा गावातच सर्व आवश्यक बाबी मिळायला हव्यात. शिक्षणाची सोय व इतर सोई सुविधा गावातच पुर्ण व्हाव्यात असे ते म्हणत. गावात सर्वांचे कल्याण अपेक्षेत असून सर्वांचा उदय वा कल्याण असणारा समाज मान्य केला आहे. सर्व समाज घटकाचे कल्याण समाविष्ट असणारे गाव हवे. त्यातूनच त्यांनी स्वावलंबी गावाची कल्पना मांडली.

### **स्वावलंबी गाव**

सर्वांच्या विकासाकरीता गावाचे सर्वांगीण कल्याण करायला हवे. सरकारबरोबर इतरही स्वयंसेवी संस्थांनीही प्रयत्न करावे की ज्यामुळे गाव स्वावलंबी होईल. ते म्हणतात की, गावात लोकशाही हवी, गावाच्या गरजा गावातच पुर्ण व्हाव्यात. शेजारच्या गावावर अवलंबून राहू नये. गाव स्वावलंबी करीता विविध योजना महत्वाच्या होत. जसे पशुची काळजी घ्यावी. जैविक शेती करावी, चरखा कताई करावी, पोष्टीक व संतुलित आहाराचे सेवन करावे. पाणी व स्वच्छ हवा मिळावी याकरीता वृक्ष लागवड करावी असा उपदेश ते करतात.

गावातील तंटे भांडणे, गावातच मिटवावे, उच्च निचता, भेदाभेद नको, अस्पृश्यता हा वरिष्ठ समजून कार्य करावे. सर्व जाती जमातीच्या कल्याणाकरीता कार्य करावे, एकुनच गावाच्या सर्वांगीण विकासाकरीता सामाजिक, आर्थिक, मानसिक व बौद्धिक दृष्ट्या मजबुत हवा. गाव स्वतंत्र म्हणजे देशाच्या स्वातंत्र्याची पाहिली पायरी होय असे ते म्हणत. महात्मा गांधी आदर्श समाजासंबंधी म्हणतात, आदर्श समाज में न कोई गरीब होगा, न भिकारी, न कोई उँचा होगा, न निचा। न कोई करोडपती मालिक होगा। न आँधा भूखा होगा नौकर। न शराब होगी, न कोई दुसरी नशिली चीज। सब अपने आप खुशीसे और गर्व से अपनी रोटी कमाने के लिए मेहनत करेगा। वहा स्त्रियों की भी वही इज्जत होगी जो पुरुषों की, और स्त्रियों तथा पुरुषों की शील और पवित्रता की रक्षा की जायेगी। अपनी पत्नी के सिवा हर एक स्त्री का उम्र के अनुसार हर धर्म में पुरुष, माँ, बहन, और बेटी समझेंगे। वहा अस्पृश्यता नहीं होगी और सब धर्मों के प्रती समान आदर रखा जायेंगा। या प्रमाणे त्यांनी आदर्श राज्याची कल्पना केली होती.

## नई तालिम

नई तालिक हा गांधीजींनी जगाला दिलेली मोठी देणगी होय. 31 जुलै 1937 रोजी 'हरिजन' मधून जो लेख प्रकाशित झाला त्यातून नई तालिम ही योजना पुढे आली.

1. प्राथमिक शिक्षण हे 7 ते 14 वयापर्यंत असण
2. हस्तोद्योगाचे शिक्षण
3. हाच परिसरातील लोकांचा व्यवसाय
4. शिक्षण हे उत्पादक व स्वयंपोषीत असावे

या नई तालिममध्ये ग्रामोद्योग व या अनुषांगीकापासून ज्यामुळे ग्राम स्वयंपूर्ण होण्याला मदत होईल. ही योजना व्यक्तीगत असली तरी सामाजिक विकास अंतर्भूत करणारी आहे.

## चरखा

चरखा हा महात्मा गांधीजींचे हत्यार होते. चरख्याद्वारा गावाचा नव्हे तर संपूर्ण देशालाच स्वावलंबी व स्वयंपूर्ण बनविणारे साधन होते. चरखा व सुतकताई हे जीवनाचे ध्येय बनविले होते. या बाबत 1934 साल हरिजन मध्ये लिहितात की, 'श्रीकप पे जीम'वद व'जीम अपससंहम'वसंत'लेजमउण भम चसंदजे'तम जीम अंतपवने पदकनेजतपमे'पबी बंद'नचचवतज श्रीकप पद तमजनतद वित जीम'मंज'दक जीम'नेजमदंदबम जीमल कमतपअम तिनपजण'

सुतकताई व खाडी वापरामुळे चरखाला चालना मिळणार होती म्हणून त्याची स्वतः व सर्व काँग्रेस कार्यकर्ते व सदस्यांनाच खादी वापरण्याची सक्ती केली होती. चरख्यांच्या वापरामुळे बेरोजगारी दूर होवून रोजगार गावातच मिळते. आर्थिक उत्पादन वाढून स्वावलंबन वाढेल असे ते म्हणत.

## कृषीचा विकास

कृषी क्षेत्राचा विकासावर त्याचा भर होता. शेती, शेतकरी हा त्यांच्या जिवाळ्याच्या विषय होता. गावातच उसाचे उत्पादन गुळ, ढेप, धान्य, मध हे व्हावे. कष्टकऱ्यांना गावातच रोजगार मिळावे. शेती विकासाकरीता चांगल्या पशूंचा बैलांचा वापर करावा. गायी सांभाळाव्यात यामुळे सेंद्रीय खत मिळेल व उत्पादन ही चांगले येईल.

गोरक्षण ज्यामुळे चांगले धन शेतीला मिळेल. चांगल्या गाईची उपलब्धता व्हावी मिळेल. चांगल्या गाईची उपलब्धता व्हावी म्हणून त्याचे रक्षणच संवर्धन करावे की त्यामुळे शेती उत्पादनात भरच पडेल असे ते म्हणत. गावच्या व शेतीच्या विकासाकरीता त्यांनी वेळोवेळी विचार मांडले.

### **सहभोजन व मंदीर प्रवेश**

आपल्याजवळील भेदाभेद व अस्पृश्यता लक्षात घेता गाव, समवेत सहभोजन व मंदीरात प्रवेशाचे कार्यक्रम त्यांनी राबविले ज्यामुळे गावात समानता व एकता नांदेल. मंदीरात प्रवेशाकरीता ते आग्रही असत. सहभोजनाने सर्वजण जवळ येतात. भेदाभेद, अस्पृश्यता कमी होवून आपलेपणा वाढीस लागतो.

### **सारांश**

महात्मा गांधीजी हे बहुआयामी व्यक्तीमत्वाचे धनी होते. ज्यांनी ग्रामीण जिवनाच्या सर्वच क्षेत्रात कार्य केले. त्यांच्या विचार कार्याचा केंद्रबिंदू हा 'गाव स्वयंपूर्ण' हा होता. त्याकरीता त्यांनी वेळोवेळी विविध उपक्रम व कार्यक्रमाची मांडणी केली. ज्यामध्ये सर्वोदय, विश्वस्त, शेती, शेतकरी, खादी, चरखा, सुतकताई, लघु व कुटीर उद्योग नई तालिम, शिक्षण बरोबर विश्वस्त सर्वोदय इ. विचार मांडला. एकुणच त्यांचे ग्रामीण विकासातील योगदान मोलाचे आहेत.

### **संदर्भ**

1. बोरीकर दिनकर (1997) : माझ्या स्वप्नातील भारत, मराठवाडा उद्योग खादी समिती नांदेड.
2. ग्राम स्वराज्य, महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी भवन, पुणे 1995.
3. महात्मा गांधी (2011) माझ्या स्वप्नातील भारत, परधान प्रकाशन, वर्धा.
4. देशपांडे अच्युत (1998) : गोरक्षा सत्याग्रह की पृष्ठभूमी परधान प्रकाशन, वर्धा.
5. मो. क. गांधी, सत्याचे प्रयोग अथवा आत्मकथा, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद, 14.
6. व्यास हरिप्रसाद, (अनुवाद) : ग्राम स्वराज्य, महात्मा गांधी, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद 14.

## घरगुती हिंसा एक समस्या

डॉ. किशोर उत्तमराव राऊत

समाजशास्त्र विभाग

संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती.

### प्रस्तावना

‘महिला’ हया समाजव्यवस्थेचा अर्धा भाग होय. ज्याचे समाजनिर्मितीमध्ये मोठे योगदान आहे. मानवी जीवनातील त्यांची भागीदारी लक्षात घेता त्यांना शेकडो वर्षांपासून दिली गेलेली वागणुक ही काहीशी निकृष्ट व दुय्यम दर्जाची होती. इतिहासातील काही अपवाद सोडले तर कोटयावधी महिला हया अन्याय अत्याचाराच्या बळीच होत्या. पुरुषप्रधान संस्कृतीमध्ये महिलावर असणारा अधिकार अबाधित होता. स्वःमालकी वा खाजगी मालमत्ता या उद्देशाने त्यांना दिली जाणारी वागणुक ही चिंताजनक बाब होय. पुरुष सत्तेने पिढ्यानं पिढ्या तिला वंचिततेचे जीवन जगण्यास बाध्य केले. अशी व्यवस्थाच निर्माण केली गेली की, स्त्री वा पत्नी ही आपल्याच अधिपत्याखाली राहिल. त्याला जातीय धार्मिकतेची जोड देवून त्यानुरूप प्रथा, परंपरा, नियम, श्रद्धा, देवी-देवता, सण-उत्सव या सांस्कृतिक अंगाने सुद्धा तिला देवत्वाचे रूप देवून कायम, वर्चस्वाखाली ठेवले. स्त्री वा पत्नीला आपल्या ‘स्व’ (Self) ची जाणीव होवू न देता नेहमीच कनिष्ठ वागणुक दिली. एकुणच महिला संदर्भातील वेगवेगळ्या प्रकाराची होणारी हिंसात्मक वागणुक विशेषतः घरगुती हिंसा (Domestic Violence) अभ्यासतांना त्याचे स्वरूप, प्रकार आणि वाढत्या घटना पाहता एका महत्त्वपूर्ण सामाजिक समस्येचे (Social Problem) हे अध्ययन होय.

### अध्ययनाचे उद्देश (Objective of the Study)

या अध्ययनात खालील उद्देशांचा समावेश केला आहे.

1. महिलांच्या सामाजिक स्थितीचे अध्ययन करणे.
2. महिलांच्या घरगुती समस्यांचे अध्ययन करणे.
3. महिलांच्या घरगुती समस्यांच्या कारणांचे विश्लेषण करणे.
4. उपाय योजना सुचविणे.

वरील उद्देशाला अनुसरून घरगुती महिलावरील हिंसा, त्याचे स्वरूप, प्रकार त्यातून उदभवणाऱ्या समस्या, कारणे इत्यादींचे विश्लेषण करतांना शेवटी उपाय सुचविले आहे. यामध्ये प्राथमिक व दुय्यम तथ्यांचा आधार मांडणी केले आहे.

### महिलांची सामाजिक स्थिती

महिला समाजव्यवस्थेचा महत्वाचा घटक असतांना गेल्या हजारो वर्षांपासून पितृसत्ताक वा पुरुषप्रधान व्यवस्थेने सातत्याने डावल्याचे चित्र आहे. अन्याय अत्याचाराची मालिका प्रारंभापासूनची आहे. ‘बळी तो कान पिळी’ या न्यायाप्रमाणे ज्याच्या हाती सत्ता असेल तो ती वापरणार. फरक एवढाच की सत्ता चांगल्या कामासाठी वापरावयाची की वाईट. याचा निर्णय त्यांना घ्यावयाचा आहे. पुरुषप्रधान संस्कृतीने सातत्याने महिलांना संवेदनाहीन, नाजूक, दुर्बल, बुद्धीने कमजोर, कायमच दुय्यमतत्व दिले.



स्त्रीला वा पत्नीला 'उपभोगाचे साधन', 'उपभोगाची वस्तू' म्हणत 'चूल आणि मूल' एवढेच कार्यक्षेत्र ठेवण्यात आले. स्त्रीला कायमच आपल्या नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न झाला.

इतिहासाकडे पाहता वेदमंत्रामध्ये अनेक ऋषीकाची नावे आहेत जसे 1) देवसम्प्रज्ञी शची 2) वाचकवी गार्गी 3) ब्रम्हवादिनी ममता 4) ब्रम्हवादिनी विश्ववारा 5) ब्रम्हवादिनी अपाला 6) ब्रम्हवादिनी घोषा 7) ब्रम्हवादिनी सुर्या 8) ब्रम्हवादिनी वाक् (सिंह एवं सिंह 2013 : 38) अशी काही उदाहरणे आढळत असली तरी पुरुष वर्गांनी आपले नियंत्रण सोडले नाही. स्त्रीला मानाचे स्थान मिळाले नाही ही वास्तविकता होय. या संदर्भात डॉ.द.ना. धनागरे लिहितात की, "पुरुष प्रधान समाजरचनेची अभेद्य चौकट असूनही मैत्रेयी, गार्गी आणि लोपमुद्रा हयांच्या पासून तर आद्यशंकराचार्याच्या मंडनमिश्रांशी झालेल्या वादविवादाचे वेळी जिने न्यायनिवाडा करण्याची भूमिका बजावली होती त्या मंडनमिश्रांच्या पत्नी उभयभारतीपर्यंत अनेक विदुषींचा अधुनमधुन उल्लेख येतो. पण अशा विदुषींची नावे सहसा शालेय पाठ्यक्रमात वा पुस्तकामध्ये आढळत नाहीत. म्हणजे न्याय म्हणावे तसे मानाचे स्थान दिले गेलेले नाही हे मान्य करावे लागेल." (धनागरे 2005:82) अशा काही नावे इतिहासात आढळत असली तरी तिच्यावरील अन्याय अत्याचार वा पुरुषी नियंत्रण प्रणाली कमी झाली नाही. मग ती कोणताही कालखंड असो वा शासन व्यवस्था, ज्यामध्ये स्त्री वा पत्नी कायमच दुर्लक्षित राहिली या संदर्भात द. ना. धनागरे पुढे लिहितात की, "वेगवेगळ्या ऐतिहासिक काळखंडात उत्पादन पद्धती साधने बदलली, राज्यसंस्थेच्या जडणघडणीचे स्वरूप बदलत गेले, तरीही घर, कुटुंब आणि त्याच्या संपत्तीवर संपूर्ण वर्चस्व पुरुषाचेच राहिले. एवढेच नव्हे तर कुटुंबाच्या उद्योगात स्त्रीने वा पत्नीने केलेल्या श्रमावरही सदैव पतीचेच नियंत्रण राहिले. मुख्य म्हणजे स्त्रीचे लैंगिक जीवनही पूर्णपणे एका पुरुषाची खाजगी संपत्ती आहे. अशा तऱ्हेने तिच्या शरीरावर हे नियंत्रण भक्कम आणि सर्वंकष होत गेले. मग ती गुलामगिरीची अवस्था असो, सरंजामशाहीचे युग असो किंवा भांडवलशाहीचे उत्पादन अवस्था असो, राज्यसंस्था बदलल्या पण पुरुषप्रधान आणि पुरुषसत्ताक व्यवस्थेत मात्र कुठलाही बदल घडून आला नाही." (धनागरे 2005:84) एवढी मजबूत परंपरागत समाजव्यवस्था होती. जिच्यावर कुठलाही परिणाम झाला नाही. स्त्री वा पत्नीला कायमच दुय्यम दर्जाची वागणूक दिल्या गेली.

भारतीय समाज संदर्भात स्त्रीच्या वैयक्तिक, वैवाहीक व कौटुंबिक जीवनातही पुरुषसत्ता कायमच राहिली.

**बाल्ये पितुर्वशे मिष्टेत्यागी गृहस्थ यौवने ।**

**पुत्रणा भर्तरी प्रेते न भजेत्स्यी स्वतत्रताम् ।।**

स्त्री लहानपणापासून वृद्धावस्थेपर्यंत ही पुरुषाच्या अधिपत्याखाली ठेवण्याची व्यवस्था केली होती. स्त्रीला एकीकडे अर्धांगिणी, गृहलक्ष्मी, मातृशक्ती, एवढेच नव्हे तर दुर्गा, सरस्वती अशा प्रकारच्या गौरवाने उल्लेख करायचा. तर दुसऱ्या बाजूने स्त्रीला वा पत्नीला कायमच आपल्या अधिपत्याखाली वा नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करायचा अशी स्थिती आपल्याकडे आहे. मुलगी जन्म झाल्यापासून प्रारंभी वडीलांच्या, मोठेपणी पतीच्या तर वृद्धावस्थेत मुलाच्या वर्चस्वाखाली तिला जगावे लागते हे मान्य करावे लागते अशी एकुन परिस्थिती आहे.

**महिलांची घरगुती समस्या**

महिलांची घरगुती परिस्थिती विचित्र प्रकारची आहे. घरी वा कुटुंबात स्त्रीला सातत्याने कमी लेखण्याचा प्रयत्न होतो. उदा. तुला समजत नाही, तु शांत रहा, चूप रहा, बोलू नको, इकडे जा, तिकडे जाऊ नको, हे कर, ते करू नको अशी वाक्ये ही दररोजच्या जीवनात पाहायला मिळतात. अर्थात त्या स्त्रीला ही ही वाक्ये एवढी अंगवळणी पडली असतात की, तिला हे कळतच नाही की यामध्ये कोणता भाव आहे. त्याविरोधी उठाव करण्याची क्षमताच समाजव्यवस्थेने हिरावून घेतल्याचे चित्र आहे. स्त्रीला बालपणापासून सातत्याने अधिक वेळा दुय्यममत्वं देण्याचा प्रयत्न कुटुंबियाकडून सर्रासपणे होतो.

### **महिलांच्या समस्या**

महिलांच्या फक्त घरगुती समस्या आहेत असे नाही तर बाहेरही तिचा सातत्याने वेगवेगळ्या बाबींचा सामना करावा लागतो. उदा. बलात्कार, अपहरण, पळवून नेणे, मारणे, जाळणे, विनयभंग, यौन अत्याचार, छेडछाड अशा कित्येक समस्या आढळून येतात. देशातील दोन तृतीयांश महिलांना कोणत्याना कोणत्या छळाला व अत्याचाराला बळी पडावे लागते. अशा अन्यायाचा त्यांनी कुठेतरी अनुभव घेतला असतो. डॉ. धनागरे लिहितात की, हुंडाबळी 1996-5513 तर 1998-9617, बलात्कार 1996-14846 तर 1998-15031, शारीरिक छळ 199-35246 तर 1998-41318, विनयभंग 1996-28939 तर 1998-31046, लैंगिक छळ-1996-5671 तर 1998-6123 (धनागरे 2005:102) तर राम आहुजा व मुकेश आहुजा यांनी लिहिल्याप्रमाणे भारतीय दंड संहिता च्या अंतर्गत 1991, 95 पर्यंत महिलावरील अपराधाचा तक्ताची आकडेवारी बलात्कार 1991-95 पर्यंत 11650, अपहरण एवं भगाना 12655, दहेज मृत्यू 5163, प्रताडना 22967, शारीरिक छेडखान 22915, छेडखान 9658. (आहुजा एव आहुजा 2006:241)

तसेच राम आहुजा व मुकेश आहुजा यांनी लिहिल्याप्रमाणे विस्तृत रूप से महिलाओं के प्रति अपराधी को दो श्रेणीयों में बांटा जाता है।

#### **1. भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध (Crime under the Indian Penal Code)**

;पद्ध बलात्कार ;पपद्ध अपहरण एवं भगा ले जाना ;पपद्ध दहेज के कारण हत्या ;पद्ध शारीरिक एवं मानसिक उत्पीडन अथवा पत्नी को पीटना ;अद्ध शारीरिक छेडछाड और चिढाना

#### **2. स्थानिक एवं विशेष विधानों के अंतर्गत अपराध**

(i) अनैतिक अधपतन (अधिनियम 1978) ;पपद्ध दहेज मागना (अधिनियम 1971) ;पपद्ध सती होने के लिए बाध्य करना (अधिनियम 1987 ) ;पद्ध महिलाओं को अभद्र प्रदर्शन (अधिनियम 1986) (आहुजा एवं आहुजा 2006 : 231)

दरवर्षी महिलांच्या खुनाच्या संख्येत वाढ झाल्याचे आढळून येते. नॅशनल काईम रेकार्ड बुरो नुसार 2014 मध्ये देशात महिलांवर दर दिवशी सरासरी 100 बलात्कार होतात. सर्वात जास्त मध्य प्रदेशात झाले आहेत. देशात 33,981 हत्या झाल्या. त्यापैकी उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक हत्या प्रेमप्रसंगातून घडल्या तर अपहरण 77237 प्रकरणे देशात तर उत्तर प्रदेशात 12,361 झाली. पुढे दिल्याप्रमाणे 5 वर्षांत 201 टक्क्यांनी अपहरणाचे गुन्हे वाढले असून 2010-38440, 2011-344,664, 2012-47592, 2013-65461, तर 2014 मध्ये 77237 गुन्ह्याची नोंद आहे. ( दिव्य मराठी अकोला गुरुवार 24 सप्टेंबर 2015 पृ.12). मुळात बलात्कार हा एकदम अनाळखी व्यक्ती कडून होत नसून तो आपल्यासारख्या जवळच्या व्यक्तीकडूनच होते. उदा. नातेवाईक,

मित्र, शेजारी, कार्यालय व कंपनी सहकारी व अधिकारी एवढी त्याची तीव्रता वाढली आहे. त्याचबरोबर हुंडा प्रथा सुध्दा सातत्याने वाढत आहे. हा कायदा 1961 मध्ये व त्यानंतर 1984 मध्ये सुधारणा झाल्यानंतरही तीव्रता वाढतच आहे. एकूणच महिलांवरील समस्यांची तीव्रता कमी न होता वर्तमानत काळातही ती वाढतांना दिसते. वर्तमान स्थितीचा विचार करता महिलांवर घरगुती हिंसा मोठ्या प्रमाणात होतांना आढळतात.

1. बलात्कार, 2. अपहरण, 3. विनयभंग, 4. हुंडा, 5. छेडखान, 6. शारीरिक छळ मानसिक छळ 7. सामाजिक आर्थिक दृष्टीने दुयमत्व, 8. भेदाची निती, 9. विषमतामुलक व्यवस्था, 10. नियंत्रण व अधिपत्याखाली ठेवण्याची मानसिकता. एकूणच महिलांवरील अन्याय अत्याचाराची बरीच मोठी यादी होवून जाईल. हे सर्व पाहता महिलांना विविध प्रकारच्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. आजही सुधारलेल्या जीवनाचा आधुनिक समजल्या जाणाऱ्या नागरी क्षेत्रात महिलांवरील अन्याय अत्याचार वा हिंसात्मक घटना सर्वाधिक असल्याची नोंद आहे. ग्रामीण-आदिवासी क्षेत्रातील हे प्रमाण कमी असले तरी महिलांची स्थिती फारशी समाधानकारक नाही. महिलांना सन्मान, इज्जत देवून समान संधीची उपलब्धी करून देणे काळाची गरज आहे. महिलांच्या विकासाशिवाय देशाचा विकास शक्य नाही. याकरीता विविध समाज सुधारकांनी महत्वपूर्ण चळवळी व आंदोलने केलेली आहेत. राजाराम मोहन रॉय, सेन, महादेव रानडे, गोखले, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षी कर्वे इत्यादी. परंतु खऱ्या अर्थाने महिलांच्या कल्याणाकरीता महात्मा जोतीराव फुले, सावित्रीबाई फुले पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी खऱ्या अर्थाने महिलांचा सर्वांगीण कल्याणाकरीता कार्य केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तर भारतीय संविधानात विशेष तरतुदी करून महिलांना सुरक्षा कवच निर्माण केले आहे.

### **घरगुती हिंसाचार कारणे**

घरगुती हिंसाचे प्रमाण पाहता याकरीता विविध कारणांचा अंतर्भाव करावा लागेल. जसे पुरुषप्रधान मानसिकता, परंपरागत व्यवस्थेचा प्रभाव, स्त्री-पुरुष असमानता, शिक्षण व नोकरीचा अभाव, कौटुंबिक अयोग्यता, आर्थिक, राजकीय दृष्टीने दुर्बलता, आधुनिकीकरण व जागतिकीकरण, चंगळवादी संस्कृतीत वाढ, फॅशन, पोशाख पध्दती इ. स्त्री स्त्रीचा छळ करते. उदा. सासू सून. पुरुषी मानसिकता तर आहेच परंतु स्त्री स्त्रीचा छळ करतांना बऱ्याच कौटुंबिक समस्या आढळतात. काही वेळा यातून भग्न कुटुंबाची स्थिती आढळते. घरगुती हा बऱ्याच कारणांचा परिणाम आहे. परंतु असे प्रकार थांबवण्यापेक्षा सातत्याने वाढतांना आढळते. गल्ली पासून तर दिल्लीपर्यंत महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मुंबई दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरात मुली व महिलांना बाहेर निघणे भितीदायक ठरत आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळून 70 वर्षांचा कालावधी लोटला असला तरीही महिला आजही सुरक्षित जीवनाची हमी देता आली नाही. गर्भातच मारण्याची पध्दती भ्रूणहत्या सारखेच प्रकार आजही खुलेआम सुरूच आहे.

### **उपाय योजना**

महिलांवरील अन्याय अत्याचार व हिंसात्मक प्रकार कमी होण्याच्या दृष्टीने काही उपाय खालीलप्रमाणे आहेत.

1. कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करावी.
2. स्वतंत्र महिला न्यायालयाची स्थापन करावी.
3. शिक्षण व प्रशिक्षणात वाढ करावी.

4. महिलांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी विशेष कृती कार्यक्रम तयार करावा.
5. महिलांच्या स्वयंसेवा संस्थांना विशेष दर्जा द्यावा.
6. महिला चळवळीकरीता चालना द्यावी.
7. मानवी मूल्यांची जोपासना करावी.
8. स्त्री-पुरुष असमानता व विषमतावादी दृष्टीकोन नष्ट करावा.

#### **सारांश**

घरगुती हिंसा (Domestic Violence) ही वर्तमान काळातील एक मोठी समस्या होय. आदिवासी व ग्रामीण समाजापेक्षा नागरी वा पुढारलेल्या समाजात ही समस्या सर्वाधिक आहे. प्रारंभापासून महिला पुरुषप्रधान मानसिकतेच्या बळी ठरल्या आहेत. त्यांच्यावर सातत्याने अन्याय अत्याचार होत आले तरी इतिहास काही नावाचा गौरवाने उल्लेख आढळतो. परंतु आजही अज्ञान, अंधान्या अवस्थेत कोटयावधी महिला जीवन जगतांना आढळतात. स्वातंत्र्यात सत्तर वर्षांचा कालावधी लोटला असला तरी संविधानात्मक सुरक्षा पूर्णशाने प्रदान करता आली नाही. महिलांच्या मनातील असुरक्षितेची भावना घर करून आहे. याचे कारण की त्यांना कोणता तरी प्रत्यक्ष अनुभव आलेला असतो. महिलांना सक्षम व समर्थपणे कार्य करण्याची संधी दिल्यास त्याही पुरुषाच्या खांद्याला खांद्या लावून कार्य करू शकतात हे कित्येक उदाहरणावरून दिसून आले आहे. महिलांचा जेवढा विकास होईल तेवढा त्या देशाचा विकास असे समीकरण पाहता आपल्या राज्यकर्त्यांनी व समाजाच्या सर्व घटकांना सोबत घेवून मानवीय, समानतेचा वा माणुसकीच्या दृष्टीने विचार केल्यास या समस्येला आळा घालता येवू शकेल.

#### **संदर्भ**

1. सिंह बी.एन. एवं सिंह जनमेजय (2013): नारीवाद, रावत पब्लिकेशन, जयपूर पृ. 38.
2. नागरे द. ना. (2005): संकल्पनाचे विश्व आणि सामाजिक वास्तव, प्रतिमा प्रकाशन पुणे, पृ. 82.
3. तत्रैव पृ. 84.
4. तत्रैव पृ. 105.
5. राम आहुजा व मुकेश आहुजा (2006): विवेचनात्मक अपराधशास्त्र, रावत पब्लिकेशन, जयपूर, पृ. 241.
6. दै. दिव्य मराठी, आकोला आवृत्ती, गुरुवार 24 सप्टेंबर 2015 पृ. 12.

**बी.एड.कॉलेज मध्ये सुक्ष्माध्यापनापूर्वी आयोजलेल्या पाठ्यपुस्तक ओळख या  
उपक्रमांच्या परीणामकारकतेचा चिकित्सक अभ्यास**

**संशोधिका**

प्रा. सविता आप्पासाहेब लोखंडे  
विमेन्स एज्युकेशन कॉलेज,  
श्रीगोंदा.

**मार्गदर्शक**

डॉ.बालाजी रंगनाथराव लाहोरकर  
प्राध्यापक एम.एड. विभाग,  
इंदिरा अध्यापकमहाविद्यालय,  
सहयोग एज्युकेशनल कॅम्पस,  
विष्णुपूरी, नांदेड.

**प्रस्तावना -**

व्यावसायिक कोर्स बी.एड. अंतर्गत अनेक उपक्रमांचे आयोजन वर्षभरात करावे लागतात. बी.एड.च्या अभ्यास क्रमात सुक्ष्म अध्यापन हा. बी.एड. चा आत्माजो विद्यार्थीनींना स्वतः मध्ये शिकविण्याचा आत्म विश्वास निर्माण करणारे अभ्यासाचा एक घटक सुक्ष्म अध्यापनात अनेक कौशल्य असतात. एक-एक कौशल्य विद्यार्थ्यांना शिकविले जातात. जी कौशल्ये त्यास अवगत होतात त्याचाच वापर करून तो आपला अध्यापनाचा पाया मजबुत करत असतो. अशा या सुक्ष्म अध्यापनासाठी प्रत्येक विद्यार्थीनीला स्वतःच्या मेथड ची इयत्ता ५ वी ते ९ वी पर्यंतची पाठ्यपुस्तकांचा वापर करून एक-एक कौशल्य पूर्ण करावयाचे असते. अशा वेळेस पाठ्यपुस्तक वाचून त्यातील आशय विद्यार्थ्यानींना असला पाहिजे त्यासाठी पाठ्यपुस्तकांची ओळख हा उपक्रम यासाठी निश्चितच उपयुक्त पडेल असे मला वाटते. विद्यार्थ्यांना आशयज्ञान चांगले व्हावे यासाठी हा उपक्रम उपयुक्त आहे.

**संशोधनाची गरज:-**

विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा या दृष्टीने विद्यार्थीनींना पाठ्यपुस्तकांची ओळख होणे गरजेचे आहे. जर आशय आधीच माहिती असेल तर तो चांगल्या प्रकारे आपल्या विद्यार्थ्यांना सांगू शकेल. त्यासाठी हा उपक्रम गरजेचा आहे. तसेच इतर विषयातील विद्यार्थीनींनाही इतर भाषा व इतर विषयामध्ये काय आशय आहे हे समजण्यासाठी हा उपक्रम गरजेचा आहे. भाषेचा इतर विषयांशी समवाय असतो तो कसा हेही आपणास या उपक्रमातून साध्य करता येतो.

सर्व विषय शिक्षकांसाठी हा उपक्रम उपयुक्त गरजेचा आहे. विविध शाखेतून मुले-मुली बी.एड ला प्रवेश घेत असतात. व पाठ्यपुस्तकांचा संबंध इयत्ता १० वी पर्यंत असतो. नंतर ही पुस्तके मुले वाचत नाही व जेव्हा बी.एड ला प्रवेश घेतात तेव्हा तो विषय शिकविण्याची वेळ येते तेव्हा पाठ्यपुस्तकात काय आहे. त्यातील संकल्पना काय आहेत हे त्यास समजत नाही ते समजण्यासाठी सुक्ष्मअध्यापनापूर्वी हा उपक्रम घेणे गरजेचे आहे.

**संशोधन समस्येचे महत्व:-**

१. छात्रध्यापकांना मध्ये आत्मविश्वास निर्माण होण्यासाठी हा उपक्रम राबविला पाहिजे.
२. प्रत्येक पाठ्यपुस्तक वाचल्याचा आनंद या उपक्रमातून विद्यार्थ्यांना मिळतो.
३. विद्यार्थ्यांचे आशयज्ञान वाढविण्यासाठी हा उपक्रम महत्वाचा आहे.
४. विद्यार्थ्यांना वाचनाची आवड निर्माण करण्यास महत्वाचे आहे.
५. इतर विषयांविषयी गोडी निर्माण करण्यासाठी उपक्रम महत्वाचा आहे.

**संशोधनाची गृहितके:-**

१. बी.एड. कॉलेज मध्ये पाठ्यपुस्तक ओळख हा उपक्रम राबवला जातो.
२. विद्यार्थ्यांची पाठ्यपुस्तक ओळख या उपक्रमाबाबत उदासिनता दिसून येते.

**संशोधनाची उद्दिष्ट्ये:-**

१. शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयात पाठ्यपुस्तकांची ओळख उपक्रम राबविण्याच्या महाविद्यालयाचा शोध घेणे.
२. पाठ्यपुस्तकांची ओळख या उपक्रमांच्या कारणाचा शोध घेणे.
३. या उपक्रमांचा अभ्यास करणे.
४. उपक्रमाचे आयोजन करणे.
५. परीणामकारकतेचा अभ्यास करणे.

**संशोधनासाठी वापरलेली पद्धती:-**

प्रस्तुत संशोधनात वर्तमान स्थितीचा विचार असल्यामुळे संशोधकीने आपल्या संशोधन अहवालासाठी सर्वेक्षण व प्रायोगिक पद्धतीचा वापर केला आहे.

**संशोधन पद्धती निवडण्याची कारणे:-**

१. माहिती गोळा करण्यासाठी सर्वेक्षण पद्धती वापरली जाते.
२. प्रत्यक्ष प्रयोग करून परीणामकारकता तपासण्यासाठी प्रायोगिक पद्धतीचा वापर केला जातो.

**संशोधनाची जनसंख्या:-**



एकूण विद्यार्थीनी - १००

कॉलेजमधील शिक्षक - ७

१०० X ५ = १०५

प्रस्तुत संशोधनाची जनसंख्या १०७ एवढी आहे.

### नमुना निवड पध्दती:-

प्रस्तुत संशोधन पूर्ण करण्यासाठी संशोधकाने असंभाव्यता नमुना निवड पध्दतीची निवड केली आहे आपल्या विषय समस्येची एकूण जनसंख्या लक्षात घेता संशोधकाने येथे केवळ सोईस्कर किंवा प्रासंगिक नमुना निवड पध्दतीचा वापर केला आहे. यामध्ये संशोधकास त्याच्या सोईनुसार नमुना निवडण्याची मुभा असते. ही पध्दती अशास्त्रीय आहे कारण यामध्ये संशोधकास नमुना निवडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असते. या पध्दतीचा वापर गरजेनुसार करणे सोईचे असते.

### नमुन्याचा आकार:-

बी.एड.कॉलेज (विमेन्स एज्युकेशन कॉलेज श्रीगोंदा येथील महाविद्यालयात हया उपक्रमांची परीणामकारकतेचा अभ्यास करण्यासाठी संशोधिकेने महाविद्यालयातील १०० विद्यार्थीनी मधील ३० विद्यार्थीनी व ७ शिक्षक असे ३७ विद्यार्थीनी शिक्षकांची निवड नमुना म्हणून केली आहे.

एकूण विद्यार्थीनी - ३०

महाविद्यालयातील - ०७

शिक्षक - ३७

प्रस्तुत कृती संशोधनात संशोधिकेने ३७ छात्रशिक्षकांची नमुना म्हणून निवड केली आहे.

### माहिती संकलनाची साधने -

१. पाठ्यपुस्तके (विविध विषयांची)
२. उपक्रम पूर्व चाचणी
३. उपक्रमांनंतर चाचणी

४. संख्याशास्त्रीय तंत्रे १. मध्यमान २. प्रमाण विचलन

**संशोधनाची कार्यपद्धती:-**

प्रस्तुत संशोधनामध्ये विद्यार्थी शिक्षिकेनी उपक्रमापूर्वी एक चाचणी घेतली त्यानंतर विद्यार्थ्यांनीना पुस्तके वाचनास दिली व उपक्रमाचे आयोजन केले व उपक्रम संपल्यावर पुन्हा चाचणी घेतली. चाचणीचे संख्याशास्त्रीय विश्लेषण केले. व उपक्रमांची परीणामकारकता अभ्यासली व निष्कर्ष काढले व अहवाललेखन केले.

सारणी क्र. १ माहितीचे संख्याशास्त्रीय विश्लेषण -

	विद्यार्थी	मध्यमान	प्रमाण विचलन
पूर्व चाचणी	८६	१५.६१	४.९६
उत्तर चाचणी	३६	२९.२५	५.८४

**अर्थनिर्वचन:-**

१. शैक्षणिक उपक्रम व वाचनाच्या सरावामुळे मुलींच्या चाचणीच्या गुणंत वाढ झालेली दिसून आली. पूर्व चाचणीच्या मध्यमानापेक्षा उत्तर चाचणीचे मध्यमान  $२९.२५ - १५.६१ = १३.६४$  ने जास्त आहे.
२. उत्तरचाचणी आणि पूर्वचाचणी प्रमाण विचलनातील फरक ०.८८ इतका आहे. उत्तर चाचणीचे प्रमाणविचलन हे पूर्व चाचणीच्या प्रमाणविचलनापेक्षा जास्त आहे. म्हणजे मध्यमानाभोवतीचे प्रसरण उत्तर चाचणीत जास्त आहे.
३. एकंदरीत पूर्व चाचणीपेक्षा उत्तरचाचणी मध्ये वाढ झालेली दिसते सदर वाढ खूप मोठी नसली तरी मात्र नक्की की, उपक्रम नेहमी पाठयपुस्तक ओळख हा राबविला असता विद्यार्थ्यांना पाठयपुस्तक वाचनाची आवडीत वाढ होईल व ज्ञानात वाढ झाली.

**निष्कर्ष:-**

पूर्वचाचणीत वर्गातील प्रशिक्षणार्थीचे पाठयपुस्तकांचे ज्ञान वाचनाची आवड कमी प्रमाणत दिसून आले उपक्रमांनंतर मात्र वाचनाच्या आवडीत वाढ झाली व ज्ञानात भर पडली.

३. इतर विषय पुस्तक वाचनाची आवड निर्माण होण्यास मदत झाली.

४. विज्ञान विषय असणारा विद्यार्थ्यांनीना भाषा विषयात रस निर्माण झाला.
५. इतिहास सारखा निरस विषय आवडीचा वाटू लागला.
६. दोन्ही चाचण्यांच्या फरकाकडे नजर टाकली असता असा निष्कर्ष निघाला की, संशोधकाने राबविलेल्या शैक्षणिक उपक्रमाचा चांगला परीणाम दिसून झाला.

**उपक्रमाबाबत विद्यार्थी शिक्षकांची मते.**

१. या उपक्रमामुळे मुलींना भाषा विषयाची गोडी निर्माण झाली.
२. या उपक्रमामुळे मुलींना इतिहासाची आवड निर्माण झाली.
३. विज्ञानाच्या शोधांची व त्याविषयाच्या माहिती जाणून घेण्याची ओढ निर्माण झाली.

**उपक्रमाबाबत शिक्षकांची मते:-**

१. या उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळी पाठ्यपुस्तके हातळण्यास सुरुवात केली.
२. आपल्या विषयाव्यतिरीक्त इतर विषयही आवडीने वाचनास घेवू लागले.

**संदर्भ सूची:-**

- कऱ्हाडे बी.एम. (२००७), शैक्षणिक संशोधन पद्धती नागपूर पिंपळासुरे प्रकाशन,  
करंदीकर सु.(२००५) कृती संशोधन, पुणे, फडके प्रकाशन.  
भिताडे वि.रा. (२००७) शैक्षणिक संशोधन पद्धती, पुणे, नितयनूतन प्रकाशन.  
(इं) लि.मुळे रा.श. उमाठे वि.तु. (१९८७), शैक्षणिक संशोधनाची मुलतत्वे नागपूर, महाविद्यालय  
विद्यापीठीय ग्रंथनिर्मिती मंडळ कृती संशोधन प्रशिक्षण हस्त पुस्तिका  
डॉ. चा.प. कदम, (२००७) शैक्षणिक संख्याशास्त्र पुणे, मिलिंद जोगळेकर प्रकाशन.

## Professional Development Programme: Developing Coping Skills in Adolescents

**Dr. Rashmi Singh**

Assistant Professor

Department of Education,

Maharana Pratap Govt. P.G. College,

Hardoi (U.P)

### Abstract

*Teacher is the agent of social change and the torch bearer of the society. Unless and until teachers are not well trained, we can not even think about any remarkable and desired change in society. India is a young country because our major portion of Indian population belongs to young force, i.e. adolescents. But they are symbolized and declared to be aggressive, undisciplined and antisocial. In simple words a destructive class of our country. Therefore, it's quite obvious that these adolescents are the most focused target of teachers and their fraternity. The reason may one vital and acceptable fact that these enormous numbers, so called 'adolescent's work force' - full of zeal, can be utilized in bringing some positive social changes in society rather than taking them and their strength as a mark of nuisance and destruction.*

*Adolescent's underachievement, despair about their future, eating disorders, alcoholism, drug abuses, bullying, vandalism and other forms of irresponsible and antisocial behavior are at their peak because adolescents failed to cope-up with their stressors. However, it is possible to develop coping skills in adolescents which will definitely going to help them in becoming competent and to take better decisions about 'how to react in stressful conditions' or in the case of adversity. Professional Development Programme for teachers must include components of delivering coping skills to their students so that adolescents can cope-up in a healthy manner rather getting panicky and to react adversely. It is also a high time to include 'emotional-management' in the core curriculum of adolescents. 'Emotional-management' will work as aid in reducing the trend of giving up or committing suicide among adolescents. They do so just because of getting over sentimental, for an instance on being failed to come up with the results as per the expectations results in emotive outbursts.*

*The present paper is covering a toolkit of positive coping skills for adolescents. By receiving the knowledge of coping, adolescents will be able to have remedies and the ways of tackling with problematic situations and finally turning odd into positive outcomes. Coping is of great importance in enhancing and grooming adolescents in making better nation and society.*

**Key Words:** Adolescents, Social Change, Stress, Emotional Management Coping Skills.

### Social Change Results in Changing World of Teaching:

The whole world has witnessed a rapid social change in the past few decades. Values are changing rapidly, old values are deteriorating very fast and new values are struggling for their existence. This is resulting in a state of confusion and chaos among all. Hence the present social environment in which teachers are working and the roles demanded from them by the society is getting complex day by day. This is due to rapidity in social change. Teachers are in constant need of developing new techniques for equipping their students, especially adolescents with a wide range of skills. In this light, teaching adolescents is one of the most demanding jobs. All this, hastens the need for development of more competence centered approach to teaching. In other words, time barred professional development programme for teachers, in general and for adolescents' teachers, in particular is the need of an hour.

### Professional Development Programme:

Professional development plays a vital role in career building of any profession and undoubtedly it possesses equal importance for the career of teachers and academicians. It not only develop all-round personality in teachers but also add ethics and values in their profession. It is always presumed that teaching contents, techniques and methods are always to be reloaded and uploaded with recent substances & procedures. Professional development is about life- long learning and growing as an educator. An adolescent's teacher must be keen always to be progressive and also refine his or her skill because he or she is going to face young minds. In simple words, teacher should make himself / herself competent enough to face an innovative class of minds. These innovative minds i.e. adolescents are very updated into new technology, fashion, music, taste, vocabulary and many other things. Teachers should load themselves with all such subjects.

To equip the teaching body with the skills and the competences needed for its new roles, it is necessary to have both, in-service or pre-service quality professional development programme. It will certainly keep teachers up to date with the skills required in today's knowledge based society. Basic objective of the programme is to develop new techniques among teachers along with the skills to tackle with contemporary issues prevailing in academics and society as well.

### Adolescents are in crisis:

Adolescence can be a particularly awkward stage for anyone. But now- a- days adolescents face new pressures as a result of advances in technology and easier access to the media. With a decrease in protective factors including demise in family and community relationships and an increase in several risk factors, made contemporary society an increasingly more dangerous place for adolescents (Le Croy & Dailey, 2001).

Here several factors are enlisted which has contributed to adolescents' stress-

- The breakdown of traditional family structure
- Impact of globalization
- Various pressures on the family unit, affecting the emotional and financial security of family members
- Pressure on adolescents to succeed and need for them to meet higher qualification requirements in order to get jobs
- The projection of violence into our lives, particularly through the media
- The greater emphasis on image and beauty, increases the stress on our adolescents to be accepted
- Decline of religions institutions as source of moral and communal support for human beings

These alone or in combination put demands on school to play a more active role in nurturing the socio- emotional development of adolescents. One thing which has to keep in mind for adolescents' teachers is that adolescents have been socialized into different gender roles, with greater emphasis being placed on autonomy and independence for boys and social connection for females( Gilligan, 1982). Female adolescents are affected by societal ideology in different ways when compared to their males-counterparts. Hence girls need gender specific education because there are unique tasks that adolescent girls must master in order to successful transition to adulthood. So schools should meet these adaptation needs of adolescents in better preparation for their future lives.

### Need of Coping Skills for Adolescents:

Nowadays adolescents and stress become synonymous. Stress is the individual's adaptation response to any demand or pressure. These demands or pressure are called stressors. A stressor is an event, while coping is what one does as a result of the stressor. Coping can be proved as a panacea for

many problems of our adolescents. The most frequently cited definition of coping is “the cognitive and behavioural efforts to manage specific external or internal demands (and conflicts between them) that are appraised as taxing or exceeding the resources of a person (**Lazarus, 1991**). From working with adolescents, **Frydenberg & Lewis** have defined coping (as) a set of cognitive and affective actions which arise in response to a particular concern.

It is possible to teach coping skills to adolescents that will help them make better decisions about how to react to stress when they face adversity. If an adolescent’s coping skills can be improved, it is feasible that he or she may perceive and react to stressors in a different manner, yielding more positive health outcomes.

### **Coping skills:**

It is better to talk about types of coping in advance to coping skills. The most common typology of coping style (**Lazarus and Folkman, 1994**) includes problem focused coping and emotion focused coping. These two factors are sometimes complemented by a third factor appraisal focused coping.

Appraisal focused coping occur when the person modifies the way they think. For example employing denial or distancing oneself from the problem. Adolescents using problem focused strategies try to deal with the cause of the problem. Appraisal focused coping is aimed at changing or eliminating the source of the stress. Emotion focused strategies involve releasing pent-up emotions. Emotion focused coping is oriented towards managing the emotion that accompany the perception of stress.

### **Developing Coping Skills:**

Learning to cope effectively with stress would be certainly helped our adolescents to better prepared to overcome life’s challenges. Positive coping lessons include-

1. Modeling of positive coping strategies on a consistent basis. It is duty of a teacher to introduce contemporary techniques of coping in order to make adolescents competent.
2. Guiding adolescents to develop positive and effective coping strategies. After introducing coping strategies teachers should make adolescents to understand them in a better way so that they can make a logical and positive use.
3. Support involvement in sports or other pro-social activities. Interacting with others is a good way to learn that they are not alone in what they are experiencing. That knowledge is comforting, physical activity is also a good reliever of some forms of stress.
4. Positive social interaction with peers. Generally a common problem prevails among adolescents. With the better understanding of coping strategies they can even assist others.
5. Creative expression: Adolescent is generally misinterpreted as the stage of stress and storm instead of the fact that it is the stage of creativity. So adolescents should realize the fact and make proper use of their strength by expressing and highlighting the creative part before the world.
6. Social and emotional competence and achievement: Nowadays emotions overrule emotional intelligence. Therefore adolescents to bring themselves in a balanced status by handling their emotions intelligently and to avoid outburst.
7. Opportunities for self definition: Every individual is bestowed with a unique feature or quality. This universal fact is generally unknown to our adolescents. So teachers should make them realize about their hidden talent or so called uniqueness.
8. Help them to develop social skills: As it’s a known fact that societal ideology have its effects more on adolescents therefore teachers should make their adolescent group to understand the reality and become socially skilled.



9. Suggest ways of coping in difficult situations. After introducing and developing different coping strategies, teachers should also assist adolescents for making them understand that when and how to make application of strategies.
10. Help them identify their problem, come up with possible solutions and evaluate pros and cons of each.
11. Help them develop ways to see problems and situations in a different light. Get them to see the positive side of things
12. Help them learn and practice skills that will allow them to participate in and enjoy new activities. In order to make adolescents participative it is important to make them realize first that they are the upcoming force of society.
13. Help them learn relaxation exercises (abdominal breathing, muscle relaxation techniques, meditation, Yoga etc.)
14. Help them develop a positive attitude. It's not only that after knowing and understanding coping strategies every problem can be tackled. It is mindset of a person which makes him competent to handle odd conditions. It is the positive attitude which will develop in adolescents so called competency.
15. To set a good example: Demonstrate self control and coping skills.
16. Help them learn to appraise situations more accurately.
17. Build a relationship so that adolescents will feel comfortable coming to you, when he or she needs help.

### Conclusion:

The aforesaid discussion can be concluded by stating that knowledge of coping skills is must for teachers in general and for teachers of adolescents in particular. Hence professional development programme, meant for adolescent's teachers have to have components of coping skills, so that they become fully aware and knowledgeable about these skills. Only then they can develop these skills into their mindset and make adolescents to get ready for coping with adverse conditions. It is always contended that coping strategies are proved to be the best tool for adolescents in overcoming their stress.

### References:

1. Frydenberg & Erica (1997), '*Adolescent Coping*'. London: Routledge
2. Gilligan, C. (1982), '*In a Different Voice*'. Cambridge, MA: Harvard University Press
3. Lazarus, R.S. & Folkman, S. (1994), '*Stress, Appraisal and Coping*'. New York: Springer
4. Le Croy, & Dailey (2001), '*Empowering Adolescent Girls: Examining the present and building skills for the future with the go girls program*'. New York: Norton Publishers.

## बीड जिल्ह्यातील जि.प.प्रा. शाळेत शैक्षणिक तंत्रज्ञानच्या साधनांची उपलब्धता एक अभ्यास

संशोधक

मार्गदर्शक

गित्ते त्रिंबक गोंविद

डॉ.अंधारे एस.जी

प्रस्तावना :

विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास शिक्षनाणे होतो. अध्ययन अध्यापक प्रक्रिया प्रभावी करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. आज शाळांना शासनातर्फे विविध साधने पुरवली जात आहेत. काही शाळा लोक सहभागातून साधनांची उपलब्धता करीत आहेत. संगणक व इंटरनेटमुळे शिक्षक व विद्यार्थ्यांना ज्ञानाची नवी कवाडे उघडी झाली आहेत. माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे शिक्षक विद्यार्थी पुस्तकी ज्ञानाच्या पलीकडे जाऊन विषयाशी संबंधित नवनवी माहिती मिळत आहे. आधुनिक शिक्षण पद्धती ही विद्यार्थी केंद्रीत बनत आहे. त्यासाठी नवनवीन साधनांचा वापर अनिवार्य ठरत आहे. जि.प.प्रा शाळेत देखील उपक्रमशील शिक्षक नवनवीन तंत्रज्ञान वापरत आहेत.

संशोधनाची उद्दिष्टे

1. जि.प. शाळेतील तंत्रज्ञान विषयक साधनांची सद्य स्थितीपाहणे.
2. तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षणप्रक्रियेचा अभ्यास करणे.
3. जि.प.शाळेत तंत्रज्ञानवापरातील अडचणींचा शोध घेणे.
4. जि.प. शाळेत तंत्रज्ञान वापरातील अडचणीवर उपाय सुचवणे.

संशोधनाची गरज

माहिती संप्रेषणतंत्रज्ञानाच्या साधनामुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर काय परिणाम होतो, तंत्रज्ञान वापरल्यामुळे शिक्षण प्रक्रिया कशी प्रभावित होते, जि.प.शाळेत कोणकोणती साधने उपलब्ध आहेत. साधनांच्यावापरात कोणत्या अडचणी निर्माण होतात. आणि त्याकशा दूर करता येतील अशा अनेक प्रश्नांच्या उत्तरासाठी प्रस्तुतविषयावर संशोधन करणे गरजेचे आहे.

संशोधनाचे महत्व :

प्रस्तुत संशोधनामुळे जि.प. शाळेतील माहिती तंत्रज्ञान साधनांची उपलब्धतेची माहिती मिळेल. शिक्षकांनी शाळेतकेलेल्या नवनवीन प्रयोगा पासून इतर शिक्षकांना प्रोत्साहन मिळेल संशोधनामुळे तंत्रज्ञान वापरातील अडचणी समजतील व त्यांवरउपाय शोधता येतील.

संशोधन पध्दती :

प्रस्तुत संशोधनासाठी सर्वेक्षण संशोधन पध्दतीचा वापर केलेला आहे.

संशोधनन्यादर्श :

प्रस्तुत संशोधनासाठी बीड जिल्हयांतील आठतालुक्यांतील 16 शाळा संशोधन न्यादर्श म्हणून घेतलेल्या आहेत.

संशोधनसाधन :

प्रस्तुत संशोधनासाठी मुलाखत व निरीक्षण या साधनांचा वापरकेलेला आहे.

संशोधन निष्कर्ष :

1. बहुतांश शाळांमध्ये रेडिओ टेलिव्हिजन टेपरेकॉर्डर उपलब्ध आहे. तर काही शाळांमध्ये टॅबलेट संगणक आहेत.
2. जि.प शाळांमध्ये पीपीटीच्या साहाय्याने घेतले जातात.
3. विद्यार्थी स्वतः संगणक, टॅबलेट प्रोजेक्टरच्या साहाय्याने शिकतात.



4. शाळांमध्ये शिक्षणाला पुरकअसे कार्यक्रम प्रक्षेपित केले जातात.
5. विद्यार्थ्यांना इंटरनेटच्या माध्यमातून अदयायवत माहिती पुरवली जाते.
6. ग्रामीण भागात इमारत, लाईटबाबत अडचणी निर्माण होतात.
7. पालक शिक्षकांना साहकार्य करत नाहीत.
8. शाळांना सर्व तंत्रज्ञान विषयक साधने मिळत नाहीत.
9. वाहीशिक्षक तंत्रज्ञान वापरा विषयी निरनसाठी आहेत.
10. जि.प. शाळेतील समस्यांकडे शासनाने अधिकाऱ्यांनी विशेष लक्ष देवुन तंत्रज्ञान विषयक समस्या सोडवल्या पाहिजेत.

संदर्भग्रंथसूची :

1. मुळे रा.श आणि उमाटे बि.तु (1998) शैक्षणिक संशोधनाची मूलतत्वे (तीसरी आवृत्ती)नागपुर : महाराष्ट्र विद्यापीठग्रंथनिर्मित मंडळ पुणे.
2. पंडीत ब.बी (1989) संशोधन अभिकल्प, नुतन प्रकाशन पुणे.
3. भिंताडे व्हि.आर (2006) शैक्षणिक संशोधनपद्धती पुणे.
4. गाजरे आर.व्हि चिटणीस एस.पाटील एन (2006) शिक्षकांचे अधिष्ठान पुणे. : नित्य नुतनप्रकाशन
- 5- जोशीबी.आर (2007) शिक्षण शास्त्र

## Quality Function Deployment Implementation for Characteristics Identification to Prevent Sand Inclusion Defect in Cast Iron Castings

V. S. Deshmukh, Research Scholar, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University,  
Aurangabad.

Dr. S. S. Sarada, Research Guide, G.P. Jalna.

### Abstract

*Cast Iron (C. I.) castings are very widely used in all fields for wide range of applications because of their inherent characteristics like vibration damping, self lubrication, ease of manufacturing of complicated shapes etc. Sand Inclusion (S. I.) is most commonly found defect in C. I. Castings and reduces the efficiency and productivity of the casting process. Efforts are made in this paper to decide the characteristics of Quality Function Deployment technique to be controlled, by finding their Characteristic Agreement Levels, for prevention of S. I. defect.*

**Keywords:** Quality Function Deployment, Castings, Cast Iron, Sand Inclusion, Characteristic Agreement Level

### 1. Introduction

Quality Function Deployment (QFD) is a tool developed for a product, whether old or new, so as to get maximum customer satisfaction. QFD when applied to new product development identifies the levels of design requirement fulfilments by controlling product characteristics. A House of Quality is a matrix developed in QFD which gives the relationships between customer desires and design characteristics. Its aim is customer satisfaction and transforms the customer requirements in the form of manufacturing planning instructions by using customer's requirements as an input and by building 4 houses of quality. The customer satisfaction is achieved by following these instructions during product manufacture.

A casting is an object made by solidification of molten metal in a mould, the configuration of the mould is decided by the shape and size of casting to be made. Usually the rejection percentage of the castings is 2 to 5% which sometimes goes as high as 10 to 25% of the number of the castings produced, which is a heavy loss to the foundries. One of the major reasons of rejection is sand inclusion (S. I.) defect.

Characteristic Agreement Level calculation method is used to identify characteristics of QFD for implementation with an objective to prevent S. I. defect in C. I. Castings. Survey method is used for collection of data from 206 foundries all over India on various characteristics of QFD and analysis is carried out for this purpose.

### 2. Quality Function Deployment

QFD uses customer desires as an input and helps the organization to gain focus on customer with the help of planning. Shorter product design and manufacture times, higher quality and reduced costs are the benefits of implementation of QFD. New product design and success of QFD both depend on identifying the customer requirements correctly and translating them into technical requirements (Eureka, 1989).

The transition of the limited capital resources into maximum competitive advantage is done by the development of large number of new technologies. It is important for the organisations to do appropriate selection of the technology based on its economic evaluation which requires considerable time and effort. A tool which allows a rapid evaluation of the feasibility of using process to manufacture products is developed from the techniques of QFD. This tool uses the relevant QFD techniques (Lowe et al., 2000).

A customer-oriented design tool used in developing a new or improved product to increase customer satisfaction is called QFD. It is done with the help of cross-functional team members who reach to a consensus in developing a new or improved product. QFD starts with a planning matrix, the house of quality (HOQ), which translates the customer needs into measurable product technical requirements (PTRs). The interrelationships between customer needs and PTRs need a robust evaluation method for determining the importance levels of PTRs in the HOQ (Karsak et al., 2003).

In the fast-paced and lean economy, the QFD tools application expertise and principles become critical with the manufacturing chain mainly i) Lean manufacturing which does not allow waste ii) Rapid organisational redesign which should get adapted to the customer needs. (Cruz-Ruiz et al., 2003)

In 1972, the QFD originated in a Japanese shipbuilding firm and Japanese academic world first codified it. The Toyota group adopted it in the early 1980's and the US auto industry followed it by mid 1980's. The QFD is defined as a 'customer driven planning process for production services'. A cross functional team approach for product development is adopted in QFD. Customers are the main focus in a competitive market to increase its size for the development of products/services (Pravin Kumar, 2008).

During the early stages of product/process development, it becomes important to know customer needs properly to distinguish oneself from the competitors. The proper utilisation of QFD is done for better creativity and lean in case-study of TRW Automotive by focusing the design efforts. QFD helped in inculcating thinking about the requirements and its implementation into the final product (Johnson et al., 2008).

In global competitive high-tech industries, the keys to survival and success for firms are technological innovation and satisfaction of customer needs. The development of new products and their success is important for keeping a competitive edge, increase in the sales and to make reasonable profit in a long run. Thus, an important task in front of the manufacturers is how to satisfy customers, by developing and delivering products that customers demand and generate profit. So, a two phased framework is prepared for selecting engineering characteristics (EC) for product design. Quality function deployment (QFD) is used in the first phase to calculate the priorities of ECs. Due consideration is given to the interrelationship among characteristics as well as the imprecise and vague judgments and information of human beings (Lee et al., 2010).

### **3. Characteristics needed to be focused for Successful Implementation of QFD**

The following characteristics are listed for their selection by the respondents on five point scale for their opinion about successful implementation of QFD with respect to C. I. castings for S. I. defect prevention.



- Market survey is essential.
- Full information of customer requirements is required.
- Full understanding of customer requirements is essential.
- Priority decision amongst different customer requirements is to be done.
- Implementation of QFD for manufacturing the casting is important.
- Customer complaints data preservation is required for its use in S. I. defect prevention.

#### 4. Training and Budget Allocation for QFD

The arrangements to be done while executing training on QFD for S. I. defect prevention-

- Training cost expenditure is to be borne by the supplier / ancillary alone.
- Training cost expenditure is to be shared by the customer.

#### 5. Characteristic Agreement Level

Characteristic agreement level (CAL) indicates the priority to be given for the implementation of the characteristics (Shivgaje et al., 2005). Number 1 indicates the top priority and so on. CALs for QFD for C. I. foundries are calculated as given in the Table no. 1 and for training cost in Table no. 2 below.

**Table No. 1**  
**Characteristic Agreement Levels for Quality Function Deployment**

Sr.No.	Characteristic	Agreement Level	Priority
1	Market survey essential	0.161	5
2	Fully informed customer requirements	0.167	3
3	Fully understood customer requirements	0.174	2
4	Necessity to decide the priority amongst different customer requirements by the foundry	0.152	6
5	Implementation of QFD for casting manufacturing essential	0.162	4
6	Preservation of the customer complaints data essential	0.183	1

**Table No. 2**  
**QFD Training Cost for the S. I. Defect Prevention**

Sr. No.	Characteristic	Agreement Level	Priority
1	Training cost borne by the supplier/ancillary	0.832	1
2	Training cost shared by the customer	0.168	2

#### Conclusion

CAL analysis resulted in giving top priority to the characteristic 'preservation of the customer complaints data essential', followed by 'full understanding of customer requirements' and 'fully informed customer requirements' by the respondents from foundries. Implementation of these characteristics like preserving the customer complaints data, fully understanding the customer requirements and having full information of customer requirements in documented form before starting the production of C. I. Castings, will help in tremendous improvement in quality and prevention of S. I. Defect. The foundry respondents also selected 'training cost is to be borne by the supplier/ancillary alone' as the first choice and 'training cost is to be shared by the customer' as the second choice. It indicates that the foundries alone have to work towards quality improvement through training their workforce without any help from their customers.

### References

1. Eureka Bill, Quality Function Deployment, Quality Today, May 1989, pp. 33-35.
2. Antony Lowe, Keith Ridgway, Helen Atkinson, QFD in new production technology evaluation, International Journal of Production Economics, Volume 67, Issue 2, 2000, pp. 103-112.
3. E. Ertugrul Karsak, [Sevin Sozer](#), [S. Emre Alptekin](#), "Product planning in quality function deployment using a combined analytic network process and goal programming approach", Computers and Industrial Engineering, Pergamon Press, NY, USA, Volume 44 Issue 1, January 2003, Pages 171-190.
4. Cruz-Ruiz Javier Santa, QFD application for tackling Internal Customers Needs as a base for building a Lean Manufacturing System, Lean Manufacturing 2003, 9th International Symposium on QFD, Dec. 2003, Orlando FL USA.
5. Pravin Kumar, "Using Fuzzy Quality Function Deployment for design optimisation" Industrial Engineering journal, Sept.2008, pp 2-8.
6. Johnson Chad, Mazur Glenn, Value based product development- Using QFD and AHP to identify, prioritize and align key customer needs and business goals, The 20th Symposium on 'QFD' (ISBN 1-889477- 20-6), Oct 24, 2008, Santa Fe New Mexico USA.
7. [Amy H. I. Lee](#), [He-Yau Kang](#), [Cheng-Yan Yang](#) & [Chun-Yu Lin](#), An evaluation framework for product planning using FANP, QFD and multi-choice goal programming, International Journal of Production Research, Volume 48, Issue 13, 2010, pp. 3977-3997.
8. Shivgaje A.J., Kasture M.S., Yadav D.B., Patole S.S., Use of Technology adoption Index in Agriculture, 7<sup>th</sup> Agricultural Science Congress, Pune, 16-18 Feb. 2005, pp. 25 - 30.

परंपरागत समाजाभिमुख पर्यावरण पुरक बांबू व्यवसाय

डॉ. एस. एस. कावळे

प्राचार्य तथा अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख  
श्री. गोविंदप्रभु कला व वाणिज्य महा.  
तळोधी (बाळापूर) ता. नागभीड  
जि. चंद्रपूर

प्रस्तावना :

भारत हा असा देश आहे की, विविधतेने नटलेला मानव समाज यात दिसून येतो. जगातील फारच कमी देशात असा मानव समाज दिसतो. सुमारे दहा लाख वर्षांपूर्वी पृथ्वीवर मानवाची निर्मिती झाली. असे जीवशास्त्र मानतात. तेव्हापासूनच मानव आपल्या विविध गरजा भागविण्यासाठी निसर्ग संपत्तीचा (वनसंपत्तीचा) वापर करतात. आपल्या बुद्धीचा वापर करून हयापासून स्वतःच्या उपजिविकेसाठी विविध वस्तू आणि साहित्य निर्माण केलीत. नंतर संस्कृती ही रितीरिवाज यातून विकसीत होत गेली. प्रत्येक मानव समाजाच्या स्वभावानुरूप संस्कृतीमध्ये काही समानता आणि काही भेद दिसतात. आपल्या देशात समाजाची मुळ रचना जातीय पद्धतीवर आधारलेली आहे. जात ही माणसाच्या सामाजिक, राजकीय व आर्थिक जीवनावर आजही नियंत्रण ठेवते. मनुष्याची किंमत किंवा श्रेष्ठत्व हे दैनंदिन व्यवहारात जसे गुणावर व कृतीवर अवलंबून असते तसेच ते जातीवर व जन्मावर अवलंबून असते.

भारतात अनेक प्रांत, अनेक भाषा, अनेक संस्कृती आहेत. त्यात अनेक जाती धर्मही आहेत. प्राचीन काळापासून बुरड ही जमात अस्तित्वात आली आहे. कारण की, हिंदु समाजाची रचना ही कामाची विभागणी विचारात घेवून केलेली आहे. उदा. कुंभार, लोहार, सुतार, न्हावी, शिंपी, सोनार इत्यादी वेगवेगळ्या जाती निर्माण झाल्या. मातीची मडकी बनविणारा कुंभार, लोखंडाचे काम करणारा लोहार, लाकडी वस्तू बनविणारा सुतार, हजाम करणारा न्हावी, कपडे तयार करणारा शिंपी, सोन्याचे काम करणारा सोनार हे व्यवसायीक नावे आहेत. समाजातील सर्व स्तरातील लोकांच्या दैनंदिन जीवनात उपयोगी पडणाऱ्या बांबूपासून विविध वस्तू तयार करतो तो 'बुरड'.

माणूस जेव्हा भ्रमंतीचे जीवन संपवून एका ठिकाणी स्थिर होतो. तेव्हापासून त्याच्या जीवनात कारागिरीचा प्रवेश होतो. व्यवहारिक उपयुक्तता आणि आर्थिक उपासना अशा दोन अंगांनी मानवी जीवनात कला—कौशल्याची वाढ होते. निवारा मिळविण्यासाठी घर बांधावयाचे पण तेवढ्यावरच संतुष्ट न राहात आपले घर शोभिवंत बनवावे. त्यात नवी—नवी उपकरणे निर्माण करावी त्यादृष्टीने मग तो कल्पना लढवू लागतो. समाजाच्या विकास क्रमात विविध व्यवसाय निर्माण होतात आणि त्यातही कला—कौशल्याला वाव मिळतो. धार्मिक कर्मकांड आणि देवतांच्या उपासना यातही विविध उपकरणांची गरज असते. त्यामुळे त्या अंगानेही समाजात कला—कौशल्याची वाढ होवू लागते. अशाप्रकारे कला—कौशल्य हे मानवी संस्कृतीचे एक महत्वाचे अंग बनते. किंबहुना एखादा मानव समाज ज्या प्रमाणात सुंदर व उपयुक्त अशा कारागिरीच्या विविध वस्तू निर्माण करतो त्या प्रमाणात त्यांच्या संस्कृतीचे मुल्यामापन होत असते. हयाच आधारावर भारतात बांबूपासून फार प्राचीन काळापासून विविध कलाकुसरीच्या वस्तू बनविल्या जातात. बायकांचे दागिने ठेवण्याचे व कुंकवाचे करंडे पूर्वी बांबूचे असत बांबूच्या वस्तू आजही घोघरी दृष्टीस पडतात. मुलांच्या खेळातही असल्या वस्तू असतात. बांबूचे तट्टे कुढासारखे उभे करून झोपडीची भिंत तयार करण्याची पद्धत फार प्राचीन आहे. अलीकडे

हया तट्टयावर विशिष्ट द्रव्य लावून त्यापासून प्लॉय बनवितात. वारा घालण्यासाठी लहान—मोठी पंखे आणि त्यावर भरतकाम, नक्षीकामही करतात.

भरतीय संस्कृती ही फार प्राचीन संस्कृती असून एक विशिष्ट असा वारसा असलेली संस्कृती आहे. परंपरेनुसार यात विविध वस्तुला फार धार्मिक महत्व आहे. परंपरेनुसार बांबूच्या विविध वस्तू वापरल्या जातात. अगदी जन्मापासून तर मृत्यूचा शेवटचा विधी पार पाडण्यासाठी सुद्धा बांबूच्या विविध वस्तू वापरूनच तो काम पूर्ण केला जातो. ज्यावेळी मुलाचा जन्म होतो त्यावेळी त्याला सुपात ठेवतात. तसेच ज्यावेळी ब्राम्हणास जे दान दिले जाते त्याकरीताही सुपाचा वापर केला जातो. तर मनुष्य मरण पावल्यानंतर त्याचा जो अंतिम विधी केला जातो त्यावेळी सुद्धा त्याला बांबूपासूनच तयार केलेल्या शिडीवर झोपवून नेल्या जाते. त्यावेळी त्याच्यासोबत जे विशिष्ट धान्य नेल्या जाते व त्याची शिदोरी म्हणून ज्या पेटलेल्या गोवऱ्या एका नवीन भांड्यात भरून नेतात ते नेतांना बांबूच्या कांभी काढून त्याची एक तिडकी तयार केली जाते व त्यावर मांडून नेली जाते ही एक फार प्राचीन भारतीय परंपरा आहे. त्याचा वापर आजही केला जातो.

कोठेही यात्रेला जात असतांना त्यांचा ध्वज बांबूच्या काठीला लावला जातो. कारण पुराणकथेत बांबूला शंकराची काठी असे म्हटले आहे आणि म्हणून त्याकाठीवरच ध्वज लावला जावा ही परंपरा आजही कायम आहे. बांबूच्या झाडाचे देवादिकापासून ते मानवजातीपर्यंत धार्मिक दृष्टीकोनातून महत्व दिलेले आहे व ते पुजनिय आहे. जसे तुळशीच्या झाडाला देवादिकांनी, साधुसंतांनी जपितपी, ऋषीमुनी यांनी जेवढे महत्वाचे स्थान दिले आहे. जसे असे मानतात की, तुळशीच्या झाडाखाली श्रीकृष्ण राहातो तसेच बांबूच्या झाडाखाली शंकर राहतो आणि म्हणून तो पुजनिय आहे आणि म्हणूनच बांबू आणि बांबूपासून तयार केलेल्या विविध वस्तू फार उपयोगी आणि त्यांना धार्मिक महत्व देण्यात आले आहे.

**बांबूच्या काही वस्तू व त्यांचे धार्मिक महत्व पुढीलप्रमाणे :-**

१) **बांबूची ढाल :-** आदिवासी समाजात आजही अशी पध्दती रूढ आहे की, बांबूपासून ढाली बनवितात आणि त्यांच्या कुळातील कोणी व्यक्ती मरण पावला तर त्याच्या नावाने ती ढाल कुलदैवत म्हणून पुजतात त्या समाजातील हा एक फार महत्वाचा धार्मिक विधी असतो.

२) **बांबूच्या झाडावरील ताडवा (फळ) :-** बांबूच्या झाडावर ताडवा (फळ) असतो तो इतका पवित्र असतो की ताडवा (फळ) ज्याच्या नशिवात असेल त्यालाच मिळतो आणि तोच त्याला खाऊ शकतो. तो खाल्ला की, बांबूच्याच काठीने मारल्याने जेव्हा त्याचे रक्ती निघते तेव्हाच तो मरतो. इतर कोणत्याही वस्तुने मारले तरी तो मरत नाही. ही एक फार मोठी धार्मिक समजूत आहे.

३) **कावळ :-** पाण्याची घागरी अथवा एखादा जड पदार्थ नेण्यासाठी दोन टोकांना शिवऱ्याचे रचनेप्रमाणे दोन्ही बांधून तयार केलेले एक साधन म्हणजे कावड होय. कावडीला धार्मिक महत्त्वही आहे. पूर्वी यात्रेकरू काशिच्या गंची कावड भरून ती रामेश्वरला वाहण्याकरीता पायी यात्रा करीत होते. कित्येक धार्मिक संप्रदायातील लोक आले देव कावडीत घालून गावेगाव हिंडवितात. दक्षिणेत सुब्रम्हण्याच उत्सवात त्यांचे भक्त कावडी खांदयावर घेवून नाचतात. श्रावणकुमाराने आपल्या वृद्ध व अंध मातापित्यांना कावडीत घालून तिर्थयात्रेला नेले होते अशी कथा आहे. चैत्र महिन्यात गोदावरीचे पाणी आणून आपल्या गावातल्या ग्राम देवतेला त्या पाण्याने स्नान घालण्याची प्रथा पैठणच्या आसपास आहे. पेशवाईत काशीहून व हिरद्वार येथून गंगोदकाच्या कावडी पुण्याला आणून त्या रामेश्वरापर्यंत नेण्याचा धंदा काही लोक करीत असत.

४) **बासरी :-** फार प्राचीन काळापासून बांबूपासून बासरी बनविण्याची परंपरा अस्तित्वात आहे. भारतीय संगीत परंपरेत बासरीला फार महत्वाचे स्थान आहे. अगदी कृष्णलीला सुद्धा बासरीतून

दिसतात. बासरी ही पोकळ बांबूपासून बनविली जाते. बासरीचे दोन प्रकार आहेत. एक आडवी व दुसरा सरळ बासरी. ६ ते ८ छिद्र पाडून बासरी बनविण्यात येते.

५) परडी :- फार प्राचीन काळापासून परीचा वापर भारतात केला जातो. परडीसुद्धा बांबूपासूनच बनवितात. लग्नप्रसंगी बांबूपासून तयार केलेल्या दोन लहान व दोन मोठ्या परड्या वापरल्या जातात. मोठ्या परड्यांचा वापर वधु-वरांची नविन कपडे परड्यात घेवून तो पडल्यास त्याचे जीवन भरभराटीने वाढते अशी समजूत आहे. हा एक धार्मिक विधी म्हणूनही लग्नप्रसंगी पार पाडला जातो. तसेच लहान परड्यांचा वापर पुजेकरीता केला जातो. काजळतील, तिळसंक्रांत, गौरी, जन्माष्टमी, चतुर्थी इत्यादी प्रसंगी बांबूपासून तयार केलेल्या परड्यांचा वापर केला जातो. धार्मिकदृष्ट्या त्या अत्यंत महत्वाच्या मानल्या जातात.

बांबूच्या वस्तूंची समाजाला विविध उपयोगासाठी आवश्यकता व त्याद्वारे अवलंबून असणाऱ्या विविध व्यवसायिकांना त्यांचा उपयोग.

उपभोगातून उत्पादनाची प्रक्रिया सुरू होते. हे अर्थशास्त्राचे मुख्य तंत्र आहे. वस्तुची आवश्यकता असल्याशिवाय ती वस्तू निर्माण केल्या जात नाही. याला बांबूच्या वस्तू अपवाद नाहीत. फार प्राचीन काळापासून म्हणजेच अगदी संस्कृतीच्या सुरुवातीच्या विकासाच्या अवस्थेपासून बांबूच्या वस्तूचा वापर केल्या जातो. अगदी जन्मापासून तर मृत्युपर्यंत मानवाच्या अंतिम विधीपर्यंत बांबूच्या वस्तूंचे मानवी जीवनात महत्त्व आहे. सामुहिक विचार करता बांबूच्या वस्तू समाजाच्या विविध उपयोगी आहेत.

अनेक व्यवसायात बांबू उपयुक्त ठरतो. खाणकाम असो की मग बांधकाम असो त्यात बांबूपासून तयार केलेल्या वस्तूचा वापर फार मोठ्या प्रमाणात केला जातो. उदा. बिडी उद्योगाला बिड्यांचे पॉकेट ठेवण्यासाठी पेठारे, फळ व्यवसायाला पेठोर, कुक्कुटपालन उद्योगाला कोंबड्या ठेवण्यासाठी बेंडवे, धान्य साठवणूकीसाठी ढोल्या, मंडप डेकोरेशनसाठी बांबूच्या चट्या, बांधकाम व्यवसायाला टोपल्या व बांबूच्या लांब चट्या, खाणकाम व्यवसायासाठी टोपल्या, गृहसजावट उद्योगासाठी आधुनिक कलाकुसरीच्या बांबूच्या विविध वस्तू यामुळे विभिन्न उद्योगात बांबूची उपयोगिता दिसून येते. त्यामुळे बांबू उद्योग हा इतर उद्योगांना चालना देणारा उद्योग होय. कागद कारखाण्यासाठी बांबूचा फार मोठ्या प्रमाणात उपयोग केल्या जातो. तसेच दोरखंड तयार करण्यासाठी दोऱ्या व्यवस्थित ठेवण्यासाठी घोडी तयार केली जाते. या घोडीचा उपयोग तागाला गुंडाळण्यासाठी केला जातो की ज्यापासून दोर, दोरखंड, गुरांसाठी दावे तयार केली जातात. शेकड्यांचे धुरे, रेंगिचा चाप, पूर्वी पाटकांबिची चटई विणून खोलीच्या विभागणीकरीता त्याचा उपयोग केला जात असे. सध्या त्याजागी प्लॉयवूड काम करते. माळी आपल्या विविध प्रकारची फुले ठेवण्यासाठी टोपल्याचा उपयोग करतो. पतंग व्यावसायामध्ये बांबूचा उपयोग केला जातो. पातळ कांबी तयार करून ढिवर व्यवसायिकांना मासोळी ठेवण्यासाठी विशिष्ट प्रकारची टोपली (धुटी). शेतकऱ्यांना शेती व्यवसायासाठी बांबूच्या वस्तूंचा बराच उपयोग होतो. उदा. टोपल्या, सुपे इत्यादींचा उपयोग होतो. बांबूच्या कचऱ्यातून निर्माण केलेल्या शोभेच्या वस्तू, बांबूच्या उपडे लटकविण्याच्या खुंट्या तयार केल्या जातात.

आजच्या आधुनिक युगात इलेक्ट्रिक उपयोगामध्ये टेबल, डायनिंग टेबल, खुर्च्या बांबूच्या होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे बांबूच्या वस्तू इतर व्यवसायिकांसाठी किंवा व्यवसायासाठी उपयुक्त आढळून आल्या आहेत.

**प्लॅस्टिकला पर्याय म्हणून बांबूच्या विविध वस्तू :**

भारतीय दृष्टीकोणातून विचार केला तर बांबूच्या वस्तूची निर्मिती बांबूच्या वस्तूसाठी लागणारा कच्चा माल व उपयोग यांचा योग्य प्रकारचा समन्वय परंपरेनुसार भारतात घातल्या गेला आहे. याचे



उत्तम उदाहरण म्हणजे खेडयापाडयातून निर्माण होणाऱ्या बांबूच्या विभिन्न वस्तू होय. कच्चा माल म्हणजे बांबू खेडयात सहज उपलब्ध होतो. त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी फारच कौशल्याची गरज नसते. स्थानिक तालुका किंवा जिल्हा बाजारपेठ उपलब्ध होवून ग्रामीण स्वयंपूर्ण अर्थव्यवस्थेत महत्वाचे योगदान या बांबूच्या वस्तूमुळे खेडे समृद्ध करण्यात आले आहे. असे जुन्या इतिहासावरून दिसते.

फार प्राचीन काळापासून बांबूच्या वस्तू मानवाच्या दैनंदिन उपयोगी ठरल्या आहेत. नेहमीच्या गरजा भागविण्या बरोबरच सणावाराला आणि धार्मिक प्रसंगीसुद्धा ह्या वस्तू वापरात आनल्या जात असत. ह्या वस्तूविषयी लोकांच्या मनात वेगळा समज होता. त्या वस्तू विशिष्ट वेळी वापरल्या जाव्यात अशी रूढी होती परंतु हळुहळु फॅशनमुळे ह्या वस्तूच्या वापरावर वाईट परिणाम झाला. फॅशनचा आजचा काळ आहे आणि फॅशनच्या युगात उपयोगीता किंवा टिकावूपणा आणि किंमत यांचा विचार केला जात नाही.

परंपरेनुसार बुरड व्यवसाय फार प्राचीन काळापासून चालत आलेला व्यवसाय आहे परंतु घरोघरी वापरात येणाऱ्या प्लॅस्टिकच्या वस्तूचा वापर वाढल्यामुळे व्यवसायावर अवकळा पसरली आहे. आपण आपल्या आजच्या फॅशनमुळे व प्लॅस्टिकच्या वापरामुळे त्या आपल्या घरी दिसत नाही. शेतकरी पावसाळयात शेतीचे काम पाऊस चालु असतांना पाण्यापासून आपला बचाव करण्यासाठी बांबू पासून तयार केलेले मोरे वापरत असत त्यामुळे मुसळधार पाऊस आला तरीपण त्यांचे रक्षण होत असे. परंतु आज शेतकरी त्याऐवजी प्लॅस्टिक वापरतो. त्यापासून शेतकरी स्वतःचा पावसापासून बचाव करू शकत नाही. अशा कितीतरी ग्रामीण भागातील दैनंदिन वापराच्या वस्तू वापरातून प्लॅस्टिकमुळे मागे पडल्या आहेत. उदा. परडी, टोपली, कचरापेटी, चटई इत्यादी.

साधारणता बुरड समाजाचा व्यवसाय हा बांबूपासून टोपले, सुपे, डोले, कडे, बेंडवे, सुपल्या, चटया, मोरे आदी तयार करणे व बाजारात विकणे मात्र सरकारच्या जंगलविषयक धोरणामुळे आता बांबू मिळणे कठीण झाले असून जंगलविषयक धोरणांचा बांबू निर्मिती व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला आहे. बांबूची अवास्तव किंमत व वन विभागाचे अडेलपणाचे धोरण यामुळे बांबू कारागीर बेकार तर झालाच आहे. परंतु त्यात आणखी भर पडली ती म्हणजे फायबर, प्लॅस्टिक, टिनाच्या वस्तू यांनी बांबूनिर्मित वस्तुची जागा घेतली आहे. त्यामुळे बांबू कारागीर दारिद्र्यात खितपत पडले आहेत. हा व्यवसाय अंतीम घटका मोजत आहे.

आजही बांबूच्या वस्तू फार उपयुक्त आहेत. आणि जर ह्यावर उपाय योजना केली गेली तर ह्या व्यवसायाला गतवैभव येवू शकतो. त्याकरीता समाज, शासन आणि बुरड कामगार यांनी एकत्रीत येवून प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

बांबू निर्मिती हे खेडे गावामध्ये करता येते. परंतु प्लॅस्टिकची निर्मिती ही शहराच्या मोठ्या कारखान्यामध्ये करता येते. बांबूपासून खुर्च्या, कपाटे, दिवाण, विविध प्रकारची आकर्षक खेळणी, आकर्षक प्राणी हे आज तयार करण्यात येतात. बांबू संवर्धन प्रक्रिया आणि विपणन संस्था या द्वारे अत्याधुनिक, आकर्षक, मौल्यवान अशा बांबूच्या वस्तूची निर्मिती सुरू झाली आहे. त्याचे केंद्र मनसर येथे होते ते बंद होऊन लाखणी जिल्हा भंडारा येथे त्यासंबंधी केंद्र निर्माण करण्यात आले. त्याद्वारे व्यापक प्रमाणावर प्रशिक्षण योजना अमलात आणली तर आजही पर्यावरणाला संतुलित ठेवण्यासाठी बांबूच्या वस्तू ह्या प्लॅस्टिकच्या वस्तुला निश्चित पर्याय ठरू शकतात. त्यासाठी सरकार, सामाजिक कार्यकर्ते, कामगार संघटना व विविध सरकारी अधिकारी यांनी एकत्र येवून विचार करण्याची आवश्यकता आहे.



बांबूच्या वस्तू खराब झाल्यानंतर सुद्धा त्याचा उपयोग करून घेता येतो. त्या पर्यावरणाला घातक ठरत नाही. परंतु प्लॅस्टिकच्या वस्तू मात्र पर्यावरणाला घातक ठरतात. आज बाजारामध्ये रंगपंचमीच्या दिवशी प्लॅस्टिकच्या पिचकाच्या उपयोगात आणल्या जातात. परंतु पूर्वी रंग उडविण्यासाठी बांबूच्या पिचकाच्या उपयोगात आणल्या जात असत. अगदी स्वयंपाक घरापासून तर दिवाण खाण्यापर्यंत किंवा कार्यालयापर्यंत विभिन्न प्रकारच्या बांबूच्या वस्तू तयार करून त्यांचा वापर वाढविणे आजही आवश्यक आहे. स्वयंपूर्ण ग्रामीण अर्थरचनेचा बांबू उद्योग हा एक कणा आहे.

**प्लॅस्टिकच्या वस्तूला बांबू वस्तूचा पर्याय :**

बांबूच्या टोपल्या	—	प्लॅस्टिकच्या टोपल्या
बांबूच्या फुलांची टोपली	—	प्लॅस्टिकची टोपली
बांबूची डस्टबिन	—	प्लॅस्टिकच्या डस्टबिन
बांबूचे झाडू (खराटे)	—	प्लॅस्टिकचे झाडू
कचरा उचलण्याचे बांबूचे सुप	—	प्लॅस्टिकच्या सुप
धान्य साठविण्याची ढोली	—	प्लॅस्टिकचे डब्बे
दुध साठविण्याचे बांबूचे सिंक	—	प्लॅस्टिकचे सिंक
बांबूचा सुप	—	प्लॅस्टिकचा सुप
बांबूची चटई	—	प्लॅस्टिकची चटई
बांबूची झोरे	—	प्लॅस्टिकची पिशवी
बांबूची डाली	—	प्लॅस्टिकच्या पट्ट्या

वरील प्लॅस्टिकच्या वस्तूला बांबूच्या वस्तू पर्यायी होवून भारतीय दृष्टीकोनातून बांबूच्या वस्तूंचा वापर हा स्वयंपूर्ण, स्वदेशी व अर्थव्यवस्थेचा आधार आहे. त्यामुळे कोणत्याच प्रकारचा पर्यावरणाला धोका निर्माण होत नाही.

- संदर्भ :—
- १) भारतीय संस्कृती कोष खंड ०२  
संपादक — पं. महादेवशास्त्री जोशी
  - २) भारतीय संस्कृती कोष खंड ०६  
संपादक — पं. महादेवशास्त्री जोशी

## आदिवासींच्या संदर्भातील शासनाच्या शैक्षणिक योजना आणि आदिवासी विकास

प्रा. शुभांगी रमेश भेंडे

मा. ज्यो. फुले महा. , बल्लारपूर

### प्रस्तावना :-

स्वातंत्र्यपूर्व काळात देश स्वतंत्र करणे हेच उद्दिष्ट असल्यामुळे भारतीयांना आदिवासींकडे पुरेसे लक्ष घालता आले नाही. परंतु स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर भारतावर आदिवासींचे प्रश्न हाताळण्याची फार मोठी जबाबदारी येऊन पडली व सरकारपुढे एक आव्हान सुद्धा होते . आदिवासी अविकसित, अज्ञानाच्या अभावामुळे समाजाच्या मुख्य प्रवाहात जुळू शकला नाही. त्यामुळे या आदिवासी बांधवांना विकसित करण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक होते. राज्यातील दुर्गम डोंगराळ भागातील आदिवासींच्या कल्याणासाठी १९८३ सालापासून स्वतंत्र आदिवासी विकास विभागाची निर्मिती झाली.

भारत देशात आज ४२५ आदिवासी जमाती असून महाराष्ट्रात ४७ आदिवासी जमाती आढळतात देशातील आदिवासि लोकसंख्येच्या १०.१७% आदिवासींचे वास्तव्य महाराष्ट्रातील सह्याद्री, सातपुडा व पूर्व गोंडवाना या तीन दुर्गम डोंगराळ वनक्षेत्रांमध्ये जास्त प्रमाणात आहेत. महाराष्ट्रामध्ये भिल्ल , गोंड , महादेव कोळी , वारली , ठाकर , आंध , हलबा , कातकरी , कोकणी , मल्हार कोळी , कोरक , कोलाम , ढोर कोळी , पारधी , परधान या अत्यंत महत्वाच्या जमाती आहेत. तर कातकरी, कोलाम व माडिया गोंड यांची 'आदिम आदिवासी गट ' म्हणून गणती करण्यात येते ( महाराष्ट्र शासन २०१२).

### उद्देश :-

१. आदिवासी समाजाकरिता सरकारद्वारा राबविण्यात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरिता कार्यरत शैक्षणिक योजनांचा अभ्यास करणे.
२. आदिवासी समाजाकरिता राबविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक योजनांची उपयोगिता अभ्यासणे.
३. आदिवासी विकासामध्ये शासकीय शैक्षणिक योजनांची भूमिका अभ्यासणे.

आज संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकाराच्या घोषणापत्रकानुसार पीडित व शोषित मानवजातीय समूहांना विकसित करणे प्रत्येक राष्ट्राचे पालनकर्तव्य मानले गेले आहे. म्हणूनच भारतीय संविधानातील आदिवासी कल्याणासाठीच्या तरतुदीमुळे आदिवासी कल्याण कार्यक्रम तयार करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकार, घटकराज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था या तिन्ही स्तरावरील शासकीय यंत्रणेवर असून दोन्ही स्तरावरील सरकारांना आदिवासी कल्याण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आर्थिक निधीची तरतूद करावी लागते. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रशासन यंत्रणेला कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी आर्थिक अनुदानही दिले जाते.

आदिवासी विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात त्याखालील प्रमाणे आहे.

### शासकीय नोकऱ्यांत आरक्षण :-

भारतीय संविधानातील ३३५ कलमानुसार केंद्रीय लोकसेवा आयोग आणि राज्य लोकसेवा आयोग तसेच निवडमंडळातर्फे भरल्या जाणाऱ्या एकूण जागांपैकी ७.५% जागा आदिवासी साठी नौकऱ्या प्रमाणेच शासकीय अनुदानावर चालणाऱ्या संस्था नौकऱ्यात सुद्धा आरक्षण देण्यात आले आहे. ज्या संस्थानि शासनाच्या या नियमाचे पालन केले नाही अशा संस्थाना नवीन भरती करताना नौकऱ्यातील आदिवासींचा अनुशेष भरून काढणे असा आदेश काढण्यात आला आहेत.

#### शैक्षणिक सवलत :-

आदिवासी लोक हे निरक्षर असल्यामुळे ते मागासलेले राहिले तसेच अज्ञानामुळे शोषणास बळी पडले आणि हाच दृष्टिकोन समोर ठेऊन सर्वसामान्य प्रवाहात आदिवासी जमातीला आणण्यासाठी शासनाने विविध उपाय योजना केल्या आहेत. आदिवासि जमातीच्या मुलामुलींना मॅट्रिक नंतरच्या शिक्षणासाठी भारत सरकारची शिष्यवृत्ती दिली जाते तसेच प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी शासकीय वस्तीगृहात हुशार आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. त्याच्या जेवणाचा पुस्तकांचा खर्च शासनातर्फे केला जातो.

- आदिवासींच्या नवीन पिढीला शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली जाते त्याचप्रमाणे व्यावसायिक शिक्षणाची सोय निर्माण व्हावी यासाठी आदिवासी विभागामध्ये आश्रमशाळा काढण्यात आली आहे.
- या आश्रम शाळेत प्राथमिक शिक्षणाबरोबरच शेती, सूत कातणे, विणकाम यासारख्या विविध व्यवसायाचे शिक्षण हि देण्यात येत आहे.
- शालांत परीक्षेपर्यंत आदिवासी मुलांना पुस्तके ,पोशाख, दुपारचे जेवण इत्यादींचा खर्च भागविता यावा म्हणून आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. हि सरकारची योजना सर्वच घटकामध्ये राबविली जाते. यासाठी मोठ्या रकमेची तरतूद शासनसंस्था करीत असते. आदिवासी मुलं मुलींसाठी सुरु करण्यात आलेल्या शासकीय वस्तीगृह सुरु करण्यामागचा उद्देश हाच कि डोंगरखोऱ्यात दूरवर पसरलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहित करणे या योजने अंतर्गत विद्यार्थ्यांना मोफत भोजन, पुस्तके, निवास, अंथरून-पांघरून शैक्षणिक साहित्य व इतर आवश्यक साहित्य विनामूल्य उपलब्ध करून देणे होय यामध्ये आवश्यक असणाऱ्या गोष्टी म्हणजे विध्यार्थी आदिवासी व राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
- आदिवासी जमातीच्या विद्यार्थ्यांची तयारी करून देण्यासाठी इलाहाबाद, जयपूर,मद्रास,पतियाळा,शिलॉंग, दिल्ली, मुंबई येथे प्रशिक्षण मार्गदर्शन केंद्र सुरु करण्यात अली आदिवासींसाठी आश्रमशाळा , मोफत शिक्षण , बालवाड्या , मुलांना राहावयास वसतिगृह , मुलींसाठी वेगळी वसतिगृह , शिष्यवृत्ती, परदेशातील शिक्षणाकरिता शिष्यवृत्ती देण्यात येते.
- लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धात्मक परिक्षेची तयारी आदिवासी विद्यार्थ्यांना करता यावी म्हणून शासनाने आदिवासि उमेदवारांना खास मार्गदर्शन करणाऱ्या संस्था स्थापन केल्या आहेत.
- विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना सहजपणे प्रवेश मिळावा म्हणून त्यांच्यासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये काही राखीव जागा ठेवल्या आहेत.

- आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणसंस्थेत प्रवेश मिळावा म्हणून प्रवेशामध्ये गुणवत्तेची अट असल्यास त्यांना ५ टक्के गुणांची सवलत दिली जाते. यामुळे आदिवासी समाजात साक्षरतेचे प्रमाण पूर्वीपेक्षा वाढले आहे. शिष्यवृत्ती योजनांमुळे शिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली आहे व दरवर्षी या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे.
- आदिवासी जमातीच्या उमेदवारांसाठी सैन्य तथा पोलीस दल भरतीपूर्व प्रशिक्षण देण्याची योजनाही राबविण्यात येते. या योजने मागचा उद्देश म्हणजे सैन्य दल, पोलीस दल, राज्य राखीव दल, औद्योगिक सुरक्षा दल व इतर संरक्षण दल इ. मध्ये अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना योग्य ते शिक्षण व प्रशिक्षण देऊन अशा दलामध्ये आदिवासी समाजातील उमेदवारांना योग्य ते शिक्षण देऊन अशा दलामध्ये नौकरी मिळविण्याच्या दृष्टीने प्रशिक्षित करणे. या प्रकारचे केंद्र नाशिक, नंदुरबार, राजुरा, जव्हार, घोडेगाव, धरणी, किनवट, चंद्रपूर, गडचिरोली या ठिकाणी सुरु करण्यात आले आहे. प्रत्येक केंद्रामध्ये एका सत्रामध्ये जवळपास १०० विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते व ह्या प्रशिक्षणाचे वैशिष्ट्ये म्हणजे हे प्रशिक्षण विनामूल्य दिले जात असून प्रशिक्षण काळात निवासी, भोजन, गणवेश इ. सुविधा मोफत पुरविण्यात येतात. एक सत्र ४ महिन्यांचे असते. त या प्रशिक्षणासाठी १८ वर्षावरील व २३ वर्षाखालील विद्यार्थ्यांची प्रशिक्षणासाठी निवड केली जाते.
- सन २००३-२००४ पासून व्यावसायिक अभ्यासक्रमात शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता दिला जातो.
- आर्थिकदृष्ट्या परवड नसल्यामुळे इतर आर्थिक सवलती शिवाय विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमात शिकत असलेल्या उदा . मेडिकल , इंजिनीरिंग , कृषी पदवी , डी. एड. , बी. एड. , बी. पी.एड. , एम. एस. डब्ल्यू. , सि.ए., पॉलीटेक्निक इ. अभ्यासक्रमात शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाचे दराने निर्वाह भत्ता अदा करण्यात येतो.
- सन १९५९-१९६० पासून महाविद्यालयात विविध अभ्यासक्रमात शिक्षण घेत असलेल्या अनु.जमातीच्या विद्यार्थ्यांना सुधारित दराप्रमाणे शिष्यवृत्ती देण्यात येते. हि शिष्यवृत्ती देताना पालकाचे आर्थिक प्रमाण पत्रचा वापर करण्यात येतो.
- ३१ मी २०१० अन्वये स्वर्णजयंती पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना आणि. अनु.जमातीच्या मुला -मुलींसाठी शाळेतील उपस्थितीचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत असल्याने त्यांचे उपस्थितीचे प्रमाण वाढविण्याकरिता १ ली ते ४ थी, ५ वि ते ७ वि पर्यंत आणि ८ वि ते १० वि पर्यंत शिष्यवृत्ती देण्यात येते. पूर्वी हि योजना फक्त मुलींसाठी लागू होती मात्र २०१०-२०११ पासून सादर योजना मुलांनाही लागू करण्यात आली.
- आदिवासी विद्यार्थ्यांचा आकस्मित मृत्यू झाल्यानंतर सानुग्रह अनुदान योजना काही नैसर्गिक अप्पत्ती व अपघाती मृत्यू आल्यास शासकीय आश्रमी मृत्युमुखी पडलेल्या विद्यार्थ्यांना शासनाची पालकत्वाची जबाबदारी म्हणून व शैक्षणिक विकासातील महत्वाची समन्वयक म्हणून टाकण्यात आलेली जबाबदारी यादृष्टीने विद्यार्थ्यांचा विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाल्यास सामाजिक दृष्टिकोनातून तातडीचे अर्थसहाय्य म्हणून विद्यार्थ्यांच्या पालकांस १५०००/- सानुग्रह अनुदान शासनाकडून मंजूर करण्याची योजना राबविण्यात येत आहे.

- शालांत व उच्च माध्यमिक शाळेत परीक्षेत विशेष प्राविण्य मिळविणाऱ्या गुणवत्ता यादीतील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहनपर बक्षीस योजना हि योजना २००३-२००४ या वर्षापासून राबविण्यात येत आहे.
- आदिवासी विद्यार्थ्यांना सैनिकी शाळेमध्ये शिक्षण देण्यासाठी राज्यातील सैनिकी शाळांना जोडून ज्यादा तुकडी सुरु करण्यात आली आहे. यामध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना माध्यमिक स्तरावर सैनिक शिक्षणाची सोया उपलब्ध करणे असा उद्देश आहे. सैनिकी शाळेमध्ये इय्यता पाचवीच्या वर्गामध्ये आदिवासी मुलांसाठी एक तुकडी सुरु केली जाते. अश्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत भोजन, निवास, गणवेश, साबण, दंतमंजन, इ. सुविधा पुरविण्यात येते. मात्र सैनिकी शाळेमध्ये दाखला घेण्यासाठी काही शैक्षणिक पात्रता पूर्ण करणे गरजेचे असते जसे वजन, उंची, शारीरिक क्षमता , धनुर्विद्या , लांब पल्याचे धावणे इ. चे मूल्यमापन करून निवड केली जाते.

#### निष्कर्ष :-

- १) आदिवासी समुदायाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक विकास घडवून आणण्यासाठी शासकीय योजनांचा ज्या प्रमाणे गरज आहे त्याचप्रमाणे त्या योजना केवळ कागदोपत्री न रहाता आदिवासी लोकांपर्यंत पोहचल्या पाहिजे या दृष्टीकोनातून सरकारने प्रयत्न करणे.
- २) आदिवासी समुदायाला सर्वसाधारण प्रवाहात आणण्यासाठी आर्थिक विकास साधायचा असल्यास सर्वप्रथम शैक्षणिक योजनांची अंमलबजावणी होणे अनिवार्य आहे.
- ३) आजही काही दुर्गम आदिवासी विभागात दळणवळणाच्या साधनांचा अभाव दिसून येतो अश्यावेळेस सरकारनी सर्वात पहिले या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यावर भर दिला पाहिजे.
- ४) आदिवासी विकासातील महत्वपूर्ण अडथळा म्हणजे आदिवासी जमातीचे शोषण करून स्वतःचा स्वार्थ साधणारी व्यक्ती आदिवासींसाठी असणारे कायदे , अधिकार इ. संबंधित योजना स्वीकारण्यास तयार होत नाही. एवढेच नव्हे तर जाणून-बुजून आदिवासी पर्यंत या सोयी-सवलतीचा लाभ पोहचू देत नाही.

#### उपाययोजना :-

- १) शासकीय शैक्षणिक सोयी-सुविधा आदिवासी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचवायची झाल्यास त्या योजनांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे व्हायला पाहिजे.
- २) संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपले कार्य व्यवस्थितपणे पार पडले पाहिजे जेणेकरून आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या सुविधांची माहिती आदिवासी पालकांपर्यंत पोहचली पाहिजे.
- ३) अधिकाधिक आदिवासींनी या सर्व सोयी सवलतीचा लाभ घेतला पाहिजे या साठी आदिवासींमध्ये जनजागृती करायला हवी.
- ४) शासकीय योजनांची माहिती देताना स्थानिक आदिवासींच्या बोलीभाषेचा उपयोग अधिकाधिक करावा.
- ५) लोकजागृतीकरिता अधिकाधिक दृक्श्राव्य साधनांचा उपयोग करावा.

- ६) प्रत्येक आदिवासी समूहाला त्यांचा स्थानिक बोली भाषेतून शिक्षण मिळेल यासाठी विशेष शैक्षणिक धोरण आखणे गरजेचे आहे.
- ७) आदिवासी समूहाला त्यांचा राहत्या ठिकाणी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे जेणेकरून स्थलांतरणाचा प्रश्न सुटेल.
- ८) आदिवासींना शिक्षण देताना युवावर्गाचा विचार करणे गरजेचे आहे. आधुनिक शिक्षण पद्धती व युवागृह शिक्षण पद्धतीत अंतर नसावे.
- ९) आदिवासी समुदायाची जीवनशैली त्यांची संस्कृती व इतर परिस्थितीचा आढावा घेऊनच व त्यांच्या गरजा ओळखून त्यानुसार स्वतंत्र कार्यक्रमाची आखणी करणे गरजेचे आहे. तेव्हाच सर्वसाधारण प्रवाहात त्यांना सामील करून घेण्यात यश प्राप्त होईल.
- १०) आदिवासी क्षेत्रातील शाळांची पटनोंदणी वाढविण्यासाठी व शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती थांबविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे.
- ११) आदिवासी शाळांचा दर्जा वाढविणे त्या दृष्टीने पायाभूत सुविधा, शिक्षणाची गुणवत्ता, नियमित शिक्षकांची सोय यावर भर देण्यात यावा.
- १२) आदिवासी युवकांना त्यांचाच बोलीभाषेत शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करणे.
- १३) आदिवासी युवकांना शिक्षणासोबत व्यावसायिक शिक्षणाची संधी प्राप्त करून देणे जेणेकरून त्यांना रोजगार किंवा स्वयंरोजगार उपलब्ध होईल व त्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन राहणीमानाचा दर्जा उंचावेल.
- १४) शासकीय योजनांची माहिती देताना त्यांना त्याच्याच बोलीभाषेतून देण्याचा प्रयत्न करावा. जेणेकरून त्याचा लाभ आदिवासी लोकांना घेता येईल.
- १५) केवळ आदिवासींना शैक्षणिक सोयी सुविधा उपलब्ध करून भागणार नाहीत तर त्यांच्या आर्थिक दर्जा सुधारावा या दृष्टिकोनातून विचार करीत असताना त्यांना त्याच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार स्थानिक स्तरावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्या.

#### समारोप :-

आदिवासी कल्याण कार्यक्रमावर दरवर्षी करोडो रुपये खर्च केले जातात मात्र आदिवासी कल्याण कार्यक्रमाचा लाभ ज्या गरजू आदिवासींना मिळायला पाहिजे होतो तो लाभ त्यांना मिळाला नाही बऱ्याचदा आदिवासी कल्याण कार्यक्रमावर केल्या जाणाऱ्या खर्चामध्ये भ्रष्टाचार होतो तर अनेकदा असे दिसून येते कि ज्या कामासाठी दिलेले पैसे दुसऱ्याच कामावर खर्च केल्या जाते आदिवासी विकास योजना उत्तम असतात मात्र त्याची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे केली जात नाही. तर काही योजना ह्या केवळ कागदोपत्रीच राहतात तर काही योजना आदिवासी लोकांच्या गरजा लक्षात घेऊन आखल्या जात नाही. कल्याण कार्यक्रम हे कितीही चांगले असले तरी आदिवासींच्या जीवन पद्धतीवर त्याचा आघात होत असेल तर अश्या योजनेबद्दल आदिवासींच्या मनात उदासीनता, सांशकता दिसून येते. अशाप्रकारे आदिवासी कल्याण कार्यक्रमात काही त्रुटी असल्या तरीही त्यांच्या अंमलबजावणीमुळे आदिवासींच्या जीवनातील अंधकार दूर होण्यास मदत होत आहे याचाच परिणाम म्हणजे आज आदिवासी समाजात युवकांमध्ये



शिक्षणाचे प्रमाण वाढत आहे आणि स्वतःवर होणाऱ्या अत्याचारापासून स्वतःची सुटका कशी करून घ्यावी याची जाणीव निर्माण होण्यास सुरवात झाली आहे. शिक्षण व जाणीव जागृतीमुळे त्यांच्यावरची धर्म व जादूची पकड सैल होत आहे. शिक्षण विषयक सोयी सवलती, आर्थिक लाभाच्या शासकीय विकास योजना इत्यादींमुळे त्यांच्यात मंदगतीने का होईना बदल होत आहे.

**संदर्भ ग्रंथसूची :-**

- १) लोटे रा. ज. आदिवासी समाजाचे समाजशास्त्र , मनोहर पिंपळापुरे ऍण्ड कं. पब्लिशर्स , हिंदू मुलीचे शाळेजवळ , महाल , नागपूर, दुसरी आवृत्ती जून २००६
- २) डॉ. प्रदीप आगलावे , साईनाथ प्रकाशन , नागपूर, सकाळ , लोकमत वृत्तपत्र अग्रलेख
- ३) इंटरनेटवरील माहिती
- ४) डॉ. प्रदीप आगलावे , भारतीय समाज प्रश्न आणि समस्या
- ५) लोकसत्ता २३ जानेवारी २०१२
- ६) लोकसत्ता २५ मार्च २०१३
- ७) कऱ्हाडे भा. कि. (२००६) "शास्त्रीय संशोधन पद्धती " पिंपळापुरे ऍण्ड प्रकाशन, नागपूर .
- ८) खडसे भा. कि. (२००६) "आदिवासी समाजाचे समाजशास्त्र" हिमालय प्रकाशन, मुंबई.

## भारतातील दारिद्र्याचे कारणे व उपाययोजना

प्रा. डॉ. नरेंद्र श्रीधर बागडे

सहाय्यक प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग

पी.डब्ल्यू.एस. कला व वाणिज्य महाविद्यालय कामठी रोड, नागपूर.

### सारांश

अल्पविकसित व अविकसित देशांपुढील सर्वात गंभीर स्वरूपाची समस्या म्हणजे दारिद्र्य. कोणत्याही व्यक्तीला चांगले जीवन जगण्यासाठी मुलभूत गरजांची पूर्तता होणे आवश्यक आहे. कोणत्याही राष्ट्राची ही अपेक्षा असते की त्या राष्ट्रातील जनतेने सुखी व समृद्ध जीवन जगले पाहिजे. परंतु ही अपेक्षा काही प्रमाणात साध्य होत नाही. दारिद्र्याची समस्या कमी अधिक प्रमाणामध्ये सर्वच देशांमध्ये आढळून येते. भारतामध्ये नैसर्गिक साधनसंपत्ती असून देखील आजही अनेक कुटूंबे किमान जीवनमानापासून वंचित आहेत. भारताला विसाव्या शतकाच्या प्रारंभापासूनच व्यापक प्रमाणात असलेल्या दारिद्र्याला तोंड द्यावे लागत आहे. स्वातंत्र्यानंतर वाढत गेलेली लोकसंख्या यामुळे आर्थिक विषमतेत वाढ झाली आहे. सरकारने यावर उपाययोजना करण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना राबविल्या आहेत, परंतु दुःखाची बाब म्हणजे आजपर्यंत दारिद्र्याचे भारतातून समुळ उच्चाटण करण्यात यश आले नाही.

**बीजशब्द** — दारिद्र्य, रोजगार, विषमता, शेती, लोकसंख्या, योजना

### प्रस्तावना :

भारतातील अनेक समस्यांपैकी दारिद्र्य ही एक महत्वाची समस्या आहे. ब्रिटीश भारतात आल्यानंतर भारतातील संपत्ती त्यांच्या देशामध्ये नेण्यास सुरुवात केली व येथूनच भारतात दारिद्र्याचे मुळे रोवल्या गेली व नंतरच्या काळात ती वाढतच गेली. ब्रिटीशांनी भारताच्या विकासासंदर्भात कधीच विचार केला नाही. त्यांच्यामुळे देशातील परंपरागत उद्योग बंद पडले, रोजगार कमी झाला व दुष्का वाढला.

जीवनाचा एक न्यूनतम स्तर टिकविण्यासाठी अन्न, वस्त्र व निवारा या बाबी आवश्यक आहेत. व्यक्तीला स्वतःच्या व कुटुंबाच्या मुलभूत गरजा पूर्ण करणे कठीण झाले आहे. ज्यावेळी व्यक्तीला व त्याच्यावर अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबाचा जीवनस्तर न्यूनतम जीवनस्तरापेक्षा खाली असतो तेव्हा त्या अवस्थेस दारिद्र्य असे म्हणतात. थोडक्यात, अन्न, वस्त्र व निवारा या मुलभूत गरजांची पूर्तता करण्याची क्षमता नसणे म्हणजे दारिद्र्य होय. ग्रामीण भागामध्ये एका व्यक्तीला एका दिवसासाठी २४०० कॅलरीज व शहरी भागात २१०० कॅलरीज पोषण आहार प्राप्त करू न शकणाऱ्या व्यक्ती दारिद्र्यरेषेखालील मानल्या जातात.

भारत सरकारने नेमलेल्या सुरेंद्र तेंडूलकर समितीच्या मते, २००९-१० या वर्षात ग्रामीण भागासाठी ६७२.४ रुपये व शहरी भागासाठी ८५९.६ रुपये इतका दरमहा दरडोई उपभोग खर्च आवश्यक आहे, यापेक्षा कमी उपभोग खर्च असणाऱ्या व्यक्ती दारिद्र्यरेषेखालील (BPL- Below Poverty Line) आहेत.

### संशोधनाचे उद्दिष्टे

- १) भारतातील दारिद्र्याचा अभ्यास करणे.
- २) भारतातील दारिद्र्यास जबाबदार असणाऱ्या कारणांचा अभ्यास करणे.
- ३) भारतातील दारिद्र्य निर्मूलनासाठी आवश्यक उपाययोजना सुचविणे.

### दारिद्र्याची व्याख्या

गिलीन आणि गिलीन यांच्या मते, “दारिद्र्य ही एक अशी अवस्था आहे की ज्यामुळे कोणत्याही व्यक्ती अपुरे उत्पन्न किंवा गैरवाजवी खर्चांमुळे स्वतःचा जीवनस्तर हा उंचावू शकत नाही. व्यक्ती स्वतःचे मानसिक स्वास्थ्य टिकवू शकत नाही. तसेच ते ज्या समाजाचे सदस्य आहेत त्या समाजाच्या जीवनमूल्यांप्रमाणे योग्य ते कार्य करू शकत नाही.”

### दारिद्र्याची कारणे

दारिद्र्य ही आर्थिक व सामाजिक समस्या असून तीने अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण केले आहे. भारतीय समाजावर कर्मसिद्धांत, पुर्नजन्म, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक यासारख्या अनिष्ट बाबींचा पगडा आहे. मागच्या जन्मातील पापाचे फळ म्हणून या जन्मातील हे दारिद्र्य होय असा दैववादी दृष्टीकोन आहे. परंतु वास्तविक पाहता व्यक्तीची अकार्यक्षमता, खर्चीक वृत्ती, आळसपणा, अज्ञान, वाईट सवयी हे व्यक्तीच्या दारिद्र्यामध्ये वाढ करत असतात.

### १) मागासलेली शेती

भारत देश हा कृषी प्रधान आहे असे म्हटले जाते, परंतु आजही भारतातील शेती ही पावसावर अवलंबून आहे. शेतकऱ्यासाठी तो एक जुगारच असतो कारण पाऊस येईल की नाही हे निसर्गावरच अवलंबून आहे. तसेच आजही शेती ही पारंपारीक पद्धतीनेच केली जाते.

### २) वाढती लोकसंख्या

जगाच्या तुलनेमध्ये लोकसंख्येच्या बाबतीत भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो. शिक्षणाचा अभाव असल्यामुळे कुटुंबनियोजनाबाबत भारतातील जनतेला पाहिजे तेवढे ज्ञान नाही. कुटुंबाचा आकार मोठा असल्यामुळे मुलभूत गरजांची पूर्तता होत नाही व त्यामुळे दारिद्र्य वाढीला लागते.

### ३) बेरोजगारी

देशातील वाढणारी लोकसंख्या व कमी आर्थिक विकास यामुळे देशातील सर्वानाच रोजगार उपलब्ध होवू शकत नाही. त्यामुळे काम करण्याची इच्छा असूनदेखील काम मिळत नाही व अनेकांना बेरोजगारीला तोंड द्यावे लागते त्यामुळे दारिद्र्यात भर पडते.

#### ४) मागासलेल्या रुढी व परंपरा

भारतामध्ये अंधश्रद्धेला जास्त महत्व दिल्या जाते त्यामुळे कित्येकांची नवीन करण्याची तयारी नसते. हिंदु धर्मांमध्ये अनेक वाईट जुन्या रुढी व परंपरा दिसून येतात त्यामुळे देशाचा विकास होत नाही.

#### ५) जातीव्यवस्था

भारतामध्ये जातीव्यवस्था हे दारिद्र्यास जबाबदार असणारा महत्वाचा घटक आहे. इतर कोणत्याही देशाच्या तुलनेत भारतामध्ये अधिक प्रमाणात जातीव्यवस्था दिसून येते. जातीमध्ये प्रत्येक जातीचा एक विशिष्ट परंपरागत व्यवसाय होता व प्रत्येकाने आपल्या जातीचाच व्यवसाय करणे बंधनकारक होते त्यामुळे अनेकांमध्ये कौशल्य असूनदेखील दुसरा व्यवसाय करता येत नसे.

#### दारिद्र्य निर्मूलनाचे उपाय

दारिद्र्य निर्मूलनासाठी किंवा दारिद्र्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतर केंद्र व राज्य सरकारने अनेक उपाय केले आहेत.

#### १) लोकसंख्या नियंत्रित करणे

भारतातील झपाट्याने वाढत जाणारी लोकसंख्या अनेक कारणांपैकी दारिद्र्यास सुद्धा जबाबदार आहे. लोकसंख्या आर्थिक विकासासाठी मारक ठरत आहे त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रित करणे गरजेचे आहे. लोकसंख्या शिक्षण, प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे, प्रौढ शिक्षणाचा प्रसार, लोकसंख्या वाढीचे दुष्परिणाम दाखविणारे पथनाट्ये, प्रसार माध्यमांतून लोकसंख्या वाढीचे वाईट परिणाम लोकांपर्यंत पोहचवून वाढत्या लोकसंख्येवर आळा घालता येतो.

#### २) रोजगार निर्माण करणे

लोकांना रोजगार नसल्यामुळे त्यांच्या हातात पैसा येत नाही व ते मागणी करू शकत नाहीत पर्यायाने बाजारातील उत्पादित माल तसाच पडून राहतो व देशाचे फार मोठे नुकसान होते. त्यासाठी देशातील जनतेला रोजगार मिळून देणे गरजेचे आहे. यासाठी देशातील लघु व सूक्ष्म उद्योगाचा विस्तार करणे, शेती सोबतच जोड धंदा करावा जेणेकरून रोजगारीत वाढ होईल.

#### ३) शेती क्षेत्राचा विकास

भारतीय शेती ही पारंपारीक असून त्यामध्ये अजूनही शेती संबंधीत कामे जुन्याच पद्धतीने करण्यात येतात. त्यामुळे उत्पादनात वाढ होत नाही परंतु शेतीमध्ये आधुनिक तंत्र, साधनाचा उपयोग

केला तर वेळ वाचून उत्पादनात वाढ होवू शकते. शेतीमध्ये सिंचनाच्या सोयी, प्रगत कृषी तंत्रज्ञान, सुधारित बि बीयाणे इत्यादींचा उपयोग केल्यास शेतीचे उत्पादन वाढविता येते व दारिद्र्याचे प्रमाण कमी करता येते

#### ४) कुटीर व लघु उद्योगाला चालना देणे

शेती क्षेत्राचा भार कमी करण्यासाठी शेतीवर अवलंबून असलेल्या जनतेला इतर क्षेत्रामध्ये रोजगार उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. शेतीमध्ये अदृश्य बेरोजगारी असल्यामुळे उत्पादनात वाढ होत नाही. अशा वेळी देशातील कुटीर व लघु उद्योगाला चालना देवून अधिक रोजगारक्षम करता येवून दारिद्र्यावर अंकुश लावता येतो.

#### ५) योजनांचे विकेंद्रीकरण करणे

अस्तित्वात असलेल्या सरकारच्या योजनांना पाहिजे त्या प्रमाणात यश मिळाले नाही. योजनांचा लाभ शेवटच्या गरजू व्यक्तीपर्यंत पोहचलेला नाही. यासाठी योजनांचे विकेंद्रीकरण करणे आवश्यक आहे त्यामुळे योजनांचा लाभ शेवटच्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवता येईल व दारिद्र्याची समस्या कमी होण्यास मदत होईल.

#### संदर्भ -

१. कन्हाडे बी. एम. 'भारतीय समाज प्रश्न आणि समस्या', पिंपळापुरे अँड कं. पब्लिशर्स, नागपूर, २०१०.
२. सुधाकर शास्त्री, नितीन कावडकर, 'भारतीय अर्थव्यवस्था', विश्व पब्लिशर्स अँड डिस्ट्रिब्यूटर्स, नागपूर, २००७.
३. आर्थिक आणि जागतिक आर्थिक विकास, महाजन मुकुंद, निराली प्रकाशन, २०१०.
- ४ अर्थसंवाद, आक्टोबर-डिसेंबर २०१३.
५. दैनिक, लोकमत, दि.०३ जून २०१६.
६. दैनिक, सकाळ, दि. २९ ऑगस्ट २०१४.

## बाल कामगार समस्येचे कारणे व उपाययोजना

प्रा. डॉ. कल्पना मंडलेकर

विभागप्रमुख, अर्थशास्त्र

जवाहरलाल नेहरू कला, वाणिज्य व

विज्ञान महाविद्यालय, वाडी, नागपूर.

### प्रस्तावना :

बाल कामगार ही एक वाईट प्रथा असून कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर एक फार मोठे ओझे आहे. मानवतेच्या नावावर कलंक आणि मुलांसाठी एक अभिशाप आहे. बाल कामगाराची समस्या सर्व समस्यापेक्षा वेगळी नसून ती एक मिश्रित सामाजिक, आर्थिक समस्या आहे. याला दूर करण्यासाठी सरकार सोबत जन सहयोगाची नितांत आवश्यकता आहे. बाल मजूरीची समस्या नष्ट करण्यासाठी काही ठोस कार्यक्रमाची आवश्यकता आहे. ज्यात प्रत्येक व्यक्ती सहभागी होऊ शकेल आणि याला समाजाचा एक कलंक म्हणून अनुभव करेल. समाजामधील व्यवस्थेमुळे बालकांना कष्टाचे जीवन जगावे लागत आहे. बालकांना कामाच्या ठिकाणी अमानवी वागणूक दिली जाते. तसेच त्यांचे लैंगिक शोषणसुद्धा केले जाते. लहान मुले देशाचे भवितव्य असून उद्याचे नेतृत्व आहेत. कारण हेच मुले भविष्यात देशाचे जबाबदार नागरिक होणार आहेत. देशाचा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, संरक्षण व एकूणच सर्व प्रगतीच्या क्षेत्राचा विकास त्यांच्यावरच अवलंबून आहे. जर यांचा सर्वांगीण विकास व्यवस्थित झाला नाही तर देशाचा विकास होणार नाही.

बाल कामगार ही काही नव्याने उद्भवलेली समस्या नसून भारतात फार पूर्वीपासून चालत आलेली प्रथा आहे. इ.स. पूर्व ३०० मध्ये कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात बाल सेवक, कुलन असा बाल कामगारांचा उल्लेख आढळतो. मध्ययुगाच्या काळात देखिल ही प्रथा अस्तित्वात होती. या पद्धतीनुसार संरजामदाराकडे गरिब लोकांना त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना व लहान बालकांना देखिल वेठबिगारी करावी लागत असे.

**शब्दसंकेत :** अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, दारिद्र्य, उद्योग, संविधान.

### संशोधनाची उद्दिष्टे :

- १) बाल कामगार मजूरीकडे वळण्याच्या कारणांचा शोध घेणे.
- २) बाल कामगार समस्या निर्मूलणासाठी उपाययोजना सुचविणे.

### भारतातील बाल कामगार प्रतिबंध व नियंत्रण कायदा (१९८६)

वयाचे १४ वर्ष पूर्ण न करता कोणत्याही उद्योगामध्ये, खाणीमध्ये, किंवा इतर कोणत्याही धोकादायक व्यवसायामध्ये काम करणाऱ्या बालकाला बाल कामगार असे म्हटले जाते. भारतातील बाल कामगार प्रतिबंध व नियंत्रण कायदा १९८६ नुसार बाल कामगारांचे वय १४ वर्ष निश्चित केले आहे; परंतु १४ वर्षावरील बालके देखिल सर्वांगीण दृष्ट्या अपरिपक्व असून ते देखिल धोकादायक उद्योगात कामे करतांना दिसतात. त्यामुळे मर्यादित वयाच्या अटीसंबंधीची उणीव निश्चितच या व्याख्येतून दिसून येते.

### बाल कामगार मजूरीकडे वळण्याची कारणे

#### दारिद्र्य

दारिद्र्य हा घटक बाल मजूरीचे कारण व परिणाम आहे. कोणत्याही आई वडीलांना असे वाटत नाही की आपल्या मुलाला कामाला पाठवावे. परंतु गरिबी व दैनंदिन गरजांची पूर्तता न झाल्याने ते आपल्या मुलाला कामास पाठविण्यास मजबूर असतात. कुटुंबामध्ये पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली गरिबी, शेतीसारखा कष्टाचा व्यवसाय करण्यासाठी दिवसभर राबत असतात. एवढे करुनही गरजा पूर्ण होत नसल्यामुळे आपल्या मुलांना शाळेत पाठवण्याऐवजी कामाला पाठवतात.



### कर्जाचा भार

आई वडील हे काही कारणासाठी कर्ज घेतात जसे, घर बांधणे, कुटुंबातील सदस्याचे दिर्घ आजारपण, बेरोजगारी. परंतु आई वडीलाकडून कर्ज देणे शक्य झाले नाही की ते आपल्या मुलाला कामावर नेतात व त्याच्या मदतीने कर्ज फेडतात. जर कर्ज देणारा मोठा शेतकरी असला तर तो कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीच्या मुलाला गुरेढोरे चरायला नेणे अशी कामे देतो. काही मुले कर्ज देणाऱ्याच्या घरीच घरगुती काम करतात.

### आई-वडीलांची बेरोजगारी

प्रौढ व्यक्तिला कामाला ठेवले तर त्यांना जास्त मजुरी द्यावी लागते परंतु त्याच कामाला लहान मुलांना ठेवले तर त्याला कमी मजुरी दिली तरी चालते अशी मालक वर्गाची भावना असते. याच कारणामुळे ते प्रौढ व्यक्तिला कामाला न ठेवता लहान मुलांना कामावर ठेवतो. प्रौढ व्यक्तिला काम मिळत नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येते व आई वडीलांना मजबूर होऊन आपल्या लहान मुला मुलींना कामावर पाठवावे लागते.

### आई-वडीलांचे आजारपण

भारतीय कुटुंबामध्ये गरिबीचे प्रमाण जास्त आहे. गरिबी असल्यामुळे पोषक अन्न मिळत नाही. आवश्यक तेवढ्या कॉलरीज त्यांना मिळत नाहीत त्यामुळे त्यांचे आरोग्य बिघडते. वेळेवर उपचार झाला नाही तर ते वाढतच जाते. आई वडील आजारी असल्यामुळे ते कामाला जाऊ शकत नाहीत. अशा वेळी ते आपल्या मुलाला काम करण्यास पाठवतात.

### पारंपारीक व्यवसाय

ग्रामीण भागातील अधिकतर मुले कोणत्या ना कोणत्या कामामध्ये व्यस्त असतात. कारण ग्रामीण भागामध्ये अनेक परंपरागत असे व्यवसाय आजही केले जातात. मुलांचे आई वडील मुलाला शाळेत पाठविण्याऐवजी आपला व्यवसाय शिकविण्यावर भर देतात, यामुळे मुलाला शिक्षणाविषयी आवड निर्माण न होता कामाविषयी आवड निर्माण होते व तो तेच काम करतो.

### आई वडीलांचा मृत्यु

३० टक्के भारतीय हे दारिद्र्य रेषेखाली जीवण जगतात. त्यांना दोन वेळचे जेवन मिळत नाही. जेवन मिळाले तर त्यामध्ये आवश्यक कॉलरीज नसतात. यामुळे व्यक्ति आजारी पडतात. कधी कधी आजारामुळे घरातील कामावत्या व्यक्तीचा मृत्यु होतो. अशावेळी मुलाला कामावर जावे लागते.

### कुटुंबामध्ये लहान मुलांची अधिक संख्या

ग्रामीण भागातील कुटुंबामध्ये मुलांची संख्या जास्त असते. यामागचे कारण आहे की एक तर ते अशिक्षित असतात आणि त्यांना कुटुंब नियोजनाचे महत्व माहित नसते. दुसरे कारण असे की, त्यांचे असे मत असते की जेवढे घरामध्ये जास्त मुले तेवढे जास्त उत्पन्न मिळते अशी त्यांची भावना असते. याच कारणामुळे ते आपल्या मुलाला कामास जाऊ देतात.

### खर्चिक शिक्षण

१४ वर्षा खालील मुलांना प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे केले असले तरी पुस्तके खरीदीसाठी व इतर शैक्षणिक साहित्य विकत घेण्यासाठी त्यांच्या कडे पैसे नसतात. कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे मुलांना शिक्षण मोफत मिळत नाही, त्यामुळे ते शिक्षणाकडे नकारात्मक दृष्टिकोणातून पाहतात व शिक्षणाकडे न वळता कामाकडे वळल्या जातात.

### श्रिमंत व्यक्तिकडून कामासाठी लहान मुलांची निवड

श्रिमंत व्यक्ति हे कामासाठी प्रौढ व्यक्तीची निवड न करता लहान मुलांना कामावर ठेवतात कारण, प्रौढ व्यक्तिला कामावर ठेवले तर त्याला जास्त मजुरी द्यावी लागते व तेच काम कमी पैशामध्ये लहान मुलांकडून करून

घेता येते तसेच श्रिमंत व्यक्ती आपल्या घरची कामे जसे बाजार आणणे, गाडी धुणे यासारखी काम फक्त दोन वेळचे जेवन देऊन करून घेतो.

#### उपाययोजना

समाजाच्या दृष्टीने बालक हा भविष्यातील संपत्ती आहे तरीसुद्धा समाजाने या बालकांवर कामाचे ओझे लादले व यामुळे बालकांवर शारीरिक व मानसिक दुष्परिणाम झाले. बाल कामगार ही समस्या फक्त भारताशीच संबंधित नसून ती एक जागतिक समस्या बनली आहे. बाल कामगार समस्येच्या निर्मूलनाकरीता पुढीलप्रमाणे काही उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

#### दारिद्र्य निर्मूलन

भारतासारख्या विकसनशिल देशामध्ये बाल कामगारांची समस्या मग ती ग्रामीण भागात असो किंवा शहरी भागात असो तिचे प्रमुख कारण म्हणजे दारिद्र्य होय. दारिद्र्य निर्मूलन करण्यासाठी सरकारच्या विविध योजना आहेत, परंतु भ्रष्टाचार, व्यावसायिक कौशल्यांचा अभाव, उदासिनता, उद्योजकतेचा अभाव यामुळे अनेक कार्यक्रम प्रत्यक्षामध्ये न येता कागदावरच राहतात. या योजना गरिब लोकांपर्यंत पोहचत नसल्यामुळे मंजूर झालेल्या पैशाचा मोठ्या प्रमाणातमध्ये दुरुपयोग होतो. बाल कामगार प्रथा नष्ट करण्यासाठी दारिद्र्य निर्मूलन करणे आवश्यक आहे व यासाठी विविध योजना गरिबांपर्यंत पोहचविणे आणि त्यांची योग्य अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.

#### बेकारीचे निर्मूलन

भारत देश हा सर्व प्रकारच्या संसाधनांनी समृद्ध आहे तरीसुद्धा मानव संसाधनांचा हवा तसा विकास होत नसल्यामुळे बेरोजगारांची समस्या निर्माण झाली आहे. सद्यस्थितीमध्ये भारतात तरुण बेकारांची वाढती संख्या एक गंभीर समस्या आहे. या समस्येचे निर्मूलन करण्यासाठी उद्योग, व्यापारी गरजा आणि शिक्षण संस्थांच्या अभ्यासक्रमांमध्ये आवश्यक ते बदल करायला हवे, यामुळे देशातील तरुण वर्गाला रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील व स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करून बेकारीचे उच्चटण करता येईल.

#### प्राथमिक आणि प्रौढ शिक्षण

अधिकतर बाल कामगारांचे आई वडील हे अशिक्षित असतात. त्यांचा शिक्षणाविषयी नकारात्मक दृष्टीकोण असतो, म्हणून ते मुलांना शाळेमध्ये न पाठवता कामाला पाठवतात. अशा प्रकारच्या अशिक्षित आई वडीलांना सर्वप्रथम साक्षर करण्याची गरज आहे. याचा परिणाम असा होईल की, प्रत्येक कुटुंब प्रमुख आपल्या मुलांच्या भविष्याबाबत सकारात्मक दृष्टीने विचार करू लागतील व मुलांना शाळेमध्ये पाठवतील, त्यामुळे प्राथमिक शाळामधील मुलांच्या गळतीचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. मुलांमध्ये शाळेविषयी आवड निर्माण झाली की, ते कामाला न जाता शाळेमध्ये जातील.

#### सामाजिक जागरूकता

लहान वयामध्ये काम केल्याने मुलांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होतात. बाल वयात रोजगारात राहून संपूर्ण आयुष्याचे नुकसान न करता या वयात त्यांना शिक्षण देऊन बौद्धिक आणि शारीरिकदृष्ट्या सक्षम झाल्यानंतर भविष्यामध्ये तो अधिक उत्पन्न मिळवेल असे मुलांच्या पालकांना पटवून दिले पाहिजे. बाल कामगार हे विविध प्रकारच्या क्षेत्रांमध्ये काम करतांना दिसतात, या कामादरम्यान त्यांचे आर्थिक, मानसिक व शारीरिक शोषण केल्या जाते. या शोषणाविषयी समाजामध्ये जागरूकता निर्माण करणे गरजेचे आहे.

#### प्रसार माध्यमांचा उपयोग

बाल मजुरीची समस्या ही खूप पूर्वीपासून चालत आलेली कुप्रथा आहे. ती नष्ट करण्यासाठी निरंतर प्रयत्नाची गरज आहे. समाजामध्ये हे पटवून दिले पाहिजे की ही वाईट प्रथा असून यामुळे मुलांचे खूप मोठे नुकसान होते. बाल कामगारांच्या समस्याकडे लोकांचे लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी सर्व प्रसार आणि प्रचार माध्यमांचा प्रभाविपणे उपयोग केला पाहिजे.

### रोजगाराच्या संधीत वाढ

दारिद्र्य, बेरोजगारी या समस्येप्रमाणेच भारतामध्ये बाल कामगार ही एक समस्या आहे. या कुप्रथेचे समुळ उच्चाटण करण्यासाठी बाल कामगारांच्या आई वडीलांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा व लहान मुलांना शिक्षणाबरोबरच रोजगार प्राप्तीच्या संधी उपलब्ध करून देणारे शिक्षण दिले पाहिजे.

### कुटुंबाचा आकार कमी ठेवणे

भारतामध्ये वेगवेगळ्या अभ्यासाच्या निरिक्षणावरून असे दिसून येते की, गरिब आणि अशिक्षित कुटुंबाचा आकार मोठा असतो. अशा कुटुंबातील कुटुंब प्रमुखाची अशी धारणा असते की, 'जास्त मुले म्हणजे जास्त उत्पन्न' होय. कारण अशी मुले थोडी मोठी होताच कुटुंबाचा आर्थिक आधार बनतात. अशा वेळी कुटुंब प्रमुखाला योग्य मार्गदर्शन करून लहान वयात काम केल्यामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामाविषयी माहिती द्यावी व कुटुंबाचा आकार नियंत्रणात ठेवण्याचे कायदे सांगावे व समाजामध्ये या समस्येविषयी जनजागृती करावी.

### संदर्भसूची :

- १) रोडे विजयकुमार (२०१३): "आर्थिक विकास: एक चिंतन", चिन्मय प्रकाशन, औरंगाबाद.
- २) देशपांडे के.ना., माळी आ.ल.(२००७): "भारतीय शिक्षणाचा इतिहास", नित्य नूतन प्रकाशन, पुणे.
- ३) कुलकर्णी शालिनी (२००९): "भारतीय व पाश्चात्य शिक्षणतज्ज्ञ", नित्य नूतन प्रकाशन, पुणे.
- ४) बोधनकर सुधीर, चव्हाण साहेबराव (२००८): "श्रम अर्थशास्त्र", श्री साईनाथ प्रकाशन, नागपूर.
- ५) Chauhan I.S. (2003): "Child Labour A Global Challenge", Deep & Deep Publication, New Delhi.
- ६) Chhina S.S. (2009): "Child Labour Problem And Policy Implications", Regal Publications, New Delhi.

## मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. सुभाष यादव

शोधार्थी, मनोविज्ञान विभाग,  
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

### Abstract :-

मानसिक स्वास्थ्य एक तरह का समायोजी व्यवहार (Adjustive Behaviour) है जो व्यक्ति को जिंदगी के सभी प्रमुख क्षेत्रों जैसे-सांवेगिक (Emotional), सामाजिक एवं शैक्षिक आदि में सफलतापूर्वक समायोजन करने में मदद करता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति या छात्र अपने व्यक्तित्व की विभिन्न इच्छाओं, आवश्यकताओं, शीलगुणों आदि के बीच एक ऐसा सामंजस्य रखता है कि जिंदगी के सभी क्षेत्रों में एक संतोषजनक समायोजी व्यवहार करने में समर्थ हो। मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन 'मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान' (Mental Hygiene) के अन्तर्गत किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान - 'मेंटल हाईजीन' एक ऐसा विज्ञान है जो व्यक्तियों में मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ रखने तथा मानसिक बीमारी को न होने देने संबंधी तथ्यों को उजागर करता है। ड्रेवर के अनुसार- "मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध मानव कल्याण से है और जो मानव-संबंधों के सब क्षेत्रों को प्रभावित करता है।"

### Key Words :-

मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हाईजीन, समायोजन, मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन में अंतर्संबंध, कुण्ठा, तनाव, अंतर्द्वंद्व, दुश्चिन्ता, दबाव, कुसमायोजन, रक्षात्मक युक्तियाँ।

### मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के प्रमुख कार्य :-

मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के कार्यो को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है- निरोधात्मक (Preventive), संरक्षणात्मक (Preservative) एवं उपचारात्मक (Curative)। निरोधात्मक कार्य से तात्पर्य मानसिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले तत्वों की रोकथाम करने से है। संरक्षणात्मक कार्य से तात्पर्य मानसिक स्वास्थ्य बना रहे इसके लिए उत्तरदायी कारकों को बनाए रखने से है। उपचारात्मक कार्य से तात्पर्य जल्द से जल्द मानसिक समस्याओं या बीमारियों को पहचान कर उसे दूर करना है।

### मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ प्रमुख बातें :-

पूर्ण मानसिक स्वास्थ्य जैसी कोई बात नहीं होती है। मानसिक स्वास्थ्य एक गतिशील अवधारणा है। बिना शारीरिक स्वास्थ्य के मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति संभव नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य समायोजन में सहायक है।

### मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्य :-

अपनी अन्तः शक्तियों से अनुभव करना, मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा/संरक्षण, मानसिक बीमारियों को रोकना, मानसिक रोगों का उपचार, लोगों के आत्मविश्वास में परिवर्तन लाना एवं मानसिक अस्पताल की अवस्थाओं में सुधार लाना इसके प्रमुख उद्देश्य हैं।

**मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों की विशेषताएँ :-**

आत्म ज्ञान, आत्म मूल्यांकन, आत्म श्रद्धा एवं आत्म विश्वास, सुरक्षा का भाव, संतोषजनक संबंध बनाए रखने की क्षमता, शारीरिक इच्छाओं की संतुष्टि, उत्पादक एवं खुश रहने की क्षमता, तनाव एवं अति संवेदनशीलता की अनुपस्थिति, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, जिन्दगी का एक स्पष्ट सिद्धांत, वास्तविक प्रत्यक्षण, स्पष्ट जीवन लक्ष्य।

**मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक :-** घरेलू वातावरण, विद्यालय का वातावरण, अभिवृत्ति/मनोवृत्ति, शारीरिक स्वास्थ्य, माता-पिता का मानसिक रोग से पीड़ित होना एवं मुख्य आवश्यकताओं की संतुष्टि।

**समायोजन (Adjustment) :-**

समायोजन व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकताओं तथा उपलब्ध साधनों एवं परिस्थितियों के मध्य एक सामंजस्य की अवस्था है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि समायोजन से तात्पर्य व्यक्ति विशेष की उस मनोदशा स्थिति अथवा किये जाने वाले उस व्यवहार प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से वह यह अनुभव करता है कि उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि हो रही है और उसका व्यवहार समाज और संस्कृति की अपेक्षाओं के अनुकूल चल रहा है। जीव विज्ञान में जिसे अनुकूलन कहा जाता है, मनोविज्ञान में इसी को समायोजन की संज्ञा दी जाती है। आईजैक के अनुसार—“समायोजन वह अवस्था है जिसमें एक ओर व्यक्ति की आवश्यकताओं तथा दूसरी ओर वातावरण के अधिकारों में पूर्ण संतुष्टि होती है अथवा यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा इन दो अवस्थाओं में सामंजस्य प्राप्त होता है।” बेरिंग व अन्य अनुसार—“समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन स्थापित करता है।” उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कोई बालक या व्यक्ति तभी तक समायोजित अनुभव करता है जब तक उसकी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति से जुड़ी हुई उसकी कोशिशों तथा परिस्थितियों के बीच संतुलन बना रहें।

**समायोजन की विशेषताएँ:-**

समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सुखी व संतोषप्रद जीवनयापन किया जा सकता है। समायोजन हमें मनोवैज्ञानिक रूप से अनुकूलन सिखाता है। समायोजन द्वारा

इच्छाओं और आवश्यकताओं में संतुलन स्थापित होता है। समायोजन व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित करता है। समायोजन व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है।

**समायोजित व्यक्ति की विशेषताएँ एवं गुणः—**

शारीरिक दृष्टि से समायोजित, संवेगात्मक रूप से समायोजित, स्वयं की अच्छाइयों तथा सीमाओं का ज्ञान, आत्म सम्मान एवं दूसरों के प्रति सम्मान की भावना, सामाजिक रूप से समायोजित, उचित महत्वाकांक्षा स्तर, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, छिद्रान्वेषी प्रकृति का न होना, लचीला व्यवहार एवं परिस्थितियों से संघर्ष करने की क्षमता।

**कुसमायोजन (Maladjustment) :—**

जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं तथा वातावरण के उन कारकों जिनसे उन इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की सही ढंग से संतुष्टि होती है के बीच एक संतुलन बनाए रखता है तब हम उस प्रक्रिया को समायोजन की संज्ञा देते हैं परंतु जब किन्हीं कारणों से यह संतुलन बिगड़ जाता है, तब इस अवस्था को कुसमायोजन की स्थिति कहा जाता है। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि यदि छात्र या शिक्षक में कुसमायोजन की स्थिति लंबे अरसे तक बनी रहती है, तो इससे उनके व्यक्तित्व में असामान्यता (Abnormality) उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है।

**बालकों में कुसमायोजन के कारणः—**

कुंठा (Frustration), शारीरिक बनावट, गरीबी, बिखरे घर, माता-पिता की मनोवृत्ति/अभिवृत्ति, दत्तक ग्रहण (Adoption), नियोजन संबंधी असुरक्षा (Employment insecurity), वातावरण, मनोरंजन के साधनों की कमी एवं बालकों के प्रति यौन-आधारित व्यवहार।

**कुसमायोजित व्यक्ति के लक्षणः—**

आत्म नियंत्रण का अभाव। हीनता की भावना से ग्रसित होना। असुरक्षा की भावना से ग्रसित होना। आत्मविश्वास की कमी। समस्यात्मक तथा असामाजिक व्यवहार। अपराधी व्यवहार का प्रदर्शन। मानसिक अस्वस्थता एवं मानसिक विकारों से ग्रस्त होना। चिन्ताग्रस्त होना। आक्रामकता। निर्दयता। धैर्य एवं सहनशीलता का अभाव। प्रेम, आदर एवं सहानुभूति का अभाव। झगड़ालु प्रवृत्ति का होना।

**समायोजन से संबंधित समस्याएँः—**

**कुंठा/भगनाशा (Frustration):—**

कुंठा व्यक्ति विशेष की वह अवस्था है जिसमें उसके प्रयत्नों पर विफलता का आधिपत्य रहता है। इस अवस्था या स्थिति में व्यक्ति विशेष यह अनुभव है कि उसकी किसी महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति में कठिनाई या प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है जो



उसके सामर्थ्य में बाधक है। सारांश में कहा जाएँ तो बार-बार प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती है तो व्यक्ति कुण्ठा अथवा भग्नाशा का शिकार हो जाता है।

### मानसिक संघर्ष/अन्तर्द्वंद्व (Conflicts):-

मानसिक संघर्ष से तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से होता है जब परस्पर दो या दो से अधिक विरोधी या एक-दूसरे से असंगत प्रवृत्तियाँ या इच्छाएँ एक साथ अपनी संतुष्टि चाहती हैं ऐसी स्थिति में दोनों प्रवृत्तियाँ एक दूसरे की संतुष्टि में बाधा डालती हैं जिससे एक तरह के संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम मानसिक संघर्ष या अन्तर्द्वंद्व कहते हैं।

मानसिक संघर्ष/अन्तः द्वंद्व मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं:-

#### 1. उपागम-उपागम संघर्ष (Approach-Approach Conflicts):-

दो धनात्मक लक्ष्यों या दो अति आकर्षक इच्छाओं में से किसी एक को चुनने की विवशता को उपागम-उपागम संघर्ष कहते हैं। इसमें दोनों लक्ष्य सकारात्मक/ धनात्मक होते हैं, जैसे-एक विवाह योग्य नवयुवक के सामने दो शादी के प्रस्ताव।

#### 2. परिहार-परिहार अन्तः द्वंद्व/संघर्ष (Avoidance-Avoidance Conflict):-

दो ऋणात्मक/अनाकर्षक लक्ष्यों या इच्छाओं में से किसी एक को चुनने की विवशता को परिहार-परिहार संघर्ष करते हैं। जैसे:- इधर गिरे तो कुआँ और उधर गिरे तो खाई।

#### 3. उपागम-परिहार संघर्ष (Approach-Avoidance Conflict):-

एक लक्ष्य हो परंतु उसके प्रति परस्पर विरोधी भाव हो, तो इसे उपागम-परिहार संघर्ष कहते हैं। जैसे- परिवार की इच्छा के विरुद्ध प्रेम विवाह किया जाये अथवा नहीं। उपागम-परिहार संघर्ष का एक अन्य प्रकार भी है:-

#### बहु उपागम परिहार संघर्ष (Multiple Approach Avoidance Conflict):-

इसमें दो या दो से अधिक धनात्मक एवं दो या दो से अधिक ऋणात्मक लक्ष्य व्यक्ति को एक साथ अपनी-अपनी ओर खींचने लगते हैं। जैसे- नौकरी पेशा महिला जिसकी शादी उसके मनपसंद परन्तु बेरोजगार युवक से होने वाली है तथा उसके बाद उसे शहर तथा नौकरी छोड़नी होती है।

#### दुश्चिन्ता (Anxiety):-

दुश्चिन्ता एक सामान्य मनोरोग है। व्यक्ति की अधूरी इच्छाएँ जो अचेतन मन में चली जाती हैं वे इच्छा जब पुनः चेतन मन में आने का प्रयास करती हैं तो व्यक्ति दुश्चिन्ता का शिकार हो जाता है। कॉलमैन के अनुसार- "भय और आशंका की सामान्यीकृत अनुभूति ही दुश्चिन्ता है।"

#### तनाव (Tension):-

जब व्यक्ति समय की मांग के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है तो वह तनाव का शिकार हो जाता है।

#### **दबाव (Stress):-**

दबाव व्यक्ति के सफलता-असफलता के बीच संघर्षरत रहने की स्थिति है। व्यक्ति के आंतरिक दबाव उसकी आत्म प्रतिष्ठा को बनाये रखने में महत्वपूर्ण होते हैं। सी.जी. मोरिस के अनुसार— “दबाव एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक प्रतिब अवस्था है जिसमें व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसे एक विशिष्ट भावना के अनुसार रहना है अथवा उसे तीव्र गति से हो रहे परिवर्तनों के साथ अनुकूलन/सामंजस्य करना है।”

#### **कुसमायोजन से बचने के उपाय:-**

कुसमायोजन से बचने हेतु मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार मानसिक मनोरचनाएँ, समायोजन युक्तियाँ या रक्षात्मक युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। मनोरचनाओं या रक्षात्मक युक्तियों से अभिप्राय व्यक्तियों द्वारा अपनायी गई ऐसी युक्तियों अथवा विशिष्ट प्रकार की व्यवहार क्रियाओं से है जिनका प्रयोग उनके द्वारा परिस्थिति विशेष में अपने आपको चिंता और कमियों से मुक्ति दिलाकर अपने आत्म तथा अहम की रक्षा के लिए एक स्थायी या अस्थायी कवच या साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। जे.डी. पेज के अनुसार— “कई प्रकार के संवेगात्मक आघात, कुण्ठाओं तथा अन्तर्द्वंद्व के फलस्वरूप जब मनोवैज्ञानिक संतुलन को खतरा पैदा हो जाता है तब मानव जिन छल-प्रपंचों तथा चक्रव्यूहों का सहारा दोषारोपण से बचने हेतु लेता है उन्हें ही रक्षात्मक युक्तियों या मनोरचनाएँ कहा जाता है। मानसिक मनोरचनाओं या रक्षात्मक युक्तियों के द्वारा व्यक्ति के समायोजन या अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए किए जाने वाले उपायों को दो भागों में बांटा जा सकता है:-

#### **1. प्रत्यक्ष उपाय**

#### **2. अप्रत्यक्ष उपाय**

##### **I. प्रत्यक्ष उपाय:-**

प्रत्यक्ष उपाय के अन्तर्गत निम्नलिखित उपायों को सम्मिलित किया जाता है:- बाधाओं का निस्तारण, अन्य मार्ग अन्वेषण, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन एवं विश्लेषण व निर्णय।

##### **II. अप्रत्यक्ष उपाय :-**

अप्रत्यक्ष उपायों के अन्तर्गत निम्नलिखित मनोरचनाओं या रक्षात्मक युक्तियों को सम्मिलित किया जाता है:-

##### **1. युक्तिकरण/तर्कसंगतीकरण/औचित्य स्थापन (Rationalisation):-**

इसमें व्यक्ति अपने व्यवहार एवं कार्यों को सही सिद्ध करने का प्रयास करता है। इस मनोरचना में व्यक्ति जो कर चुका है अथवा जो करने वाला है उस कार्य के

संबंध में तर्क देकर उचित ठहराने का प्रयास करता है। जैसे अंगूर प्राप्त न होने पर, इसे इस तर्क से सिद्ध करना कि अंगूर खट्टे है।

**2. प्रक्षेपण (Projection)**

प्रक्षेपण के अन्तर्गत व्यक्ति अपनी कमजोरियों और दोषों की झलक दूसरों में देखने का प्रयास करता है। व्यक्ति अपने दोषों तथा कमजोरियों के लिए वातावरण तथा परिस्थितियों को दोष देकर अपने अहम् और आत्मसम्मान की रक्षा का झूठा प्रयत्न करता है। जैसे नाच न जाने, आंगन टेढ़ा।

**3. अन्तः क्षेपण (Interjection)**

जब व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के शीलगुणों या वातावरण के गुणों को अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित कर लेता है तब यह प्रवृत्ति अन्तः क्षेपण कही जाती है। जैसे किसी के दुःख में दुःखी होकर स्वयं उसके जैसा अनुभव करना। अन्तः क्षेपण की प्रक्रिया प्रक्षेपण के विपरीत है।

**4. दमन (Repression)**

इस रक्षा युक्ति में असामाजिक एवं अनैतिक इच्छाओं को चेतना से हटाकर अचेतन में डाल देता है।

(नोट—जबकि शमन (Suppression) में व्यक्ति चेतन रूप में तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थिति या इच्छाओं को भुलाने का प्रयास करता है।)

**5. प्रतिगमन (Regression)**

पीछे की ओर लौटना अथवा भूतकाल में वापिस जाना प्रतिगमन कहलाता है। इसके अन्तर्गत कोई व्यक्ति अपने आप को मानसिक तनावों और संघर्षों से बचाने के लिए अपनी आयु स्तर के नीचे के स्तर का व्यवहार करने लगता है। जैसे—एक विवाहित लड़के या लड़की का अपनी माँ के सामने फूट-फूटकर रोना।

**6. विस्थापन (Displacement)**

व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के प्रति अपने विचारों या भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाता है एवं अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु को माध्यम बनाता है तो इसे विस्थापन कहा जाता है। जैसे ऑफिस में बॉस से डाँट पड़ने पर घर आकर बॉस का गुस्सा पत्नी पर उतारना। या जैसे जिस बालक को माता-पिता से अच्छी तरह डाँट पड़ी है वह आक्रोश की अभिव्यक्ति के लिए बगीचे के फूलों को माध्यम बना लेता है।

**7. आत्मीकरण (Assimilation)**

अपने गुण दोष भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुण व दोषों को अभिव्यक्त करना आत्मीकरण कहलाता है। इस मनोरचना में व्यक्ति अपने व्यवहार तथा अपनी क्रियाओं को किसी अन्य व्यक्ति के अनुसार बनाने का प्रयास करता है।

**8. दिवा-स्वप्न (Day Dreaming)**

इसमें व्यक्ति अपने पसन्द की निजी काल्पनिक दुनियाँ बसाकर अपने आप को उसी में बंद कर अपनी अतृप्त इच्छाओं, दूषित भावनाओं या कुण्ठाओं की संतुष्टि करता है अर्थात् हवाई किलों के माध्यम से संतुष्टि प्राप्त करता है। जैसे वास्तविक दुनिया में क्रिकेट का एक पराजित खिलाड़ी सपनों में क्रिकेट का सितारा बनकर चौका-छक्का लगाकर दर्शकों की प्रशंसा लूट रहा होता है।

**9. उदात्तीकरण/शोधन/मार्गान्तीरण (Sublimation)**

इस मनोरचना में व्यक्ति अपनी असंतुष्ट या दमित इच्छाओं की पूर्ति समाज द्वारा अमान्य व्यवहार के माध्यम से न करके इनकी पूर्ति समाज द्वारा स्वीकृत लक्ष्यों या उद्देश्यों के रूप में प्रतिस्थापित करके करता है। इस मनोरचना से संबंधित व्यवहार समाज की दृष्टि में मान्य होता है। समाज में इसका एक निश्चित मूल्य होता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास, बैजू बावरा इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। किशोर अवस्था में संवेग नियन्त्रण का सर्वोत्तम उपाय शोधन ही है।

**10. क्षतिपूर्ति (Compensation)**

क्षतिपूर्ति में व्यक्ति अपनी हीनताओं एवं आयोग्यताओं से उत्पन्न मानसिक तनाव को कुछ ऐसी क्रियाएँ करके दूर करता है जिसमें उसे श्रेष्ठता तथा आत्म संतोष का भाव होता है। जैसे अच्छा धावक की योग्यता न हो तो अच्छा गायक बन जाना।

**11. स्थानान्तरण (Transference)**

व्यक्ति मानसिक संघर्ष से बचने के लिए स्थानान्तरण मनोरचना का भी प्रयोग करता है। स्थानान्तरण एक ऐसी मनोरचना है जिसमें व्यक्ति अपने प्रेम, आक्रामकता या घृणाका भाव एक व्यक्ति या वस्तु से हटाकर दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध स्थापित कर उसे जोड़ता है।

**12. प्रतिक्रिया निर्माण (Reaction Formation)**

इस मनोरचना में व्यक्ति मानसिक संघर्ष से बचने के लिए किसी कष्टकर एवं अप्रिय इच्छा तथा प्रेरणा के ठीक विपरीत इच्छा या प्रेरणा विकसित करता है। जैसे भ्रष्ट नेता द्वारा भ्रष्टाचार के विरोध में भाषण देना।

**13. प्रत्याहार (Withdrawal)**

इस मनोरचना में व्यक्ति मानसिक संघर्ष या तनाव से बचने के लिए इस तरह की स्थिति उत्पन्न करने वाली परिस्थिति से अपने आप को दूर रखता है। इस मनोरचना का अधिक प्रयोग करने से व्यक्ति लज्जालु एवं भीरु स्वभाव का हो जाता है।

#### 14. नकारात्मकता (Negativism)

इस मनोरचना में व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति विकसित कर लेता है तथा अपने अहं को मानसिक संघर्ष या तनाव से बचा लेता है। इस मनोरचना का उपयोग बच्चों द्वारा अक्सर किया जाता है प्रायः यह देखा जाता है कि बच्चे उन कार्यों को नहीं करते हैं जिन्हें माता-पिता उन्हें करने के लिए कहते हैं बल्कि उन कार्यों को करते हैं जिन्हें माता-पिता उन्हें नहीं करने के लिए कहते हैं।

#### 15. तादात्म्यीकरण (Identification)

इस मनोरचना में व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करने लगता है। इसके अलावा अपनी जान-पहचान वाले किसी व्यक्ति की सफलता से स्वयं को दूसरों के सम्मुख पहचान करवाना भी तादात्म्यीकरण कहलाता है।

**समायोजन प्रक्रिया में अध्यापकों का योगदान/समायोजन स्थापित करने में अध्यापकों का योगदान:-**

संतुलित बुद्धि और विकास पर ध्यान देना चाहिए। बालकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयत्न करना। बालकों को उनकी ताकत और कमजोरी का ज्ञान करवाना। आकांक्षा का उचित स्तर तय करना। तनाव संबंधी सहनशीलता विकसित करना। समाज और संस्कृति की मांगों से सामंजस्य स्थापित करना। स्वस्थ एवं उचित वातावरण प्रदान करना। निर्देशन व परामर्श की व्यवस्था करना। विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना तथा उनका मनोबल विकसित करना। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रबंधन करना।

**संदर्भ सूची :-**

- Baron, R.A. & Misra, G (2015), Psychology: New Delhi : Pearson Education India.
- Singh Arun Kumar (2017) Adhunik Samanaya Manovigyan, New Delhi : Moti Lal Banarsai Das.
- Cicarelli, S.K. White, J.N. & Misra, G (2017) Psychology, New Delhi : Pearson Education India.
- Gerrig, R.J. Zimbardo, P.G. Suartal, F. Brennen, T. Donalson, R & Archer, T. (2013), Psychology & Life, New Delhi : Pearson Education India.



- 
- Baron, R.A. Branschomble. N.R., Byrne, D. & Bhardwaj. G (2012), Fundamentals of Social Psychology, Noida : Dorling Kindersely South Asia.
  - Morgen King, Introduction to Psychology : TMH
  - Dr. Prabha Sharma, Prakash Naryan Natani (2007), Educational Technology and Class Room Management : Maya Prakashan Jaipur.
  - Myers D.G. (1994). Exploring Social Psychology. New York : MC graw Hill.
  - Arun Kumar Singh. Samaj Manovigyan ki Ruprekha ; Moti Lal Banarsi Das Delhi.
  - [www.mhrd.gov.in](http://www.mhrd.gov.in)
  - [education.gov.in](http://education.gov.in)
  - Singh Arun Kumar : Siksha Manovigyan : Moti Lal Banarsi Das Delhi.
  - Singh Arun Kumar : Manovigyan Mein Mapan Avam Mulayankan, New Delhi : Moti Lal Banarsi Das
  - Agarwal J.C. (2016), Educational Technology, Information and Communication Technology : Shri Vinod Putak Mandir Agra.